Sixth Series, Vol. XV—No. 51.

Friday, May 5, 1978
Vaisakha 15, 1900 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(10)

PA[illegible] LIBRARY
Acc. No. [illegible](2)
Date 12.8.78

(Fourth Session)

सत्यमेव जयते

(*Vol. XV contains Nos. 51—58*)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Rs. 4.00

CONTENTS

(Sixth Series, Volume XV, Fourth Session, 1978

No. 51, Friday, May 5, 1978/Vaisakha 15, 1900 (Saka)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions :	
Starred Questions Nos. 988, 990, 991, 993 and 994 . .	1—35
Short Notice Question No. 8	36—47
Written Answers to Questions :	
Starred Questions Nos. 987, 989, 992 and 995 to 1006 . . .	48—62
Unstarred Questions Nos. 9201 to 9314, 9316 to 9368, 9370 to 93 and 9382 to 9400	62—261
Papers laid on the Table	261
Committee on Papers laid on the Table—	
Fourth Report presented	262
Matters under Rule 377—	
(i) Centrally sponsored Rural Link Roads Scheme— Dr. Laxminarayan Pandeya	262—64
(ii) Reported Sharp Fall in price of Short Staple Cotton in Gujarat—Shri Motibhai R. Chaudhary	264—66
(iii) Reported Strike by Employees of Instrumentation Ltd.— Shri A. K. Roy	266
(iv) Ganges Printing Ink Factory Ltd. Howrah (West Bengal)— Prof. Dilip Chakravarty	267
(v) Reported Deterioration in Law and Order Situation in Delhi Shri Nirmal Chandra Jain	267—68
Motion *re.* Draft Five-Year Plan, 1978—83—	
Shri M. N. Govindan Nair . . .	268—71
Shri Tej Pratap Singh	272—82
Shri Ramjiwan Singh	282—92

*The sign + marked above the name of a Member Indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

Shri Dhirendranath Basu . . . . . 292—95

Shrimati Kamala Bahuguna . . . . . 295—300

Shri Vasant Sathe . . . . . 300—30

Shri Chandra Pal Singh 307-308

Bills Introduced—

(i) Motor Vehicles (Amendment) Bill (Amendment of Section 95) by Shri R. D. Gattani 309

(ii) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill (Insertion of new section 40A) by Shri Tej Pratap Singh . . . 309-10

(iii) Trade and Merchandise Marks (Amendment) Bill (Amendment of section 78, 79 etc.) by Shri Kanwar Lal Gupta . 310

(iv) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 30) by Shri G. M. Banatwalla 310-11

(v) Minimum Wages (Amendment) Bill (Amendment of section 2 and 3) by Shrimati Parvathi Krishnan 311

(vi) Beedi and Cigar Workers (Condition of Employment) Amendment Bill (Amendment of sections 2, 17, etc.) by Shrimati Parvathi Krishnan 311

(vii) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 48 and Seventh Schedule) by Shri R. D. Gattani . . . 312

(viii) Indian Trusteeship Bill by Shri Arjun Singh Bhadoria 31

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 51) by Shri Hari Vishnu Kamath—

Motion for circulation—

Shri P. K. Deo . . . . . 313—15

Shri Shankar Dev 315-16

Shri Shanti Bhushan 316

Income-tax (Amendment) Bill—

Motion to consider—

Shri Kanwar Lal Gupta . . . . . 317—24

Dr. Ramji Singh . . . . . 325—30

Shri Hukamdeo Narain Yadav . . . . . 330—37

COLUMN

Shri P. K. Deo . . . . . 337—39

Shri Manoranjan Bhakta . . . . . 339—41

Shri Vayalar Ravi . . . . . 341—45

Shri Ram Naresh Kushwaha . . . . . 345—50

Shri H. M. Patel . . . . . 350—51

Shri Kanwar Lal Gupta . . . . . 351—55

Constitution (Amendment) Bill—

(Insertion of new Articles 23A, 23B and 23C)

Motion to consider—

Shri Y. P. Shastri . . . . . 355—70

Dr. Ramji Singh . . . . . 370—74

LOK SABHA

Friday, May 5, 1978/Vaisakha 15, 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रोज-वुड और चन्दन की लकड़ी का निर्यात

*988. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) देश के किन-किन भागों में रोज-वुड और चन्दन की लकड़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और गत वर्ष, देशवार यह कितनी मात्रा में निर्यात की गई ;

(ख) इसमें कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). रोज वुड मुख्यत: केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में उगाई जाती है । चन्दन की लकड़ी मुख्यत: कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है और इसका उत्पादन प्रधानत: कर्नाटक राज्य के मैसूर क्षेत्र में संकेन्द्रित है । वर्ष 1976-77 में भारत से निर्यात की गई रोज वुड चन्दन की लकड़ी का मूल्य तथा परिमाण (देशवार) संलग्न विवरण–I में दिया गया है ।

(ग) हमारी नीति ऊंचे दाम देने वाली मदों तथा रोज वुड के विनियर्स तथा प्लाइवुड नथा सुगंधी की मदों तथा चन्दन के तेल के ही निर्यात बढ़ाने की है । जहां तक रोजवुड का सम्बन्ध है, लट्ठों तथा चिरी हुई लकड़ी के निर्यातों पर कोटा प्रतिबन्ध लगाए गए हैं जब कि चिप्स बिलेटों तथा स्पेंटडस्ट पूलक्स के निर्यात सम्बन्धित राज्य वन प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण तथा परिवहन परमिटों में दी गई मात्रा तक आयात की अनुमति है । ये उपाय असाधित लकड़ी के निर्यातों को हतोत्साहित करने के लिये किये गये है ताकि स्वदेशी उद्योग के विकास के लिये बड़ी मात्रा में कच्चा माल मिल सके, जो रोजगार तथा निर्यात अभिमुख है ।

विवरण–I

रोजवुड

देश	इकाई	1976–77	
		मात्रा	मूल्य (रु०)
आस्ट्रेलिया	क्यू०मी०		6,728
बैल्जियम		72	1,99,062
केमरून			1,946
कनाडा		21	2,76,943
डेनमार्क		414	17,02,870
दुबाई		9	76,145
फ्रांस		305	23,20,174
जर्मन लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य		1437	1,27,62,780
यूनान		6	11,201
हांगकांग		668	9,25,297
इजराइल		45	1,95,271
इटली		3065	2,78,83,378
जापान		14334	5,75,23,850
मारीशस		1	5,433
ओमन		14	1,21,355
नीदरलैंड		196	5,50,170
न्यूजीलैंड		7	48,666
नार्वे		79	5,44,542
सऊदी अरब		8	48,475
सिंगापुर		14	1,31,604
स्पेन		214	8,82,467
स्वीडन		16	95,341
स्विटजरलैंड		39	2,24,455
ब्रिटेन		341	11,01,037
सं० रा० अमरीका		632	40,68,073
		21937	11,16,97,263

चन्दन की लकड़ी

देश	इकाई	1976–77 मात्रा	1976–77 मूल्य (रु०)
दुबाई	मे० टन	5	27,940
फ्रांस		5	1,78,000
हांगकांग		169	61,21,775
जापान		36	17,73,718
ओमन		1	38,984
सऊदी अरब		14	3,84,022
सिंगापुर		58	27,26,563
स्पेन		1	12,743
सूडान		66	17,00,106
ब्रिटेन		2	53,000
सं० रा० अमरीका		2	30,103
		354	1,30,46,949

श्री ईश्वर चौधरी : माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है, उसमें सरकार की यह नीति स्पष्ट की गई है कि चन्दन और रोज़-वुड की लकड़ी के निर्यात की अनुमति स्वदेशी उद्योग के विकास को मद्देनज़र रखते हुए ही दी जाती है । किन्तु चन्दन की लकड़ी के निर्यात के बारे में जो विवरण दिया गया है, उससे पता चलता है कि जिन देशों को निर्यात किया जा रहा है, उसकी मात्रा बराबर है, लेकिन रेट अलग-अलग हैं । उदाहरण के लिए ब्रिटेन के लिए मूल्य 53,000 रुपये और यू०एस०ए० के लिए 30,103 रुपये दिया गया है । इसी प्रकार दुबाई के लिए 27,940 रुपये और फांस के लिए 1,78,000 रुपये मूल्य दिया गया है । ऐसा लगता है कि निर्यात के सम्बन्ध में एग्रीमेंट करने में खर्च का भी असर पड़ता होगा । चन्दन और रोज़वुड लकड़ी की देश में ही खपत हो और स्वदेशी उद्योग-धंधों का विस्तार हो, क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित प्रदेशों को कोई मश्वरा और सहयोग दिया है ?

मैं उद्योग मंत्री जी से यह भी जानना चाहता है कि इसको आगे बढ़ाने के लिये आप ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री आरिफ बेग : अध्यक्ष महोदय, हम यही चाहते है कि जो कीमती लकड़ियां ह, उन का उपयोग अधिक से अधिक हमारे अपने देश में हों, जिसचे लोगों को रोज़गार मिले और जो उनसे बना हुआ सामान हो, उस को अधिक से अधिक विदेशों में भेजें, जिसमें हमको फारन-एक्सचेंज कमाने का मौका मिले । इस सम्बन्ध में हमने जो नीति बनाई है उस के अनुसार अगले तीन वर्षों में हम इस कीमती लकड़ी को लाग-बुड की

शक्ल में बाहर नहीं भेजेंगे, बल्कि फर्नीचर या दूसरी चीजों की शक्ल में, वैल्यू एडेड आइटम्ज़ की शक्ल में, बाहर भेजेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले ।

श्री ईश्वर चौधरी : मैं मंत्री जी का बहुत आभारी हूं, हमारी भावना भी यही थी कि हमारे यहां का कच्चा माल हमारे यहां ही खपत हो और उनके माल बना कर हम बाहर भेजें, जिससे हमें फारेन-एक्सचेंज मिल सके । लेकिन दूसरी ओर हमारे कुछ प्रदेशों के वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है, जिसके कारण कीमती लकड़ी जैसे चन्दन की लकड़ी का दुरुपयोग हो रहा ह, जिससे मैं समझता हूं–मंत्री महोदय भी चिन्तित होंगे ।

क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में प्रदेशों के वन-विभागों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन निकट भविष्य में बुलाकर, उन्हें इस तरह के सुझाव देंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं––जैसा आपने कहा है कि हम कच्चा माल अपने यहां खपाकर, उनसे जो माल बनेगा, उसको विदेशों में भेजेंगे––क्या आप इस सम्बन्ध में कोई कारखाना लगाने का विचार कर रहे है या जो सम्बन्धित ठेकेदार है, उन को इस तरह का परामर्श दे रहे हैं ?

श्री आरिफ बेग : जैसा मैंने अभी माननीय सदस्य को बतलाया था––सरकार की नीति यही है कि हम अधिक-से-अधिक लोगों को रोज़गार दें । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी सदन को बतलाना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से अभी तक इस कीमती लकड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया था । रोज़-वुड के वृक्ष को पूरी तरह से बढ़ने में 100 वर्ष से 150 वर्ष लगते है । यदि हमने इसकी तरफ तवज्जह नहीं दी, तो अगले कुछ वर्षों में यह लकड़ी हमारे यहां नहीं मिलेगी । दो-चार वर्ष में इसका जो आज का उत्पादन 30 हजार क्युविक मीटर है, वह घट कर आधा रह जायगा । इसलिये सरकार ने इसकी तरफ तवज्जह दी है कि इसकी रक्षा की जाय, इस के कारखाने लगें, लोग इसका सामान बनायें और इस तपह से हजारों लोगों को काम मिल सके ।

DR. V.A. SEYID MUHAMMAD : In the statement placed before the House on the Table, it is stated that export is being discouraged for making available large quantities of raw material in order to develop indigenous industry. May I ask (a) what is the quantity exported and (b) what is the consumption every year of the indigenous industry. Is it not a fact that consumption by the indigenous industry is much, much lower than what is exported, the consequence being a slump in the maket, and that the industrialists are getting these logs at throw-away prices ? I would like to be enlightened on this matter.

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : So far, only wood in log forms or, at the most, in sawn forms, was exported outside. Now, there are hundreds of our carpenters and artists who can add value to the wood and then it could be exported. Therefore, what we have done is that we have restricted exports. For 1977-78 we allowed 10,000 cubic metres to be exported ; for 1978-79 it will be 6,000 cubic metres and for 1979-80 it will be 3,000 cubic metres. And then we shall not allow rosewood to be exported in log form. But we have not said that they cannot export it outside with added value, because in that case, we will be earning more foreign exchange and we shall be generating more employment. Otherwise, the same wood, if exported in log form, would not bring us much. Besides, as my colleague rightly pointed out, let us not forget that the presnt production of 31,000 cu. metres will come down to about 16,000 cu. meters within for years to come. We have never thought about it. Under the circumstances, when such a valuable commodity is being exported outside, it should be the endeavour of the country to see that we earn maximum possible foreign exchange and also give maximum employment to our people.

MR. SPEAKER : His question has not been answered.

SHRI MOHAN DHARIA : Therefore, I say that is not correct that it is being just given away at a throw-away price.

DR. V.A. Seyid MUHAMMAD : My question was : Is it not a fact that the consumption is much lower than the quantity exported every year, the consequence being that the logs are being kept in godowns and there is a slump in prices ?

SHRI MOHAN DHARIA : Sir, we convened a conference of all the officers concerned of the State Governments. We have told them not to allow the cutting of these logs or this wood ; it should only be on the basis of our indigeoous consumption and exports also. All of them have agreed. This policy has been appreciated by all the State Governments concerned and this policy has beeen evolved after long deliberations with the State Governments.

DR. V.A. SEYID MUHAMMAD : Even now it is not anwered. My question was : Is not the consumption much lower than the quantity exported ?

SHRI MOHAN DHARIA : I have said that this is a very important wood ; it is not that way needed for indigenous purposes. The whole point is that we were just exporting logs....

MR. SPEAKER : His question is : Is not the consumption....

SHRI MOHAN DHARIA : I said, Yes.

SHRI A. C. GEORGE : The answer given both by the Minister of State and Cabinet Minister on the face of it looks very innocent, but behind it, there is a very sinister move. Sir, you are quite well aware that the rosewood, it has been indicated in the reply also, is grown in the States of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. In 1975, there was conference held by the IG of Forests with the representatives of the State Governments of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala, the exporters concerned and the industrialists in Bombay and it was decided that 20 to 25 thousand tonnes can be exported every year. This is a definite and sinister move by a few industrialists in the name of value added and high-sounding words to get their raw material at throw-away prices and to deny employment to forest workers in the State of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka and lakhs and lakhs of other workers. May I know from the hon. Minister whether he would be kind enough to look into the fact whether only 2,000 tonnes of rosewood is being consumed at present by the Industries and the availability being 25,000 tonnes, it is only just an excuse to get the rosewood at glut price and it is a sinister move by the Bombay Industrialists.

SHRI MOHAN DHARIA : I would like to make it clear that this is not the earlier Government which would fall a victim to any industralist. It is a Government thinking absolutely indepedently in the interest of the country... (*Interruptions*). There is nothing like a sinister move ; on the contrary, we have taken a scientific approach. Instead of exporting wood of such rich quality at throw-away prices outside, we are going to earn more foreign exhange. We held a conference of the conservators of forests in Delhi. And all of them agreed, 'Yes, it is a wrong move; we should not have exported in the long form. We should have made efforts here,' and I have aleady agreed that if they want to add value and for that if they require some machinery to be imported and if it is not available within the country, we are prepared to allow them to import that machinery. and, again, if they want certain credit facilities....

MR. SPEAKER : You have mentioned that.

SHRI MOHAN DHARIA : We shall make them available. We shall see that value cold be added. And, let us not forget as I said, one tree takes nearly 150 years to grow. Under the circumstances when one tree requires nearly 150 years, should we not be cautious and when the government hss taken these steps which were not taken by the earlier government, instead of commending the job, it is most unfortunate that my friends there should have given some political colour. It is these mistakes committed by him that we are rectifying.

SHRI A. C. GEORGE : The 150 years is applicable to both the industry as well as the exporters.

MR. SPEAKER : Question No. 989—Shri P.G. Mavalankar—absent.

Import of Rudraksha Beads

*990. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is fact that 'Rudraksha' beads are being imported in the country from Indonesia ;

(b) if so, how much quantity of these were imported in 1974, 1975, 1976 and 1977 and at what cost ;

(c) is it a fact that heavy import duty is levied on the Rudraksha ;

(d) whether complaints have been received from public that the importers are doing black market in Rudraksha ; and

(e) if so, will the Government decide to import Rudraksha through S.T.C. and distribute the same through Government Emporia and Consumer Societies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) to (e). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No licence for import of 'Rudraksha' beads has been issued during 1977-78. However, according to the erstwhile import licences, Rudraksha beads of Indonesian origin were being imported by them from Singapore due to non-availability of direct shipping space from Indonesia. Government has no further information in this regard.

(b) Yearwise value of import licences issued during the period 1974-78 is given below :

	Rs.
1974-75	7,500
1975-76	20,000
1976-77	12,500
1977-78	Nil

The quantity of 'Rudraksha' beads imported actually against these values is not recorded separately.

(c) The existing rates of duty on the import of Rudraksha beads is 75% it is in the form of seeds and 120% if it is in the form of finished articles. This duty is in conformity with the general structure of the tariff and the duty applicable to similar category of goods.

(d) No, Sir.

(e) Rudraksha beads have already been included in the Restricted list of items in Appendix 5 of the Import Policy, 1978-79. No imports through the S.T.C. are considered necessary.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : Before I ask my supplementary, would the Government correct the statement because there was a calling attention motion in the Rajya Sabha and in spite of this even in this reply certain facts have not been given. If the government had corrected the statement, then I would have asked my supplementary. The Government say that they have no further information in this regard. Secondly, it is said "The quantity of 'Rudraksha' beads imported actually against these values is not recorded separately. . . ."

MR. SPEAKER : It is only Rs. 10,000—12,000 worth of goods.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : How can I ask my supplementaries, if they do not give full information ? I have been writing to the government for the past so many months and the Government know each and everything and why should they hide it ? Unless the full information is there ...

MR. SPEAKER : Either you ask or do not ask.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : I want to know whether it is a fact that it is the normal practice that the government notes the quantities imported against the import licences given and if so, why in this case the quantities actually imported were not recorded ? This is the normal departmental practice which the Government have not followed then how can I ask my question ?

MR. SPEAKER : You do not put the question but only you make a speech....

DR. VASANT KUMAR PANDIT : My question is : is it a fact that in April 1978 about 87 bags worth of Rudraksha beads about Rs. 30 lakhs wete confiscated by the Police and the Police were inquiring into it through the CBI, while the Customs Department is trying to cover it up? My submission is that a full and complete answer has not been given in this reply. Is it a fact that such an incident has come to the knowledge of the Government and if so, what action has the government taken ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : I do share the concern of the hon. Member that along with the price, the quantity of Rudraksha beads should also have been recorded. This is for the year 1974-75, 1975-76 and 1976-77. Unfortunately there is no mention of the quantity on the

records. We have issued instructions that it should be both price and quantity also, but it will be for the future period.

It is true that certain bags were confiscated: as I am getting the information from the hon. Minister of Finance beause so far as the Customs is concerned, it is very much within the Ministry of Finance, they say, 'Yes, it is very much, there. They were imported by the Bharat Sadhu Samaj and they were allowed to sell it after the confiscated goods were released to them.' But I do not know further details.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : Is it a fact that Bharat Sadhu Samaj was given licence for importing 'Rudraksha'? They imported it through two businessmen who fabricated the documents from the original Import licences. On fabricated copies of import licence, 92bags were imported. Out of this on by seven bags reached Sadhu Samaj and they sold it on no profit and no loss basis. This was one of the conditions of the import licence that this will be sold on 'no profit and no loss, basis and the remaining goods which have now been confiscated have also perculated the black market and now large scale smuggling and black marketing is going on in Rudraksha. Particularly because now the content of political power in Rudraksha has been proved during the erstwhile Government and, therefore.....

MR. SPEAKER : You are a very experienced parliamentarian. The question hour cannot be converted into a speech.

This does not arise from your question. You should have put a question.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : Mr. Bhattacharyya and Shri Vinay Kumar Shah have been involved with the support of the then erstwhile Minister. Therefore the entire....

MR. SPEAKER : I do not know. This is not a question.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : If so, ...

MR. SPEAKER : Actually this does not arise from the question at all.

DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will this Government ansure this House at strictist action would be taken against those who have smuggled these goods and since we require Rudraksha, will it be channelised through S.T. C. and sold on no profit and no loss basis through the-coperative societies?

SHRI MOHAN DHARIA : So far as the first charge is concerned, it is being investigated by the officials of the Ministry and I can assure the hon. member that there is nothing like suppressing anything and if anybody is found guilty, necessary measures will be taken against guilty persons regarding import of Rudraksha. In his current year, according to our policy, it is placed on restricted list and those who want to import Rudraksha, we shall take care that they distribute it in a fair manner and there is nothing like profiteering. There cannot be black marketing because so far the price of a particular thing is not prescribed, till that time there cannot be black marketing. At the most it can be profiteering. We shall see that profiteering does not exist.

SHRI VASANT SATHE : I would like to know firstly, has the Government found out what is the special value or quality of this bead of Rudraksha? After all, about the value and import and smuggling, I do not know. I am told it makes old man young and gives vitality etc. I do not know. I would like to know....

MR. SPEAKER : It is very good, but does not arise from the question.

SHRI VASANT SATHE : I am just wanting to know, what is the value? Does the Government have any scientific method of finding out the genuine Rudraksha and a fake Rudraksha ? This is why smuggling takes place. We are talking of import. What are you going to import? Do you know that you are importing from Nepal or from somewhere else genuine Rudraksha? Suppose you get beads which are carved just like Rudraksha and given colour and sold to you, how will you know that they are genuine? I do not know. Does the Minister know?

Dr. Vasant Kumar Pandit is an astrologer. We are not astrologers. They know the value of Rudraksha. They can pass it on to a man....

MR. SPEAKER : I never knew that you are an astrologer.

SHRI VASANT SATHE : I am not. I am a victim.

They are supposed to ward off influence of certain 'grah'. We have seen a big personality, in spite of Rudraksha, it did not help.....

MR. SPEAKER : Mr. Sathe, your observations are very interestng, but not relevant.

SHRI VASANT SATHE : Why is there import of Rudraksha and how is the Government ensuring that genuine Rudraksha is imported and is made available ? How will he ensure that it is made available to those who really need it if it is of medicinal or some other use? How will he ensure that ?

SHRI MOHAN DHARIA : It is put on the restricted list. We shall try to ensure that genuine Rudrakshas are allowed to be imported and made available.

So far as quality is concerned. I may suggest that better advice and better information would be available from the Leader of the Hon. Member. My reference is to the other great Leader, not this Leader here....

श्री हुकमचन्द राय कछवाय : माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया है कि भारत साधु समाज के लोगों को हम ने परमिट दिया था, इन्हें मंगाने के लिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप ने इन्हें परमिट कब दिया था और कितना मंगाने की अनुमति दी गई थी और जो लाया गया था उसे ईमानदारी से वितरित किया गया था या चोरबाजारी में उसे बेचा गया। मेरे पास समाचार पत्रों की बहुत सी कटिंग्स हैं, जिनमें नाना प्रकार के समाचार आए हैं और यह भी उन में आया है कि इस का काफ़ी गरम बाजार था देश के अन्दर। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो नाना जो प्रकार के घोटाले हुए हैं और अभी बनारस में काफ़ी माल पकड़ा गया है, उस सब के बारे में आप वास्तविक जांच करवाएगें कि क्यों माल छिपा कर रखा था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप का क्या अनुमान है कि कितना माल चोरी-छिपे आता है और कितना चोरी छिपे जाता है और कौन-कौन लोग उस में शामिल हैं। एक समाचार पत्र में तो यह भी कहा गया है कि यह माल जो पकड़ा गया है, अगर सरकार उसकी छानबीन करवाएगी, तो बहुत से सफ़ेद पोश पकड़े जाएंगें। मैं जानना चाहता हूं कि इन सारी बातों की जांच करवा कर क्या मंत्री महोदय सदन को विश्वास में लेंगे ?

श्री मोहन धारिया : जैसा मैं ने पहले बताया है, उसकी जांच तो जारी है। जो लाइसेंस दिये गये वे पहले जमाने के थे यानी नई गवर्नमेंट के आने से पहले वे लाइसेंस दिये गये थे और मैं यह भी कहूंगा कि माननीय सदस्य के पास जो मालूमात हैं, उन्हें वे हमारे पास भेज देगें तो हम फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के पास उन को भेज देगें ताकि जांच करवाने में उन को और सुविधा रहे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने यह भी पूछा था कि जो लाइसेन्स दिये गये, उन में कितने मंगवाए गए और कब मंगाए गये।

अध्यक्ष महोदय अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

New Tourist Centres in Gujarat

*991. SHRI AHSAN JAFRI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to lay a statement showing :

(a) how many tourist centres have been set up by the Central Government in Gujarat state ;

(b) is there any plan to start new Tourist centres in Gujarat by the Central Government;

(c) the details of tourist centres in which the Central Government have decided to set up Janata Hotels; and

(d) the total amount which Central Government is going to spend for developing the tourist centres in Gujarat upto 1980?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (घ). राज्य सरकार से प्राप्त हुए पर्यटन विकास के बारे में पर्स्पेक्टिव प्लान पर राज्य की 1978–83 की पर्यटन संबंधी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के समय विचार-विमर्श किया जाएगा और उसी समय यह भी तय किया जाएगा कि

कौनसी स्कीमों को केन्द्रीय और कौनसी स्कीमों को राज्यीय क्षेत्र में आरम्भ किया जाएगा। परन्तु उनमें से केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा आरम्भ की जाने वाली स्कीमों की संख्या साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) 1978–83 की पर्यटन संबंधी केन्द्रीय पंचवर्षीय योजना में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के चार महानगरों और ऐसे अन्य चुने हुए पर्यटन केन्द्रों पर, जिनका निर्धारण एक सर्वेक्षण कर लेने के बाद किया जाएगा, जनता होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है, परन्तु यह केन्दीय योजना में इस स्कीम के लिए उपलब्ध कराए गए साधनों पर निर्भर करेगा। आरंभ में एक जनता होटल का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है जिसके लिये सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

विवरण

दूसरी, तीसरी योजनाओं, तीन वार्षिक योजनाओं, चौथी योजना तथा पांचवी योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में गुजरात में प्रारम्भ की गई पर्यटन स्कीमों को दर्शाने वाला विवरण

दूसरी पंच-वर्षीय योजना

क्रम सं०	स्कीम का नाम	व्यय
1	2	3
1.	अहमदाबाद में पर्यटक ब्यूरो . .	5,046

तीसरी पंच-वर्षीय योजना

भाग—I

1.	लोथल में जल-सप्लाई	1,07,310
2.	ससन के विश्राम-गृह में सुधार . . .	68,860
3.	केशोद और ससन के बीच तथा ससन से गिर तक परिवहन सुविधाएं	62,031

भाग—II

1.	पोरबन्दर में निम्न आय-वर्गीय विश्राम-गृह . .	33,188
2.	चोरवाड में होलिडे होम	50,000
3.	नल सरोवर में कैफेटेरिया	25,000
4.	लोथल में कैंटीन-व-रिटायरिंग रूम . .	98,820
		4,45,209

1	2	3
	वार्षिक योजना 1966–67	
1.	लोथल में जल-सप्लाई (पूर्व योजना का अवशिष्ट)	1,000
2.	लोथल में कैंटीन-व-रिटायरिंग रूम	31,000
3.	ससनगिर फारेस्ट बंगले का सुधार	13,000
		45,000
	वार्षिक योजना 1967–68	
1.	लोथल में जल-सप्लाई स्कीम (पूर्व योजना का अवशिष्ट)	5,000
2.	लोथल में कैंटीन-व-रिटायरिंग रूम (पूर्व योजना का अवशिष्ट)	10,000
3.	लोथल के कैफेटेरिया के लिए एप्रोच रोड	30,000
4.	साबरमती में पर्यटक बंगला	6,000
		51,000
	1968–69	
1.	साबरमती में पर्यटक बंगला	73,000
	चौथी पंच-वर्षीय योजना	
1.	साबरमती आश्रम में पर्यटक बंगला	3,63,000
2.	साबरमती आश्रम में सौं-एट-लुमिएर शो	12,00,000
3.	गिर वन में विश्राम-गृह	9,14,000
4.	गांधीनगर में युवा होस्टल	3,24,000
5.	पोरबंदर में पर्यटक बंगला	5,00,000
6.	गिर के वन्य जीव शरण-स्थल के लिए दो मिनी-बसों की व्यवस्था	82,000
		33,83,000
	पांचवीं पंच-वर्षीय योजना 1974–75	
1.	गांधीनगर में युवा होस्टल	8,085
2.	पोरबंदर में पर्यटक बंगला	3,57,850
3.	ससनगिर में फारेस्ट लॉज	1,11,000
		4,76,935

1	2	3
	1975–76	
1.	गांधीनगर में युवा होस्टल . . .	68,295
2.	पोरबंदर में पर्यटक बंगला . . .	1,77,037
		2,45,332
	1976–77	
1.	गांधीनगर में युवा होस्टल . . .	312
2.	पोरबंदर में पर्यटक बंगला	40,380
3.	ससनगिर में फारेस्ट लॉज	1,93,354
		2,31,046
	1977–78	
	ससनगिर में फारेस्ट लॉज (भारत पर्यटन विकास निगम) के माध्यम से उपकरणों व साज-सज्जा की व्यवस्था के लिए .	6,59,000

श्री अहसान जाफरी : मैं ने जो सवाल पूछा था उस में यह कहा था कि गुजरात में पर्यटक केन्द्र खोलने के बारे में सरकार क्या करने जा रही थी । इस सम्बन्ध में यह सवाल था पर जो स्टेटमेंट रखा गया है, इससे मालूम पड़ता है कि काफ़ी समझदारी के साथ गुजरात में टूरिस्ट सेन्टर्स को डेवलप करने के सिलसिले में जो बात थी, उसे नज़रान्दाज किया जा रहा है । मैंने जो सवाल पूछा था, उस में यह था कि डिटेल्स दी जाएं कि केन्द्रीय सरकार गुजरात में जनता होटल और टूरिस्ट सेन्टर्स बनाने के लिए 1980 तक क्या करने जा रही है लेकिन जवाब यह दिया गया कि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो प्लान स्टेट गवर्नमेंट से मिले हैं, उनके ऊपर हम सोच विचार करेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी प्लान दिये जा चुके हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वेरावल काम्प्लेक्स के लिए जो ससनगिर सोमनाथ और द्वारिका के बीच में है, वह एक ऐसी जगह है जहां सब जा सकते हैं । सोमनाथ और ससनगिर में लाखों आदमी यहां के आते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं । उस के लिए आप ने क्या किया है या आयन्दा क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में ठोस बात बताएं । इतना ही कहा है कि जो प्लान मिला है उस पर हम सोच विचार करेंगे । सवाल यह है कि जो प्लान मिल चुका है उसके बारे में आपने क्या सोचा है ? कितना पैसा अब आप खर्च करने जा रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जैसा मैंने निवेदन किया है 1978–79 के लिए स्टेट सैक्टर में जो 25 लाख रुपया मिला है उसका

विवरण मैंने दे दिया है । छठी योजना का जहां तक सवाल है उसके बारे में जैसा परस्पैक्टिव प्लान स्टेट गवर्नमेंट हे मिला है उस पर हम विचार करेंगे और माननीय सदस्य का जो सुझाव है द्वारिका के बारे में और बीच के इलाके को डिवेलेप करने फे बारे में उस पर निश्चित रूप से अन्य वातों के साथ-साथ विचार किया जाएगा ।

जहां तक जनता होटलों का सवाल है जैसा मैंने निवेदन किया है सर्वेक्षण करने के बाद कि कहां कहां इनकी आवश्यकता है निर्णय किया जाएगा और उसके साथ-साथ जो साधन उपलब्ध होंगे उन के अनुसार विचार किया जाएगा ।

इसके अलावा मैंने यह भी कहा है कि केवल केन्द्रीय साधनों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है । जनता होटलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों और राज्यों के जो पर्यटन निगम हैं उनको भी साधन जुटाने चाहियें । लोगों से भी मैंने अपील की है कि जनता होटलों के निर्माण में वे मदद करें ।

श्री अहसान जाफरी : जनता होटल शुरू करने के लिए, उनका सिलेक्शन करने का जो आपने क्रम शुरू किया है क्या गुजरात उस में नहीं आता है, क्या वहां कोई सेंटर ही नहीं बन सकता हैं । गुजरात में यात्री बाहर से बहुत बड़ी संख्या में आते है, वहां सूरत, अहमदाबाद आदि शहर है, गीर के वहां जंगल है, द्वारिका है, वेरावल का कम्प्लैक्स है, ये सब हैं । दस करोड़ 32 लाख के करीब आप खर्च करने जा रहे है चार शहरों के लिए मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता आदि के लिए । गुजरात में जनता होटल बनाने के लिए कोई प्लान ही आपकी समझ में नहीं आता है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : समझ में तो आता है । लेकिन दस करोड़ का जो प्रावधान किया गया है यह चार जो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं और जहां ये जनता होटल बनेंगे 1250 कमरे वाले उनके लिए ही यह पर्याप्त होगा । सर्वेक्षण के बाद लगेगा और जो नई नीति बनेगी और हर साल रोलिंग प्लान के अनुसार देखेंगे कि क्या उपलब्धियां हुई हैं और क्या कमियां रह गई हैं, तो इस पर विचार किया जा सकता है और राशि का पुन: निर्धारण किया जा सकता है ।

श्री धर्मसिंह भाई पटेल : It has been stated in the Statement attached to the answer on page 2 that in 1977-78 there is a scheme for a forest lodge at Sassangir (for equipment and furnishings through I.T.D.C.) Costing Rs. 6,59,000—मैं जानना चहता हूं कि यह जो फर्निचर अभी तक नहीं पाहुंचा है इसको आप कब तक भेज देंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है इसको मैं देख लूंगा और जल्दी सामान पहुंच जाएगा ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : अम्बा जी जोकि आबू के निकट है उसको पर्यटन केन्द्र बनाने की मांग की गई है, उसका पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की मांग की गई है । पिछल साल की यह जो मांग है इसके बारे में भी क्या सोचा गया है । यह हिल्ली एरिया भी है, तीर्थ स्थान भी है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक तीर्थ स्थलों का सवाल है जैसा इसके पहले भी मैं सदन में बता चुका हूं हम एक सेंट्रल सोसाइटी बना रहे हैं जिस में हम आप जो लोग हैं उनसे भी साधन जुटाने को कहेंगे और सरकार की ग्रांट इन एड भी होगी । तीर्थ स्थानों में आम तौर से तीर्थ यात्री धर्म शालाओं में ठहरना पसन्द करते हैं । अब धर्म शालाओं पर कहां कहां और क्या क्या सुधार किया जाए ताकि वे रहने लायक बन जाएं, इस सब पर विचार करते समय निश्चित रूप से माननीय सदस्य के सुझाव को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

SHRI HITENDRA DESAI : Gujarat has a complex—Veraval Complex—from where we go to Dwarka, Somnath and even go to Gir where Gir lion is famous in Asia. So, Veraval is there; Ahmedabad is there. Gandhi Ashram is here. Will the Government consider putting up of the Janata Hotel either at Ahmedabad or at Veraval?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : माननीय सदस्य का जो सुझाव है जैसा मैंने निवेदन किया है इस पर हम विचार कर सकते है ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अन्तर्गत बने नियमों की क्रियान्विति

*993 **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय/विभाग ने अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा अधिनियम, 1963 और जून, 1976 में उसके अन्तर्गत बने नियमों के बारे में सूचित किया है और उनका पालन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय विभाग ने उपरोक्त उपबंधों और नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और राजभाषा से संबंधित नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों का पूरी तरह से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

श्री नवाब सिंह चौहान : यदि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक विवरण भी सदन में रख देते, तो अच्छा होता ।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने राजभाषा अधिनियम को देखा होगा और उस के नियमों को भी पढ़ा होगा .... (**व्यवधान**)

SHRI K. GOPAL: Sir, same type of questions for various Ministries are appearing every day in the list of oral questions. There is some fraud. It must be probed.

(*Interruptions*)

SHRI VASANT SATHE : It is high time this Hindi chauvinism is stopped. In fact, they are doing more harm than benefit to Hindi.

MR. SPEAKER : Mr. Gopal, if you have any positive complaint against the office you let me know. I will give you an opportunity to prove it. But you cannot on the Floor of the House say that they are fraud. They are not here to defend themselves. It is not proper. If there is any circumstantial evidence I am prepared to look into that. If anyone of you have a genuine complaint I am prepared to go into the matter but I deplore the remark which has been made. It is not proper to make allegations against the staff in the open House. They will get frustrated. The ballot may favour one person today and another person some other day.

SHRI K. GOPAL : This is the circumstantial evidence. You may please to go into it. How can it come everyday ? I am fully convinced.

(*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA : Sir, we have no allegation against the office but an impression gets created in the mind of the people from Southern States that Hindi is being imposed as same type of questions are put again and again and discussed on the Floor of the House.

श्री नवाब सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने से पहल मैं यह कहन। चाहता हूं कि वैलट के बारे में शिकायत इमें भी है । परन्तु वहां मेम्बरों को भी बुलाया जाता है । इस लिए आप आपोज़ीशन के इन सदस्यों को कहिये, जो इस बारे में शिकायत कर रहे है, कि वे जा कर वैलट को देखा करें ।

यहां तो कभी साल में एक दो कोई आ जाता है और अचानक ही आ जाता है। जिसको हम नहीं चाहते है वह आ जाता ह। इसलिए मैं और ज्यादा कुछ इस पर नहीं कहूंगा।

मैं यह पूछना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने क्या राजभाषा अधिनियम के अन्दर और रूल्स के अन्दर यह देखा ह ....

MR. SPEAKER: Everybody knows it. You need not explain the rules. Please come to the question.

श्री नवाब सिंह चौहान: ए बी सी राज्यों के लिए क्या क्या किस तरीके से वह बना हुआ है और क्या यह सच है कि तमिलनाड को राजभाषा अधिनियम के परव्यू से बिलकुल अलग रखा गया है? आप का स्टैंडर्ड क्या है हर एक श्रेणी के राज्यों के लिए यह क्या बताने की कृपा करेंगे?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरे मंत्रालय के लिए आया हुआ यह पहला ही सवाल है और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो फैसला हमारी गवर्नमेंट ने दिया है उस के मुताबिक पूरी कार्यवाही नहीं चलती है, यह भी कहना ठीक नहीं है। परन्तु हमें यह जरूर ख्याल में सुना होगा कि पूरे मुल्क को साथ में लेकर जाना होगा। जिस वक्त हम हिन्दी इंट्रोडयूस करना चाहते हैं तो यह काम मुहब्बत से होगा, किसी प्रकार के कोयसिव तरीके से नहीं होगा।

श्री नवाब सिंह चौहान: इस को अगर उन्होंने पढ़ा होता तो मालूम होता कि कोई चीज इस तरह जबर्दस्ती नहीं लादी गई है। तीस वर्षों के अन्दर अभी आप यह नहीं कर पाए है कि आप के दफ्तरों के ऊपर बाइलिंगुअल साइन बोर्डस लग सकें। क्या आप यह समझते है कि यह इतना बड़ा काम है? इतना छोटा काम भी नहीं हुआ है। दफ्तरों में यहां जो मामूली से मामूली चीज कही गई ह क्या आप ने उस की जानकारी की है उसे किया गया है? इतना थोड़ा काम है उस की भी जानकारी नहीं की जाती है और फिर यह कहा जाता है कि हम देश को रखना चाहते है। इस में कोई देश को गिराने की बात है ही नहीं।

श्री मोहन धारिया: जैसा मैंने बताया जो इंस्ट्रक्शन्स दिए हुए है उन का पूरा पालन तो होता ही है। इतना ही नहीं, बल्कि हाउस को यह जानकर खुशी होगी कि हमारे जो इंटरनेशनल ऐग्रीमेंट या प्रोटोकाल होते हैं; हम ने अब ऐसा शुरू किया है कि अंग्रेजी के के साथ हिन्दी में प्रोटोकाल और ऐग्रीमेंट होता है और उस पर भी दस्तखत किए जाते है। तो यह तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन में नहीं था, फिर भी हम ने शरू किया है। लेकिन मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि यह काम सब को साथ में लेकर होगा। कोई जबर्दस्ती करेगा तो उस से हिन्दी की हानि होगी, कोई फायदा नहीं होगा, यह मैं कहना चाहूंगा।

SHRI DINEN BHATTACHARYA: The hon. Minister has given the answer. Now, may I know whether it is in his knowledge that in the Department of Commerce, so many employees who are in Class III service are not getting any promotion because they have not yet passed the prescribed Hindi examination? Is that correct? If so, how many officials are there in this category?

SHRI MOHAN DHARIA: Sir, I have gone into this aspect and also here and I am prepared to take the House into confidence and say that in the Commerce Ministry—the House will be happy to know—because of the training programmes, out of 608, except 108, all have taken necessary lessons of Hindi. In Civil Supplies and Co-operation, out of 236, there are only 25 who are yet to get training. We are making all possible efforts that they should take that training. It is our effort that all should try to understand Hindi language. So far as the promotions are concerned, it is not correct to say that they are being held up because they do not know Hindi.

Investigation into non-payment of Income Tax by Birla Group

*994. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of FINANCE be pleased to lay a statement showing :

(a) whether the investigation into the non-payment of income-tax and avoidance of income-tax by several firms controlled by Birla Group have been completed;

(b) if so, what are the names of the companies and the charges; and

(c) if the investigations are complete, the action taken against these companeies ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c). The process of unearthing tax-evasion and avoidance is a continuous one. The cases of the Birla Group continue to be under investigation.

2. During the financial years 1976-77 and 1977-78, besides other cases, the cases of Electric Equipment and Construction Company Limited, Hyderabad Asbestos Cement Products Ltd., India Steamship Company Ltd., Hindustan Aluminium Corporation Ltd., Gwalior Rayon and Silk Manufacturing Company Ltd., Kesoram Industries and Cotton Mills Ltd., Orient Paper Mills Ltd., and Texmaco Ltd. belonging to the Birla Group have been investigated. Tax avoidance and evasion through various devices including claim for bogus selling commission, inflation of purchases, excessive capitalisation for claiming higher development rebate and depreciation, wrong claim for bad debts, under valuation of closing stock, passing of capital outlay as revenue expenditure etc. have been detected. Assessments have been and are being made after making necessary disallowances and additions; penal proceedings being initiated wherever called for.

श्रीमती मृणाल गोरे : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकती हूं कि विड़ला जैसे उद्योग समूह से सम्बन्धित कम्पनियों की जांच सतत रूप से चालू रहेगी और रहनी चाहिये । एक मंत्री महोदय के जवाब से मैं देख रही हूं कि कर की चोरी का कोई भी तरीका इन लोगों ने छोड़ा हो—ऐसा मुझे नहीं लग रहा है । मैं कहना चाहूंगी कि कई बार इस लोक सभा में इसके बारे में सवाल पूछे गये हैं लेकिन बार बार यही जवाब सुनने में आया कि जांच चालू है, जांच की कार्यवाही चालू है और इसके बारे में जो भी मालूमात होंगे वह टेबल पर रख दिए जायेंगे । 8 जुलाई, 1977 को श्री हुकम देव नारायण यादव ने जो सवाल क्रमांक संख्या 2911 पूछा था जिसका सम्बन्ध सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पयदन शुल्क से था, उसके भाग (ख) और (ग) की सूचना के सम्बन्ध में उत्तर देते हुये बतलाया गया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी । इस प्रकार चांच तो हमेशा चालू रहेगी इसमें कोई शक नहीं है परन्तु मेरा प्रश्न है कि जिन कम्पनियों के नाम दिये हैं उनके बारे में 1976–77 साल में किसी भी कम्पनी की जांच पूरी नहीं हुई कि कितनी चोरी हुई और कितना दण्ड लगाया गया—क्या कोई एक भी आंकड़ा सरकार इन कम्पनियों के बारे में नहीं दे सकती है ?

SHRI H. M. PATEL : I am afraid there is certain misunderstanding. Continued investigation does not mean that there is no recovery of taxes from these groups. I think the Birla Group of companies pays regularly at least Rs. 50-60 crores every year in taxes; investigation does not mean that no recovery is being made.

Take Electric Equipment and Construction Company Limited. I mention the type of things that were found and what is being done. There was a claim of substantial commissions paid through cheques to various persons. I hope other do not learn from this. Those persons are alleged to have rendered services for obtaining orders from the State electricity boards and other parties. Enquiries from electricity boards and other parties revealed that those persons did not render any service and some of the persons were found to be non-existent. The entire claim of commissions being bogus is proposed to be disallowed and an addition of Rs. 6·81 lakhs is proposed to be made on this score in the assessment year 1971-72 reopened for this purpose. Similar claims in other areas are being enquired into.

In the case of Hyderbad Asbestos Cement Products Ltd., the company claimed mining expenses in Nepal which were found on enquiry to be expenses on exploring and prospecting. It was further found that the mines were not commercially exploited at all. The company surrendered for taxation a claim to the extent of Rs. 47 lakhs. The same company also claimed substantial mining expenses as revenue expenses in respect of Indian mines. On investigation they were found to be developing and prospecting expenses. They were in the nature of capital expenditure. The amount of Rs. 42 lakhs was determined as capital expenditure to be disallowed during the assessment years 1964-65 to 1972-73. Some of the assessments are yet to be made. Similar disallowance has been made in the assessment year 1973-74. The company also claimed commission paid to certain associated concerns; the payment was found to be made for no services having been rendered at all by the payees.

एक माननीय सदस्य : क्या यह दोबारा पढ़ रहे हैं ?

SHRI H. M. PATEL : I am only telling दोबारा नहीं पढ़ रहा हूं—

I hope you are understanding what I am saying.

India Steam Ship Company Limited. The shipping companies are entitled to development rebate allowance at 40 per cent to total cost of purchase of a ship in additional to usual depreciation to the extent of full cost. Thus ....

श्रीमती मृणाल गोरे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस स्टेटमेंट को यहां रख देते तो अच्छा था । इस तरह पढ़ने में तो बहुत समय चला जाएगा और हमको प्रश्न पूछने का समय नहीं मिलेगा ।

SHRI H. M. PATEL : I think it is desirable that you know this. If you want to ask other questions, I am willing. But this will be of interest to you. Thus for capital expenditure of say, Rs. 100, the total deduction allowed to the shipping companies comes to.... (*Interruptions*)

MR SPEAKER : Mr. Minister, there are two things. You could have given this in a proper statement because it is a very long statement. I am only suggesting to you. And further from waht you say, it looks as if a separate income-tax department is necessary for this company.

SHRI H. M. PATEL : May I say that it is necessary and that is why we have in fact a cell in Delhi? I may say that I could not have given this kind of information in a statement because I had to reply to the qestions. It is arising from this question that certain additional information is furnished. If the House do not wish to hear information of this kind, I will keep them. Otherwise, I would say that this is of interest. If you like, let me give you the information about his company only. I need not give you anything more.

SHRI KRISHAN KANT : The details should be laid on the Table of the House.

SHRI H.M. Patel : It is not exhaustive. (*Interruptions*).

श्रीमती मृणाल गोरे : अध्यक्ष महोदय, इस तरह मुझे दूसरा सवाल पूछने का समय नहीं बचेगा । मैंने पहले सवाल में पूछा था—इसके बारे में कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है....

MR SPEAKER : Shrimati Gore, may I suggest to you a course? After the supplementary, we shall leave it for a half-an-hour discussion.

SHRI H. M. PATEL : No, no. There is no point in half-an-hour discussion.

MR SPEAKER : It is a very important matter.

SHRI H. M. PATEL : I have no objection to half-an-hour discussion. (*Interruptions*) I am saying that it is not strictly correct. I think you must be aware that the Birla Group consists of a very large number of companies. For instance, the Report of the Industrial Licensing Policy Enquiry Committee, 1969 lists 203 companies as belonging to larger industrial houses of the Birlas. The said report also lists in addition 73 companies as Birla second-tier companies.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Birla Empire.

SHRI H. M. PATEL : Of course. Now they have gone upto a much larger number. To give you an idea of what is involved, I was trying to give you instances of some of the major companies as to what is happening. The entire thing would mean that you will have to write volumes. and I do not think that the House has time either in half-an-hour discussion or otherwise, to do this thing.

It is not necessary either. But I can assure the House that all these matters are being fully investigated and nobody is allowed(*Interruptions*).

SHRI C. M. STEPHEN : The whole matter is covered in a report of Public Accounts Committee, which we have submitted to the House.

SHRI H. M. PATEL : The hon. Member is now telling this. But he aware as to for how many years the Sarkar Commission which they had appointed many many years ago-has been working on this thing. Why did they not do anything about it, and allowed it to go on for many, many years? It is still to report. We are definitely going into this thing and see that the matter is investigated.

श्रीमती मृणाल गोरे : आपने जो यह अलग अलग कम्पनियों के मामलों के बारे में बताया, यह बिल्कुल सही है कि वोल्यूम भर जायेंगे लेकिन बिड़ला कम्पनियों की चोरी का कभी पता नहीं लगेगा । सवाल यह है कि इनमें जो जांच चल रही है, उसके बारे में आपने कुछ किया है या नहीं ? किस प्रकार की कार्यवाही की और क्या दंड उन्हें मिला और मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या दूसरी कायवाही उनके खिलाफ नहीं हो सकती है ?

SHRI H. M. PATEL : We are taking all steps that we can, as is called for.

SHRIMATI MRINAL GORE : What are the steps? प्रोसीक्यूसन किया है ।

SHRI H. M. PATEL : All manner of steps. I think prosecution comes in at a certain stage. Before that, I may tell you that the number of cases in which there are court orders which prevent any further action being taken against the tax payers, is very large. For instance, I will give you a case here. There is one instance of Shri Raja Baldev Das Birla, Jaipur and of Shri Santosh, Pilani. From 1970-71 to 1974-75 there were demands of Rs. 11-odd lakhs each year. This whole demand has been stayed by the Calcutta High Court. I can go on giving you cases.

MR SPEAKER : Her question is not whether action has not been taken, but in how many cases have you been able to take action: and what action has been taken.

SHRI H. M. PATEL : Action means that you disallow certain items that may be called for; and the amount of tax payable is increased—which they have to pay. The point then is, is it that since it is paid, there is no further action called for? Penaties are also levied, as called for under the rules, For this the whole processis gone through.

AN HON. MEMBER : Why not Tihar jail ?

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह बताया है कि कुछ केसेज में तो इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, कुछ कोर्ट में पड़े हैं, कुछ कोर्ट ने रोक दिये हैं और ऐसा लगता है कि कोई एक्शन उनके खिलाफ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बिरला के मामले बहुत समय से पड़े हुये हैं, तो क्या वे इस बात पर विचार करेंग कि जो मामले कोर्ट में बिरला के खिलाफ पड़े हुये हैं उनके लिए एक स्पेशल बेंच बनाई जाये ? कोर्ट में 15, 15 साल से मामले उनके खिलाफ पेन्डिग पड़े हुये हैं और मामले इन्वेस्टीगेशन में हैं । क्या मंत्री महोदय की नालिज में यह है कि जो आदमी इन्वेस्टीगट कर रहे थे, उनमें से बहुत से बिरला के यहां जा कर नौकरी करने लग गये हैं और बिरला ने उनको बहुत बड़ी बड़ी पेमेन्ट पर रख लिया है और उन्होंने इन केसेज को खराब किया है ? क्या मेम्बर आफ पार्लियामेंट की कोई ऐसी कमेटी बन सकती है जो इस सारे मामले की जांच करे और यह देखे कि जो इन्वेस्टीगेशन करने वाले लोग हैं, क्या बिरला के प्रेसर में आकर तो कहीं उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और कोई गड़बड़ तो नहीं है । इसके लिए आपने क्या किया है ?

करे। उस का यह अधिकार हो जाता है कि वह अपना पूर्ण जीवन जिये और उसको वह सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। यह बात अगर कहीं भी स्वीकार की गई तो हम उसकी भूरिभूरि प्रशंसा करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने एम्पलायमेंट गारंटी की स्कीम लागू की है और केन्द्रीय सरकार के सामने वह स्वीकृति के लिए है। अभी उस को स्वीकृति नहीं मिली है। मैं मानता हूं कि न केवल उस को ही केन्द्रीय सरकार स्वीकृति देगी बल्कि समूचे देश के लिए इसे स्वीकार किया जाएगा और लागू किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री सही माने में इस देश के महान गांधीवादी नेता हैं। सत्य पर उन की अटूट निष्ठा है। यह जो घोषणापत्र तैयार किया गया था इस में उन की भी सहमति है। यह वचन उन्होंने दिया है कि देश की जनता को इसलिए उनसे हमारी यह अपेक्षा है कि वह यह अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिससे आगे आने वाली मानव जाति उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए याद रखे कि उन्होंने अपने देश के नागरिकों को काम करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया, हिन्दुस्तान को उन्होंने यह अमिट वरदान दिया और आगे आने वाली संतति के लिए भी सदा सदा के लिए यह वरदान दिया। कभी कभी वह यहां कह दिया करते हैं कि यह अनएम्प्लायमेंट एलावेंस नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह डोल है, यह भिक्षा है, दान है। किन्तु यह भिक्षा नहीं है। यह अधिकार है। काम प्राप्त करने का हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। वे भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इस देश में हम पैदा हुए और आप से चाहते हैं कि आप इस अधिकार को स्वीकार करें और मान्यता प्रदान करें क्योंकि आप ने वचन दिया है और आपके वचन पर अगर हिन्दुस्तान का नागरिक विश्वास नहीं करेगा तो फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति इस देश के अन्दर है जिस के वचन पर विश्वास किया जायगा? इसलिए इस बात को नहीं कहना चाहिए कि यह डोल है, यह दान है, यह भिक्षा है। यह भिक्षा नहीं है। यह हमारा अधिकार है और हमें प्राप्त होना चाहिये। यहां के हर नागरिक को हर नवयुवक को यह मिलना चाहिए। इस से उस को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप वंचित रखना चाहेंगे तो इस देश की जनता अब यह जान गई है कि वह अपना अधिकार कैसे ले सकती है। अगर उसने अपनी लोकतांत्रिक आजादी का अधिकार ले लिया है तो वह काम और जीविका का अधिकार भी ले लेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कहा करती थीं कि 26 जून 1975 के पूर्व की स्थिति अब इस देश में कभी नहीं आएगी, वह समझती थी कि इस देश की नियति का निर्णय करने का अधिकार के वल उन को है, लेकिन देश की जनता ने बता दिया कि 26 जून, 1975 के पूर्व की स्थिति आएगी तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारी कुछ भी स्थिति नहीं है। देश की जनता ने यह बता दिया. कि 26 जून 1975 के पहले की स्थिति हम लौटा कर ही रहेंगे और वह कर के दिखा दिया। अगर हम यह कहेंगे कि यह अधिकार हम तुम्हें नहीं प्रदान करेंगे तो जिस तरह से उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से वह अधिकार ले लिया और उन को इतिहास के गर्त में ढकेल दिया, उसी तरह इतिहास के गर्त में हमारा भी कहीं पता नहीं रहेगा अगर हम ने अपने वचनों को पूरा नहीं किया।

आज देश के नवयुवकों को बहुत बड़ा आघात लगा है। उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा है भविष्य की अनिश्चितता की। उनकी इस भविष्य की अनिश्चितता को मिटाना, उनके भविष्य में प्रकाश लाना-यह हमारी सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य का यह दायित्व आज से ही नहीं है, प्राचीन काल में भी माना गया था कि राज्य का दायित्व है कि जो लोग उस राज्य में बसते हैं, उनको आघात से बचाये,

डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया है । 1978–79 के लिये बिहार के सम्पूर्ण राज्य के लिए एक व्यापक नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत डी० डी० टी० का छिड़काव (रोग से प्रभावित क्षेत्रों में दो बार), रोगियों का पता लगाना तथा उनका उपचार करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना तथा अनुसन्धान कार्यक्रम चलाना, शामिल हैं। वर्ष 1978–79 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के रूप में 134.85 लाख रुपए का कुल परिव्यय रखा गया है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार रोगियों के उपचार के लिए औषधियां देगी ।

2. बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में काला-अजार सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय में एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल बनाया है।

3. रोग से प्रभावित लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एंटीमनी औषधियां प्रदान की हैं।

4. जिन रोगियों पर एंटीमनी औषधियों का असर नहीं होता है उन्हें पेन्टामिडाइन तथा लोमिडिन औषधियां देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये औषधियां खरीद की हैं और बिहार तथा अन्य राज्यों को दे दी हैं ।

5. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने स्वयं मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामड़ी तथा सहर्सा जिलों के काला-अजार से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है तथा इस कार्यक्रम का निरीक्षण किया है ।

6. बिहार में क्षेत्रीय कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के केन्द्रीय दलों ने कई बार दौरे किये हैं ।

7. काला-अजार के निदान तथा नियंत्रण के बारे में चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारम्भ किया गया है ।

8. इस रोग को फिर से फैलने से रोकने के उपाय सुझाने के लिए अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने इस मामले को बहुत पहले उठाया था । उस समय उठाया था जब किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया था । मैंने रूल 377 के तहत इस मामले को उठाया था । 9 जुलाई की यह बात है । उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि काला अजार से सिर्फ सात आदमियों की मौतें हुई हैं । मैंने सरकार को उस समय चेलेंज किया था कि सात आदिमियों की नहीं अकेले वैशाली जिले में दो हजार लोग मरे हैं । इसी हाउस में मैंने कहा था इस चीज को । मैंने यह भी कहा था कि यदि सरकारकी रिपोर्ट सही होगी तो मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा । यह मैंने चैलेंज देकर कहा था उस समय । अफसोस की बात है कि कितनी गड़बड़ रिपोर्ट दी जाती है । मंत्री महोदय यहां बैठे हुये हैं । जो उनको लिख कर दे दिया जात है वही पढ़ देते हैं । श्री यादव ने एक प्रेस कान्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने स्वयं बताया था कि बिहार के चार जिलों में काला-अजार से चार हजार लोग मारेमें हैं । यह 25 सितम्बर की प्रेस कांफ्रेंस उन्होंने कहा था और 27 सितम्बर के हिन्दुस्तान में यह छपा था ।

दिल्ली के राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान द्वारा गत अगस्त के दौरान विहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा सीतामढ़ी जिलों का सर्वेक्षण करने के बाद बताया गया था कि साठ सत्तर हजार व्यक्ति काला अजार से पीड़ित हैं तथा आठ हजार व्यक्तियों की मत्यु हो चुकी है। यह बात स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े संस्थान ने कही है । 1 सितम्बर के पेपर में आया है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा निदेशक, श्रीमती डा० स० ट्रिकी, ने हाजीपुर में निरीक्षण करके कहा कि अकेले वैशाली जिले में 800 गांव काला-अजार की चपेट में हैं। मैंने यह मांग की थी कि काला अज़ार की रोक-थामके लिए डब्ल्यू० एच० ओ० के लोगों को बुलवाया जाये । एक सेंट्रल कमेटी जांच करने के लिए वहां विहार में गई थी । बाद में डब्ल्यू० एच० ओ० के लोग भी वहां गये थे । उन लोगों ने वहां पर जा कर जांच और सर्वेक्षण किया ।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के मलिक आप हैं, आप हम लोगों को गाइड कीजिये कि हम कैसे काम करें । मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि काला अजार से दो हजार से ज्यादा आदमी मरे हैं और सरकार का जवाब बार-बार आता है—अभी भी उसने यही कहा है—कि 270 लोग मरे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकारी रिपोर्ट सत्य है कि 270 आदमी मरे हैं या सरकार के आफिशल्ज, और खुद मंत्री महोदय, ने एन्क्वायरी करने के बाद जो यह कहा कि 4,000 लोगों की मृत्यु हुई है, वह सत्य है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार काला-अजार की रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही कर रही है । दिल्ली के अखबारों में आया है कि यहां पर मलेरिया पहले से छः गुना बढ़ रहा है । मैं बताना चाहता हूं कि मलेरिया का डेवलप रूप काला अजार है । यदि सरकार मलेरिया को नहीं रोक सकेगी, तो वह काला-अजार को भी नहीं रोक सकेगी । मलेरिया के केसों में छः गुना वृद्धि हो गई है और 29 अप्रैल के समाचारपत्रों में आ रहा है कि उत्तर विहार में काला-अजार का पुनः प्रकोप हो गया है और दस हजार आदमी उससे बीमार हैं । इसलिए सरकार को इस बीमारी की रोक-थाम के लिए युद्ध-स्तर पर काम करना चाहिये ।

बिहार में पेंटामाइडीन इन्जेक्शन और इस बीमारी की रोक-थाम की दूसरी दवायें सड़ गल रही है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में कितने लोग काला-अजार से मरे हैं, और काला-अजार तथा मलेरिया की रोक-थाम के लिए सरकार के द्वारा अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं और वह आगे क्या कदम उठाने जा रही है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने बहुत से सवाल एक साथ उठा दिए हैं । एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां जहां काला-अजार का प्रकोप हुआ है, वहां मैं गया हूं और बाद में मैं सहरसा में भी गया हूं । हमने अपने विभाग के अधिकारियों को भी वहां भजा था ।

मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं कि हमने माननीय सदस्य से यह आग्रह किया था कि हमारे लोग वहां जा रहे हैं, इसलिए जिस जिस एरिया में यह बीमारी फैलने की उन्हें जानकारी हो, वह बता दें । लेकिन उन अधिकारियों को सहयोग देने में वह असमर्थ रहे । अगर वह यह जानकारी दे देते, तो अधिक अच्छा होता और इस काम को करने में आसानी होती ।

जहां तक जानकारी रखने की बात है, मेरे पास बिहार के एक एक हिस्से की जानकारी है और उसका सर्वेक्षण किया गया है । इस नक्शे में जहां लाल रंग है, वह वैडली एफेक्टिड है, जहां हरा रंग है, वह उससे कम एफेक्टिड है और जहां पीला रंग है, वहां यह बीमारी स्कैटी है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के अतिरिक्त सहरसा इस बीमारी से प्रभावित हैं ।

MR. SPEAKER: Anyway, that is not the proper way.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इन पोस्टरों से पता चलता है कि कैसे इस बारे में प्रचार किया जाता है और कैसे इस को रोका जा सकता है। इस के लिए भी प्रयास किया गया है । जहां तक हो सकता है, इसकी रोक-थाम की दवाओं को सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है ।

दूसरी बात—इन्होंने मलेरिया और कालाजार को मिलाने का प्रयास किया है । मलेरिया का कीड़ा दूसरा होता है । कालाजार का सैंट फ्लाइ होता है, यह उड़ता भी नहीं है । वह उड़ता है । प्रिवेंटिव मेजर का जहां तक सवाल है दोनों में डी०डी०टी० काम आता है और डी०डी०टी० की जितनी आवश्यकता है उसको हमने पूरा करने की कोशिश की है। एक छिड़काव कौन कहे, दो दो छिड़काव के लिए हमने साधन दे दिये है । जितनी दवाइयों की आवश्यकता है उतनी दवाइयां वहां उपलब्ध करा दीं हैं । तो जो भी व्यवस्था हो सकती है चाहे हमने खुद जा कर के चाह अधिकारियों को भेज करके कर दी है और बिहार सरकार को भी इन्लाइटेन कर दिया है । तो बिहार सरकार भी उसके लिए तैयार है । मैं समझता हू कि मैंने पूरी सूचना इस विवरण पत्र में दे दी है । अगर आप कहें तो मैं फिर पढ़ दूं — 134.86 लाख रुपये उसमें खर्च करने की स्कीम हमने बना दी है 1978–79 के लिए, उस में छिड़काव, पम्प और दवा वगैरह सब के लिए व्यवस्था कर दी है । दो तीन जिलों में तो छिड़काव प्रारंभ हो गया । दो तीन जिलों में और शुरू है और जिलों में भी दो चार दस रोज में छिड़काव का काम प्रारम्भ हो जायगा । तो यह जो कहा जा रहा है कि हुमने पूरी तैयारी नहीं की, यह बात नहीं है । हमने पुरी तैयारी की है और यह हमने उस समय भी वैशाली और मुजफ्फरपुर में जाकर कहा है ।

एक माननीय सदस्य : आदमी कितने मरे हैं ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आदमी की मौत का निश्चित डाटा देना बहुत कठिन है । इसी एन्क्वायरी के लिए हमने अपने अधिकारियों को वहां भेजा । आज माननीय सदस्य यहां कह रहे हैं लेकिन मैंने अधिकारी भेजा माननीय सदस्य को साथ देकर के और उनसे कहा कि जहां जहां उन्होंने हजारों के मरने की बात देखी है उस गांव के बारे में हमको बता दें ताकि हम और लेखा जोखा ले सकें, लेकिन वहां पर हमारे माननीय सदस्य नहीं उपस्थित हो सके । तो हमको जो सरकारी आंकड़े मिले हैं, जो खोज खबर से सूचना है वह 229 की 1977 की है और 6 इधर की मिली है। इसीलिए हमारे पास आंकड़े गिनती के हिसाब से जो आ सके हैं वह आए हैं। और भी कुछ मरे हों तो वह हम वहीं कह सकते लेकिन वह आंकड़े उपलब्ध भी नहीं हो पा रहे हैं उपलब्ध करने के लिए हम अपने अधिकारी को भेजते है, अगर माननीय सदस्य अभी उसमे जानकारी देने की कोशिश करेंगे तो हम उस जानकारी को हमेशा लेने को तैयार रहेंगें ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न था, उसका जवाब नहीं आया । मैं मंत्री महोदय की सराहना करता हूं कि उन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया ।

लकिन मैं इतना ही पूछना चाहता था कि मंत्री महोदय का वह जवाब सही था कि 4 हजार लोग मरे हैं या सरकारी रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा है कि 270 लोग मरे हैं वह सही है ?

MR. SPEAKER: He has said that it was only a rough estimate. After enquiries, he has satisfied himself about correct facts. It may be right or it may be wrong, I am not concerned about it. Please asked the second supplementary.

श्री राम विलास पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न है । यह स्थिति इतनी भयंकर है कि चार हजार लोग मरे हैं, मंत्री महोदय भी इसको कबूल करते हैं लेकिन सरकार चलाने का अपना हथियार है और मंत्री महोदय बहुत बारीक तरीके से निकल रहे है । मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं, मैंने पहले भी पूछा था कि क्या इन चार जिलों में भी कालाजार है या बिहार से बाहर हरयाना, उत्तर प्रदेश इन दूसरे सूबों में भी आने लगा है और यदि आने लगा है तो सरकार कालाजार को युद्धस्तर पर रोकने के लिए भविष्य में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जहां तक 1978 का सवाल है 1978 में दूसरे और किसी राज्य से सूचना नहीं मिली है कि वहां कालाजार हो रहा है । 1977 में कुछ केसेज की खबर मिली थी जैसे बंगाल, मेघालय और एकाध और जगह से यह खबर मिली थी और वह भी कम्यूनिकेबल डिजीज के कारण, जैसे दो बीमार विलिंगडन में आए थे तो वह भी दोनों बीमार बिहार के थे, लौट करके चले गए । इसी तरह बंगाल में भी जो कुछ बीमार हुए थे, वह भी कम्यूनिकेबल डिजीज होने के कारण 1977 में वहां गए थे । मेघालय से जो सात केसेज की रिपोर्ट आई थी वह भी पहले के ही थे और वह बीमार चल रहे थे । दूसरे किसी प्रदेश से 1978 में हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली बिहार को छोड़ कर और बिहार में भी जो भयंकर स्थिति की बात है तो हम ने सारे 31 ज़िलों को जो एग्ज़ामिन कर के देखा तो जिस जिले में काफी है उस में तो हमने दो बार छिड़काव की पूरी व्यवस्था कर दी है । जिसमें थोड़ा भी है उस को भी हमने छिड़काव के लिए लिया है और सारे बिहार के लिए जो मलेरिया के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं डी डी टी स्प्रे का, प्रिवेंटिव मेजर्स मलेरिया और कालाजार दोनों के लिए एक ही है । इसलिए सम्पूर्ण बिहार उसमें कवर्ड है । इस तरह से सम्पूर्ण बिहार में हम वार फुटिंग पर कहिए या जिस फुटिंग पर भी चाहिए, हम इस काम को कर रहे है ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, विगत वर्ष सहरसा जिले के खानबरसा ब्लाक में कालाजार से पांच सौ आदमियों की मृत्यु हुई थी जिसके सम्बन्ध में मैंने यहां पर नियम 377 के अन्तर्गत उल्लेख किया था । मंत्री महोदय भी उस ब्लाक में घुमने गये थे और उन्होंने स्वयं भी देखा परन्तु उनके आने के बाद वहां कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । इसका नतीजा यह हुआ है कि सहरसा जिले के जो अन्य ब्लाक हैं वहां भी कालाजार भयंकर रूप से शुरू हो गया है और सैकड़ों आदमी मरे हैं । मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी खुद वहां देखकर आए हैं, उनके साथ अफसर भी गए थे लेकिन उनके आने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसका क्या कारण है ?

दूसरी बात यह है कि डी डी टी के बारे में आजकल यह कहना है कि जहां भी उसका छिड़काव होता है वहां उससे मच्छर नहीं मरते हैं । हम लोग अपने घर में ही डी डी टी छिड़कते है लेकिन एक भी मच्छर नहीं मरता है । पता नहीं डी डी टी मरी हुई है या क्या बात हैं । क्या मंत्री जी इसकी जांच करेंगे ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जहां तक सहरसा का सवाल है, 1977 में वहां पर 455 केसेज हुए थे और 1977 तथा 1978 को मिलाकर 1464 केसेज हुए हैं और तीन मौतों की खबर है ।

जहां तक डी डी टी के छिड़काव का सवाल है, मलेरिया के जो कीटाणु हैं उनमें कहीं कहीं पर डी डी टी के प्रति रेजिस्टेंस है इसलिए वहां पर दूसरी चीज जैसे वी एच सी या मैलाथियान का प्रयोग किया जाता है । लेकिन कालाजार के सिलसिले में कहीं से यह रिपोर्ट नहीं आई है कि डी डी टी के छिड़कने से सैंड फ्लाई नहीं मरती है । इसलिए इस के सम्बन्ध में यह प्रश्न नहीं उठता । परन्तु जहां तक छिड़काव की बात है हम अभी भी उसमें लगे हुए हैं । चार जिले जो हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सहरसा में दो बार छिड़काव करने का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : छिड़काव नहीं किया गया है, छिड़काव होता भी है तो मच्छर मरते नहीं हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उसका समय आ गया है, छिड़काव प्रारम्भ हो जायेगा अगर अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : मैं मंत्री जी का ध्यान इस पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि मैं खुद भी कालाजार का मरीज रह चुका हूं लेकिन उस जमाने में जबकि यह दवायें नहीं थीं, जब यह समझा जाता था कि इस मर्ज के शत प्रतिशत रोगी मर जाते हैं—सन् 1920 में—लेकिन उस समय जो ब्रह्मचारी की दवा थी, मैं नाम भूल रहा हूं,—हां याद आया टारटार एमेटिक (Tarter-Emetic) उसकी वजह से किसी तरह से बच गया और आज आपसे बातें कर रहा हूं ।

MR. SPEAKER : Are you suggesting that without medicine it is better?

श्री मृत्युंजय प्रसाद : उसका असर यह हुआ कि कालाजार तो चला गया परन्तु वह रोग अपना असर मेरे स्वास्थ्य पर छोड़ गया । आज वे दवायें तो छोड़ दी गईं लेकिन नयी नयी दवायें निकली हैं जिनका आफटर इफेक्ट, बाद का असर कुछ भला नहीं रहा है, वैसा ही रहा है । इसलिए कालाजार की रोकथाम के लिए आप सैंट फ्लाई मारें, मच्छर मारें परन्तु इस रोग के बाद आदमी अधमरा होकर न रह जाये उसके लिए आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ?

MR. SPEAKER: It is a suggestion for consideration.

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, कालाजार का प्रकोप न केवल बिहार में बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक बढ़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि कालाजार की चिकित्सा के लिए हेल्थ विभाग ने प्लानिंग कमीशन से 2 करोड़ 11 लाख रुपए की मांग की थी उसे प्लानिंग कमीशन ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि चिकित्सा राज्य का मामला है—क्या यह बात सही है ? क्या पैसे के अभाव में ही जहां जहां कालाजार का प्रकोप बढ़ा है वहां वहां समुचित रूप से न चिकित्सा हो रही है और न ही उसका ठीक से सर्वेक्षण कराया गया है ? सरकार को यह भी पता नहीं है कि पूरे देश भर में कालाजार से कितने लोग मरे हैं । इस लिये मैं जानना चाहता हूं—क्या यह बात सही है कि प्लानिंग कमीशन से इस के लिये रुपये की मांग की गई थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने यह कह कर उस मांग को ठुकरा दिया कि यह मामला राज्य सरकार का है, केन्द्र का नहीं है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने पुरानी बात को उठाया है । यह जनता सरकार के समय की बात नहीं है । जनता सरकार के आने के पहले इस तरह की मांग की गई थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने यह सोच कर कि स्वास्थ्य का

विषय राज्य सरकारों का है, किसी एक बीमारी का इलाज किया जाना है तो वह राज्य सरकारें करें—उन्होंने उस समय उस मांग को स्वीकार नहीं किया था । बाद में इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा और गत वर्ष जैसे ही हमें इस बीमारी का पता लगा, हमने प्लानिंग कमीशन को एप्रोच किया और उन को बताया कि इस को स्वास्थ्य के विषय में नहीं लिया जाना चाहिये, बल्कि इस बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया है, इस लिये पैसा दिया जाये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया । मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं—मलेरिया फंड से 134.86 लाख रुपये की पूरी योजना बना कर हम बिहार में उस कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं और पैसे के अभाव में या दवा के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे —यह निश्चित बात है ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

New All-Cargo Flights from New Delhi to London by Air India and British Airways

*987 SHRI K. MALLANNA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some new all-cargo flights from New Delhi to London have been decided by the Air India and British Airways ;

(b) whether some new destinations have also been brought on its services through India, Tokyo and Kuala Lumpur in the East and Baghdad in the West ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. With effect from April 1978, British Airways have introduced some scheduled services through India, which touch Tokyo and Kuala Lumpur in the East, and Baghdad in the West, but these are not all cargo, but passenger-cum-cargo services.

(c)

S. No.	Flight No.	Routing	Type of Aircraft	Day of operation
1.	BA 003	London/Frankfurt/Delhi/Kuala Lumpur/Hongkong.	B—747	Saturday
2.	BA 021	London/Doha/Delhi/Hong Kong/ Tokyo.	VC 10	Tuesday
3.	BA 022	Tokyo/Hong Kong/Delhi/Doha/ London.	VC 10	Monday
4.	BA 221	London/Beirut/Baghdad/Delhi	VC 10	Wednesday & Sunday
5.	BA 220	Delhi/Baghdad/Beirut/London	VC 10	Monday & Thursday

Special Compensatory Allowance to Central Government Employees at Gandhi Nagar, Gujarat.

*989. PROF P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government employees at Gandhinagar, Capital of Gujarat have been getting special compensatory allowances ;

(b) if so, since when and how much and on what basis and calculation ;

(c) whether the said Central Government employees are still continuing to receive such a capital allowance;

(d) if so, how many employees get how much; and

(e) if not, why not?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (e). Central Government employees working in Gandhinagar were granted Compensatory Allowance at the rate of 12½ per cent of pay subject to a maximum of Rs. 100 per month with effect from 1-6-1969 keeping in view the difficult living conditions in the initial stages of development of the new Capital of Gujarat. Consequent upon upward revision of pay scales of Central Government employees on the recommendations of the Third Pay Commission, the rate of the allowance was reduced to 10 percent of pay, subject to a maximum of Rs 100 p. m. with effect from 1-4-74. The allowance at the above rate has been granted to all Central Government employees at Gandhinager upto 31st March, 1978. The question whether it should be extended beyond the above date or not is under consideration.

Committee on National Policy on Tourism

*992. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have since constituted a committee to evolve a national policy on tourism ; and

(b) if not, what are the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir.

(b) The Govt. has now revised its earlier decision and a formal Committee for National Policy on Tourism is not being set up. However, a National Tourism Policy statement will be made soon.

नवरंगपुर देवास में हवाई पट्टी का निर्माण

*995. **श्री केशवराव धोंडगे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में कन्धार तालुक के स्थान पर नवरंगपुर के पास में हवाई पट्टी का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई अनुरोध किया गया है ;

(ख) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी हां ।

(ख) से (घ). प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि किसी भी अनुसूचित या गैर-अनुसूचित एयर-लाइनों ने यातायात की कम संभावनाओं के कारण नवरंगपुर देवास या कंधार के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने में रुचि नहीं दिखाई ।

श्री राम रेयन्स कोटा (राजस्थान) द्वारा आयात-लाइसेंसों का कथित दुरुपयोग

*995. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री श्री राम रेयन्स, कोटा (राजस्थान) द्वारा आयात लाइसेंसों के कथित दुरुपयोग के बारे में 23 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित

प्रश्न संख्या 4972 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स श्रीराम रेयन्स, कोटा (राजस्थान) के विरुद्ध जांच अभी तक चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या इस मामले सम्बन्धी पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग). इस मामले की अभी जांच चल रही है ।

Study of Impact of Demonetisation of High Denomination Notes

*997. SHRI HARI VISHNU KAMATH : Will the Minister of FINANCE be pleased be refer to the answer to Unstarred Question No. 598 regarding impact of demonetisation of high denomination currency notes on 24th February, 1978 and state:

(a) whether the study of the impact of demonetisation of high denomination notes has been completed;

(b) if so, whether a detailed statement regarding the impact and effects of the measure will be laid on the Table ;

(c) whether the measure has fully served the purpose which Government had in view ; and

(d) if not, what the precise position is ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (d) . The impact of the measure in all its aspects is still being studied.

So far as the Income-tax Department is concerned enquiries as necessary, are being made, into the sources of the high denomination notes tendered for exchange.

As per information presently available, survey under section 133A and examination under section 131 of the Income-tax Act, 1961 have been conducted in respect of 12,883 declarations. Search and seizure operations have also been conducted under section 132 wherever warranted. Evidence gathered indicates substantial evasion of tax in a number of cases.

Representation from Kerala for withdrawal of excise duty on Electricity

*998. SHRI K. A. RAJAN :
SHRI N. SREKANTAN NAIR :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a representation was made to the Minister by an All-Party delegation from Kerala requesting him to withdraw the excise duty on electricity ; and

(b) if so, the details and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) Yes, Sir.

(b) In support of the withdrawal of the duty it was urged by the representationists that the main attraction of the State for industries is cheap power : imposition of the duty takes this facility away. The State Electricity Board is operating at a loss; with the new imposition, the Board cannot consider any increase in its Tariff to raise resources for itself.

The comparative advantage of cheaper power available in the State will continue to remain, so, as the levy on electricity is uniform throughout India. It cannot be said that the imposition of the duty by itself will preclude the Electricity Board from increasing its Tariff.

The levy on electricity being of all-India coverage, could not be withdrawn for the reasons given by the representationists.

Representation for withdrawal of Central Excise on Branded Beedies

*999. SHRI C. K. CHANDRAPPAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Central Excise duty of Rs. 0·50 per 1000 branded beedies introduced in March, 1975 has resulted in decreased market for branded beedies because of spurious beedies in the market.

(b) if so, whether the Government has received any representation requesting

to withdraw this duty on branded beedies; and

(c) if so, the details and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) in pursuance of the recommendations of the Tobacco Excise Tariff Committee, in the 1975 Budget, central excise duty at the rate of rupee one per 1000 was imposed on hand-made branded bidis. No duty was imposed on non-branded bidis. In the 1977 Budget, this rate was raised to Rs. 2 per 1000. Exemption to non-branded bidis, however, continued. Some reports have been received that, as a result of exemption to non-branded bidis, there appears to be a shift in business from branded to non-branded bidis.

(b) Yes, Sir.

(c) It has not been possible to accede to the request to withdraw the duty on branded beedies.

खाद्य तेलों के आयात के लिये लाइसेंस जारी करने के बारे में गोयल समिति का प्रतिवेदन

*1000. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोयल समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि बम्बई तथा जामनगर की एक प्रसिद्ध कम्पनी मैसर्स जमनादास माधवजी एंड कम्पनी ने विभिन्न नामों में खाद्य तेलों के आयात के लाइसेंस प्राप्त किये थे;

(ख) क्या तन्ना एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल एक्सपोर्टर एंड एस्टेट एजेंसी तन्ना ट्रेडिंग कारपोरेशन दीपक एंटर-प्राइजिज, जमनादास माधवजी एंड कम्पनी, जमनादास एण्ड संस, उषा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कम्पनी, और तन्ना एंड सन्स, जामनगर, नामक ये सभी कम्पनियां उपरोक्त कम्पनी की सहायक कम्पनियां हैं और एक ही लैटर पैड का प्रयोग करती है जिस पर II–ए नत्थालाल पारिख मार्ग, बम्बई, उनके पते के रूप में छपा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो मैसर्स जमनादास माधवजी एंड कम्पनी ने उपरोक्त (ख) भाग में उल्लिखित कम्पनियों ने नाम में कितने मूल्य तथा कितनी मात्रा के खाद्य तेलों आदि के आयात के लाइसेंस ले रखे हैं और इस मामले में कब और किस प्रकार की जांच की गई थी और की गई अनियमितताओं के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा क्या तथा कोई तक कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख). शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट से है । रिपोर्ट में माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट फर्मों के समूहों का उल्लेख बड़े आकार के अन्तः सम्बन्धित लाइसेंस-धारियों के दृष्टांत के रूप में किया गया है ।

(ग) इन फर्मों को जारी किये गये लाइसेंसों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । अब तक की गई जांच पड़ताल से इन पार्टियों के विरुद्ध कोई बात सामने नहीं आई है ।

विवरण

क्रमांक	फर्मों के नाम	जितनी मात्रा का लाइसेंस जारी किया गया	जारी किये गये लाइसेंसों का मूल्य
1.	मैसर्स जमनादास माधवजी एंड कंपनी, बम्बई	19,100 मे० टन	9,19,39,916 रु०
2.	मैसर्स तन्ना एक्सपोर्टस प्रा० लि०, बम्बई	3,276 मे० टन	1,91,83,159 रु०
3.	मैसर्स इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स एंड एस्टेट एजेन्सी, बम्बई	3,492 मे० टन	2,83,48,785 रु०
4.	मैसर्स तन्ना ट्रेडिंग कार्पोरेशन, बम्बई	8,959 मे० टन	6,16,64,694 रु०
5.	मैसर्स दीपक इन्टरप्राइजिज, बम्बई	5,685 मे० टन	3,73,37,352 रु०
6.	मैसस जमनादास एंड सन्स, बम्बई	5,220 मे० टन	3,47,48,812 रु०
7.	मैसर्स ऊषा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कं०, बम्बई	4,052 मे० टन	2,65,11,777 रु०
8.	मैसर्स तन्ना एंड सन्स, जामनगर	—	49,00,000 रु०
9.	मैसर्स जमनादास माधवजी एंड कंपनी, जामनगर	—	7,26,97,500 रु०

Manufacture of Carbon Dioxide without Licence by Mohan Meakin Breweries

*1001. SHRI C. R. MAHATA :
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a faet that Mohan Meakin Breweries, Mohan Nagar, Ghaziabad, had been manufacturing carbon dioxide gas without a licence as required under the Central Excise Act, 1944 and using in the manufacture of beer since November, 1972; and

(b) if so, what are the details in this regard and the action taken/proposed so far by the Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) and (b). In an order of adjudication dated 4-4-1978 under the Central Excises and Salt Act, the Collector of Central Excise, Kanpur, has held the following contraventions of Central Excise Law by Mohan Meakin Breweries Ltd., Mohan Nagar, Ghaziabad to be established:—

(a) That between 1-11-1972 and 12-7-1976, they had manufactured and removed over 19 lakh kilograms of carbon dioxide gas, which was liable to Central Excise duty and for the manufactue of which a Central Excise licence was required, without having paid duty or applied for a Central Excise licence ;

(b) That between 13-7-1976 and 20-6-1977, they had further manufactured over 6 lakh kilograms of carbon dioxide gas after applying for a Central Excise licence but without accounting for this production in the statutory accounts and without payment of duty ;

(c) That between 21-6-1977 and 27-10-1977 they had manufactured a further quantity of over 2 lakh kilograms of carbon dioxide gas. Although they had obtained a licence for its manufacture, they accounted for, and paid duty on, a quantity of less than 4000 kilograms. The Collector computed the Central Excise duty on the gas removed without payment of duty during the period under

consideration at Rs. 27,79,799·87 (Rupees twenty seven lakhs seventy nine thousand seven hundred and Ninetynine and paise eighty seven only) and demanded this duty from the company. He further held that the Company had acted deliberately in defiance of the law for long years, contravening the provisions of the Central Excise Rules and defrauding the Government of huge amounts of revenue. He therefore imposed on the Company a penalty of Rupees One Crore under Rule 173Q of the Central Excise Rules, 1954. He also, under the same rule, ordered confiscation of the land, buildings, plant and machinery used in the manufacture, storage etc. of the carbon dioxide gas, with an option to the Company to redeem the same on payment of a fine of Rs. 50 lakhs.

Section 33 of the Central Excises and Salt Act, 1944, provides for adjudication of offences by officers empowered under the Act, and Section 9 *ibid* provides for prosecution of persons who evade the payment of any duty payable under the Act or commit other offences as specified in that section. The case has already been adjudicated with the results indicated above. The Company filed a writ petition to the Delhi High Court. According to the order dated 24-4-1978 of a division bench of the High Court :—

(i) The petitioner would file an appeal to the Central Board of Excise and Customs against the Collector's order ;

(ii) Until the disposal of the appeal, recovery of the Excise duty and penalty would not be enforced ;

(iii) In case there was any consideration of prosecuting the petitioners, the Court and the petitioner thereby would be informed ;

(iv) Provisional assessments might be made for future periods, and subject to the furnishing of security bonds by the petitioners, there would be no recovery of the amounts so assessed.

Further action to be taken by the Collector and by the Central Board of Excise and Customs will be in accordance with law and the merits of the case and within the confines of the High Court's order.

Declaration by M/s Delhi Bottling Company to Excise Authorities

*1002. SHRI MALLIKARJUN : Will the minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of the Government that soft drinks manufacturers, by the name of M/s. Delhi Bottling Company, have declared to the Excise Authorities that Cola nuts extract is not used in their drink "Thums up", but at the same time they are advertising in the press, hoardings and other media that it is a cola ;

(b) if so, are they not evading excise duty by false declaration; and

(c) if so, what action does the Government propose to take against the defaulting company ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) Yes, Sir; the manufacturer has declared in the price list that cola nut extract is not used in the manufacture of drinks including "Thums up". The manufacturer is advertising in the Press that "Thums up" is a refreshing cola.

(b) and (c). Aerated waters not containing extracts of cola (kola) nuts and falling under sub-item (2) of item No. 1D of the Central Excise Tariff are exempted from duty in excess of 25% ad valorem in respect of the first clearances for home consumption not exceeding 50 lakhs bottles by or on behalf of a manufacturer from one or more factories during any financial year susequent to 1977-78. Aerated waters containing extract of cola nuts are liable to duty at the tariff rate of 55% ad valorem. The assessment of "Thums up" was being made provisionally by the Collectorate under rule 9B of the Central Excise Rules and was to be finalised on receipt of the report of Chemical Examiner on an analysis of the beverage. The Chemical Examiner's report has since been received by the concerned Collector and it has confirmed that "Thums up" is free from cola nut extract. In view of this report, the assessees cannot be said to have made a false declaration to the Central Excise department or to have evaded Central Exscise duty.

कृषि भूमि जोतों पर करों संबंधी राज समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

*1003. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे कृषि भूमि जोतों पर करों सम्बन्धी राज समिति द्वारा की गई सिफारिशों को एक निर्धारित अवधि में क्रियान्वित करें ;

(ख) क्या किसी राज्य ने केन्द्रीय सरकार से इन सिफारिशों की पुनः जांच करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कृषि सम्पत्ति और आय के कराधान से सम्बन्धित समिति (राज समिति) की रिपोर्ट को, उसमें दी गई सिफारिशों की शीघ्रता से जांच करने और उन पर अमल करने की दृष्टि से कार्यवाही करने के लिए नवम्बर, 1972 में राज्य सरकारों के पास भेजा गया था।

(ख) कुछ राज्य सरकारों ने बताया है कि कृषि जोत से सम्बन्धित कर का हिसाब लगाने का तरीका जैसा कि राज समिति द्वारा सुझाया गया है, बहुत ही जटिल है और यह कहा है कि वे कृषि आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में इससे ज्यादा आसान तरीकों को पसद करेंगे।

(ग) 1978—83 की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें राज समिति द्वारा सुझाये गये तरीके के अनुसार कृषि जोत के सम्बन्ध में प्रगतिशील कर लगाने के बारे में एक बार फिर विचार कर लें। लेकिन यदि ऐसा करना सम्भव नहीं समझा जाए तो सभी राज्यों में भू-राजस्व में क्रमिक दरों पर अधिभार शामिल किया जाना चाहिये ताकि कृषि कराधान की प्रणाली में क्रमिक वृद्धि लागू की जा सके और कृषि क्षेत्र से संसाधनों को जुटाया जा सके।

Price Control on goods manufactured out of Filament Yarn

*1004. SHRI L. L. KAPOOR : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether State Trading Corporation allowed actual users import directly hug quantity of polyster filament yarn andewhether this additional quantity was 400 tonnes more than the 1100 tonnes during the year 1976-77 ;

(b) whether the imported yarn was allotted by S. T. C. to certain firms after charging a small percentage as handling charges, though there was premium of about 300 per cent on polyster yarn ;

(c) if so, indicate the list of such firms, quantity allotted/imported ;

(d) is there any price control on the goods manufactured out of this yarn, and

(e) if not, the reason for allowing such huge quantity of this imported yarn ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) During 1977-78, STC was asked to arrange import of Polyster filament yarn to supplement indigenous production and to make it freely available to actual users at reasonable prices.

Action against smuggling of Indian Film Prints

*1005. SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the custom men in Bombay have busted a racket of smuggling of Indian film prints ;

(b) if so, the particulars thereof ;

(c) the names and number of persons arrested by the Customs for this offence; and

(d) the action taken or proposed to be taken against the persons so arrested ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) and (b). According to reports received by the Government, on 5-1-78, the Customs authorities at Bombay, seized 25 years of different films from the baggage of a foreign passenger while he was attempting to smuggle them out of the country. The

particulars of the seized films are as follows :—

Name of the firm	*No. of reels*
Devdas (Hindi) . . .	5
Talaq (Hindi) .	4
Pati-Patni (Hindi) .	4
Karigar (Hindi)	4
Aasra (Hindi) . .	4
Under Capricon (English) .	3
The man who know too much (English)	1
TOTAL . .	25

(c) One person was arrested. His name is Robert Johnston. He was subsequently released on bail by the Court.

(d) Prosecution has been launched against the person and the same is pending in the Court. further investigations are in progress.

Commuted Pension to Central Government employees seeking voluntary Retirement

*1006. SHRI S. NANJESHA GOWDA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that Central Government employees who seek voluntary retirement are eligible for commuting their pensions after appearing before a Medical Board while the employees who retire on superannuation can get their pensions commuted without appearing before the Medical Board ; and

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to remove this anomaly ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) The primary aim of the medical examination held for the purpose of commutation of pension is to determine whether the pensioner is in normal health or not. As a measure of simplification of procedure, orders have been issued allowing commutation of pension without a medical examination to Government servants retiring on superannuation, since in their case it can be safely assumed that they are in normal health. It is not proposed to extend these orders to those seeking voluntary retirement, as the assumption of normal health cannot be made safely in all such cases.

New Air Routes for Newly Developed Tourist Spots

9201. SHRI MOHINDER SINGH SAYIAN WALA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to open new air routes in the country linking inter-alia prospective and newly developed tourist sports ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVAIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). The question of connecting small towns and places of tourist and other interests by third level operations is engaging the attention of the Government. A preliminary project report prepared by the Indian Airlines is under examination by a Committee constituted to go into the various aspects of the proposal.

Incentives to Gem and Jewellery Trade

9202. SHRI RAM KISHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Rajasthan there is a three per cent levy at every point on semi-precious stones while in Maharashtra and Gujarat there is no sales tax on them thereby escalating the cost of finished semi-precious pieces by 30 per cent ;

(b) whether it is also a fact that in Rajasthan manufacturers and traders having a turnover of Rs. 5,000 a year or more are required to get themselves registered for sales tax while in Delhi and the limit is Rs. 1 lakh and in Bombay Rs. 50,000 and it has resulted in the employment at wholesale level ; and

(c) what steps Government propose to take to remove the snags and offer incentives to the gem and jewellery trade ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) Levy of tax on sales or purchases of goods inside a State is a State field of taxation. In Rajasthan, there is 3% sales tax multipoint basis on gems and jewellery and semi-precious stones. In Gujarat and Maharashtra also, gems and jewellery are

subject to sales tax. However, in Gujarat synthetic precious stones and diamonds are exempt from tax.

(b) A turnover limit for a manufacturer for getting himself registered for the purpose of sales tax is Rs. 5,000/- per year in Rajasthan. In Maharashtra, manufacturers or importers with in an annual turnover of Rs. 10,000/- and re-sellers with an annual turnover of Rs. 30,000/- have to get themselves registered. In Delhi, manufacturers with an annual turnover of Rs. 30,000/- and dealers with an annual turnover of Rs. 1 lakh have to get themselves registered. No information is available regarding employment at wholesale level.

(c) It is understood that the Rajasthan Government is appointing a Committee to examine the grievances of gems and stones trade and a decision will be taken by that Government on receipt of the report of that Committee.

स्टेट बैंक आफ इंडिया की सुलतानपुरी पुनर्वास बस्ती (दिल्ली) स्थित शाखा द्वारा गृह निर्माण के लिये दिये गये ऋणों की वापस अदायगी

9203. **श्री पायस टिर्की :**
श्री के० लकप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की सुल्तानपुरी पुनर्वास बस्ती (दिल्ली-41) स्थित शाखा द्वारा गृह निर्माण के लिए दिए गए ऋणों की वापस अदायगी के लिए मासिक किस्तों की राशि में कमी करने के बारे में बैंक अधिकारियों से कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या बस्ती की एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर किस्त की राशि 60 रुपए से घटाकर 30 रुपए कर दी गई है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस विषय पर पुनः विचार करना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). भारतीय स्टेट बैंक ने इस पुनर्वास कालोनी में अपने मकानों के निर्माण पूरा करने के लिए सुलतानपुरी के निवासियों को अधिकतम राशि 2500/– रुपए तक ऋण के रूप में मंजूर की थी। वापसी की किश्तें सभी के लिए 60/– रुपए नहीं तय की गई थीं, क्योंकि अलग अलग मामलों में ऋण की राशि अलग अलग थी। यद्यपि सामान्यतया ऋणों की वापसी अदायगीकी अवधि 2–3 वर्ष तय की गई थी परन्तु अब इसे बढ़ा कर अधिक से अधिक 5 वर्ष कर दिया गया है बशर्ते कि ऋणकर्ता और उसके जमानती (गारंटर) इसके लिए बैंक से अनुरोध करें और उससे सम्बन्धित सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करें।

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इसे सुलतानपुरी कल्याण संघ के अध्यक्ष से एक प्रतिवेदन मिला है जिसमें अनुरोध किया गया है कि वसूली कार्यक्रम को फिर से निर्धारित करें जिस पर शाखा प्रबन्धक 31 मार्च, 1978 को उक्त संघ के अध्यक्ष से मिले थे और इस मामले में उन्हें बैंक की नीति स्पष्ट कर दी जिससे वह सन्तुष्ट हो गये हैं।

Framing of rules for Deputation of Employees

9204. SHRI C. N. VISVANATHAN : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3294 on 17th March, 1978 regarding rules followed by Export Inspection Council and Export Inspection Agency in respect of service matters to their employees and state :

(a) whether Export Inspection Council/Agency so far had no comprehensive service rules for its employees since they have failed to frame their own rule for deputation but are following Central Government Rules; and

(b) if so, how many employees so far have been absorbed in the Council/Agency from the other departments and how many Council/Agency employees on deputation to other sectors have been absorbed ; what is their terms and conditions of absor ption and whether

any one of them have been allowed past service benefits as provided under Central Government Orders on the subject ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) Export Inspection Council have framed service rules for the employees of the Export Inspection Council and Export Inspection Agencies. Since the Council is adopting the deputation rules, orders and instructions etc. issued by the Central Government for its employees, no need has been felt to frame separate rules for the purpose.

(b) 21 employees have been absorbed in the Export Inspection Council/Export Inspection Agency from other departments and 5 employees of the Export Inspection Council/Export Inspection Agency have been absorbed in other organisations. The terms and conditions in each case are decided on merits keeping in view the Central Government deputation rules, orders, instructions etc. and all relevent considerations.

Proposal to make super Bazars more broad-based

9205. SHRI YASWANT BOROLE : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government have decided to make the super bazar more broad-based to make available commodities of daily use even for the lower sections in the society ; and

(b) if so, what steps are being taken to take the idea to the rural countryside to make it really broad-based ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) In order to ensure that benefits which are available from the infra-structure of consumer co-operative reach the vulnerable sections of the urban community, particularly those living in slums, residential areas of scheduled castes and areas inhabited by workers in the un-organized sector, it has been decided that the main thrust of the Centrally Sponsored Scheme, should be directed towards establishment of a large number of small/smaller branches for the benefit of weaker/weakest sections of the community. Guidelines for setting up of such units have been circulated to the State Governments.

(b) With a view to encouraging and assisting distribution of essential consumer goods in the rural areas through the existing Cooperative structure at the village level and marketing and consumer co-operative structure at the higher level, the National Cooperative Development Corporation has formulated a scheme for providing financial assistance to selected cooperatives at village and mandi levels. The scheme envisages that assistance will be provided to cooperatives for undertaking distribution of controlled and non-controlled commodities in the rural areas.

Extension of special oil facility by I.M.F.

9206. SHRI SARAT KAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the International Monetary Fund has lately decided to extend the special oil facility to developing countries including India at subsidised rates ;

(b) if so, what are the details of the scheme ; and

(c) the extent of credit expected by India under the said scheme and how it would affect the over-all oil import bill of India during the ensuring year ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c). Presumably, the Hon'ble Member is referring to the "Subsidy Account" which was established by the International Monetary Fund on August 1, 1975 to assist certain developing member-countries to meet the cost of using the 1975 Oil Facility. The use of the 1975 Oil Facility carries charges at the rates of 7·625 per cent per annum for the first three years. 7·75 per cent for the fourth year, and 7·875 per cent per annum for the final three years. The objective of the "Subsidy Account" is to reduce the effective rate of annual charge payable under the said Facility by about 5 per cent per annum. India, which made a drawing equivalent of SDR 201·34 million under the 1975 Oil Facility in August 1975, has so far received an amount equivalent of SDR 17,300,937 (about Rs. 17·69 crores) from the 'Subsidy Account'. A further receipt of Rs. 10 crores has been assumed on this account in the Budget for the year 1978-79.

Filling up of reserved vacancies for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the Income -tax Department in Tamil Nadu

9207. SHRI A. MURUGESAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state ;

(a) what are the qualifications fixed for consideration for promotion to

the post of Supervisor Grade I and Grade II in the Income Tax Department as per recruitment rules ;

(b) the number of posts of Supervisor Grade I and Grade II sanctioned and filled up in the Income Tax Department, Tamilnadu charge during the years 1975, 1976, 1977 and 1978 ;

(c) the number of posts of Supervisor Grade I and Grade II that should have been reserved for S.C. and S. T. employees as per 40 point roster ; and

(d) the backlogs, if any, in filling up the reserved vacancies with reasons for the backlog and what are the medical steps taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Grant of Loan and Aid to Neighbouring Countries.

9208. SHRI PRADYUMNA BAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) Whether any policy has been adopted towards the giving of loan and aid to the neighbouring countries and is so, what are the main features thereof ; and

(b) if not, whether any policy will be drawn up ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) : Assistance to foreign countries is extended on the basis of requests received from these countries to finance their priority requirements. Within this general policy framwork and in accordance with Government's established policy to develop closer economic and other relations with neighbouring countries efforts are made to allocate the maximum possible resources for assistance to these countries.

Appointment of Common Chairman to Minimise Expenditure and Improve Efficiency

9209. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVAIATION be pleased to state :

(a) the motive behind the appointment of common Chairman for Air India and Indian Airlines ;

(b) whether it is a fact that the sole motive of the Government is to minimise the Administrative expenditure and improve the efficiency of the two organisations ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken in that direction ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). A common chairman for Air India and Indian Airlines has been appointed to secure greater coordination between the two Corporations and to ensure utilisation of the infrastructural facilities to the best advantage of both the Corporations.

(c) Joint scheduling exercises, joint fleet planning, common usage of facilities at stations served by both Indian Airlines and Air India and Ground facilities being set up at Trivandrum.

बिहार में पर्यटन विकास पर खर्च किया गया केन्द्रीय राजस्व

9210. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में पर्यटन विकास पर केन्द्रीय राजस्व की कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में बिहार में इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई और वह खर्च की गई कुल धनराशि की कितने प्रतिशत थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) वित्तीय वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में विकास स्कीमों पर केन्द्रीय क्षेत्र में किया गया व्यय क्रमशः 3,81,05,933 रुपए, 2,76,91,048 रुपए तथा 3,76,12,156 रुपए था ।

(ख) बिहार में वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान किया गया व्यय क्रमशः 36,30,000 रुपए,

17,80,000 रुपए तथा 4,29,000 रुपए था। अतः व्यय की गई कुल राशि का प्रतिशत तीन वर्षों के लिए क्रमशः 9.5 प्रतिशत, 6.43 प्रतिशत तथा 1.14 प्रतिशत बनता है।

दैनिक 'आवन्तिका' और मेहता प्रिंटिंग प्रेस उज्जैन के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीमा बढ़ाया जाना

9211. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आवन्तिका" दैनिक और मेहता प्रिंटिंग प्रेस, उज्जैन के मालिक गलत और जाली बिल दिखाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपनी सीमा बढ़वाते रहे हैं और यदि हां, तो क्या नगर के कुछ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में पिछली सरकार से शिकायतें की थीं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इनको दैनिक 'आवन्तिका' के लिए नियत अखबारी कागज पर स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया और सैंट्रल बैंक आफ इंडिया से समय-समय पर धन मिलता रहा है और यदि हां, तो इस प्रकार बैंकवार और तिथिवार कितनी धनराशि प्राप्त की गई; और

(ग) क्या अखबारी कागज पर बैंकों से धन निकलवाना बैंकों द्वारा उक्त दैनिक के साथ सहयोग करना है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रथा को रोकने के लिए सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Indian Participation in Third Country Projects

9212. SHRI SUKHDEO PRASAD VARMA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether any guidlines have been framed to encourage Third country projects with Indian participation amongst others ;

(b) if so, the details of the above,and

(c) effective steps being taken to securue highly developed countries to associate Indian entrepreneurs for Third country projects ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) to (c). Although no specific guidlines have been formulated separately to encourage Third Country projects with Indian participation, possibilities of such cooperation have been explored during the meetings of Joint Commission / Joint Committees with various countries. Discussions have been also been held on commercial and industrial cooperation and in some cases joint machinery has also been set up for monitoring the process of implementation. Further, in order to facilitiate association of Indian entrepreneurs for third country projects, focal points have been identified for certain countries to exchange information and pursue possibilities for promoting industrial collaboration and third country joint ventures.

Expenditure incurred in Foreign Exchange by Directors of Mokalbari Kanoi Tea Estate Private Ltd., Calcutta.

9213. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state ;

(a) whether the Central Government have ordered detailed investigation into the unauthorised expenditures incurred in foreign exchange by the directors of Mokalbari Kanoi Tea Estate Private Limited, Calcutta and their family members during year 1977;

(b) if so, whether in order to evade the enquiries the directors of the Company have informed the Enforcement Directorate officials that their passports were all lost and have brought out fictitious FIR of police station ;

(c) if so, what measures have been taken against these directors to prove beyond doubt that passports were actually lost and also steps taken against the person or persons who lost the passport of directors and family members ; and

(d) the detailed report of investigation and sources thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) Yes, Sir.

(b) Only one director of Mokalbari Kanoi Tea Sstate Pvt.Ltd., Calcutta,i.e., Shri Murlidhar Kanoi, has intimated to Enforcement Directorate regarding the loss of his passport and also filed a photostat copy of FIR lodged with the police station. Enquiries made with the police have revealed that the report regarding the loss of the passport was in the fact lodged with them.

(c) In view of the fact that the photostat copy of the FIR lodged with the Police authorities has not been found to be a fictitious documents, no further action was considered necessary regarding the loss of passport.

(d) The information cannot be divulged in public interest.

Instructions issued by Central board of Excise and Customs

9214. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

What instruction was issued by the Central Board of Excise and Customs to combat the evil of fake T.P.I permits and how far the same has proved effective to meet the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : The transport permit in the form known as TP-I is one of the statutory transport permits prescribed under rules 25, 32 and 33 of the Central Excise Rules, 1944. This form of transport permit is prescribed to cover the movement of duty -paid unmanufactured tobacco from one place to another . If any person carries, transports or receives such tobacco without a valid TP-I permit or enters any particulars in the permit in respect of any such tobacco, which are or which he has reason to believe to be false, he shall be liable to a penalty not exceeding two thousand rupees, and the tobacco in respect of which offence is committed, shall be liable to confiscation. To prevent misuse of such permits, confidential instructions were issued in 1974 to all Collectors of Central Excise to tighten preventive control and to ensure that non-duty paid tobacco was not transported on the strength of such T.P. I permits. Certain preventive measures to be adopted by Central Excise Officers were also indicated in the instructions.

2. It will not be in the public interest to give publicity to the confidential instructions issued to the Central Excise Officers because this would have the effect of rendering the prescribed checks less effective. These checks have no doubt made it more difficult for unscrupulous elements to repeat the type of evasion observed in the past.

Prices of Ground Equipments

9215. SHRI NARENDRA SINGH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 5044 on the 31st March, 1978 regarding Indian Airlines placed orders for equipments without questions and state :

(a) how the price of ground equipments were ensured to be correct without calling for tenders and specially when the management was fully aware about prevailing much lower prices in the market which were less by more than 16 percent;

(b) if so, why the management preferred to pay much higher prices ;

(c) whether it is also not necessary that equipments have to meet the standard and specification of IATA and ATA too; and

(d) if so, why this set practice was not followed in this case ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Indian Airlines placed order for dollies at Rs. 13550/- per dolly in 1975. Indian Airlines now in 1978 placed a repeat order for the same type of dollies with the same supplier at the 1975 price. It is not correct to state that the prevailing market price is 16% lower for the same type of dollies of the same specification and quality. In fact the prices have escalated by about 12 to 15% for raw material and labour.

(b) Does not arise.

(c) In the tender enquiry for the first batch of pallet dollies, Indian Airlines had stipulated that this should be on the basis of widely accepted drawings and

specifications as in use with international operators. The units procured by Indian Airlines were in accordance with the drawing and specification in use with various international operators and these units have given satisfactory and trouble free service during their intensive use for more than a year.

(d) Does not arise.

Deposit and Lending rates of Commercial Banks

9216. SHRI D. AMAT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Reserve Bank of India has directed all the commercial banks to reduce their deposit and lending rates; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). Information regarding the revisions made by the Reserve Bank of India in the interest rate structure of the scheduled commercial banks effective from March 1, 1978, is set out in Statements I and II.

STATEMENT I

Changes introduced in Deposit Rates of Scheduled Commercial Banks, with effect from March 1, 1978

1. *Deposits Rates*

	Per Cent per annum	
	Rates prior to March 1, 1978	New rates
Currents Deposits	Nil	Nil
Savings Deposits	3% on savings deposits with cheque facility and 5% on savings deposits without cheque facility	4½
Fixed Deposits (including recurring deposits, cumulative deposits etc.)		
(a) 15 days to 45 days	3	2½
(b) 46 days to 90 days	3½	3
(c) 91 days to less than 6 months	4	4
(d) 6 months to less than 9 months	4½	4½
(e) 9 months to less than 1 year	5	5
(f) 1 year to 3 years	6	6
(g) Over 3 years upto 5 years	8	7½
(h) above 5 years	10	9

Scheduled commercial banks with deposit liabilities below Rs. 25 crores will be allowed to pay 1/4 per cent more on savings deposits and on fixed deposits upto 5 years. Regional Rural Banks will be allowed to pay ½ per cent more on savings deposits and on fixed deposits upto 5 years.

2. For purposes of compounding interest rates the rests shall be quarterly or longer.

3. All the term deposits made prior to March 1, 1978, will continue to earn interest at the contracted rate for the remaining part of the maturity period.

Statemnt II

Changes introduced in lending rates of scheduled commercial banks, with effect from March 1, 1978

Lending Rates

1. *Maximum Lending Rate on Advances*: The maximum rate of interest chargeable by banks on short period advances (without prejudice to penal charges) will be as follows:

Banks with Demand and Time Liabilities of	Rates prior to March 1, 1978	New rates
	Per cent	Per cent
(a) Over Rs. 50 crores and banks incorporated outside India	16-1/2	15
(b) Between Rs. 25 crores and Rs. 30 crores	17-1/2	15
(c) Below Rs. 25 crores	No ceiling	16

2. *Food Credit*: The rate of interest charged by banks on credit extended for food procurement by Government and Government authorised agencies will be reduced from 12 per cent to 11 per cent.

3. *Term Loans*: Rates on term loans for priority purposes have been reduced in the recent past. No significant change in these is, therefore, proposed. However, as a measure of rationalisation, the scheme of term loans has been slightly adjusted as follows:

	Rates prior to March 1, 1978	New rates
	Per cent	Per cent
(a) Term loans of not less than 3 years for capital investment in priority areas	12·50	12·50
(b) Term loans of not less than 3 years for all other purposes		
(i) Between 3 and 7 years	15·00	14·00
(ii) Above 7 years	14·00	

4. The maximum lending rates specified above will also apply to advances against commodities subject to selective credit control.

5. For purposes of compounding, the rests shall be quarterly or longer.

6. The Bank Rate will remain unchanged at 9 per cent. However, the rate charged by the Reserve Bank on refinance given for food advances is being reduced from 10 per cent to 9 per cent.

Consequently to the changes in lending rates prescribed as above the banks have been asked to reduce the lending rates broadly on the following lines:

(a) For banks with deposit liabilities in excess of Rs. 25 crores, all rates of 16-1/2 per cent and above to be brought down to 15 per cent. For banks with deposit liabilities less than Rs. 25 crores, similar adjustment of the higher rates to 16 per cent.

(b) For existing rates between 13 1/2 and 15 per cent, reductions should work out, *on an average*, to 1 per cent, with reductions in the upper ranges being more than the average.

(c) Existing rates of interest over 12-1/2 per cent and upto 13 1/2 per cent should be brought down close to 12½ per cent; and if reductions imply going to rates marginally below 12½ per cent (i.e. minimum lending rate), banks may do so and inform the Reserve Bank accordingly.

(d) For the existing rates of 12-1/2 per cent and below, some reduction should be effected.

(e) The existing rates charged under the Differential Rates of Interest Scheme remain unchanged.

(f) The concessional term lending rates for small-scale industry, agriculture, etc., and for crop loans below Rs. 2500 announced on December 12, 1977 will remain unchanged.

(g) The minimum lending rates of 14 to 15 per cent in respect of advances against commodities subject to selective credit control remain the same as at present, such advances are also subject to the new ceiling rates.

Food Credit

The rate of interest on food credit is reduced from 12 per cent to 11 per cent. As regards the rates on the refinance facilities by the Reserve Bank, the food refinance rate has been reduced from 10 to 9 per cent.

Export Credit:

The rates of pre-shipment credit should be reduced by 1/2 per cent, i.e. from 11-1/2 and 13-1/2 per cent to 11 and 13 per cent, respectively, and the rate on post-shipment credit from 11-1/2 per cent to 11 per cent. The rates on deferred payment exports continue unchanged at 8 per cent. The export refinance rate is also reduced from 10-1/2 per cent to 10 per cent.

Exemption in Income

9217. SHRI MAHI LAL:
SHRI DHARMA VIR VASISHT:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that income of wife and husband is not clubbed for income tax purposes;

(b) whether it is also a fact that income from interest on savings dividends etc. is also exempt upto Rs. 3000 for income tax purposes;

(c) if so, whether Government intend to exempt income from housing property also to this extent particularly when Government is encouraging building activity; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) (a) Income derived by an individual is not clubbed with the income derived by his or her spouse, except in the following circumstances:

(i) where the income arises to the spouse of an individual from the membership of the spouse in a firm carrying on business in which such individual is also a partner;

(ii) where the income arises to the spouse of an individual by way of salary, commission, fees or any other form of remuneration whether in cash or in kind, from a concern in which such individual has a substantial interest, except in cases where the spouse possesses technical or professional qualifications and the income is solely attributable to the application of his or her technical or professional knowledge and experience;

(iii) where the income arises to the spouse of an individual from assets transferred directly or indirectly to the spouse by such individual otherwise than for adequate consideration or in connection with an agreement to live apart;

(iv) where the income arises to any person or association of persons from assets transferred (otherweis than for adequate consideration) by an individual directly or indirectly to such person or association of persons, to the extent such income is for the immediate or deferred benefit of the spouse of such individual;

(v) where an individual converts his separate property into property belonging to the Hindu undivided family of which he is a member and, at any time, thereafter, there is a partition of the Hindu undivided family, the income derived by the spouse of such individual out of her share in the converted property received on partition.

(b) Yes, Sir. Under section 80L of the Income-tax Act, income derived by a taxpayer from investments in specified categories of financial assets such as, Government securities, shares in Indian companies, deposits with banks, qualifies for deduction upto an aggregate amount of Rs. 3,000 in computing the taxable income.

(c) and (d). Government is not considering any such proposal. However, in computing the income from a newly constructed house property, the annual value thereof is reduced by an amount up to Rs. 1,200 in respect of each residential unit for a total period of five years from the date of completion of its construction.

The Finance Bill, 1978 seeks to raise the deduction in relation to buildings, the erection of which is completed after 31st March, 1978, from Rs. 1,200 to Rs. 2,400.

राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

9218. **श्री चतुर्भुज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विकास कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोली गई हैं;

(ख) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा कोटा, झालावाड़ा और बूंदी जिलों में कितने ग्रामीण बैंक (लीड बैंक) खोले गये और यदि कोई बैंक नहीं खोला गया तो इस बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जून, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार राजस्थान में वाणिज्यिक बैंकों की 479 शाखायें ग्रामीण स्थानों में कार्यरत थीं। इनमें से 224 शाखायें भारतीय स्टेट बैंक की, 146 राष्ट्रीयकृत बैंकों की और 60 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थीं।

(ख) लीड बैंक योजना के अधीन सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने कोटा और झालावाड़ जिलों का लीड दायित्व संभाला है जब कि बूंदी जिले का लीड दायित्व बैंक आफ बड़ौदा का है।

इन जिलों में वाणिज्यिक बैंकों और सम्बन्धित लीड बैंकों के शाखा जाल के ब्यौरे के बारे में जिलेवार उपलब्ध सूचना नीचे दी जा रही है :—

30—6—77 की स्थिति के अनुसार

जिला	बैंक शाखाओं की कुल संख्या	जिनमें से ग्रामीण शाखायें	लीड बैंक की शाखाओं की कुल संख्या	जिनमें से ग्रामीण शाखायें
कोटा	55	19	8	5
झालावाड़	21	13	8	6
बूंदी	15	10	6	5

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ बड़ौदा दोनों ही सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, और यह प्रयास कर रहे हैं कि वे उपेक्षित क्षेत्रों और विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण की गति बढ़ाने और कम बैंक वाले क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए अपने समक्ष रखे गये लक्ष्यों को पूरा कर लें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का कार्यकरण

9219. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के मधुबनी जिले में खजौली, बेनीपथी, विसफी, हरलरावी और राहिका ब्लाकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही हैं और उनसे ऋण लेने वाले

ग्रामीण लोगों को परेशान किया जाता है; और

(ख) इन बैंकों को वर्ष 1976 और 1977 में ऋण के लिए कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितने मंजूर किये गये और कितने रद्द किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). यथासम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Fair price Shops/Consumer Cooperatives

9220. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) how many of fair price shops/consumer cooperative shops are located in towns and cities with more than 50,000 population and how many in rural areas;

(b) the average number of families or persons covered by each centre in urban and rural areas; and

(c) the method of financing them and to feed the centres with regular stocks of essential items marketed through them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): (a) There are about 2,38,569 fair price shops (including those run by consumer cooperatives). Out of these, 1,84,006 are in rural areas and 54,563 in urban areas, covering a population of 4,394 9 lakhs of rural population and 1,490.6 lakhs of urban population.

(b) The average number of families or persons covered by each fair price shop in urban and rural areas varies from State to State and District to District and area to area.

(c) While supplies of stocks to fair price shops is arranged by the Food Corporation of India or other agencies approved by the Government, finance for the operation of the fair price shops is arranged by the licence holders or through normal trade channels or from commercial banks. In the case of fair price shops, run by cooperatives, finances are generally provided by the cooperative banks.

Project India

9221. SHRI NATHU SINGH: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state what are the details of 'Project India' recently finalised with the International Trade Centre (Geneva) UNCTAD/GATT and which kind of activities will it cover?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : The International Trade Centre GATT/UNCTAD, Geneva (ITC) has a three year Integrated Programme on Technical Co-operation in Trade Promotion with the Government of India, Department of Commerce. ITC has similar programmes with other developing countries also, although the one with India is the largest. Under this programme, during the three year period from 1st July, 1977 to 30th June, 1980, ITC will provide funds totalling US $ 4·62 million made available to its Trust Funds by the Swedish International Development Authority (SIDA). The programme of activities to be undertaken under this project are finalised on an annual basis.

2. The object of the programme is to provide inputs in terms of training facilities, export services, documentation and teaching aids in the field of trade promotion to various export promotion and servicing organisations in India to enable them to undertake merchandising, research and training activities. During the first year from 1st July, 1977 to 30th June, 1978, an allocation to the extent of US $ 1.48 million has been made for such activities to be undertaken by 12 organisations like the Trade Development Authority, Indian Institute of Foreign Trade, Trade Fair Authority of India, Processed Foods Export Promotion Council, Spices Export Promotion Council, Cardamom Board, Marine Products Export Development Authority, Cotton, Textiles Export Promotion Council, Engineering Export Promotion Council and the All India Management Association. The activities already undertaken or to be undertaken in 1977-78 include :

(a) Merchandising activities like organisation of Buyer-Seller Meet in the United States, market orientation tours in selected countries and sales-cum-study tours for selected products;

(b) research activities like market surveys for selected products in selected countries and studies on export infrastructure;

training activities like organisation of workshops for trainers in export management and training programmes for management staff in exporting units.

3. The objective of the Department of Commerce is to extend the range of activities as well as the organisations involved in this programme and with this end in view, during 1978-79 similar activities will cover 16 export promotion and servicing organisations.

Opening of Banks in unbanked areas of Assam

9222. SHRI AHMED HUSSAIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) what action is being taken by the Government of India on the request of the Government of Assam to provide at least one bank at each block headquarter of Assam which are still unbanked;

(b) name of Block Headquarters of Assam which will be provided with a branch of the nationalised bank during the current year;

(c) has the Government accepted the proposal of the Government of Assam to extend the repayment period of short term loan given to marginal farmers to two harvests instead of one;

(d) the reason why other Nationalised Banks are not opening branches in the N.E. Region including Assam and what are the future plans of these banks for this region; and

(e) what is the type of loans being given by the present bank(s) in Assam and whether they will be instructed to give adequate soft term loans for the purpose of cattle; high yielding seeds, Fertilizers and to those who have been victimised due to land erosion due to the floods?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H.M. PATEL): (a)As part of the programme to ensure availability of minimum banking facilities in underbanked areas, the banks have been advised to open by June 1978, at least one branch in each of the unbanked community development blocks. Banks have also been advised to give preference to unbanked block headquarters while drawing up their branch expansion programmes.

(b) The branch expansion plans of the banks for the current year are being scrutinised by the Reserve Bank of India. However, names of the 15 unbanked blocks in the State of Assam which would be provided with banking facilities before June 1978 are set out in the Statement.

(c) The Reserve Bank has advised the bank that in respect of recovery of crop loans where multiple cropping prevails or one of the two seasonal crops is pronouncedly more important than the other, the due date for the repayment of crop loans should be related to the time of sale of the main crop.

(d) The public sector banks are endeavouring to open more branches in the North-Eastern Region including Assam as would be evident from the fact that the number of commercial bank branches in the N.E. Region has increased from 151 as at the end of December 1970 to 561 as at the end of December 1977. Of these, 459 were of public sector banks. As at the end of December 1977, banks had 103 licence swtih them for opening branches in the N.E. Region. Of these, 69 were with the public sector banks.

(e) In Assam, as elsewhere, commericial banks grant short-term loans for financing seasonal operations and term loans for purchase of milch cattle, minor irrigation, poultry/dairy development etc. In regard to credit facilities to victims of floods and other natural calamities, commercial banks have been advised by the Reserve Bank to take appropriate action for rephasing of the loans, so as to afford relief to the affected borrowers as also to make them eligible for fresh finance in the subsequent years.

Statement

List of unbanked blocks in Assam where banks propose to open offices before 30th June, 1978

Name of District	Name of Block	Name of Centre	Name of Bank
1	2	3	4
Cachar . .	1. Katlichera	Katlichera	Union Bank of India
Goalpara . .	2. Matia	Matia	Pragjyotish Gaonlia Bank
	3. Boitamari	Boitamari	Do.
Kamrup . .	4. Mandia	Mandia	Do.

1	2	3	4
	5. Borigog	Borigog	United Commercial Bank
Nowgong . .	6. Juria	Juria	Punjab National Bank
	7. Bhurbandha	Bhurbandha	United Bank of India
Sibsagar . .	8. Central Jorhat	Kakojan	Do.
	9. Eastern-Jorhat	Nakachari	Do.
Mikir Hills . .	10. Donkamokam	Donkamokam	State Bank of India
	11. Nilip	Sokhualla	Do.
	12. Amri	Ullukanchi	Do.
	13. Soochang	Jerikingding	Do.
North Cachar Hills	14. Diyung Valley	Mahur	Do.
	15. Harangjao	Harangjao	United Bank of India

Recruitmnt Rules of Export Inspection Council/Agency

9223. SHRI SHANKER SINH JI VAGHELA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state :

(a) whether it is obligatory on the part of Export Inspection Council to notify the recruitment rules of Export Inspection Council/Agency under quality Control Act;

(b) if not, whether he can ensure that recruitments by Export Inspection Council are made strictly in accordance with recruitment rules in force and no deviation is being made; and

(c) whether a copy of recruitment rule in force will be laid on the Table?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) No, Sir.

(b) Recruitments by the Export Inspection Council are made in accordance with their recruitment rules. However, specific complaints in this regard, when brought to the notice of Government are examined and necessary action taken in the matter.

(c) A copy each of existing recruitment rules of the Export Inspection Council/Agency is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT 2247/78]

Development of Nirmahal, in Agartala as Tourist Resort in Tripura

9224. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Nirmahal, Agartala is considered to be a beautiful and charming spot fit for being developed into a Tourist resort in Tripura ;

(b) if so, whether any scheme has been submitted for developing it into a Tourist resort if so, the details of the scheme and cost thereof ; and

(c) whether Government have approved the scheme ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) No proposal has been submitted to the Central Department of Tourism for developing Nirmahal as a tourist resort. However, it is understood that the State Government has already initiated action for carrying out improvements to Nirmahal for which purpose Rs. 1·00 lakh has been provided in the Tourism sector of the State Annual Plan for 1978-79.

(c) Does not arise.

Reduction in import duty on Capital Goods and General Surcharge of Excise on locally produced Goods

9225. SHRI RAMDEO SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the recent reduction in import duty on capital goods and general surcharge of 5 per cent excise on locally produced goods was meant to encourage using more imported machinery than locally produced machinery ; and

(b) the reasons why the import duty was not increased, and have Open General Licensing to increase revenue from import duty and depend less on excise revenue ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) No, Sir. The import duty has been reduced from 40% to 25% only on certain specified items of capital equipment, not produced indigenously, with a view to bringing down capital cost. This decision has been taken after taking note of the significant suggestions in regard to customs duties made by the Jha Committee. This reduction of import duty would not affect the locally produced machinery.

A special excise duty at the rate of 1/20th of the basic duty of excise has been levied as part of the 1978 Budget as a revenue raising measure. Those items of capital equipment, etc. on which import duty reduction has been effected are such as have little or no indigenous angle. Therefore, the question of the special excise duty affecting similar indigenous goods does not arise.

(b) Since the intention is to reduce capital costs, the question does not arise.

Losses due to theft and Strikes in Public Undertakings in Maharashtra

9226. SHRI R. K. MHALGI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the losses due to theft and strikes in each Central Government , public undertakings separately in Maharashtra State during the year 1976-77 and 1977-78; and

(b) what are the measures contemplated by Government to prevent such losses ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). The information in regard to manufacturing organisations of the Central Government Corporations located in Maharashtra State is being obtained and will be placed on the Table of the House.

Loss due to import of rapeseed and rapeseed oil

9227. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) is it correct that the Government of India recently suffered a loss of Rs. 3·86 crores due to lack of coordination between various Government agencies connected with the import of rapeseed and rapeseed oil from Canada and negligence on the part of officials of the State Trading Corporation; and

(b) what action has been taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Method of Recruitment of Clerks and officers in Reserve Bank, State Bank of India and other Public Sector Banks

9228. SHRI R. KOLANTHAI VELU: SHRI P. S. BAMALINGAM :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the method of recruitment of clerks and officers to Reserve Bank, State Bank of India and other public sector banks;

(b) whether such posts are invariably advertised throughout India ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) the latest date on which the advertisements for clerical and officers posts in each such Bank appeared in the recent past and the newspapers in which it appeared ; and

(e) the present stage of the proposals for a common recruiting agency ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c). The recruitment for officers staff in public sector banks is done on an all-India basis after calling for applications through advertisements in newspapers and candidates are selected after a written test and an interview. Clerical recruitment is generally done on a regional basis after notifying the vacancies to the employment exchanges and also simultaneously issuing local advertisements for the recruitment. The selection of candidates for clerical posts is made after a written test followed by an interview of the candidates who qualify in the written test.

(d) Information to the extent possible is being collected and will be laid on the Table of the House.

(e) This matter is under consideration of the Government.

Recruitment of Clerks in Punjab National Bank

9229. SHRI K. A. RAJU : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Punjab National Bank held an examination for recruitment of clerks on 6th February, 1978 ;

(b) the number of candidates who appeared and the number who qualified for final interview ;

(c) the precise criteria followed for determining the candidates to be called for interview ;

(d) whether it is a fact that nongraduates, though otherwise qualified, were given a comparatively lower weightage even when their performance in the written examination was quite good ;

(e) if so, the reasons therefor ; and

(f) the reasons for the enormous time lag from the advertisement to the publication of the final result ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir. The test was also held on 25th & 26th December, 1977 for Reserved Category candidates and on 23rd January, 7th, 8th and 9th February, 1978 for general category candidates.

(b) The number of candidates who appeared from reserved category was 1609 and those in the general category was 8435. The number of candidates who qualified from these two categories was 189 and 2812 respectively.

(c) In the case of reserved category candidates, the Bank called all those candidates who qualified in the written test. From the general category, however, candidates equal to three times the number of vacancies were called for interview.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

(f) Results have been declared only in respect of reserved category candidates. A number of factors such as adequate notice to the candidates for applying, scrutiny of applications and testing a large number of candidates was responsible for the time lag between advertisement and publication of final results.

Muslim Officers in various categories in Income Tax Department

9230. SHRI MAHMOOD HASAN KHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total number of Income Tax Commissioners in the Income Tax Department and the number of Muslim Income Tax Commissioners ;

(b) the total number of Assistant Commissioners of Income Tax and the number of Muslim Assistant Commissioners ;

(c) total number of Income Tax Officers; and the number of Muslim Income Tax Officers; and

(d) total number of Income Tax Inspectors and the number of Muslim Income Tax Inspectors ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) :

(a) Total No. of Commissioners of Income-tax.	Number of Muslim Commissioners of Income-tax.
59	3
(b) Total No. of Assistant Commissioners of Income-tax.	Number of Muslim Assistant Commissioners of Income-tax.
551	12
(c) Total No. of Income-tax Officers	Number of Muslim Income-tax Officers
3689	89

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Guidelines issued to Nationalised Banks for granting loans to Educated unemployed and self-employed Persons

9231. SHRI AMARSINH V. RATHAWA : Will the Minister of FINANCE be pleased to State :

(a) whether the Government has issued any guidelines to nationalised banks for granting loans to educated unemployed, self-employed persons belonging to weaker sections and for small industrialists ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether such category of people are facing great hardship for such grants ;

(d) whether Government propose to make rules more liberal so that actual person of these categories can get loans at the earliest; and

(e) how much such loans have been sanctioned and granted to such categories of persons by different nationalised banks (Statewise and Bankwise) during January to April, 1978 ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). In pursuance of the accepted policy of the Government to create avenues of gainful employment, the public sector banks have been advised to enlarge the flow of credit to the neglected sectors to the level of 33·3% of their aggregate credit by March, 1979. Further to stimulate the growth of small and cottage industries the Ministry of Industry has recently formulated a new scheme, which envisages assistance to the State Governments for provision of margin money to small units involving investment in plant and machinery not exceeding Rs.1 lakh. The public sector banks have also been advised to actively participate in the implementation of the scheme.

(c) and (d). In order to ensure expeditious disposal of loan applications, banks have been advised to dispose of loan applications involving credit limits upto Rs. 10,000 within 3 to 4 weeks and those involving credit limits of Rs.10,000 and above within a period of 3 month from the date of receipt of applications.

(e) The available data on the outstanding credit of public sector banks under Employment Promotion Prgrammes as at the end of December, 1977, are set out in the statements I & II.

Statement I

Number of applications sanctioned and amount outstanding with Public Sector Banks under employment oriented programme as at the end of December, 1977.

Name of the Bank	No. of applications sanctioned	Amount outstanding (Rs. lakhs)
A. State Bank of India	23350	2242·82
B. Subsidiaries of SBI	7063	475.39
C. *Nationalised Banks* :		
1. Central Bank of India	5899	514·91
2. Bank of India	6601	1504·61
3. Punjab National Bank	3178	1029·82
4. Bank of Baroda	1880	290·18
5. United Commercial Bank	3013	616·95
6. Canara Bank;	11248	630·68
7. United Bank of India	4524	995·00
8. Dena Bank	1862	217·98
9. Syndicate Bank	2626	573·40
10. Union Bank of India	1806	201·43
11. Allahabad Bank	1472	200·92
12. Indian Bank	730	39·20
13. Bank of Maharashtra	3843	309·22
14. Indian Overseas Bank	3134	171·74
TOTAL	82229	10014·25

(Data provisional)

Statement II

State-wise advances by public sector banks under employment oriented porgrammes as at the end of December, 1977.

State/Union Territories	No. of applications sanctioned	Amount outstanding (Rs. lakhs)
1. Andhra Pradesh	11237	541·82
2. Assam	882	109·15
3. Bihar	11202	1091·58
4. Gujarat	1834	155·35
5. Haryana	355	99·37
6. Himachal Pradesh	23	5·62
7. Jammu & Kashmir	1040	69·93
8. Karnataka	4558	1015·82
9. Kerala	4204	156·36
10. Madhya Pradesh	3257	595·78
11. Maharashtra	24672	2124·68
12. Manipur	180	64·89
13. Meghalaya	46	13·94
14. Nagaland	1	0·08
15. Orissa	341	82·81
16. Punjab	742	158·87
17. Rajasthan	660	208·10
18. Tamil Nadu	4514	115·20
19. Tripura	127	7·76
20. Uttar Pradesh	2673	433·14
21. West Bengal	8376	2172·49
Union Territories		
23. A. & N. Islands		
24. Arunachal Pradesh	..	..
25. Chandigarh	39	85·85
26. Dadra & N. Haveli	..	..
27. Delhi	1202	696·05
28. Goa, Daman & Diu	55	1·43
29. Lakshadweep	..	..
30. Mizoram	..	..
31. Pondicherry	9	8·18
TOTAL	82229	10014·25

(Data provisional)

Articles in 'Dharam Yug' Regarding Income Tax Raids in Jaipur Palaces

9232. SHRI MOHAN LAL PIPIL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to certain articles that appeared in the different issues of Hindi weekly Magazine (Dharam Yug) during the period from 5th to 11th September and 12th to 18th September 1976 in regard to raids and searches carried out by the Income tax authorities in Jaipur palaces;

(b) whether it is a fact that in the said articles details have been given which could ordinarily not be available otherwise than through official records;

(c) whether it is also a fact that the writer of these articles is a close relative of a sernior officer of his Ministry; and

(d) whether there has been any leakage of official secrets to the writer of these articles ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) Yes, Sir.

(b) This in not correct. The articles published in the Hindi Weekly Magazine 'Dharamyug' are apparently a piece of imaginative journalistic story. These do not contain information of a secret or confidential nature borne on the official records. Such information as these articles contain could easily be gathered from different sources such as the publicity given to the searches in the media as well as from the replies to the questions and discussions in the Parliament on the subject from time to time.

(c) Yes Sir.

(d) No, Sir.

जयपुर नागौर ग्रांचलिक रूरल बैंक के चेयरमैन द्वारा मकान का निर्माण

9233. **श्री राम कंवर बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्याश्री शान्ति लाल जैन ने जयपुर नागौर ग्रांचलिक रूरल बैंक के चेयरमैन का पद सम्भातने के बाद इन्दौर में लगभग 2 लाख रुपए की लागत वाला अपना निजी मकान बना लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : जी नहीं । श्री शान्ति लाल जैन ने, अक्तूबर, 1975 में जयपुर नागौर ग्रांचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर का अध्यक्ष पद संभालने के बाद, किसी मकान का निर्माण नहीं किया है ।

इटावा जिला (उत्तर प्रदेश) में पूर्विया टोला में मारे गये छापों में बरामद वस्तुयें

9234. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने अप्रैल, 1969 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पूर्विया टोला में मारे गये छापों के दौरान बरामद चांदी और सोने की 79 पेटियों के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे;

(ख) क्या वर्ष 1969 में जिन व्यक्तियों के यहां छापे मारे गये थे उनके और उनके परिवारों के नाम में लाखों रुपयों की सम्पत्ति इटावा शहर के विभिन्न बैंकों में जमा पड़ी थी परन्तु न तो इस मामले की कोई जांच की गई और न ही तत्सम्बन्धी पास बुकों को जब्त किया गया;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो बैंक दस्तावेजों के अनुसार सरकार द्वारा बरामद जेवरात के सम्बन्ध में और बैंक में जमा धन-राशि सम्बन्धी दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ). आयकर प्राधिकारियों ने अप्रैल, 1969 में इटावा जिला के पूर्विया टोला में मैसर्स रामनारायन तथा बद्री प्रसाद और उनके परिवारों के सदस्यों के परिसरों की तलाशी ली थी । 1948–49 तथा 1954–55 से 1969–70 तक के कर-निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित खाता-बहियों और दस्तावेजों के अलावा 18.52 लाख

रुपए से ऊपर के सोने और चांदी के आभूषण पकड़े गये थे । बैंक की कोई पासबुक नहीं पकड़ी गई थी । पकड़ी गई सामग्री, निर्धारिती द्वारा दी गयी सूचना तथा विभाग द्वारा की गयी जांच-पड़ताल के आधार पर, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ बैंकों में जमा रकम के सम्बन्ध में की गई पूछताछ भी शामिल है, कर-निर्धारण वर्ष 1954–55 से 1969–70 तक के कर-निर्धारण पूरे कर लिए गए थे । छिपायी गयी आय 26 लाख रुपए निर्धारित की गई थी और उस पर कर-निर्धारण वर्ष 1956–57 से 1969–70 तक कर-निर्धारित किया गया था । इन कर-निर्धारणों के परिणामतः 23 लाख रुपए से अधिक की मांग जारी की गई गई ।

जारी की गई इस मांग की तरफ 13 लाख रुपए से अधिक की रकम पहले ही अदा की जा चुकी है । पकड़ी गई परिसम्पत्तियों में से कुछ छोड़ दी गई हैं। शेष परिसम्पत्तियों को, बकाया पड़ी मांग के प्रति प्रतिभूति के रूप में रखा गया है । इस बकाया मांग में अर्थदण्ड तथा कर-निर्धारण के पश्चात् लगाया गया ब्याज भी शामिल है ।

Income tax raid on Vishnu Sugar Mills Ltd., Bihar

9235. SHRI PALAS BARMAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) is it a fact that the Enforcement Branch of the Income Tax orgainsed a raid on Vishnu Sugar Mills Limited, Gopalganj, Bihar, 21, Chakraberia Lane, Calcutta 20, and the head office of the Mills Gillander House Calcutta simultaneously on 19th/20th August, 1976;

(b) is it a fact that unaccounted money, valuable jewelleries and records were seized from the respective places; and

(c) if so, what action the Government have taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) to (c). Income-tax authorities conducted search and seizure operations at the premises of M/s. Vishnu Sugar Mills Ltd. and connected cases on the 19th/20th August, 1976 at calcutta, Gopal Ganj and Jasidih (Bihar). These operations resulted in seizure of cash of Rs. 55,000/-, jewellery worth Rs. 2 lakhs and books of account and documents.

In the course of proceedings under section 132(5) of the Income-tax Act, the explanation given for the source of the cash was accepted after due verification, but the cash was ajusted in the discharge of the existing tax liabilities. The jewellery was found duly accounted for and declared for wealth-tax purposes and was, therefore, released.

The seized books of account and documents have been scrutinised. Requisite enquiries are being made.

व्यापार गृहों पर बकाया कर

9236. **श्री विनायक प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की आस्तियों वाले व्यापार गृह कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं । तथा उनमें से प्रत्येक पर विभिन्न प्रकार के करों की बकाया राशियां कितनी हैं; और

(ख) 5 करोड़ से 15 करोड़ रुपये की आस्तियों वाले व्यापार गृह कितने हैं और उनके नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक पर विभिन्न प्रकार के सरकारी करों की बकाया राशियां कितनी हैं और सरकार ने इन राशियों को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है और उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित व्यापारिक घरानों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ? प्रश्न की प्रभाव सीमा के अन्तर्गत आने वाले व्यापारिक घरानों की

संख्या, उनके नामों तथा उनकी तरफ बकाया विभिन्न करों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में बहुत समय लगेगा। तथापि, ऐसे बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित मामलों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध है जिनकी आयकर की सकल बकाया, 31 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपए से अधिक है। 31 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार ऐसे 63 मामलों में 26.17 करोड़ रुपए की आयकर की सकल मांग में से 31-12-77 तक 7.15 करोड़ रुपए वसूल हो गये हैं। कम हो गये हैं और इस प्रकार 19.02 करोड़ रुपए बकाया रह गये हैं। इसमें आयकर की शुद्ध बकाया की रकम 10.19 करोड़ रुपए है।

Names of the States which have taken laon from World Bank

9237. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the States which have taken loans from the World Bank, also indicating the schemes/projects from which loans have been sanctioned during 1976-77 and 1977-78; and

(b) how much amount of the loans taken by the States have been utilised for schemes for which these were taken ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). State Governments do not borrow directely from the World Bank—International Development Association Group. The enclosed Statement gives information on the Bank group assisted projects in the States for which loan/credits had been approved in 1976-77 and 1977-78 as also the aid utilised for these project upto March 31, 1978. Aid is received on a reimbursement basis as and when expenditure is incurred on the projects.

Statement

Name of States projects for which IBRD/IDA have snactioned loans during 1976-77 *and* 1977-78

(U.S. $ Million)

Sl. No.	Name of State	Name of Project & Source	Amount	Year of Signing Agreements	Amount disbursed upto end March, 1978
1	2	3	4	5	6
1	Andhra Pradesh	Andhra Pradesh Irri. (IBRD)	145·0	1976-77	4·3
2	Assam	Assam Agriculture Dev. (IDA)	8·0	1977-78	Nil
3	Bihar	Research & Extension (IDA)	8·0	1977-78	Nil
4	Gujarat	Gujarat Fisheries*	18·0	1977-78	Nil
5	Kerala	Kerala Agriculture Dev. (IDA)	30·0	1977-78	Nil
6	Mahrashtra	Bombay Urban Trpt (IBRD)	25·0	1976-77	2·8**
7	Maharashtra	Maharashtra Irrigation (IDA)	70·0	1977-78	Nil

*IDA $ 4 million and IBRD $ 14 million

**Upto end February, 1978

1	2	3	4	5	6
8	Madhya Pradesh .	Madhya Pradesh Agri. (IDA)	10·0	1977-78	Nil
9	Orissa	. Orissa Agri Dev. (IDA)	20·0	1977-78	0·2
10	Orissa	. Orissa Irrigation (IDA)	58·0	1977-78	Nil
11	Rajasthan	. Raj. Agriculture Extn. (IDA)	13·0	1977-78	Nil
12	Tamil Nadu .	. Pariyar Vaigai (IDA)	23·0	1977-78	Nil
13	Tamil Nadu .	. Madras Urban Dev. (IDA)	24.0	1977-78	0.6
14	West Bengal .	. West Bengal Agri. Dev. (IDA) .	12.0	1976-77	Nil
15	West Bengal .	. Calcutta Urban Dev. II(IDA) .	87.0	1977-78	Nil

NOTE : IBRD—International Bank for Reconstruction and Development (World Bank).
IDA—International Development Association.

रिजर्व बैंक आफ इंडिया में लोगों द्वारा फटे-पुराने नोटों का बदला जाना

9238. **श्री लालजी भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया में बहुत से व्यक्ति कुछ रकम लेकर फटे-पुराने नोटों के बदले नये नोट देते हैं ;

(ख) क्या यह काम रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के बिल्कुल सामने होता है और बहुत से लोग यह व्यापार करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह काम वैध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). सरकार को किसी ऐसे कदाचारों का पता नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

Procedure for appointment of principal, Staff Training College, Federal Bank

9239. **SHRI R. L. P. VERMA:**
SHRI MANOHAR LAL :
Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the qualifications and procedure for appointment of Principal, Staff Training College, Federal Bank; Alwaye, Kerala;

(b) whether it is a fact that a Third Class Graduate' who is the son of present Chairman of the Bank and is only 18—20 years old, has been appointed as Principal of this Staff Training College ignoring the prescribed rules and regulations to fill up the post of Principal and has superseded a number of employees ;

(c) whether it is also a fact that the person working as Principal has been demoted as Vice-Principal; and

(d) if so, full details thereof and action proposed to be taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (d). It has been ascertained from the Federal Bank Ltd. that there is no post of Principal in their Staff Training College at Alwaye. The Bank's Chairman is functioning as its 'head' and is assisted in the day to day work by an officer of the Bank designated as Chief Instructor. The Federal Bank has also reported that it has no proposal to post the son of its Chairman to the Staff Training College.

Supply of Income-tax Assessment Records to Comptroller and Auditor General

9240. SHRI JYOTIRMOY BOSU : SHRI MOHAN LAL PIPIL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the instructions of the Government for supplying the Income-tax assessment records to Comptroller and Auditor General when requisitioned by him;

(b) is Government aware that the assessment record of Shri I. P. Gupta Member Central Board of Direct Taxes and his HUF were not made available to Comptroller and Auditor General for about two years; and

(c) if this is correct then what action Government propose to take to prevent such delay in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) Files are requistioned by Audit Parties when the local audit of an Income-tax Office is taken up. According to instructions of the Central Board of Direct Taxes and the practice followed in this regard the files requisitioned for audit have to be made available to the Audit without any delay. Further if for any reason a file is not available with the Income-tax Officer at that time the fact is to be intimated to the Audit and the file made available as soon as possible for that audit or the next audit of that Income-tax Office.

(b) In so far as the case of Shri I. P. Gupta in the status of individual is concerned it has been found that the Receipt Audit Officer of the Accountant General, Central Revenues, New Delhi initially sent a requisition on 16·5.1977 for the assessment records of Shri I. P. Gupta for 'reference and return'. Since no receipt audit inspection was going on, the Income-tax Officer concerned requested the Senior Deputy Accountant General on 30.4.1977 that the audit objections in the case may be sent so that these could be scrutinised with reference to the records. The Income-tax Officer did not receive any reply form the Senior Deputy Accountant General for some time. Subsequently after exchange of some correspondence the relevant records were made over to the Receipt Audit on 1.4.1978.

M/s. I. P. Gupta (HUF) is assessed regularly in District X(8) from the assessment year 1972-73. The Receipt Audit of the Accountant General, Central Revenues, New Delhi, never requisitioned the file of M/s. I. P. Gupta (HUF) during the course of their annual audit for the year 1972-73 to 1976-77. However, the Receipt Audit Officer of the Accountant General, Central Revenues, New Delhi, wrote demi-officialy to the Income-tax Officer concerned on 5.8.1976 stating that the records were required by him "in connection with certain information to be furnished to higher authorities". The audit Officer did not indicate as to what type of information was required by higher authorities. However, after exchange of some correspondence, the relevant assessment records were made available to the Audit on 9.3.1978.

(c) Standing instructions on the subject as referred to in answer to part (a) of the question already exist. These will be reiterated.

Negotiated Settlement arrived at between LIC and National Federation of Field Workers Association

9241. SHRI R. P. DAS : SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state ;

(a) whether the Government are aware of a negotiated Settlement arrived at between the Life Insurance Corporation of India and National Federation of Field Workers Association; in respect of revision of pay scales minimum work norms and other service conditions;

(b) if so, whether the outcome of the said agreement has been enforced or not ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) (a) and (b). Negotiations are being held with National Federation of Field Workers with a view to evolving norms for appraising the performance of Development Officers.

Recruitment of New Hands in Development Banking Centre

9242. SHRI DINEN BHATTACHARYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Development Banking Centre sponsored by I.F.C.I. held an interview for recruitment of new hands;

(b) if so, the total number of applicants turned up and the Statewise breakup;

(c) is it also a fact that the authorities conducting the interview and in *Viva-voce* test enquired about the following :— "Comments on Charan Sing's economic thought on the Indian Economy;" and

(d) if so, whether it is permissbile to put such a question which causes embarrassment and to the applicant ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (d). Interviews were held for the recruitment of Research Assistants by the Development Banking Centre of the Management Development Institute on 17th and 18th March, 1978.

The State-wise break-up of the 39 applicants who turned up for interview is given below :

AndhraPradesh	6
Assam .	1
Bihar	2
Delhi .	8
Haryana .	3
Himachal Pradesh .	2
Karnataka	2
Kerala .	1
Orissa .	1
Punjab .	2
Rajasthan	4
Tamil Nadu .	3
Uttar Pradesh	1
West Bengal .	3
TOTAL :	39

There was no prepared text or set form of the serveral hundred questions asked by the Board consisting to our members. The questions were meant to assess the capabilities of the candidates in the areas of general knowlege, awareness of the recent socio-economic developments in the Indian economy, analytical ability, grasp of the tools and methods of research particularly in collecting and analysing data and the depth of insight in the field of specialisation. Some applicants may have been asked to comment on Shri Charan Singh's economic thought. The main purpose in asking questions was to find out whether an applicant keeps in touch with the recent development of thought in the area of his specialisation and not to embarass any candidate.

Utilisation of youhg hostels built in States

9243. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to State :

(a) whether the Youth Hostels built in some States are being fully utilised for the purpose for which they were built;

(b) whether any annual report is also demanded from the state Governments in whose States these Hostels have been built; and

(c) whether Government gives concessions to the trekking parties/expeditions also in case they need accommodations in these hostels and if not the reasons ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The 14 Youth Hostels which have been functioning so far have been commissioned between 1975-1976 except Jaipur. The occupancy at these hostels has therefore been low.

The Government has appointed a Study Team to inspect and identify defects/shortcomings in the working of these establishments and suggest remedial measures wherever necessary with a view to increase the occupancy and to achieve objective of making these hostels as nucleus of youth activities.

(b) The Wardens of Youth Hostels submit monthly as well as Annual Performance Reports in respect of the hostel under their charge.

(c) No, Sir. This is under consideration.

Permission to Chairman, Central Board of Excise and Customs to be away from the Country

9244. SHRI VASANT SATHE : Will the Minister of FINANCE be pleased to to state :

(a) is it not the overall responsibility of the Chairman, Central Board of Customs and Excise to be associated with the preparation and presentation of budget in the Lok Sabha and its consideration; and

(b) what were the compelling circumstances which prompted the Government to permit the Chairman, Central Board of Excise and Customs to be away from the country when he should have been present in India ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) The Chairman, Central Board of Excise and Customs is very much concerned with all budgetary exercises relating to indirect taxes and he was in fact fully associated with them.

(b) In deputing officers to go abroad to represent Government at international conferences, Government carefully consider the urgent commitments at home and importance of the deputation abroad. The session of the United Nations Commission on Narcotic Durgs is of vital importance to India and Government considered it necessary that the Chairman, Central Board of Excise and Customs should lead the Indian delegation. Even so, because of his preoccupations with the Budget, he had to delay his departure and could join the Indian delegation at Geneva only for the second week of the U. N. Session.

तस्करी का सोना

9245. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976–77 की तुलना में वर्ष 1977–78 के दौरान कितनी मात्रा में सोने की तस्करी की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : देश में चोरी छिपे लाये गये सोने की मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं हैं । परन्तु, 1977 में, सीमा शुल्क अधिकारियों ने 160 लाख रुपये मूल्य का 264 किलो ग्रा० निषिद्ध सोना पकड़ा, जब कि उसके मकाबल में 1976 में 83 लाख रुपये मूल्य का 175 कि०ग्रा० निषिद्ध सोना पकड़ा गया ।

Companies in Public Sector

9246. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) total number of companies in the public sector and the total money invested in them by the Government;

(b) in how many companies there is a loss and what was the total loss in such losing companies during 1976-77 and 1977-78;

(c) number of companies which have not submitted their accounts in time in the last two years; and

(d) what action has been taken against each of them ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). The latest year for which complete audited accounts are available is 1976-77. In that year, there were 158 Central Government enterprises. The investment by Central Government by way of equity and loans in these companies amounted to Rs. 9816 crores as on 31-3-1977. During the year, 43 companies suffered losses amounting to Rs. 146·91 crores. The completed audited accounts for 1977-78 will be available towards the end of the year.

(c) and (d). Two companies were not able to report their audited accounts in time for the preparation of the Bureau of Public Enterprises' Annual Report on the "Working of Industrial and Commercial Undertakings of the Central Government (1976-77)" which was placed on the Table of the House in February, 1978. Companies have been requested to be more punctual in completion of their accounts and audit.

Closing the Transport Department in the Eastern Zone of I.T.D.C.

9247. SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware about the conspiracy of closing of the Transport Department in the Eastern Zone of ITDC for the benefit of big private transport agencies;

(b) whether Government are aware that the amount of loss of Eastern Zone of ITDC during the period of 1977-78 is about 1·5 lakhs, if so, the reasons threof;

(c) whether Government are aware that out of seven ITDC airconditioned car, six are lying idle in a garrage in Calcutta; if so, the reasons thereof ;

(d) whether attention of Government has been drawn to the malpractices, corruptions, and nepotism prevailing in ITDC ; and

(e) if so , what steps have been taken to stop these things ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir. There is no proposal to close down the I.T.D.C. Transport Establishment in the Eastern Zone at present.

(b) In the Eastern Zone the Corporation is operating its transport Units at Patna, Varanasi and Bhubneshwar. Out of these Patna and Varanasi have shown profits while Calcutta and Bhubaneshwar have incurred losses. The aggregate net losses in the Eastern Zone have decreased from Rs. 2·81 lakhs during 1976-77 to Rs. 1·65 lakhs during 1977-78.

The Government have constituted a Committee to go into the question of the working of the Transport Division and suggest remedial measures so as to enure optimum utilisation of the fleet and its most economical operation.

(c) The fleet of the Calcutta Transport Unit includes 7 airconditoned imported cars which are 6-8 years old. Out of these 2 are on the road and other 3 would be available for operations by the end of May 1978 after repairs. The remaining 2 need uneconomical extensive repairs, therefore, the question of their disposal or alternative use is under consideration.

(d) and (e). In the absence of reference to any specific charges/allegations it is not possible to furnish information/facts. All charges relating to mal-practices, corruption and nepotism are carefully looked into the ITDC Management and appropriate remedial action is taken from time to time.

Employees of Government of India Mint, Alipore, Calcutta

9248. SHRI MUKUNDA MANDAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether he has received any representation from Shri A. K. Biswas, President I. G. Mint Scheduled Caste/Scheduled Tribes Employees Council, Calcutta-53, for ensuring justice to the employees of the India Government Mint, Alipore, Calcutta; and

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the steps taken in regard thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH) : (a) Yes, Sir, a representation has been received.

(b) In 1976, some employees of the India Government Mint, Calcutta, filed a suit in the High Court at Calcutta representing, inter alia, against alleged wrongful promotion of a "junior" colleague. In their Judgement of 23-2-1978, the High Court directed the Mint authorities to adjust the seniority of the petitioners alongwith other Upper Division Clerks on the basis of the length of continous service in the grade of Upper Division Clerk and prepare a fresh seniority list.

(c) The Mint authorities have been advised to revise the seniority list of Upper Division Clerks on the basis of the length of service prior to 22-12-1959.

सेंट्रल एक्साइज विभाग, कानपुर में निरीक्षकों के विरुद्ध विभागीय जांच

9249. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल एक्साइज विभाग कानपुर के अन्तर्गत कितने निरीक्षकों के विरुद्ध विभागीय जांच 6 साल से अधिक समय से चल रही है; और

(ख) उपरोक्त मामलों में लम्बे समय से चल रही जांच के कारण संबंधित निरीक्षकों को धन की कितनी हानि हुई और उनकी पदोन्नति रुकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय कानपुर के 4 निरीक्षकों के खिलाफ 6 वर्षों से भी अधिक समय से विभागीय कार्यवाही चल रही है। इन में से तीन के खिलाफ जांच पूरी

हो चुकी है और चौथे निरीक्षक के खिलाफ जांच चल रही है ।

(ख) चूंकि संबंधित निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाहियों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए यह हिसाब लगाना संभव नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण उन्हें किस हद तक वित्तीय नुकसान हुआ है अथवा कहां तक उनकी पदोन्नति रुकी हुई है ।

Iron Ore Exported from Orissa Mines

9250. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the total quantity of iron ore exported from the Orissa Mines in the year 1977 and during the first quarter of 1978;

(b) what percentage of such ore has been exported through Paradeep port, Haldia port and Vizag port (separatelly); and

(c) the amount of foreign exchange earned from export of iron ores from Orissa during the last two years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) and (b). Iron Ore produced in Mines located in Orissa/ Bihar is exported through the ports of Paradeep and Haldia. Separate figures of Orissa iron ore passing through Paradeep and Haldia ports are not maintained. However, 60 to 70% of iron ore exported through Paradeep and Haldia originates from mines located in Orissa.

Table below gives the exports made through Paradeep and Haldia ports during 1977 and the first quarter of 1978 :

Port	Quantity	Value
	million tonnes	Rs. Crores
Paradeep : 1977 .	2·479	33·80
1-1-78 to 31-3-78 .	0·450	6·45
	2·929	40·25
Haldia : 1977	0·093	1·35
1-1-78 to 31-3-78	0·039	0·56
	0·132	1·91

Iron ore frm Orissa/Bihar mines is not exported through Vizag.

(c) Foreign exchange earned during 1976-77 and 1977-78 for exports through Paradeep and Haldia ports is given below :

Port	1976-77	1977-78
	Rs. crores	Rs. crores
Paradeep . .	35·16	36·37
Haldia . . .		1·94

Slash in Target of Export of Iron Ore During 1978-79

9251. SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to State :

(a) whether the export target of iron ore during 1978-79 has been slashed; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) and (b). The export target of iron ore for 1978-79 is under the consideration of the Government.

छोटे, मध्यम तथा बड़े किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से दिये गये ऋण

9252. **श्री अधन सिंह ठाकुर :**
श्री रामानन्द तिवारी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि विकास के लिए छोटे, मध्यम तथा बड़े किसानों को कितनी राशि के ऋण दिये ;

(ख) ऋणों के भुगतान के रूप में कितनी राशि वसूल की गई और वास्तव में कितनी राशि वसूल होनी चाहिए थी ; और

(ग) उक्त अवधि में कितनी राशि बट्टे खाते डाली गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मार्च, 1973 से 1977 तक के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार किसानों को दिए गए प्रत्यक्ष ऋणों और उनकी बकाया राशि के जोतवार वितरण विषयक आंकड़े संलग्न विवरण में दिए जा रहे है ।

(ख) किसानों को मंजूर किये गये प्रत्यक्ष ऋणों के बारे में वसूली विषयक आंकड़े जून के अन्त की स्थिति के आधार पर संकलित किये गये हैं। जून, 1973 से 1977 तक के वर्षों से सबधित मांग और वसूली की स्थिति संलग्न विवरण में दी जा रही है ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक सामान्यतया अपनी वार्षिक आय में से अपने लेखा परीक्षकों की संतुष्टि के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान रखते हैं तथा उन ऋणों को ऐसे प्रावधानों में से बट्टे खाते डाल देते है जो उनके प्रबन्धकों द्वारा अन्तिम रूप से अशोधनीय मान लिये जाते है । बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबन्धों के अधीन, बैंकों को संविधिक अधिकार दिये गये है कि वे अशोध्य और संदिग्ध उन ऋणों की राशि की मात्रा को गुप्त रखें जिनके लिये उनके लखा परीक्षकों ने सन्तोष के अनुरूप प्रावधान कर दिया है ।

विवरण

मार्च, 1973 से 1977 तक के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को मंजूर किये गये प्रत्यक्ष ऋणों और उनकी बकाया राशि (अल्पकालिक और मध्य/दीर्घकालिक दोनों प्रकार की) का जोतवार वितरण दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

जोत का आकार	भारतीय स्टेट बैंक समूह		राष्ट्रीयकृत बैंक		जोड़	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मार्च 1973						
5 एकड़ तक	182623	27.63	328947	35.11	511570	62.74
5 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक	81184	13.00	120830	33.56	182014	48.56
10 एकड़ से अधिक	62965	28.91	150785	88.74	213750	117.65
जोड़	306772	69.54	600562	157.41	907334	226.95

1	2	3	4	5	6	7
मार्च, 1974						
5 एकड़ तक .	289661	32.84	448145	52.59	737806	85.43
5 एकड़ से अधिक और						
10 एकड़ तक .	86846	18.79	163124	45.21	249970	64.00
10 एकड़ से अधिक	81717	47.02	198765	127.47	280482	174.49
जोड़	458224	98.65	810034	225.27	268258	323.92
मार्च, 1975						
5 एकड़ तक .	409480	62.31	576892	73.01	986372	125.32
5 एकड़ से अधिक और						
10 एकड़ तक	116201	26.75	178771	57.43	294972	84.18
10 एकड़ से अधिक	99833	67.28	208101	148.71	307934	215.99
जोड़	625514	146.34	963764	279.15	1589278	425.49
मार्च, 1976						
5 एकड़ तक .	607708	90.74	854453	112.11	1462161	202.85
5 एकड़ से अधिक और						
10 एकड़ तक	163089	37.16	228168	72.92	391257	110.08
10 एकड़ से अधिक	140834	83.38	240363	183.11	381197	266.49
जोड़	911631	211.28	1322984	368.14	2234615	579.42
मार्च, 1977						
5 एकड़ तक .	972592	137.34	1150693	157.33	2123285	294.67
5 एकड़ से अधिक और						
0 एकड़ तक .	252596	55.84	295109	97.23	547705	153.07
एकड़ से अधिक	190154	122.49	280628	221.37	470782	343.86
जोड़	1415342	315.67	1726430	475.93	3141772	791.60

विवरण

जून 1973 से 1977 तक को समाप्त हुए वर्षों के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को मंजूर किये गये प्रत्यक्ष ऋणों की स्थिति वसूली की दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	मांग	वसूली	मांग से वसूली का प्रतिशत
जून, 1973			
भारतीय स्टेट बैंक समूह .	40.43	19.23	47.6
राष्ट्रीयकृत बैंक . .	41.32	23.81	57.6
जोड़ . .	81.75	43.04	52.7
जून, 1974			
भारतीय स्टेट बैंक समूह	55.22	28.37	51.4
राष्ट्रीयकृत बैंक .	149.37	70.23	47.0
जोड़ . .	204.59	98.60	48.2
जून, 1975			
भारतीय स्टेट बैंक समूह .	95.18	55.04	57.8
राष्ट्रीयकृत बैंक . .	201.98	94.13	46.6
जोड़ . .	297.16	149.17	50.2
जून, 1976			
भारतीय स्टेट बैंक समूह	115.03	64.92	56.4
राष्ट्रीयकृत बैंक .	265.28	128.71	48.5
जोड़ .	380.31	193.63	50.9
जून, 1977			
भारतीय स्टेट बैंक समूह	164.97	91.20	55.3
राष्ट्रीयकृत बैंक . .	343.27	155.93	45.4
जोड़ . .	508.24	247.13	48.6

सहकारी समितियों का कार्यकरण

9253. **डा० रामजी सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सहकारी समितियां संतोष जनक रूप से कार्य नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनके कार्यकरण में गति लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार हैं ; और

(ग) सहकारी समितियों के जरिए सार्वजनिक वितरण पद्धति में अनियमितताओं को रोकने के बारे में क्या प्रबन्ध किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) देश में सहकारी संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति करती रही हैं, यद्यपि कुछ मामलों में उनका कार्यकरण सर्वथा संतोषजनक नहीं है ।

(ख) कुछ सहकारी संस्थाओं के असंतोषजनक ढंग से कार्य करने के कारण अधिकतर ये हो सकते हैं—प्रबन्ध में त्रुटि होना, व्यावसायिक प्रबंध का अभाव होना, कमजोर पूंजीगत ढांचा होना, व्यापार मूलक नीतियां तथा प्रक्रियायें न अपना पाना, सदस्यों की निष्ठा का अभाव, निहित स्वार्थों की वृद्धि आदि ।

सहकारी समितियों का ठोस आधार पर विकास करने तथा उन्हें कारगर बनाने के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में सहकारी समितियों के पंजीयकों तथा सहकारिता के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलनों में विचार-विमर्श किया जाता है । भारत सरकार ने हाल ही में एक कार्यवाही कार्यक्रम का सुझाव दिया है, जिसमें राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी प्रशासन को सक्रिय करें तथा उनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रभावी कार्यवाही कार्यक्रम शुरू करें और सहकारी समितियों के उचित प्रकार से कार्य करने के लिए कारगर उपाय करें ।

(ग) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि उचित दर की दुकानों के आवंटन में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिये सहकारी समितियों का विकास किया जाना चाहिये । सहकारी समितियों को आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने के लिये भी कदम उठाये गये हैं; ताकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपनी उचित भूमिका अदा कर सकें ।

Delayed Take-off of Planes from Palam Airport

9254. SHRI RAJE VISHVESHVAR RAO : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) is it a fact that not a single plane these days leaves Palam Airport in time ;

(b) what is the reason therefor; and

(c) action Government proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). No, Sir. For the period 1st April to 25th April, 1978 out of 561 Indian Airlines flights, 464 take-offs were on schedule and there were 97 delays exceeding 15 minutes. For the period 1st April to 15th April, 1978, out of 71 Air-India flights, 9 left on Schedule and 40 flights were delayed for a period beyond 15 minutes.

Most of delays were due to consequential factors like late arrival of aircraft at Delhi and Engineering/Traffic problems.

(c) Government have set up a Committee under the Chairmanship of Secretary, Civil Aviation, consisting of the representatives of Air-India, Indian Airlines, Civil Aviation Department, India Meteorological Department and International Airports Authority of India to

examine the delays taking place in arrival and departure of scheduled services operated by Air-India and Indian Airlines.

सिक्किम की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों पर प्रतिबन्ध

9255. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री के० बी० चेतरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विदेशी पर्यटकों की सिक्किम यात्रा पर कुछ प्रतिबन्ध थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन प्रतिबन्धों में कुछ सीमा तक ढ़ील दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि फोरेनर्स (प्रोटेक्टिड एरियाज़) आर्डर, 1958 के अन्तर्गत सिक्किम एक सुरक्षित क्षेत्र है इसलिये विदेशी पर्यटक ग्रुपों को दो दिनों के लिए केवल गंगटोक तथा रूमटेक ही जाने की अनुमति दी जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग विदेशी पर्यटक अब दो दिनों के लिए गंगटोक जा सकते हैं तथा, यदि वे चाहें, तो 4 दिन के लिये फोडांग तथा रूमटेक भी जा सकते हैं । 20 के ग्रुपों में यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को, जिनका पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंटों द्वारा प्रबन्ध किया गया हो, यात्रा समय को मिलाकर 10 दिन की अवधि के लिये पश्चिमी सिक्किम के ज़ोगरी क्षेत्र में ट्रेकिंग की भी अनुमति दी जाती है बशर्ते कि वे वागडोगरा तक विमान द्वारा जायें और ट्रेकिंग के लिए निर्धारित मार्गों से ही यात्रा करें ।

Applications from Small Scale Units of Paints and Varnishes for refund of Duty

9256. SHRI R.V.SWAMINATHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that many small scale units of paints and varnishes who were working under simplified procedure were asked to pay duty for April, 1978, despite concessions announced by Government in budget for 1978-79 in February, 1978 ;

(b) whether these units have applied for refund;

(c) if so, whether no action has so far been taken on these applications;

(d) the reasons for the same; and

(e) by what time the refund is being made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) to (e). Information is being collected from the various collectorates and will be placed on the Table of the Sabha.

Non-availability of National Development Bonds in Nationalised Banks, Bombay.

9257. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Development Bonds are not available in the nationalised banks in Bombay and New Delhi ;

(b) if so, the reasons thereof ;

(c) if so, the details of National Development Bonds sold by the nationalised banks through its offices in Bombay during the past six months ; and

(d) details bank-branch-wise ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). The National Development Bonds are available in the nationlised banks in Bombay. These are not, however, at

present available in some of the nationalised banks in New Delhi. Sufficient quantities of these bonds are kept by the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India and the banks in New Delhi have been advised to obtain their requirements from them for meeting the demand from the public.

(c) and (d). The bank-branch-wise details of N. D. Bs. sold by the nationalised banks through their offices in Bombay during the period October, 1977 to March, 1978 to the extent information is at present available, are given hereunder :

Public Sector Banks in Bombay — *Figures in Rupees*

1	2
1. *State Bank of India*	**1,21,050**
(i) Cuffe Parade	1,000
(ii) BARC Trombay	1,000
(iii) Bombay Main Branch	*92,250
(iv) Shivaji Park	4,000
(v) I.I.T. Pawai	6,800
(vi) Girgaon	11,000
(vii) Malad (East)	5,000
2. *Bank of Baroda*	**97,500**
(i) Kandivili	7,300
(ii) Sir P. M. Road	7,400
(iii) Shivaji Park	37,800
(iv) Ambedkar Road	2,000
(v) Sion	2,000
(vi) Bori Bunder	4,000
(vii) Khar	1,000
(viii) Marine Drive	31,000
(ix) Colaba	5,000
3. *Syndicate Bank*	**43,700**
(i) Pali Hill Bandra	30,000
(ii) Chambur	8,700
(iii) Tardeo	1,000
(iv) New Marine Lines	4,000
4. *Indian Bank*	**17,000**
(i) King's Circle	7,000
(ii) Chembur	5,000
(iii) Malad	3,000
(iv) Bombay Fort	2,000
5. *Central Bank of India*	**94,110**
(i) Bombay Main Office	43,650
(ii) Wadala	35,000
(iii) Dadar (B.S. Road)	6,000
(iv) Chembur	5,050
(v) Opera House	210
(vi)Prabhadevi	4,000
(vii) Naigaum	200
6. *Punjab National Bank*	**4,000**
(i) Andheri	4,000
7. *Allahabad Bank*	**35,000**
(i) Khar (Bombay)	35,000
8. *Canara Bank*	**40,000**
(i) Tamarind Lane, Bombay	5,000
(ii) Fort Bombay	3,200
(iii) Matunga (East)	5,130
(iv) Sion, Bombay	8,020
(v) Sindhi Society Chembur	15,000
(vi) Goregaon West	4,450
9. *Bank of India*	**2,11,470**
(i) Bombay Office	51,000
(ii) Vile Parle	600
(iii) Churchgate	6,870
(iv) Versoa	3,000
(v) Museum Savings	22,000
(vi) Goregaon	500
(vii) Hill Road, Bandra	8,900
(viii) Mulund East	4,500
(ix) Worli Naka	300
(x) Electric House	2,000

1	2
(xi) Ghatkopar (West)	7,500
(xii) Prabhadevi	49,500
(xiii) Andheri .	10,000
(xiv) Fort	5,000
(xv) Casrow Baug	30,000
(xvi) Wode House Road	4,200
(xvii) Dadar (West)	6,500
10. *Union Bank of India*	**41,170**
(i) Nariman Point	100
(ii) Nepean Sea Road	1,500
(iii) B. S. Marg	70
(iv) A.R. Street	3,500
(v) Borivli (W)	500
(vi) Matunga	500
(vii) Dahisar	34,000
(viii) Bhiwandi .	1,000
11. *Bank of Maharashtra*	**1,18,000**
(i) Fort, Bombay	10,000
(ii) Borivli(E)	3,00
(iii) Borivli (W)	9,500
(iv) Chembur .	15,800
(v) Bandra (E)	4,100
(vi) Lalbaug	4,000
(vii) Vile parle (E)	7,300
(viii) Worli	22,000
(ix) Bombay Central	20,000
(x) Mulund	5,000
(xi) Thakurdwar	5,000
(xii) Kandivli	5,000
(xiii) Mazgaon .	10,000
GRAND TOTAL . .	8,23,800

Demand for Airport at Dhanbad in Bihar

9258. SHRI A. K. ROY : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there has been continuous demand to have an airport at Dhanbad, Bihar for commercial flight by India Airlines, if so, the result thereof ;

(b) whether it is a fact that Dhanbad being Head Quarter of many Central Government establishments is handicapped for quick communication with Centre.

(c) whether it is a fact that all the industrial centres like Ranchi and Jamshedpur are having stoppage for commercial flights; and

(d) if so, reason for discriminations against Dhanbad ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) to (d) . There have been requests for an aerodrome at Dhanbad. Indian Airlines or non-scheduled operators have not evinced any interest in operating air services to Dhanbad. There are no plans for developing an aerodrome at Dhanbad. Indian Airlines are presently operating a daily Boeing 737 service to Ranchi. No scheduled air services are operated to Jamshedpur.

Export Subsidy for Sugar and Natural Rubber

9259. SHRI GEORGE MATHEW : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) what is the difference in view the Central Government has taken regarding the export subsidy for sugar and that of natural rubber ;

(b) what is the basis under which the price of RMA-I-X sheet—(natural rubber) was fixed at Rs. 655 per quintal in 1977 August; and

(c) whether the Central Government is willing to give a minimum Remunerative price to the one and a half lakh of small growers in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) Under the International Sugar agreement which was ratified by India, a quota of sugar exports has been fixed for India. This committed export is canalised through the S.T.C. As this export transaction involves certain losses, a subsidy by Co-

vernment is envisaged. As regards natural rubber Government authorises S.T.C. to purchase surplus rubber only for export from time to time and such export operations are made on a commercial basis.

(b) and (c). The question of revision of the minimum price of rubber consequent on the increased price of inputs was considered by Government and the minimum price per quintal of Grade-I rubber was raised from Rs. 520 to Rs. 655 with differentials for other grades. While revising the minimum price due regard was given for the need to give a fair return specially to the small grower and for maintaining prices of all essential commodities at reasonable levels. These prices were notified on 6th August, 1977 and are now effective upto 31st May, 1978. In the meantime, the position is being reviewed.

विदेशों में भारतीय एम्पोरियम

9260. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में इस समय भारत के एम्पोरियम की देशवार संख्या क्या है और उनमें पृथक-पृथक कितने कितने भारतीय और विदेशी कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या भारतीय वस्तुओं को लोकप्रचलित बनाने के लिए गत वर्ष कुछ नये एम्पोरियम विदेशों में खोले गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के न्यूयार्क, पेरिस, नैरोबी तथा टोकियो में विदेश स्थित चार एम्पोरियम हैं । इन एम्पोरियमों में कार्य करने वाले भारतीय तथा विदेशी कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

	भारतीय कर्मचारी	विदेशी कर्मचारी	
		नियमित	अंशकालिक
1. न्यूयार्क—सोना शाप एंड वेयर हाउस	7	2	1
2. पेरिस—सोना शाप एंड वेयर हाउस	2	4	2
3. नैरोबी—सोना शाप . .	2	3	—
4. टोकियो—सोना शाप . . .	1	1	2

(ख) और (ग) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा पिछले वर्ष विदेशों में कोई नया एम्पोरियम नहीं खोला गया ।

Development of Airports at Renigunta and Tirupati

9261. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to develop airports at Renigunta and Tirupati ;

(b) if so, the proposals; and

(c) when will they be implemented ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) to (c). An airport already exists at Renigunta near Tirupati town, Indian Airlines is operating a daily HS-748 service to Tirupati/Renigunta.

Air Service between Gandhidham and Bombay

9262. SHRI ANANT DAVE : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether any representation received by the Government from the Gandhidham Chamber of Commerce regarding Air service between Gandhidham and Bombay ;

(b) whether it is true that this demand is pending since long with his department; and

(c) whether there is any proposal before Government for New Air services to the Backward areas ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) Due to severe constraints of aircraft resources, it has not been possible for Indian Airlines to provide a service to Kandla. Besides, Kandla is at a short distance from Bhuj which is well connected with Bombay. However, a connection to Kandla will be considered as and when some turbo-prop resources become available.

(c) A proposal for third-level feeder air services in the country is under the consideration of Government.

Facilities of Tourism in Sikkim

9263. SHRI K. B. CHETTRI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) What are the existing facilities of tourism in the State of Sikkim;

(b) whether the Central Government has formulated any concrete policy with regard to tourism in view of the acute difficulties of transport facilities;

(c) if so, the details thereof;

(d) if not, the reasons thereof; and

(e) whether any fresh proposal to attract foreign tourists to visit Sikkim is under the consideration of the Government; if so, details thereof and if not, why not ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) A total of 420 beds are available in Gangtok, and it is understood that loan have been granted to private entrepreneurs by the State Government for adding 300 beds in the next two years. The State Government is also constructing a 78-bed tourist hotel which is expected to be commissioned shortly. A 50-bed tourist lodge has been provided at Pemayangtse and a cafetaria has been opened at Rangpo. As regards transportation, the Sikkim Nationailsed Transport has a large fleet of buses out of which six 30-seater buses are being run on Siliguri/Gangtok route, 3 buses on Gangtok/Kalimpong route and 3 10-seater mini buses on Gangtok/Darjeeling route. In addtion, private transport operators also ply vehicles to meet the requirements of road travellers. The State Department of Tourism has a 10 seater mini-bus which is used for conducted sight-seeing tours.

(b) to (d) No schemes have been formulated for tourism development in Sikkim primarily because there is restriction on the entry of international tourists into Sikkm. However, the investment by the Centre in developing tourist facilities in Sikkim will be considered in consultation with the State Govt. while finalising their Tourism Plan at the time of discussion on the State Five Year Plan 1978-83. As regards transport facilities, a provision of Rs. 5 lakhs has been made in the tourism sector of the State Annual Plan 1978-79 for the purchase of vehicles for use by tourists.

(e) With the liberalisation int he entry of international tourists into Western Sikkim it is proposed to arrange, in consultation with the Sate Government, trekking programmes in that area for attracting international tourists.

Setting up of Export-import Bank

9264. SHRI JANARDHANA POOJARY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether All India Manufacturers Organisation's Association has urged for setting up Export-Import Bank; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Government does not appear to have received any representation from the All India Manufacturers Organisation for the setting up of an Export-Import Bank.

(b) Does not arise.

Fixation of support price for mustard seed

9265 SHRI D.B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government of India have recently fixed the support price for mustard seed for the fair average quality for the current year; and

(b) of so, the details regarding the policy of Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) Yes, Sir.

(b) Support price for mustard seed for the fair average quality has been fixed at Rs. 225 a quintal for the 1977-78 season. The support price ouerations have been entruted to National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED)

Central loan outstanding against States

9266. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the amount of Central loan outstanding against different States and Union Territories as on 31st March, 1978 separately;

(b) the amount realised by the Centre by way of principal and interest; and

(c) the amount of central loan and grant separately provided to each State and Union Territory during 1977-78 ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The accounts for 1977-78 have not yet been finalised. A statement giving the latest available information is laid on the Table of the House.

(b) and (c) The actuals including the State-wise details will be available only after the accounts for 1977-78 are finalised. However, according to the Revised Estimates for 1977-78, (which are not prepared State/Union territory-wise) the relevant information for the year is as follows:—

	(Rupees in crores)
(i) Recovery of Central loans from States and Union Territory Governments .	860
(ii) Interest payments by State and Union territory Governments on Central loans	524
(iii) Gross disbursement of Central loans to State and Union territory Governments . . .	2020
(iv) Payments of grants-in-aid to State and Union territory Governments . .	2032

Statement

(Rupees in crores)

S.No.	States	Amount of loan outstanding on 31-3-76
1	2	3
1.	Andhra Pradesh .	770
2.	Assam .	443
3.	Bihar .	836
4.	Gujarat	393
5.	Haryana .	242
6.	Himachal Pradesh	168
7.	Jammu & Kashmir	411
8.	Karnataka	486
9.	Kerala .	409
10.	Madhya Pradesh .	483
11.	Maharashtra .	743
12.	Manipur	58
13.	Meghalaya	20
14.	Nagaland	29
15.	Orissa	560
16.	Punjab .	253
17.	Rajasthan	820
18.	Tamil Nadu .	485
19.	Tripura .	48
20.	Uttar Pradesh	1,073
21.	West Bengal .	946
22.	Sikkim .	1
		9,677

1	2	3
	Union Territoies	
1.	Arunachal Pradesh	4
2.	Goa, Daman and Diu	74
3.	Mizoram	13
4.	Pondicherry . .	15
	Total	106
	Total States & Union territories . . .	9,783

Note: Accounts for 1976-77 and 1977-78 have not yet been finalised.

Direct recruitment to the cadre of Auditors in Indian Audit and Accounts Department

9267. DR.V. A. SEYID MUHAMMED: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether in the direct recruitment to the cadre of Auditors in some of the field offices of the Indian Audit and Accounts Departments, graduation is not followed as the minimum qualifications whereas it is so for candidates to All India Service Examinations conducted by UPSC;

(b) whether in some offices even the advertised qualifications such as graduation with first or second class or post graduation with first or second class are ignored and those having the highest marks among them are chosen for the written test and others are left out; and

(c) whether the list of candidaets selected for interview as well as for appointment after interview in the recruitment to the cadre of Group D; Clerk/typist and Auditors in the Department are not published by the authoritics whereas such lists are published by the UPSC at every stage in the recruitment to the All India Services?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b): The minimum qualification prescribed for appointment as Auditor is 'University Degree', and it is accordingly indicated in the advertisement.

Sometimes the number of applications received in response to an advertisement is too large and so to bring down the number of applicants to manageable proportions, screening is done by the Central Recruiting Agencies in the Indian Audit and Accounts Department. Such screening is done by grouping the applications in the descending percentage of marks, and calling for written test, applicatants of the higher groups to the extent of 7 times the number of the anticipated vacancies in the case of general category persons and 10 to12 times for Schedule Caste/Schedule Tribe candidates.

A model advertisement form has, however, been prescribed for use by all the Central Recruiting Agencies in the Indian Audit and Accounts Department in order to ensure uniformity in the matter of recruitment.

(c) The position of the panels prepared by the Union Public Service Commission for recruitment to All India Services and the panels prepared by the Central Recruitment Agencies in the Indian Audit and Accounts Department is not similar. The normal life of the panel prepared by the Central Recruiting Agencies in the Indian Audit and Accounts Department is one year and the size of the panel is normally double the likely number of vacancies as anticipated for the panel year, thus keeping a safe margin for dropouts during the currency of the panel for one year. Depending on the vacancies that may actually arise, all the persons empanelled may not be appointed during the currency of the panel, and, therefore, the position of a person in the panel is not intimated to the individuals. Only persons who are expected to be appointed in the next two months are informed of the fact, so that they can keep ready for joining when the offers of appointment are given to them.

Allocations by Centre for construction of Janata Hotels

9268. SHRI D. G. GAWAI: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the total allocation approved by the Centre for the construction of Janata hotels in the country;

(b) the number of Janata hotels to be constructed during 1978-79 and the locations thereof;

(c) whether the construction work on each of such Janata hotel has started;

(d) when the construction is likely to be completed;

(e) the particulars of facilities to be provided there for tourists; and

(f) whether Government propose to ask the private parties who are engaged in construction five star hotels to switch over to construction of Janata hotels?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) (a) The Five Year Plan 1978-83 envisages the construction of Janata Hotels at Metropolitan Cities of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras and smaller units at other places, which would be identified after a survey is undertaken. Allocation for these different schemes would be made available after detailed schemes in respect of each location are finalised.

(b) The Government has approved the construction of a 1250-bed Janata hotel (Ashoka Yatri Niwas) in New Delhi at an estimated cost of Rs. 300 lakhs for which an allocation of Rs. 50 lakhs has been agreed to during 1978-79.

(c) and (d). The foundation stone of the Janata hotel in New Delhi was laid on 4th May, 1978 and the hotel is expected to be commissioned in phases during 1980-81.

(e) The Janata hotel (Ashoka Yatri Niwas) in New Delhi will consist of 505 double bedded rooms and 60 four bedded family rooms with attached toilets to be rented at low tariff. In addition, there will be a restavant-cum-coffee shop, a speciality restaurant, a shopping arcade, tourist information offices and a recreation room.

(f) The Government will give every encouragement to private parties to put up Janata hotels.

Money spent by Nationalised Banks on Litigation

9269. SHRI DALPAT SINGH PARASTE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the money each nationalised bank spent on litigation against its staff during the last three years;

(b) the particular reasons of increasing expenses on court cases by Banks on their staff; and

(c) the reaction of Government to this situation and particularly to the one mentioned in the weekly Blitz dated the 11th March, 1978, under the heading "Bank squanders public money on litigation against staff"?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). Information to the extent possible is being collected and will be laid on the Table of the House.

Additional Central Aid demanded by States

9270. SHRI HITENDRA DESAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) have the States demanded additional Central aid during 1977-78;

(b) if so, how much assistance is demanded by each of these States and Union Territories; and

(c) how much amount has been paid to each one of them ?

THE MINISTER OF FINANCE. (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). The State Governments and Union Territories made during 1977-78 several requests for additional Central assistance for various purposes such as for meeting gaps in resources, for meeting expendture necessitated by natural calamities, for acceleration of the irrigation projects etc. to the Ministry of Finance, the Planning Commission and other administrative Ministries concerned. The details of such requests and the amounts released against them are being collected and will be laid on the table of the House.

Payment of Life Insurance Premiums after laps of Five years

9271. SHRI SUBHASH AHUJA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the number of persons who, after a continuous lapse of five years, paid life insurance premiums between 1974 and 1978 consequent on the modifications in the conditions for life insurance?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): The change in policy conditions, which the Life Insurance Corporation had introduced some time ago, related to grant of paid-up values and not to revival of lapsed policies. The earlier condition that paid-up values under life insurance policies would be granted after 3 years' premiums had been paid was modified, in respect of policies issued on or after 1-1-1976, to provide that a paid-up policy would be secured if premiums under a policy have been paid for a period of 5 years or one-fourth of the original premium-paying period of the policy, whichever is less, subject to the condition that premiums have been paid for a minimum period of 3 years. As regards revival of lapsed policies, the condition continues to be that a lapsed policy may (on compliance with the necessary requirements) be revised during the life-time of the life assured, but within a period of 5 years from the date of the first unpaid premium and before the date of the maturity of the policy. Revival of policies which have remained lapsed

for more than 5 years is considered only in exceptional cases.

2. The modified condition for grant of paid-up values applies only to policies issued on or after 1-1-1976, all of which are less than 5 years old, and, therefore, the question of any premiums being paid consequent on the modification, under policies which have stood lapsed for 5 years, does not arise.

Study regarding International Debt Repayments

9272. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have since made any in-depth study of the various problems in respect of international debt repayments of the country;

(b) if so, the result of the study; and

(c) action taken thereon?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) While the Government has not made any formal in-depth study of the various problems in respect of international debt repayments of the country, the matter is kept under constant review:

(b) and (c), Does not arise.

Rise in the prices of edible oils

9273. SHRI PRASANNBHAI MEHTA Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prices of edible oil again rose during the month of April, 1978;

(b) if so, whether the prices of the same had been reduced during the months of February and March, 1978;

(c) if so, what was the main reason for increase of prices during April , 1978;

(d) whether any action has been taken against those held responsible for this increase; and

(e) the steps being taken to check them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) No. Sir. During the first four weeks of April, 1978 the wholesale price index for edible oils has been lower by 1·2% as compared to the corresponding period in March, 1978.

(b) There was also fall in the wholesale price index for edible oils as a whole in the months of February, 1978 and March, 1978 to the extent of 2·9% and 0·3% respectively as compared to the preceding months.

(c) to (e). Does not arise in view of answer to (a) above.

उत्पादन में वृद्धि के कारण पोलियस्टर फिलामेंट के मूल्य में वृद्धि

9274. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बजट में घोषित "उत्पादशुल्क" के फलस्वरूप उत्पादकों का विचार पोलियस्टर फिलामेंट के मूल्य को 3 रुपये प्रति किलोग्राम से चढ़ाकर 4 रुपये प्रति किलोग्राम करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयोजन से कोई कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) मूल उत्पादन-शुल्क के 1/20वें भाग की दर के हिसाब से विशेष उत्पादन-शुल्क के लगाये जाने के परिणामतः, पोलियस्टर फिलामेंट सूत पर बजट से पूर्ववर्ती उत्पादन-शुल्क की दर में 2.45रु० से 3.85 रु० तक प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो जायेगी । यह ज्ञात नहीं है कि क्या पोलियस्टर फिलामेंट सूत के उत्पादक उत्पादन शुल्क की यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं को पूरी की पूरी अन्तरित करने का प्रस्ताव रखते हैं अथवा आंशिक रूप से ।

(ख) भाग (क). के उत्तर में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने के बारे में इस समय सोच-विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

चेकोस्लोवाकिया को अफीम के डोडे के चूरे का निर्यात

9275. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अफीम के डोडे का चूरा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) क्या चेकोस्लोवाकिया और कुछ अन्य देशों को इसका निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या उसका निर्यात बढ़ाया भी जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) फसल वर्ष 1977–78 में पोस्त की काश्त लगभग 6 5,000हेक्टेयर रकबे में की गई थी और पोस्त की भूसी का अनुमानित उत्पादन 39,000 मी० टन होने की संभावना है ।

(ख) जी हां । वर्ष 1977 में, निर्यात की गयी पोस्त की भूसी की कुल मात्रा 3,886 टन थी, जिसमें से 1,444 टन भूसी का निर्यात चेकोस्लोवाकिया को किया गया था ।

(ग) और (घ). भारतीय पोस्त की भूसी को तुर्किस्तानी पोस्त की भूसी से कड़ा मूकाबला करना पड़ रहा है, जिसमें केवल मारफीन की मात्रा ही अधिक नहीं है बल्कि इसलिये भी कि तुर्किस्तान आयातकर्ता देशों के, जो युरोप में हैं, नजदीक होने के कारण तुर्किस्तानी भूसी की कीमत में अपेक्षाकृत कम भाड़ा लगता है । परन्तु, पोस्त की भूसी से विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने की दृष्टि से निर्यात के प्रयोजनार्थ, पोस्त की भूसी से मारफीन, कौडीन और अन्य एलकालायड निकालने के लिये 12,000 टन पोस्त की भूसी की प्रक्रिया करने की क्षमता वाला एक संयंत्र लगाने का निर्णय किया है ।

I.A. to buy Two more Airbuses

9276.SHRI MANORANJAN BHAKTA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be please to state :

(a) whether Indian Airlines proposes to buy two more Airbuses if so, whether any agreements has since been signed for the purpose; and

(b) if so, details and which are the routes where these airbuses will be utilised?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK): (a) Yes, Sir. Indian Airlines have signed an agreement with M/s. Airbus Industries France, in April, 1978 for the purchase of two additional A300B 2 Airbus aircraft.

(b) These aircrafts are proposed to be utilised for increased frequencies on the Delhi/Bombay sector and introduction of Airbus operations on the Bombay/Trivandrum sector. Stepping up of frequencies to the Gulf to a daily flight and operations on the Delhi/Hyderabad/Bangalore and Bombay/Goa routes from November, 1978 are also under consideration of the Indian Airlines.

Decline in Revenue from Tourism

9277. SHRI C. K. JAFFER SHARIEF : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that revenue from tourism has declined considerably;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir. The foreign exchange receipts from tourism has been estimated at Rs.283 crores in 1977 as against Rs. 225 crores in 1976.

(b) and (c). Do not arise.

S. T. C.

9278. CHAUDHURY BALBIR SINGH: Will the Minister of COMMERCE CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are getting the working of the STC examined by outside agency ;

(b) whether STC is reorganizing its offices by constituting branch office for the Northern area ;

(c) whether STC's headquarter's office is overstaffed; how many Managers were recruited during the Emergency whether there was any justification for recruitment at that time;

(d) whether it is a fact that STC Management is trying to post Managers outside Delhi and what will be the criteria for posting outside Delhi ; and

(e) how many New Branch Offices, S.T.C. Management propose to open ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) Yes, Sir. The Indian Institute of Management, Ahmedabad, was asked to make a review of the working of the S.T.C., M.M.T.C. and their subsidiaries;

(b) Yes, Sir. It has already established a Branch Office in Delhi to serve the northern region.

(c) No, Sir. The number of Managers recruited during 1-6-1975 to 31-3-77 is 89.

Recruitment was necessary to cope with the increase in the volume of work in the Head quarters due to growing export/ import activities of the Corporation.

(d) Posts in the Managerial cadres are transferable. Transfers are made after careful consideration by Management in the interest of the Corporation. Deployment of Managers at Head-quarters and Branch Offices is made depending upon the changing nature of operation and the work load in the Branch Offices from time to time.

(e) The Corporation has been continuously studying export potential in different regions. As and when the potential in a particular region is well established, it opens branch office in that region.

Failure to Reduce issue price of Rapeseed Oil and its supply to States

9279. SHRI GADADHAR SAHA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) reduction in issue price of the rapeseed oil and its supply for States in our country;

(b) whether it is a fact that the issue price of crude rapeseed oil which is used after refining by the proper section of people is not reduced while the issue price of other imported oils used by Vanaspati manufacturers are reduced;

(c) whether it is a fact that these imported oils used as component of Vanaspati are used by more affluent section of the people; and

(d) the reasons of failure of Indian rapeseed oil?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) to (d). The issue price of raw rapeseed oil supplied to the State Governments was initially fixed at Rs. 6300/- per tonne. The State Governments were to refine the oil and to distribute it to the consumers at an end-retail price not exceeding Rs. 8·50 per kg. Subsequently, w.e.f. 25-8-77, the issue price of the raw oil was reduced to Rs. 5300/- per tonne to unable the State Governments to distribute the refined oil at a price not exceeding Rs. 7·50 per kg. After a further review, the issue price has been further reduced to Rs. 4800/- per tonne w.e. from 1st May, 1978 with a view to distributing the oil at an end retail price of Rs. 7/- per kg. The issue price of soyabean oil and rapeseed oil, being issued to the vanaspati manufacturer is currently Rs. 5,950/- per tonne, which is higher than the issue price of the crude rapeseed oil supplied to the State Governments.

एयर इंडिया द्वारा "लोकहीड" विमान की खरीद

9280. **श्री राम सेवक हजारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के लिए "लौकहीड" विमान खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Reorganisation of Central Excise Divisions

9281. SHRI RAJARAM SHANKAR RAO MANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a proposal to reorganise Central Excise Divisions and include Nasik, Jalgaon, Dhulia and Aurangabad in the Nagpur Division; and

(b) if so, what are the reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) and (b), Government have no intention at present of including Nasik, Jalgaon, Dhulia and Aurangabad districts of Maharashtra in the Nagpur Central Excise Collectorate.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के जांच के लिये आयोग की नियुक्ति करना

9282. **श्री उग्रसेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये थे और क्या उनके कार्यकरण एवं प्रबन्ध की जांच के लिए तथा उक्त बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई थी और आयोग की सिफारिशों की प्रति सभा पटल पर कब रखी जायेगी; और

(ख) क्या सरकार इन बैंकों के शाखा मैनेजरों को समान कार्य के लिये समान वेतन संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुरूप वेतन-मान, महंगाई भत्ता तथा अन्य सुविधाएं देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) देश में विद्यमान 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रो० एम०एल० दांतवाला की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी ।

समिति की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त हो चुकी है तथा इस पर तत्परता पूर्वक विचार किया जा रहा है ।

(ख). वेतनमानों में संशोधन तथा स्टाफ को दिए जाने वाले अन्य भत्तों के प्रश्न पर सरकार इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर जिनकी अभी प्रतीक्षा है, विचार करेगी ।

भारतीय हथकरघा के सिले सिलाये वस्त्रों की मांग

9283. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय हथकरघा के सिले सिलाये वस्त्रों की मांग बढ़ी है;

(ख) क्या अनेक देशों के साथ करार हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1976–77 और 1977–78 में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख). हथकरघा परिधानों की मांग, जिसे 1977 में सं० रा० अमरीका में मंदी के बाजार हालात तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में एक पक्षीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था, जनवरी 1978 से पुनः होने लगी है । पता चला है कि निर्यात व्यापारियों द्वारा सं० रा० अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, स्कैंडेनेविया, आस्ट्रेलिया, जापान आदि के अपने प्रतिपक्षियों के साथ संविदाएं की गई हैं ।

(ग) 1976–77 तथा 1977–78 (अप्रैल, 77–जनवरी 78) में हथकरघा परिधानों के निर्यात से उपार्जित विदेशी मुद्रा क्रमशः 155.15 करोड़ रुपये तथा 71.34 करोड़ रुपये रही । हथकरघा परिधानों के निर्यात के आधार पर नकद मुआवजा सहायता तथा आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों, विदेशों में विशेषीकृत वस्त्र में भाग लेने, नए बाजारो का पता लगाने तथा विद्यमान बाजारों में नई मदों का प्रचलन करने के लिए बिक्री-सह अध्ययन दल भेजना, गहन प्रचार अभियान के अलावा केन्द्रीय योजना के अधीन महत्वपूर्ण हथकरघा केन्द्रों में निर्यात उत्पादन परियोजनाओ की स्थापना परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना कतिपय ऐसे प्रयास हैं जो हथकरघा परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए हैं ।

आयातित सीमेंट पर कर से छूट

9284. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयातित सीमेन्ट पर कर से छूट देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह छूट किस आधार पर दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां । आयातित सीमेंट को मूल, उपसंगी और प्रतिसंतुलनकारी सीमाशुल्क से छूट दी गयी है ।

(ख) देशी सीमेंट की कमी के कारण सीमेंट के आयात की जरूरत पड़ी है । लेकिन, आयातित सीमेंट की लागत, बीमा, भाड़ा सहित मूल्य देशी सीमेंट के शुल्क सहित मूल्य से अधिक है । आयातित सीमेंट को समस्त मूल, उपसंगऔर अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट इस कारण दी गयी थी कि देशी बाजार में यह बहुत महंगा न हो जाये ।

हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन मिर्जापुर में उत्पादशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया एल्यूमीनियम का स्टाक

9285. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने, वर्ष 1975 में, हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन, रेणुकूट, मिर्जापुर से एल्यूमीनियम के स्टाक पकड़े थे; और

(ख) यदि हां, तो नये कानूनी उपबंधों के अधीन उक्त कारपोरेशन के प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). जी, हां केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों ने 1975 में एल्युमीनियम-भण्डार के दो मामले पकड़े थे । एक मामले में, पार्टी ने अभिग्रहण के खिलाफ दिल्ली-स्थित उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय ने माल पकड़ने की कार्यवाही को तथा कारण बताओ नोटिस को मंसूख

कर दिया था। दूसरे मामले में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के नियम 52 (क) के उल्लंघन के लिए विभागीय न्याय-निर्णय किया गया था।

Grant of Contracts/Licences in respect of the Ministry

9286. SHRI R. N. RAKESH : Will the MINISTER OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to stat : the total number of contracts/licences granted in respect of Commerce Civil Supplies and Cooperation Ministry, its attaced and subordinate offices including the public sector undertaking for the entire period of Janata Government regime and the share there, if any, to S.C. and S.T. in each category of such contracts/licences and if not, why?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Inclusion and Development of any other Airport into International Airport

9287. SHRI AHMED M. PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number and details of International Airport operating in India;

(b) whether there is any proposal to include and develop any other airport into International airport; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) There are four international airports in India at present. These are at Delhi, Bomaby, Calcutta and Madras.

(b) No, Sir. Not at present.

(c) Does not arise.

Complaints Regarding Irregularities Committed in Delhi Stock Exchange

9288. SHRI BALDEV SINGH JASROTIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any complaints were received by Ministry about serious malpractices and gross irregularities being committed in Delhi Stock Exchange and also about rank speculation being indulged in certain shares;

(b) if so, whether any inquiry was held on such complaints; and

(c) what were the findings and what action and steps were taken thereon and to prevent recurrence of such irregularities and malpradtices?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c) No specific cases of serious malparctices, gross irregularities or rank speculation carried on in the Delhi Stock Exchange have been brought to the notice of the Government. There has, however, been a complaint alleging that the affairs of the Delhi Stock Exchange are being run by the Executive Director in contravention of the bye-laws, rules and regulations of the Stock Exchange. This has been looked into and has not been found to be substantiated.

Value of Special Bank Notes

9289. SHRI B. C. KAMBLE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) total value of special Bank notes issued since coming into force of Constitution of India, till today;

(b) the purposes for which such Spcial Bank notes were required to be issued;

(c) total value of Special one rupee notes issued by Government since coming into force of Constitution of India, till to-day; and

(d) purposes for which special one rupee notes were required to be issued?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) About Rs. 53·59 crores.

(b) Out of the above figures, about Rs. 53·53 crores were issued as Special Gulf Notes for use in the Gulf States and Rs. 5·58 lakhs as Special Haj Notes for use for Haj Pilgrims.

(c) Rs. 39·45 lakhs.

(d) These were issued as Speical Gulf notes for use in the Gulf States.

Meetings of the Committee on Roll of Controls

9290. SHRI DHARAMA VIR VASISHT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

Whether any meetings of the panel, set up by the Government recently to study the role of controls and subsidies in relation to prices, production, distribution, licenses and imports have since been held?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : Yes, Sir. The panel has so far held two meetings on the 5th March and 14th April, 1978.

Grant of Import Licences for Polyester Fibres

9291. SHRI YADVENDRA DUTT : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether import licences for Polyester Fibers have been granted to a couple of textile magnates of Western India;

(b) if so, their names and amounts for which licences were granted;

(c) is it a fact that these licencees have sold their licences at the premium three hundred per cent over the actual price of the licences of Rs. 4 crores; and

(d) if so, what action is proposed to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) and (b) Polyester fibre was put on the Free Licensing Scheme for import by Actual Users engaged in textile industry, on 22nd November, 1976. The same policy continued in 1977-78. Particulars of import licences are published in the Weekly Bulletin of Import Licences, Export Licences and Industrial licences issued by the Chief Controller of Imports & Exports. Copies of the Bulletin are available in the Parliament Library. During 1978-79, import of this item is allowed under Open General Licence to Actual Users (Industrial).

(c) No such instance has come to the notice of Government.

(d) Does not arise.

Consumer Cooperative Stores

9292. SHRI DURGA CHAND : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Delhi Administration has instituted a probe in the working of the consumer cooperative stores;

(b) whether the probe is also being instituted into the Central Government Consumer Stores;

(c) if so, what are the details thereof?

(d) what is the result thereof;

(e) what action has been taken against the defaulting stores; and

(f) what is the number of such stores working in the capital?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) Yes, Sir.

(b) No probe under Section 55 of the Delhi Cooperative Societies Act 1972 is instituted into the Central Government Consumers Cooperative Stores.

(c) to (e). The Delhi Administration had received complaints in the past against certain consumer cooperative stores for not properly utilising the dry fruit licences issued by the Joint Chief Controller of Import and Exports. In this regard, the Administration had issued orders of enquiry under the Delhi Cooperative Societies Act, 1972 against 19 defaulting stores. Enquiry had also been ordered in 4 cases where serious complaints had been received against managing committee of the stores or the working of the stores. On receipt of the complaints for not utilising the dry friut licences, the Administration has decided not to issue existence certificate which is one of the conditions for issuing dry furit licence. The reports of enquiry in respect of 5 stores have been completed and show cause notice in one case has been issued under Section 63 of the Delhi Cooperative Societies Act.

(f) Number of such defaulting stores working in the capital is 23.

Popularisation of Units of Unit Trust of India

9293. SHRI D.D. DESAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether units of the Unit Trust of India are becoming popular in semi-urbn and rural areas;

(b) if so, what percentage of investment in units comes from these areas; and

(c) whether there are any schemes for further popularising units?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c). With a view to making the units popular in semi-urban and rural areas, the Unit Trust of India has initiated a scheme in July 1977 for the appointment of Chief Representatives in selected districts of the country. For each district, a target is fixed for the sale of units varying from Rs. 12 lakhs to Rs. 70 lakhs per annum. Systematic and intensive publicity and sales promotion programmes are chalked out and implemented in these districts to educate the people about the units and its benefits. To begin with, the Chief Representatives were appointed in 15 districts of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Gujarat and in Chandigarh. During January to March 1978 the scheme has been extended and Chief Representatives have been appointed in one more district of Gujarat, two districts in Bihar and one district each in West Bengal and Kerala.

2. It is difficult to make a precise estimate of the business coming from all the semi-urban and rural areas. It may, however, be stated that the business received in the first 9 months of the current accounting year of the Trust (July 1977 to June 1978) from the selected districts, where the Chief Representatives are functioning, aggregated to about Rs. 3 crores as against the target of Rs. 3·67 crores fixed for these districts for the first year.

Realisation of Custom and Central Excise dues from M/s Kores India

9294. SHRI RAMESHWAR PATIDAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount realised as Custom and Central Excise due from M/s Kores India during the last three years;

(b) the amount actually due from them for the above period;

(c) steps contemplated to realise the full dues; and

(d) the action taken for default in payment of Government dues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) As far as Customs dues are concerned, statistics are maintained commodity-wise and not importer/Exporter-wise. Hence the required information in so far as Customs dues are concerned is not readily available. The position regarding Central Excise duty is given below :—

The total amount of Central Excise duty realised from M/s Kores India during the last three years is reported to be as under :—

1975-76	. .	Rs. 11,89, 105·37
1976-77	. .	Rs. 14,81,312·10
1977-78 (upto February 1978)	. .	Rs. 12,15,841·17

(b) The amounts are the same as above in so far as Central Excise duty is concerned. Two Central Excise cases are pending adjudication in respect of this company in which the duty involved amounts to Rs. 25,000/- approximately. It is only when the cases have been adjudicated that it can be said whether these amounts are due from the company.

(c) and (d). Does not arise, so far as Central Excise duty is concerned.

Closure of cashew factories

9295. SHRI VAYALAR RAVI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cashew factories are closed down due to the lack of imported nuts supplied by Cashew Corporation of India;

(b) if so, what are the steps taken by the Government to provide imported nuts to these factories; and

(c) the steps taken by the Government to discourage the opening of new factories while there is already a scarcity for the raw raw material—the imported nuts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) :

(a) and (b) : The imports of raw cashewnuts have been declining over the past few years due to reduced exportable surplus available with the East African countries, who are India's major suppliers of raw cashewnuts. Consequently, the allotment of imported raw cashewnuts per unit by the Cashew Corporation of India has gone down.

The distribution of imported raw cashewnuts is made according to the distribution policy as laid down in the Import Trade Control Policy in force. All eligible factories are allotted imported raw cashewnuts; the actual quantum of allotment may, however, vary depending upon the availability of raw cahewnuts.

(c) As per the distribution policy, only those factories are eligible for allotment of raw cashewnuts who had participated in the import and export trade of cashewnuts and operated cashew processing factories in any of the scalendar years 1968, 1969 and upto 31-8-1970. There fore, any factory established after 31-8-1970 will not be eligible for allotment of imported raw cashewnuts.

Training Imparted to Apprentices in Public Undertakings

9296. SHRI G.M. BANATWALLA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether certain Public Undertakings take apprentices and impart a training to them for one year or so for the purpose of filling up their future vacancies;

(b) whether the apprentices are given and they do the same quantum of work in the various Branches as the other regular employees do under the pretext of imparting training to them;

(c) the percentage of the apprentices turned out after completion of the training period and the reasons therefor; and

(d) the names of the Public Undertakings which practise and follow the above mentioned procedure?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H.M. PATEL) : (a) Apprentices are taken as per the Apprentices Act 1961 and rules thereunder. Apprentices are taken to impart training and not for filling up future vacancies.

(b) The training of apprentices is as per the syllabus prescribed under the Apprentices Rules. The same work as for the regular employees is not obtained for obtainable from the apprentices. They, however, contribute to some extent when they are 'on the job training'.

(c) The number of the apprentices to be recruited depends upon the number given by the Apprenticeship Adviser based on the survey of plants according to the proportion laid down in the Apprentices Act. Apprentices cease to be on the roll after completion of the training. They may be given employment depending on the vacancies available.

(d) All industrial and commercial undertakings are required to follow the above procedure.

Import of Phthalic anhydride

9297. SHRI K. RAMAMURTHY : Will the Minister of COMMERCE, AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether there has been huge stockpile of phthalic anhydride with producers;

(b) whether Government have proposed to import the same commodity affecting even the limited market within the country for phthalic anyhdride; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) Government are not aware.

(b) and (c). Phthalic Anhydride appears in the absolute banned List in Appendix 4 to Import Policy, 1978-79 and will be requlated accordingly.

जयपुर से दिल्ली के लिये प्रातःकालीन विमान सेवा

9298. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-दिल्ली प्रातःकालीन विमान सेवा बन्द कर दी गई है जिससे जयपुर के लोगों को भारी कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सेवा को पुनः चालू करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). 20 दिसम्बर, 1977 से लागू इंडियन एयरलाइन्स की समयावलि में सेवा सं० आई० सी०-492 (बम्बई-औरंगाबाद-उदयपुर-जयपुर-दिल्ली) के समय में बम्बई-त्रिवेन्द्रम सैक्टर पर और अधिक क्षमता की आवश्यकता की पूर्ति करने की दृष्टि से परिवर्तन किया गया । इस समय परिवर्तन से यात्रियों में कुछ असंतोष पैदा हो गया है, परन्तु विमानों की कमी के कारण निकट भविष्य में इस उड़ान के समय में पुनः परिवर्तन करना व्यवहार्य नहीं होगा । परन्तु, विमानों की स्थिति में सुधार होते ही इस पर विचार किया जाएगा ।

Earning of Foreign Exchange and Export Duty on Export of Tea

9299. SHRI PURNANARAYAN SINHA : Will the Minister of COMMERCE, AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) the total amount of Export Duty and Foreign Exchange earned yearwise by the Union Government from 1st April, 1971 till the last accounting year in respect of tea exported from this country;

(b) the share of Export Duty and Foreign Exchange earnings together with Excise Duty and Surcharges allotted to Assam, West Bengal, Tripura, Uttar Pradesh, Punjab, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu during the above period ; and

(c) what total amount has been expended on the Tea Board by the Union Government during the above period for its establishment and advancement of Tea Culture, Research and Production,

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) :

(a) The export earnings from tea since 1971-72 are as under:—

Years	*Rs. crores*
1971-72	160·92
1972-73	147·29
1973-74	144·85
1974-75	223·54
1975-76	238·29
1976-77	295·26
1977-78	550·00 (Provisional)

There was no export duty on tea during 1971-72 to 1976-77. Export duty at the rate of Rs. 5/- per kg. was imposed on tea w.e.f. 9th April, 1977. The amont of export duty on tea earned during 1977-78 is being collected and statement will be laid on the Table of the House.

(b) Information regarding export duty, excise duty and surcharge is being collected and will be laid on the Table of the House.

Foreign exchange earnings are not a part of the Revenue receipts of the Govt. of India and hence the question of sharing the same with the State Government does not arise.

(c) The amounts released to Tea Board by Government for Revenue Expenditure are given below:

	(Rs. crores)
1971-72	1·45
1972-73	1·76
1973-74	1·95
1974-75	2·33
1975-76	2·85
1976-77	2·66
1977-78	3·13

Number of posts remaining vacant in Madras circle of State Bank of India

9300. SHRI K. T. KOSALRAM : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) It is a fact that a large number of posts under different categories (officers, assistants, clerks, messengers) sanctioned

for the years 1976 and 1977 are still remaining vacant in the Madras circle of State Bank of India ;

(b) the reason for keeping such large number of posts unfilled;

(c) whether any general recruitment tests and departmental promotion tests have been held to fill up the posts;

(d) if so, what is the outcome ; and

(e) the steps proposed to be taken to fill up the posts without further delay?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (e). No, Sir. While all the posts in all categories sanctioned for the year 1976 have been filled up, only 8 posts of officers sanctioned for the year 1977 remain unfilled. To fill up the 8 posts of officers referred to above, a promotion test was scheduled to be held in March, 1978 but was postponed pending formulation of Bank's policy for making reservations for scheduled castes and scheduled tribes candidates in the matter of promotions. The Bank has reported that its policy in this regard is now evolved and it expects to conduct the promotion test shortly.

Central Excise on cigars

9301. SHRI NATVERLAL B. PARMAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) is it true that Central Excise on cigars have been removed twice;

(b) the reasons for removing the excise; and

(c) the reasons for re-imposing the excise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) Yes, Sir.

(b) Duties on cigars and cheroots were removed in the 1965 Budget on the ground that only insignificant revenues were accruing from the levy. The duty was re-imposed in 1966 but was again withdrawn on 26-7-71 as it was then reported that the industry was languishing.

(c) Hand-made branded biris are paying duty at the rate of Rs. 2·10 per 1000. Cigarettes are also subjected to relatively higher rates of duty. In this context it was considered that branded cigars and cheroots should also bear some duty. Till 28-2-1978, cigars and cheroots attracted duty only if their value was Rs. 50 or above per 100. This was modified into a slab structure with graduated rates of duty, introduced as part of the 1978 Budget proposals.

Resumption of export of onion

9302. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government have decided to resume export of onion; and

(b) if so, the details and reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) Yes, Sir

(b) As in the past, NAFED continues to be the canalising agency for export of onions. NAFED will keep a strict control on the exports in terms of quantity, quality and unit value realisation.

Export of onions has been resumed keeping in view the good onion crop; decline in prices in the producing areas; present reasonable price level of onions for consumers; short storage life of onions and the demand from the friendly countries who have been traditional importers of onions from India. Proper safeguards have been taken to watch the interests of consumers and the growers.

Seizure of Hashish in New Delhi

9303. SHRI P. K. KODIYAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Directorate of Revenue Intelligence has seized hashish worth about Rs. 1·5 crores in New Delhi ;

(b) whether some persons including some passengers have been arrested in connection with this smuggling ;

(c) what are the details thereof ;

(d) the names of the passengers and country they belong to ; and

(e) further action taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) to (c). On 20-4-78 the officers of the

Directorate of Revenue Intelligence, seized 32 Forklift trolley tyres, at Palam airport. On examination, about 2·5 kgs. of hashish was found concealed in each of these tyres. In addition, 157 similar tyres were seized on 22-4-78 from two different godowns at Delhi. On opening of all the 189 tyres, about 480·350 kgs. of hashish of estimated value of about Rs. 1·5 crores in U.S.A., was recovered and seized. Two persons, one Indian and another Israeli, were arrested in this connection.

(d) No passenger has been arrested in this regard.

(e) Appropriate action under the law is being taken. The two persons involved in the offence have been detained under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974.

Report of Bhoothalingam Study Group on Wages, Incomes and Prices

9304. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI :
SHRI AMARSINH V. RATHAWA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the study group headed by Shri Bhoothalingam has submitted its report ;

(b) if so, the details thereof and action taken thereon ; and

(c) if not, by what time the report is expected ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) By about middle of May, 1978.

Amalgamation of Insurance Companies into G.I.C.

9305. DR. BALDEV PRAKASH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any categorisation was done after the amalgamation of Insurance Companies into G.I.C. and its subsidiaries ;

(b) if so, the guidelines and conditions in details on which the categorisation was made of lower management ; and

(c) the number and name of officers working in different companies who were decategorised to non-officers posts and vice-versa ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) Lower Management Service Committee was appointed by the Board of the General Insurance Corporation of India for each of its subsidiaries to categorise and recommend names of persons who were considered suitable to hold posts at lower management level viz. Assistant Managers, Administrative Officer and Assistant Administrative Officers. The Committee, for the purpose of categorisation and their placement on lower management level, took into account various factors such as position held, nature of duties, suitability for the post in view, qualification, salary and the size of operations of the erstwhile insurer.

(c) Presumably, the Hon'ble Member has in mind the cases of those employees who claimed to be officers but who were not categorised as such by the said Committee. As there were a number of representations by aggrieved employees against their initial categorisation, Appeal Committees were constituted in each subsidiary of G.I.C. to consider suh cases. The appeal Committee have decided most of these cases taking all relevant facts into consideration.

The information relating to the number of the appellants who have now been categorised as officers as well as the number of employees whose appeals have been rejected is being collected.

Oil Seeds Production

9306. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) total production and import of edible oil seeds, yearwise during the last three years ;

(b) whether there is scarcity of edible oil in the country ; and

(c) if so, factors responsible for the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) A statement is annexed.

(b) and (c). There has been a persistent gap between demand and production of edible oils. As an immediate measure, the shortfall of edible oil is being met by imports, both through STC and through private trade. In addition, efforts are also being made to

augment indigenous edible oil production.

Statement

Year	Production of Oilseeds ('000 tonnes)
1974-75	10,538
1975-76	11,585
1976-77	9,523

Year	Imports of Oilseeds (in tonnes)
1974-75	19,039
1975-76	18,105
1976-77	8,212

देश में युवक केन्द्र

9307. **श्री लालजी भाई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने युवक केन्द्र (यूथ होस्टल) हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) उनके रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और युवक केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) युवा होस्टलों के वार्षिक रख-रखाव पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता क्योंकि इनको पूरा हो जाने पर इन्हें प्रबंध-व्यवस्था के लिए एक बार राज्य सरकार को सौंप देने के पश्चात् यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की हो जाती है । तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग युवा होस्टल के वार्डन एवं असिसटैंट वार्डन के वेतन संबंधी व्यय का वहन करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को वार्षिक 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता देता है।

(ग) केन्द्रीय सेक्टर में और युवा होस्टल बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

युवा होस्टल

युवा होस्टल का नाम	चालू होने की तारीख	शय्या क्षमता	टैरिफ दरें
1. अमृतसर	20-7-1975	46	
2. औरंगाबाद	10-1-1976	46	
3. भोपाल	20-6-1975	46	

युवा होस्टल का नाम	चालू होने की तारीख	शय्या क्षमता	टैरिफ दरें
4. डलहौजी	20-5-1975	44	मैदानी क्षेत्रों में प्रति
5. दार्जीलिंग	2-11-1975	44	रात्रि प्रति शय्या 5
6. गांधीनगर	21-5-1976	46	रुपए तथा पहाड़ी
7. हैदराबाद	8-5-1976	46	क्षेत्र में प्रति रात्रि
8. जयपुर	9-1973	46	प्रति शय्या 6
9. मद्रास	1-7-1975	46	रुपए ।
10. नैनीताल	23-5-1976	44	
11. पणजी	27-9-1976	46	
12. पंचकुला	15-3-1975	46	
13. पटनीटॉप	1-4-1976	44	
14. पुरी	14-11-1975	46	
15. त्रिवेन्द्रम	शीघ्र ही चालू हो जाएगा ।	46	
16. पाण्डीचेरी	निर्माण किया जा रहा है ।	46	
17. मैसूर	निर्माण किया जा रहा है ।	46	

Fall in Quality of I. S. I. marked Goods and Shaving Blades

9308. SHRI M. ARUNACHALAM : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the quality of ISI marked goods in general and the Shaving Blades in particular are falling below the stand ard ;

(b) whether the Ministry have any plan to take action against such erring companies ; and

(c) if so, details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Joint Ventures with Asian Countries

9309. SHRI SURYA NARAYAN SINGH : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the number of joint ventures set up in different fields with different Asian Countries; and

(b) whether the proposal to set up some more such ventures with those countries is under consideration of Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) A statement showing the number of joint ventures set up in different fields with different Asian Countries is attached.

(b) Yes, Sir.

Statement

Joint Ventures set up in different fields in different Asian Countries

Sl. No.	Name of the country	No. of joint ventures	Field of collaboration	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Malaysia	25	Light engineering	6
			Oil seeds crushing, refining and fractionation	3
			Textiles	3
			Chemicals and Pharmaceuticals	2
			Glass and glassware	2
			Non-ferrous metal products	2
			Auto ancillaries	1
			Commercial vehicles	1
			Precision tools	1
			Sugar factory	1
			Plastic products	1
			Consultancy	1
			Rubber products	1
2.	Indonesia	7	Textiles	3
			Iron and Steel Products	2
			Paper	1
			Light Engineering	1
3.	Thailand		Textiles	3
			Iron and Steel Products	1
			Hacksaw Blades	1
4.	Singapore	4	Auto ancillaries	1
			Consultancy	1
			Precision tools	1
			Enamelled wire	1
5.	U. A. E.	4	Consultancy	1
			Non-ferrous metal products	1
			Cylinders and tanks for LPG gases	1
			Chemicals	1

(1)	(2)	(3)	(4)	
6.	Philippines .	3	Light engineering	1
			Textiles	1
			Copra crushing	1
7.	Sri Lanka	3	Light engineering	1
			Glass and glassware	1
			Leather products	1
8.	Hong Kong .	2	Consultancy	1
			Stationery products	1
9.	Oman	2	Consultancy	1
			Trading and marketing	1
10.	Iran .	2	Auto ancillaries	1
			Engineering contracts	1
11.	Afghanistan .	1	Corrugated boxes	1

Enforcement of Compulsory Registration of Exporters

9310. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) why and when was the scheme for the compulsory registration of exporters enforced and what was the number of registered exporters with each designated registering authority in the first year of implementation of the scheme: at the end of the third Five Year Plan; and on 1st January, 1978; and

(b) what is the estimated number of exporters who were exporting Indian products from India at the end of the first five year plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) The scheme regarding registration of exporters came into force along with the export promotion schemes under which import entitlements were issued against exports. The erstwhile export promotion schemes were withdrawn after devaluation of the Indian Rupee in June, 1966. Thereafter the policy for Registered Exporters was introduced which also provides REP benefits to Registered Exporters only. There is no compulsory scheme as such for registration of exporters.

Information regarding the number of Registered Exporters with registering authorities in the first year of the implementation of the scheme, at the end of the Third Five Year Plan and as on 1-1-1978 is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The information is not available with the Government.

विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल

9311. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 के दौरान विदेशों में भेजे गये प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की संख्या और नाम क्या हैं तथा वे किस-किस देश में और किस-किस तारीख को गये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Merger of Dearness Allowance of Central Government Employees with Basic Salaries

9312. SHRI MOHINDER SINGH SAYIAN WALA :

SHRI MADHAVRAO SCINDIA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have under active consideration proposals to merge a part of the dearness allowance of its employees with their basic salaries;

(b) if so, when a decision is likely to be taken in the matter; and

(c) if not, the reasons for the same, keeping in view of pensioners who are being hit hard by rising prices?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c). The question of merger of a part of the dearness allowance paid to the Central Government employees with pay is under discussion with the Staff Side of the National Council of the Joint Consultative Machinery. The discussions are still in progress and are expected to be concluded by the end of June, 1978.

Indian Cotton Textiles Outpriced in World Market

9313. SHRI K. MALLANNA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian cotton textiles are being outpriced in the world market;

(b) if so, the reasons for the same; and

(c) whether Government propose to introduce a cash assistance scheme or some such measures in this context?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) to (c). With a view to rendering our exports of cotton textiles competitive in the world market, a Cash Assistance Scheme is being operated by the Indian Cotton Mills' Federation under which cash compensatory support is provided on exports of cotton textiles. Government has been contributing to the scheme towards the incidence of non-rebatable Indian taxes borne by the exported cotton textiles and to meet the differential between the international and domestic cotton prices. The scheme for 1978-79 has already been announced by the Federation.

वित्त मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन

9314. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें से राज-भाषा विभाग की सिफारिश पर नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची विवरण 'क' के रूप में सदन-पटल पर रखी गयी है । इन में से जिन सदस्यों को राजभाषा विभाग की सिफारिश पर नामजद किया गया है उनकी सूची विवरण 'ख' के रूप में सदन पटल पर रखी गयी हैं ।

विवरण 'क'

हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची है

1.	वित्त मंत्री	अध्यक्ष
2.	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क)	उपाध्यक्ष

3.	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रत्यक्ष कर)	उपाध्यक्ष
4.	श्री मोहन लाल पिपिल सदस्य, लोक सभा	सदस्य
5.	श्री यू० एस० पाटिल सदस्य, लोक सभा	सदस्य
6.	श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
7.	श्री जनार्दन रेड्डी सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
8.	श्री सुधाकर पाण्डेय, काशी नागरी प्रचरिणी सभा, वाराणसी	सदस्य
9.	डा० श्री निवास मिश्र, प्रोफसर इंस्टीट्यूट आफ इकनामिक ग्रोथ, नई दिल्ली ।	सदस्य
10.	डा० कृष्ण नाथ शर्मा, अर्थशास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी	सदस्य (इन्होंने समिति पर काम करने में अपनी असमर्थता जाहिर की है ।)
11.	प्रो० जी० सुन्डर रेड्डी विद्यानगर, विशाखापत्तनम् (आंध्र प्रदेश)	सदस्य
12.	श्री रघुवीर सहाय, सम्पादक 'दिनमान' नई दिल्ली	सदस्य
13.	श्री कमलेश, डी०/4, कालिन्दी कालोनी नई दिल्ली ।	सदस्य
14.	हिन्दी सलाहकार तथा सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
15.	वित्त सचिव	सदस्य
16.	सचिव (आर्थिक कार्य विभाग)	सदस्य
17.	सचिव (व्यय विभाग)	सदस्य

18.	गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
19.	अध्यक्ष, के० उ० शुक्ल तथा सीमाशुल्क बोर्ड	सदस्य
20.	अध्यक्ष, के० प्रत्यक्ष कर बोर्ड	सदस्य
21.	अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम	सदस्य
22.	अध्यक्ष, विविध बीमा निगम	सदस्य
23.	महानिदेशक, सरकारी उद्यम ब्यूरो	सदस्य
24.	अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग पक्ष)	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
26.	अपर सचिव (प्रशा०)	सदस्य सचिव

विवरण 'ख'

सरकारी सदस्य

(1) अपर सचिव (बैंकिंग)

(2) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

गैर सरकारी सदस्य

(1) श्री सुधाकर पाण्डेय, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

(2) डा० श्रीनिवास मिश्र, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकनामिक ग्रोथ, नई दिल्ली ।

(3) प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी, विद्या नगर, विशाखापतनम (आंध्र प्रदेश)

(4) श्री रघुवीर सहाय, सम्पादक, 'दिनमान' नई दिल्ली ।

(5) श्री कमलेश, डी/4, कालिंदी कालोनी, नई दिल्ली ।

(6) डा० कृष्ण नाथ शर्मा, अर्थशास्त्र विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी । — इन्होंने समिति पर काम करने में अपनी असमर्थता जाहिर की है ।

Development of Social and Cultural Tourism

9316. SHRI RAM KISHAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to develop social and cultural tourism in the country; and

(b) the details in regard to the religious and cultural pilgrimage centres to be covered in this programme?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) The development of a large number of centres of cultural and religious interest has been undertaken in various Plan peiods. For the development of new centres of cultural interest, the following criteria have been suggested in the Central Tourism Plan 1978—83 :—

(i) the existing and future tourism potential of the place for attracting both international and domestic tourists;

(ii) its accessibility;

(iii) its development in relation to the existing and/or future travel pattern or circuit of tourists within the country;

(iv) its relation to the overall promotional strategy and the development programme of the Department; and

(v) the investment that the State Government concerned would make for developing the infrastructure such as roads, water and electric supply, transport facilities (all these not necessarily charged to the Tourism Sector).

Based on the above criteria, new centers of cultural interest will be selected for development in consultation with the State Governments. In so far as the development of pilgrim centre is concerned, it is proposed to form a Society under the Societies Registration Act of 1860 which will be responsible for the selection of pilgrim centres for releasing funds for the maintenance/improvement/expansion of dharamshalas/sarais/musafarkhanas at these centres.

वित्तीय सहायता के रूप में राज्यों को दिये गये अनुदान

9317. **श्री गंगाभक्त सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वित्तीय सहायता के रूप में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को दिये जाने वाले अनुदानों की तुलना में ऋणों के अधिक अनुपात के कारण उन पर ऋण का भार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1977—78 के अन्त तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर केन्द्रीय सरकार का पृथक-पृथक ऋण भार कितना था ;

(ग) वर्ष 1978—79 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय सरकार को कितनी राशि और उस पर कितना ब्याज अदा किया जायेगा; और

(घ) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से ऋणों के भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की पद्धति में अभी हाल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । राज्यों के ऋणों की रकमों में जो वृद्धि हो रही है वह मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष जो ऋण दिए जाते हैं उनकी रकमें राज्य सरकारों द्वारा की गई वापसी अदायगियों से अधिक होने के परिणामस्वरूप हैं ।

(ख) 1977—78 के लेखों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें बिल्कुल हाल की उपलब्ध सूचना दी गई है ।

(ग) 1978–79 के बजट अनुमानों (जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तैयार नहीं किए जाते) के अनुसार संबंधित सूचना नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपयों में)

(i) राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से केन्द्रीय ऋणों की रकमों की वसूली	1030
(ii) केन्द्रीय ऋणों पर राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा की गई ब्याज की अदायगियां	575

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऋण मंजूर किए जाते हैं। अभी हाल में वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें किसी राज्य सरकार ने ऋणों की वापसी अदायगी के संबंध में छूट देने के लिए कहा गया हो।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य	31 मार्च, 1978 तक बकाया ऋणों की रकम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	770
2.	असम	443
3.	बिहार	836
4.	गुजरात	393
5.	हरियाणा	242
6.	हिमाचल प्रदेश	168
7.	जम्मू और कश्मीर	41
8.	कर्नाटक	486
9.	केरल	409
10.	मध्य प्रदेश	483
11.	महाराष्ट्र	743
12.	मणिपुर	58
13.	मेघालय	20
14.	नागालैंड	29
15.	उड़ीसा	560
16.	पंजाब	253
17.	राजस्थान	820
18.	तमिलनाडु	483
19.	त्रिपुरा	48
20.	उत्तर प्रदेश	1,073
21.	पश्चिम बंगाल	946
22.	सिक्किम	
		9,671

संघ राज्य क्षेत्र

1.	अरुणाचल प्रदेश	4
2.	गोआ, दमन और दीव	74
3.	मिजोरम	13
4.	पांडिचेरी	15
	जोड़	106

जोड़—राज्य व संघ राज्य क्षेत्र 9,783

टिप्पणी : 1976–77 और 1977–78 के लेखों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

चम्बर आफ कामर्स, जूनागढ़ का अभ्यावेदन

9318. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 11 फरवरी, 1978 को सौराष्ट्र, गुजरात में जूनागढ़ सिटी की यात्रा की थी और क्या चैम्बर आफ कामर्स, जूनागढ़ ने उस अवसर पर उन्हें कोई अभ्यावेदन दिया था और यदि हां, तो इस अभ्यावेदन में किस प्रकार की मांगें की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से कौन-कौन सी मांगे अब तक पूरी कर दी गई हैं और कौनसी मांगे पूरी की जानी हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक मांग कब और कैसे पूरी की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग). ज्ञापन के ब्यौरे और उस पर की गयी कार्यवाही के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और उत्तर सदन-पटल पर रख दिया जाएगा ।

Tripartite Agreement among India, Egypt And Yugoslavia

9319. SHRI YASHWANT BOROLE: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the term of the tripartite agreement among India, Egypt and Yugoslavia has been extended by another five years although nothing tangible has so far resulted in the matter of customs tariffs agreed to in principal;

(b) if so, what new steps are sought to be taken in this direction during the coming five years; and

(c) the names and quantum of new items included now in the list of commodities to be commerced ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) and (b). The Tripartite Agreement has been extended by a period of 5 years upto 31st March, 1983. The Agreement has had a modest impact in creating new and additional opportunities for trade between the three partners. It is expected that the extended Agreement will promote further trade and strengthen economic cooperation among the participating countries.

(c) No new item, apart from 134 items already covered by the Agreement has been included in the extended Agreement, so far.

Private Operators to run Air Service on Routes not Covered by I.A.

9320. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to permit private operators to run air services on routes not covered by Indian Airlines; and

(b) if so, the salient features thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) Government have been considering proposals by Private Operators for permits to operate air services on routes not operated by Indian Airlines. At present no proposal from private operators is pending for consideration by the Government.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की बिहार में शाखाएं

9321. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की बिहार में, बैंक-वार. कितनी शाखाएं हैं ;

(ख) बैंक-वार कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनमें बिहार के कितने कर्मचारी काम करते हैं और अन्य राज्यों के कितने हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विश्व बैंक के माध्यम से विदेशी सहायता

9322. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री विश्व बैंकों के माध्यम से विदेशी सहायता के बारे में 2 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 251 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को 1 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1978 तक के वित्तीय वर्ष के लिये 110 करोड़ रुपये की अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त हुई है और यदि हां, तो कब; और

(ख) क्या यह राशि उसी प्रयोजन के लिये खर्च की जा रही है जिसके लिये वह मिली है और यदि हां, तो अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और यह राशि कहां खर्च की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जुलाई, 1977 में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ समूह ने 1 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1978 के अपने वित्त वर्ष में भारत को 110 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता देने का वचन दिया था। इसमें से 87.9 करोड़ अमरीकी डालर की रकम का विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुमोदन किया जा चुका है । आशा है 30 जून, 1978 से पहले शेष रकम का अनुमोदन भी प्राप्त हो जाएगा ।

(ख) मानक पद्धति के अनुसार विश्व बैंक समूह की सहायता से चलाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता की राशि, किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है । चूंकि इन परियोजनाओं के लिए सहायता का अनुमोदन अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, इसलिए इन परियोजनाओं के लिए बैंक समूह द्वारा 31 मार्च, 1978 तक कोई संवितरण नहीं किया गया है ।

Pending Applications of Sterling Tea Companies for Dilution of Shares under Fera

9323. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what further action has been taken in the matter of pending applications of Sterling Group Tea Companies operating and controlling various tea estates in India in regard to dilution of their shares in respective companies in accordance with the provisions of Foreign Exchange Regulation Act;

(b) whether most of such applicants seek Government's approval for transfer of shares and control to particular buyer or group of people without offering their shares to general public;

(c) if so, the details thereof with name of owners that propose to transfer in the above manner; and

(d) what preventive steps have been taken to see that no underhand foreign exchange transaction is resorted to and offer to sell shares to general public is done through the press?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The valuation of the Indian business of the Sterling Tea Companies is presently in progress.

(b) No, Sir. In most cases the proposal is for offer of shares to the public through a Prospectus.

(c) Does not arise.

(d) The scheme of Indianisation and the mechanism of offer of shares to the Indian residents are such that there is no scope for underhand foreign exchange transaction through private arrangement. The offer of shares to the general public will be done through a Prospectus in accordance with the prescribed proceddures.

Tea estates in cachar

9324. SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that number of tea estates in district cachar, Assam have been approaching the Central Government for the last two years or so far assistance and help of the Central Government in the matter of realisation of their sums and dues payable by State Governments in order that these may tone up financial stability;

(b) if so, the facts thereof alongwith the names of such tea estates;

(c) the total amount of outstanding dues payable to them by Central and State Governments and their agencies; and

(d) the steps taken to assist such tea estates in Cachar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) :

(a) to (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

House built by Chairman of a public undertaking

9325. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

SHRI MADAN LAL SHUKLA :

SHRI MADHAV PRASAD TRIPATHI :

DR. BIJOY MONDAL :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the attention of the Government has been drawn to report published in the Economic Times dated 7th January, 1975 regarding house built by the Chairman of a Public Undertaking; and

(b) if so, has the Government investigated into the report and indentified the Chairman?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H.M. PATEL) :

(a) and (b) Presumably the Hon. Member is referring to the old report containing excerpts from the inaugural address given by the former Chief vigilance Commissioner at the Institute of Secretariat Training & Management. In this no reference was made to any 'house built' by a Chairman of a Public Undertaking but only to the furnishings in the house of a Chief Executive of a Public Enterprise. This was gone into and appropriate action taken.

गुजरात सरकार के निर्यात निगम द्वारा मलेशिया की एक फर्म के साथ ठेके पर हस्ताक्षर किया जाना

9326. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार के निर्यात निगम ने मलयेशिया की एक फर्म के साथ 52 लाख रुपये का भुगतान लेने के बाद 10 हजार टन नारियल के तेल की सप्लाई के लिये एक ठेके पर हस्ताक्षर किये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में जनता दुकानों का खोला जाना

9327. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु इस वर्ष किन-किन गांवों में जनता दुकान खोली गई हैं/खोली जानी हैं;

(ख) इन दुकानों पर कौन-कौन सी उपभोक्ता वस्तुएं बेंची जाती हैं और किस-किस वस्तु का कितना कितना मूल्य है; और

(ग) ये दुकानें चलाने का कार्य किस अधिकारी को सौंपा गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) राजस्थान के किसी भी गांव में कोई जनता दुकान न तो खोली गई है और न ही खोलने का प्रस्ताव है। तथापि, वर्ष 1978-79 में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं द्वारा शहरी इलाकों में लगभग 50 जनता दुकानें खोली जानी हैं।

(ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा खोली जाने वाली जनता दुकानें आवश्यक वस्तुओं का वितरण करेंगी और नियंत्रित तथा अनियंत्रित वस्तुयें बेचेंगी।

(ग) उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं द्वारा जनता दुकानें शहरी इलाकों में खोली जानी हैं।

Promotion of Shri I.P. Gupta, Member, Central Board of direct taxes during Emergency.

9328. SHRI MOHAN LAL PIPIL :

SHRI JYOTIRMOY BOSU :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the instruction of Government regarding promotion of officers when vigilance enquiries are pending against them;

(b) whether the vigilance clearance is necessary when important promotions are made;

(c) whether it is a fact that at the time when Shri I.P. Gupta was promoted as Member. Central Board of Direcct Taxes during Emergency vigilance enquiry was pending and then Finance Secretary passed adverse remark against his integrity;

(d) has the Government not laid down any time limit for vigilance enquiries by Central Bureau of Investigation (CBI) as well as departmental officers and if no limit is laid down what is the average time taken to complete such enquiries; and

(e) whether the enquiries initiated against him during the year 1975-76 have been completed and if so, the outcome of th ese enquiries?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H.M. PATEL) ;

(a) The extent instructions do not bar the promotion of an officer till on the conclusion of the investigation a decision is taken to issue a charge sheet to him or to sanction his prosecution.

(b) The Ministry/Department while processing and submitting names and particulars of eligible officers for consideration for promotion is required to certify the integrity of the officers concerned.

(c) and (e). No vigilance enquiry was pending against Shri I.P. Gupta at the time when he was appointed Member Central Board of Direct Taxes. After making confidential verification the Central Bureau of Investigation did not register any case against him for open enquiries. It is not correct to say that Finance Secretary had made any observation which could be construed as adverse remarks against the integrity of Shri I.P. Gupta.

(d) No rigid time limits as such have been laid down for completion of vigilance enquiries which depend on the facts and complexities of the particular case and the scope of the investigation. However the Central Bureau of Investigation has internal administrative instructions to guide its officers with a view to ensuring expeditious completion of the enquiries in the cases registered by it for open investigations.

आपात स्थिति के दौरान औद्योगिक वित्त निगम, दिल्ली में स्थानान्तरण

9329. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान औद्योगिक वित्त निगम, दिल्ली में कितने स्थानान्तरण किये गये और उसके क्या कारण थे तथा क्या उन कर्मचारियों के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें हैं जिन्हें उक्त निगम में पुनः नियुक्त कर दिया गया था और यदि हां; तो आरोपों के कारण ऐसे कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया जिन्हें वापस ले लिया गया ;

(ख) क्या श्री के० के० गोपाल स्वामी और श्री एल० डी० मुंडुकर नाम के कर्मचारी

उक्त निगम के अहाते में मर गये थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कोई शव परीक्षा की गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय वित्त निगम ने सूचित किया है कि आपात स्थिति के दौरान (जून, 1975 से मार्च, 1977 तक), विभिन्न स्तरों के 56 अधिकारियों का, इसके (निगम के) अलग-अलग कार्यालयों में स्थानान्तरण किया गया था । यह सभी स्थानान्तरण कार्य की अपेक्षाओं तथा भारतीय वित्त निगम की आवश्यकताओं के अनुसार किए गए थे । उपर्युक्त में से, 20 स्थानान्तरण पदोन्नति के कारण 4 सेवा निवृति के परिणामस्वरूप, 9 का स्थानान्तरण अनुकंपा-आधार पर उनके आवेदन करने पर तथा 23 स्थानान्तरण सामान्यतः निगम की आवश्यकताओं को देखते हुए किये गये । किसी भी कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण किसी प्रकार की शिकायतें या आरोपों के कारण नहीं किया गया और न ही इस कारण से किसी कर्मचारी का ट्रांसफर वापिस किया गया ।

(ख) स्वर्गीय प्रबन्धक श्री एल० डी० मुंडुकर की मृत्यु भारतीय औद्योगिक निगम के कार्यालय या इसके अहाते में नहीं हुई थी । उनकी मृत्यु 10-2-1977 को उनके निवास स्थान पर ही हुई थी । वह पिछले कई वर्षों से मधुमेह से पीड़ित थे तथा लगभग अपंग हो गये थे ।

सहायक प्रबन्धक स्वर्गीय श्री के० गोपालस्वामी 6 अगस्त, 1977 को आम दिनों की तरह कार्यालय आए थे तथा शाम 6 बजे तक कार्यालय में कार्य करते रहे । उसके बाद वह अचानक गिर पड़े । एक डाक्टर जो कि कुछ ही मिनटों में डाक्टरी मदद के लिए पहुंचा, उसने श्री गोपाल स्वामी को मृत घोषित कर दिया । डाक्टर के अनुसार, श्री गोपाल स्वामी की मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हुई ।

(ग) चूंकि श्री मुंडुकर की मृत्यु उनके घर पर हुई थी इसलिए निगम द्वारा उनके शव को पोस्ट-मार्टम के लिए भेजने का प्रश्न नहीं उठा । श्री गोपाल स्वामी की मृत्यु ऊपर बताए गए हालात में एक स्वाभाविक मौत थी तथा उनके परिवार के सदस्यों ने, जिन्होंने शव प्राप्त कर लिया था, इसे पोस्ट-मार्टम के लिए भेजना उचित नहीं समझा ।

Visit of U.S. Aid team to States to study Development needs

9330. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a three member U.S. Aid team had undertaken a tour of some States in the country during March this year to study their development needs; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Presumably, the Honourable Member is referring to the U.S. AID Study Team which visited India from the 6th to the 24th March, 1978 and also visited a few States (Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar). It held discussions with senior officials of the Government of India and State Governments and also met some distinguished economists, social scientists and leading Public men in the country.

(b) The purpose of the Team was to participate in the continuing dialogue between the two countries for recommending the type, composition and medium term strategy of U.S. Government's bilateral assistance programme for India for 1980 and beyond. This was a five member Study Team headed by Prof. Charles E. Lindblom. After holding their discussions in Delhi as well as in the States mentioned above, the Team members left India on 25-3-1978. The Team would submit its report to the U.S. authorities in due course.

Ban Imposed by Maharashtra Government on the movement of Pulses outside Maharashtra

9331. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL

SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Karnataka Chamber of Commerce and Industry has in a letter to him said the ban imposed by Maharasthtra on the movement of pulses outside that State would adversely affect the interests of consumers in States like Karnataka which are deficient in this item; and

(b) whether the Central Government has also been requested to enforce its declared policy of allowing free movement of foodgrains and not permit any State to impose movement restrictions as is done by Maharashtra presumably with the consent of the Union Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Maharashtra has stated that it has not imposed any ban on the movement of pulses outside the State. According to the existing policy of the Central Government, there should be no restriction on movement of foodgrains throughout the country except in the statutory rationing area in West Bengal. There is to be no restriction in the free inter-State movement of pulses.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी समितियों का अधिक्रमण

9332. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह शिकायत मिली है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी समिति नियमों का उल्लंघन करके सभी सहकारी समितियों को भंग कर दिया है और क्या इन समितियों के लिए चुनाव की तारीखों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार और उनमें से कुछ का प्रबन्ध राज्य सरकार ने अपने लोगों को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) मध्य प्रदेश सहकारी समिति अध्यादेश, 1977 जिसका स्थान अब एक अधिनियम ने ले लिया है के उप-खण्ड 7-क के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों की 7173 सहकारी समितियां अपने अधिकार में ले ली गई हैं और इन समितियों की देखभाल करने के लिये सरकारी कर्मचारियों को कार्यभारी अधिकारियों के रुप में नियुक्त किया गया है ।

(ख) यथा संशोधित कानून के उपबन्धों के अनुसार चुनाव 24 नवम्बर 1978 तक या इससे पहले कराये जाने हैं ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और आयकर अधिकारियों द्वारा इटावा में मारे गए छापे

9333. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च/अप्रैल, 1969 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और आयकर अधिकारियों ने इटावा में छापे मार कर जो कागजात जब्त किए थे, उनमें कितना-कितना माल अंकित था और कार्यवाही पूरी किए बिना उन कागजातों को वापिस करने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या उपरोक्त अधिकारियों ने छापों के दौरान सभी चल और अचल संपत्तियों के मूल्यों को शामिल किया था यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जब्त किए गए जेवरात व्यापारियों द्वारा रखे गए गिरवी रखी संपत्ति मानी गई है अथवा उप उपरोक्त व्यक्ति के परिवार की संपत्ति मानी गई है जिसके यहां छापा मारा गया था और स्वर्ण नियंत्रण कानून के उपबंधों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की की गई है तथा अब तक आयकर की कितनी राशि वसूल की गई है और कितनी वसूल की जानी है ; और

(घ) क्या गिरवी रखा माल उनके मालिकों को लौटाने और आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ). अप्रैल, 1969 में इटावा जिले के पूर्विया टोला में मेसर्स रामनारायण तथा बद्री प्रसाद और उन के परिवार के सदस्यों के परिवारों की तलाशी लेने और माल पकड़ने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के दौरान आयकर प्राधिकारियों ने 18.52 लाख रु० से अधिक मूल्य के सोने तथा चांदी के जेवर पकड़े तथा इस के अलावा 1948–49 तथा 1954–55 से 1969–70 तक के कर-निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित लेखा-पुस्तकें और दस्तावेज भी पकड़े । पकड़ी गयी सामग्री, कर-निर्धारिती द्वारा दी गयी सूचना तथा विभाग द्वारा की गयी जांच-पड़ताल के आधार पर, 1954–55 से 1969–70 तक के कर-निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित कर-निर्धारिणों को पूरा किया गया । छिपाई गयी आय को 26 लाख रु० आंका गया और उस पर 1956–57 से 1969–70 तक के कर निर्धारण वर्षों में कर निर्धारण किया गया जिस के परिणामत: 23 लाख रु० से अधिक की मांग जारी की गयी । कर-निर्धारण पूरा करते समय गिरवी रखी गयी वस्तुओं के रूप में पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों की लागत को भी हिसाब में ले लिया गया था । गिरवी रखी गयी वस्तुओं का हिसाब पकड़े गये कागजात में रखा गया था । कोई भी कागजात उचित कार्यवाही किये बिना वापिस नहीं किया गया ।

जारी की गयी मांग में से 13 लाख रु० से अधिक रकम की अदायगी की जा चुकी है । पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों में से कुछ परिसम्पत्तियां उस कर निर्धारिती को वापस दे दी गयी हैं जिस के कब्जे से वे पकड़ी गयी थी । शेष परिसम्पत्तियों को बकाया मांग की, जिस में कर-निर्धारियों के बाद लगाया गया अर्थदण्ड तथा ब्याज भी शामिल है, बाबत जमानत के रूप में रोक रखा गया है । फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार आयकर तथा धन कर अधिनियमों के अन्तर्गत 17.56 लाख रु० की मांग बकाया है ।

66,400 रुपये मूल्य का 3838 ग्राम शुद्ध सोना तथा 11,85,600 रु० मूल्य के 91,955.75 ग्राम सोने के जेवर स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये । पकड़े गये जेवर वे जेवर थे जो श्री बद्री प्रसाद के पास अन्य गिरवीदारों तथा व्यक्तियों द्वारा गिरवी रख गये थे । स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 16–2–1974 के न्यायनिर्णय सम्बन्धी आदेश में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कानपुर ने, इस बात का समाधान हो जाने पर कि जेवर श्री बद्री प्रसाद से भिन्न ऐसे अन्य व्यक्तियों के हैं जिन्होंने स्वयं स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं किया था, गिरवी रखे गये जेवरों को, स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम की धारा 71 के परन्तुक में की गयी व्यवस्था के अनुसार जब्त करने के आदेश नहीं दिये परन्तु इन को श्री बद्री प्रसाद को वापस करने के आदेश दिये जिसके कब्जे से ये जेवर विभाग द्वारा पकड़े गये थे । पकड़े गये जेवरों के 8 बक्सों में से, जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के पास थे, 4 बक्सों को 15 तथा 16 मार्च, 1978 को आयकर प्राधिकारियों की उपस्थिति में दुबारा तोलकर छोड़ दिया गया था । उन दस दलालों को, जेवर वापस किये जाने की तारीख तथा स्थान के सम्बन्ध में सूचना दे दी गयी थी, जिन्होंने श्री बद्री प्रसाद के पास 2000 ग्राम से अधिक के जेवरों को गिरवी रखा था । शेष चार बक्सों का, मेसर्स राम चरण लाल राम नारायण की ओर बकाया आयकर की वसूली के सम्बन्ध में आय कर प्राधिकारियों द्वारा अभिग्रहण कर लिया गया है ।

Merger of Dearness Allowance with pay of Central Government Employees

9334. SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Finance Secretary had met on the 3rd of April, 1978 the members of Staff Side of Standing Committee of the J.C.M. (National Level) to discuss the question of merger of dearness allowance with pay of the Central Government employees in order to reach the benefits thereof to the retiring employees;

(b) if so, whether any agreement was arrived at; and

(c) if not, the reasons for the same?

THE MINISTR OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The question of merger of dearness allowance with pay is linked with certain other important issues relating to Dearness Allowance which require careful consideration. Discussions with the Staff Side of the Joint Consultative Machinery on the various issues are still in progress and are expected to be concluded by the end of June, 1978.

Purchase of goods from Britain under Aid Programme

9335. SHRI YASHWANT BOROLE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the aid programme India is constrained to purchase goods, services from Britain even when they are uncompetitive for fear of lapsing of the aid ;

(b) if so, whether there are plans to identify well in advance those goods and services which India must purchase under the aid programme during the coming years;

(c) if so, what steps are being taken in this direction; and

(d) the way in which the present quantum of aid is being utilised.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). The United Kingdom extends assistance to India on a grant basis. The grants are tied to purchases from the United Kingdom. In this background, it is our effort to try and use these grants for purchase of goods and services which are of economic importance to us and which are available at internationally competitive prices. The latter is, however, not always possible particularly in view of the fact that U.K. extends very substantial assistance, the amount for the current year being £ 144 million or approximately Rs. 225 crores. In such a situation we have, in some cases, to secure British goods and services at prices which are not internationally competitive but which economically cost us nothing, as they are financed out of these grants.

(d) The present quantum of aid i.e. £ 144 million for the year 1977-78 is to be utilised in the following manner:

(i) £ 30 million	For import of machinery and equipment for the mutually agreed large value projects.
(ii) £ 20 million	For import of capital equipment and services by the public and private sectors including funding through the financial institutions like ICICI and IFCI.
(iii) £ 20 million	For meeting the import requirements of the power sector of the Indian economy.
(iv) £ 70 million	For the import of a wide variety of maintenance goods including component spare parts, raw materials and commodities.
(v) £ 4 million	Debt Relief.

The practice is to identify well in advance goods and services which could be purchased from U.K. under the grant assistance. Similarly Projects for which machinery and equipment could be imported from U.K. to our advantage are also identified in advance, the objective being to effect imports on a preferential basis of such items from Britain the prices of which are not greatly out of line with the prices obtaining in other countries.

Management Councils for Government Undertakings

9336. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to set up "Management

Councils" for various Government undertakings and public sector establishments;

(b) will such councils take up the question of scientific methods accountability and viability in such organisations; and

(c) how many such Management Councils have already been established and which are the units for which Government is planning such councils ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The whole question of workers participation in management at different levels i.e. at plant, shop and corporate levels in private, public and co-operative sectors is presently being considered by the Tripartite Committee on workers participation in management and equity, appointed in September '77.

(b) The Committee will consider such matters.

(c) Though the Management Councils based on the Tripartite Committee's recommendation are yet to come into being, a scheme for workers participation in industry at shop-floor and plant levels was adopted in October 1975. This scheme has been adopted, till February 1978, in 545 units in the Central public sector.

Decision regarding Functioning of Multinational Corporations in India

9337. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government had any consultations with the representatives of the Multinational Corporations in India and abroad recently;

(b) if so, what were the issues discussed; and

(c) what decisions have been taken with regard to their functioning in India?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c). Presumably, the Honourable Member has in mind the Roundtable organised by the Business International of USA between the 29th January and 1st February 1978. The Roundtable was in the nature of an informal discussion relating to Government policies on trade, development and investment. Suitable clarifications were given with reference to the new Industrial Policy of the Government and also the role assigned to foreign investment in the new policy.

जीवन बीमा निगम द्वारा धुम्रपान न करने वालों को रियायत दिया जाना

9338. श्री लालजी भाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सिग्रेट न पीने वाले व्यक्तियों को विशेष रियायत देने के लिये जीवन बीमा निगम में एक योजना लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं । जीवन बीमा निगम की मृत्यु सारणियां सामान्य अनुपातों पर स्वीकृत जीवनों के अनुभव पर आधारित है जिनमें सिगरेट पीने वाले भी शामिल हैं । लेकिन प्रस्तावकर्ता की डाक्टरी करने पर उच्च रक्त चाप, हृदय की स्थिति आदि जैसी प्रतिकूल स्थिति के साथ-साथ अधिक सिगरेट पीने की बात निगम द्वारा नोट कर ली जाती है और ऐसे मामलों में उचित अतिरिक्त प्रीमियम वसूल किया जाता है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Mosquitos in Aeroplanes

9339. SHRI KESHAVRAO DHONDGE: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether any complaint has been received by Government in regard to mosquito nuisance in the aeroplanes; and

(b) if so, the details thereof and the steps being taken by Government to remove it ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b). Yes, Sir. There have been complaints of mosquito nuisance in the aroplanes. In order to make the aircraft free of mosquitoes, the Air-India and the Indian Airlines carryout extensive spraying of insecticides in the aircraft cabins before the departure of the plane.

This problem is due to the existence of marshy land/spots around the airport/ terminal buildings. Effective steps are being taken to eradicate /minimise the menance with the help of the local authorities.

Revenue loss due to reduction of customs duty on import of stainless Steel Sheets

9340. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the estimated annual loss o revenue to the exchequer as result of the reduction in customs duty on the import of stainless steel sheets; and

(b) the extent to which the reduction in the import duty has resulted in decrease in, price of stainless steel utensils?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) On 18th June, 1977 duty on stainless steel plates, sheets and strips was reduced from 320% *ad valorem* to rates ranging from 40% to 120% *ad valorem*. The total loss of revenue by this reduction was estimated to be Rs. 14·65 crores per annum. On 15th July, 1977, the import duty rates on certain varieties of stainless steel plates, sheets and strips were increased to 220% *ad valorem*; this increase was subject to certain conditions; it is not possible to estimate the possible revenue gain from this increase easily.

(b) As stainless steel utensils are manufactured in the country from out of indigenous as well as imported stainless steel sheets which are of various sizes and qualities, it is not possible to precisely estimate the extent of decrease in prices of stainless steel utensils as a result of reduction in the import duty.

विदेशी सहायता

9341. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बजट में अनुमानित राशि की तुलना में कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होने की आशा है ;

(ख) क्या अनुमानित राशि में किसी कमी की आशा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) देश की 'प्लान' योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) चालू वर्ष में जितनी विदेशी सहायता प्राप्त होने की आशा है, उसका अनुमान 1978–79 के बजट में दिखाया गया है।

(ख) अब तक की स्थिति के अनुसार किसी कमी की आशा नहीं हैं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

More Assignment given to top Appointees in IAC and Air India

9342. PROF. P. G. MAVALANKAR : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have recently made one or more appointments in the IAC and Air India top set up giving more than one assignment/responsibility to the existing members of the Boards of Directors of IAC and Air India;

(b) if so, full facts thereof; and

(c) reasons for so doing and the advantages expected to accrue from such practice ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). ACM P .C. Lal has been appointed as common Chairman of the Boards of Air-India and Indian Airlines and Shri K. G. Appusamy, Managing Director, Air-India,
man of the Boards of Directors of Air-India and Indian Airlines.

(c) Common Chairman and Vice-Chairman of the two Boards have been appointed with a view to securing greater coordination between the two Corporations and to ensure utilisation of the infrastructural facilities to the best advantage of both the Corporations.

Visit of the Commerce Minister to Foreign Countries

9343. PROF. P. G. MAVALANKAR : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether he recently visited London on an official assignment;

(b) if so, the purpose and duration of such a visit;

(c) whether he visited other capitals or countries while he was abroad; and

(d) if so, where and far what ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) and (b). Yes, Sir. The purpose of the visit of Minister of commerce, Civil Supplies and Cooperation to London was to participate in the meeting of the Commonwealth Ministers held on 13th and 14th April, 1978, to review the state of negotiations on the common Fund. He arrived in London on 12th and left London on 15th April, 1978.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Victimisation of Employees of Auditor's and Accountant General's Office at Rajkot

9344. PROF. P. G. MAVALANKAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether one or more employees of the Auditor's and Accountant General's office at Rajkot in Gujarat have been victimised during the 1974 railway strike;

(b) if so, details thereof ;

(c) whether the suspension, etc. orders have been now revoked by the Janata Government;

(d) if so, when and how; and

(e) if not, why not ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). Action was taken against employees for participation in the May 1974 Strike in accordance with the orders of Government.

For their participation in the May 1974 strike and post-strike demonstrations in the office of Additional Accountant General, Rajkot 10 permanent/quasi-permanent employees were placed under suspension and 266 temporary employees were served with termination notices.

(c) to (e). The orders of suspension against 9 employees were revoked in January, 1976 and against one in December, 1976.

Termination notices in the case of 252 temporary employees were withdrawn before the expiry of the notice period, in July 1974. In the case of 9 others, these were withdrawn in December, 1977, after review of their cases under the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965.

Instructions for reinstatement of the remaining 5 employees have also been issued on the 17th April, 1978.

Change in Service and Refreshments Served by I A C on short and long Flights

9345. PROF. P. G. MAVALANKAR : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether IAC have recently improved/changed services and contents of refreshments and beverages on various short and long flights run daily by IAC all over the country;

(b) if so, broad details thereto;

(c) reasons for effecting such changes; and;

(d) response, if any, from the travelling passengers to these changes ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) Effective 1st January, 1978, both vegetarian and non-vegetarian dishes are being served on all flights according to the dietary preference of the passengers. Squasees served as cold drinks have been replaced by fruit juices. Tea and coffee are freshly brewed in flight wherever possible.

(c) These changes have been effected with a view to ensuring better passenger satisfaction.

(d) These improvements, on the whole have been well received by the passengers.

Income tax dues against textile mills in Ahmedabad

9346. SHRI AHSAN JAFRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any amount of Income Tax dues are outstanding till date against the textile Mills in the city of Ahmedabad and their Directors;

(b) the details thereof; and

(c) what steps are taken to collect such dues so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) to (c). The requisite information is not readily available; it is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

राजभाषा क्रियान्वित समिति

9347. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय/विभाग में राजभाषा क्रियान्विति समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977 में इसकी बैठकें किन-किन तारीखों को हुई और उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये;

(ग) उनमें से कितने निर्णयों की पूर्णतया क्रियान्विति की गई; और

(घ) पूर्णतया क्रियान्विति न किये गये निर्णयों की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) वाणिज्य विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें 18-3-77 तथा 3-9-77 को हुई थीं तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग की एक बैठक 30-9-77 को हुई थी। इन बैठकों में लिये निर्णय संक्षेप में क्रमशः विवरण 1 तथा 2 में दिये गये हैं।

(ग) कुल 29 सिफ़ारिशों में से 17 सिफारिशें कार्यान्वित हुई हैं।

(घ) इन बैठकों में की गई सिफारिशों को अनुपालन के लिए सभी संबंधित कार्यालयों के ध्यान में लाया गया और इन्हें कार्यान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण 1

वर्ष 1977 में वाणिज्य विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 18 मार्च, 1977 और 3 सितम्बर, 1977 को हुई थी। इन बैठकों में निम्नलिखित निर्णय किये गये :

18-3-77 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में किए गए निर्णय

1. वाणिज्य विभाग के हर अनुभाग में हिन्दी में टिप्पण तथा आलेखन के लिए कुछ मिसिलें निर्धारित करना।
2. वाणिज्य विभाग के अधीन हर कार्यालय में कम से कम एक हिन्दी अनुवादक, एक टंकक और एक हिन्दी टाइपराइटर की व्यवस्था करना।
3. वाणिज्य विभाग के अधीन सभी निगमों तथा कम्पनियों के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने की एक योजना शुरू करना।
4. सभी कार्यालयों को 'कार्यालय सहायिका' खरीदने के लिए कहना।
5. 'सामान्य आदेशों' की परिभाषा एक बार फिर परिचालित करना, ताकि वे द्विभाषिक रूप में जारी किये जा सकें।
6. वर्ष 1977 के सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में सामान्य जानकारी देने वाला एक विस्तृत परिपत्र अग्रिम में जारी करना।
7. हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद कैसे की जा सकती है, इस बारे में एक विस्तृत परिपत्र जारी करना।

3-9-1977 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में किए गए निर्णय

1. ऊपर (1) में दी गई योजना वाणिज्य विभाग के अधीन सभी सम्बद्ध तथा

अधीनस्थ कार्यालयो और कम्पनियों तथा निगमों आदि के कार्यालयों को लागू करना।

2. यह सुनिश्चित करना कि हिन्दी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले सभी लिफाफों पर पते केवल हिन्दी में लिखे जायें।

3. वाणिज्य विभाग में अपना काम हिन्दी में करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन व पुरस्कार देकर तथा गोपनीय रिपोर्टों में अच्छी प्रविष्टियां करके प्रोत्साहित करना।

4. हिन्दी की अच्छी योग्यता रखने वाले टाइपिस्टों और आशुलिपिकों को क्रमश: हिन्दी टाइप तथा आशुलिपि में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।

5. वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी अधिकारी द्वारा सभी अनुभागों का दौरा करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिन्दी में टिप्पण तथा आलेखन के लिए मिसिलें निर्धारित की जायें।

6. हिन्दी में काम करने की आवश्यकता बताने के लिए अनुभाग अधिकारियों की बैठकें बुलाना।

7. दोनों भाषाओं के टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों की सूची तैयार करना।

8. हिन्दी अनुभाग को चाहिये कि वह उन अनुभागों का हिन्दी टाइप का कार्य न ले, जिनके पास दोनों भाषाओं के टाइपिस्ट हैं।

9. वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अनुभाग का दौरा करें कि हिन्दी में किये जाने वाले काम का ब्यौरा रखने के लिए हर अनुभाग मे एक रजिस्टर रखा जाये।

10. नकद पुरस्कार योजना फिर परिचालित की जाये और कार्यान्वित की जाये।

विवरण II

नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 30 सितम्बर, 1977 को हुई बैठक में किये गये निर्णय

(1) उन अनुभागों को स्मरण पत्र भेजा जाये, जिन्होंने अभी तक अपने मानक मसौदे हिन्दी में अनुवाद कराने के लिए नहीं भेजे हैं।

(2) वनस्पति निदेशालय द्वारा उनके यहां प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी शब्दावली की सूची तुरन्त भेजी जाये, ताकि अंग्रेजी हिन्दी शब्दावली का संकलन तैयार किया जा सके।

(3) मंत्रालय के हिन्दी आशुलिपिक के मंत्री महोदय के निजी अनुभाग में तैनात किये जाने से जो पद खाली हुआ है उसे तुरन्त भरने के लिए कार्रवाई की जाये।

(4) पहली फरवरी, 1977 को हुई बैठक में किये निर्णय के अनुसार जिन संगठनों ने हिन्दी के कार्य के लिए पदों का सृजन अभी नहीं किया है, वे इस बारे में तुरन्त कार्रवाई करें। सुपर बाजार में भी हिन्दी अधिकारी तथा अनुवादकों के पद बनाये जायें।

(5) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सुपर बाजार को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिये स्मरण कराना।

(6) वनस्पति घी, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय, वायदा बाजार आयोग और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को टिप्पण तथा आलेखन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नकद पुरस्कार देने की योजना में रखी गई 500 कर्मचारियों को शर्त से विशेष मामले के रूप में छूट देने के बारे में राजभाषा विभाग को पुनः स्मरण पत्र भेजा जाये।

(7) हिन्दी में मिले पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाने है। हिन्दी में मिले पत्रों के शत प्रतिशत उत्तर हिन्दी में देने के लिये राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के प्रयासों की सराहना करने के लिये अध्यक्ष की ओर से परिषद को एक प्रशंसा पत्र भेजा जाये।

(8) समिति का विचार था कि शुरू शुरू में हिन्दी भाषी राज्यों आदि को सभी पत्र हिन्दी में भेजना संभव नहीं हो सकेगा। इसके लिये एक सोपानवार कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की गई।

(9) हिन्दी तथा अंग्रेजी में जारी किये जाने वाले कागजात हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जायें।

(10) हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को टिप्पण तथा आलेखन में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोतसाहित किया जाये।

(11) सुपर बाजार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाये। सभी कार्यालयों द्वारा अपनी-अपनी समिति की तिगाही बैठकें नियमित रूप से बुलाई जायें।

(12) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा प्रकाशित 'संघ की राजभाषा' नामक पुस्तिका क्रय करके राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों तथा विभाग से संबंधित सभी कार्यालयों, संगठनों आदि को भेजी जायें।

राजभाषा क्रियान्विती समिति का गठन

9348. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय/विभाग में राजभाषा क्रियान्विति समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977 में इसकी बैठकें किन-किन तारीखों को हुई थीं और उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये;

(ग) उनमें से कितने निर्णयों की पूर्णतया क्रियान्विति की गई; और

(घ) शेष निर्णयों की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वित्त मंत्रालय के निम्नलिखित विभागों/संगठनों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है :—

(1) आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग को छोड़कर)

(2) आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)

(3) राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रभाग)

(4) राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

(5) राजस्व विभाग (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड)

(6) व्यय विभाग (संस्थापना प्रभाग)

(7) व्यय विभाग (सरकारी उद्यम कार्यालय)

(8) व्यय विभाग (रक्षा प्रभाग)

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें इन समितियों की 1977 के दौरान हुई बैठकों की तारीखें दी गई हैं।

(ग) और (घ). इन बैठकों में लिये गये निर्णयों, उनके कार्यान्वयन और उनके कार्यान्वयन में हुआ विलम्ब, यदि कोई हो, के संबंध में विस्तृत सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

1977 के दौरान वित्त मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की हुई बैठकों की तारीखें

वित्त मंत्रालय के विभाग/खण्ड जिससे राजभाषा कार्यान्वयन समिति सम्बद्ध है	बैठकों की तारीखें
1	2
आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग को छोड़कर)	19-3-1977, 27-6-1977 और 17-10-1977
आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)	9-3-1977 और 2-11-1977
राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रभाग)	7-5-1977 और 27-9-1977
राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)	7-4-1977, 25-6-1977 और 26-9-1977
राजस्व विभाग (केन्द्रीय उपाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड)	10-5-1977, 21-9-1977 और 30-11-1977
व्यय विभाग (संस्थापना प्रभाग)	23-3-1977 और 15-11-1977
व्यय विभाग (सरकारी उद्यम कार्यालय)	28-4-1977 और 8-9-1977
व्यय विभाग (रक्षा प्रभाग)	25-4-1977

वित्त मंत्रालय में हिन्दी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षित टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर

9349. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग में इस समय कुल कितने टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर क्रमशः हिन्दी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षित हैं;

(ख) उनमें से कितने टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर पूर्णतया हिन्दी का काम करते हैं;

(ग) शेष हिन्दी टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों की सेवाओं का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनके उपयोग के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ). वित्त मंत्रालय के सचिवालय में 103 टाइपिस्ट और 102 स्टेनोग्राफर क्रमशः हिन्दी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षित हैं। इनमें से 23 टाइपिस्टों और 6 स्टेनोग्राफरों की सेवाएं पूर्णतया हिन्दी के काम के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। शेष टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों की सेवाएं भी, (जो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में प्रशिक्षित हैं) उनके अंग्रेजी काम के अलावा, जब कभी जरूरत पड़ती है हिन्दी के काम के लिए उपयोग में लाई जाती हैं।

Construction of Aerodrome at Karipur near Calicut in Kerala

9350. SHRI C. K. CHANDRAPPAN : SHRI N. SREKANTAN NAIR : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether any provision has been made for the construction of an aerodrome at Karipur near Calicut in Kerala;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) what is the present stage of construction of the aerodrome ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) to (d). Yes, Sir. A provision of Rs. 90 lakhs exists in the Sixth Plan for construction of an aerodrome at Calicut. A token provision of Rs. 0·50 lakhs has been made during 1978-79. Land has already been acquired. Revised plans and estimates are under preparation.

आयात तथा निर्यात से सम्बन्धित संकल्पना में परिवर्तन

9351. **श्री सुखदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने व्यापार में वृद्धि के उद्देश्य से आयात तथा निर्यात संबंधी संकल्पना में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वस्तुओं के लिये परम्परागत मंडियों के अतिरिक्त नई मंडियों की खोज करने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता। तथापि बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय विपणन तथा सूचना प्रणाली के रूप में राज्य व्यापार संगठनों तथा अन्य अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की सहायता से हमारे निर्यातकों की सौदा करने की शक्ति को सुदृढ़ करके नये बाजारों का पता लगाना सरकार की निर्यात नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

Scheme to Encourage Semi Processed Mica

9352. SHRI L. L. KAPOOR : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) its it a fact that a number of malpractices continue by the exporters of Mica, if so, what are the effective steps that are proposed to remove such malpractices;

(b) have Government any scheme to encourage semi processed mica, if so, the details thereof; and

(c) is it a fact that Mica Trading Corporation finds itself helpless against private exporters, and therefore needs overhauling and reorganisation; if so, proposals in this direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) In the Third meeting of the Mica Advisory Committee held on the 27th January, 1978, certain allegations were made regarding non-payment of minimum wages, sale of scarce varieties of mica at prices lower than those

chich the market could bear, sale of "difficult-to-obtain" mica without cash memos and supply of mica to MITCO by the big exporters through the weaker section. The allegations, which were in general terms, are being looked into and, on receipt of specific complaints, suitable action in the matter wojld be taken.

(b) semi-processed Mica generally refers to a stage in the course of processing crude Mica. As such, there cannot by anyscheme to encourage the production of this item.

(c) No Sir.

Appointment of permanent Finance Commission to review overdrafts by States

9353. SHRI AGHAN SINGH, THAKUR :
SHRI RAMANAND TIWARY :
SHRI OM PRAKASH TYAGI :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a permanent Finance Commission to study and review the cases of overdrafts and non-plan schemes of the State Governments;

(b) whether some States have made request to this effect and if so, their names; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) No, Sir.

(b) Suggestions to this effect have been made from time to time; recently the Government of Kerala made such a suggestion.

(c) Government are not convinced of the need for a permanent Finance Commission.

Promotions in Central Excise M. P. and Vidarbha Collectorate, Nagpur

9354. DR. RAMJI SINGH :
SHRI RAM KISHAN :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the percentage fixed for officials having 'Very Good' remarks in their Confidential Reports for promotion to Deputy Office Superintendent ;

(b) whether promotion from U.D.C. to aforesaid post was made during Emergency by a single Departmental Promotion Committee and if not, by how many D.P.Cs. and the actual number of supersessions made by each D.P.C.;

(c) whether any promotions/supersessions of U.D.Cs., Deputy Office Superintendents Level II and Level I and Office Superintendents against whom departmental enquiries are/were in force, have been made;

(d) if so, the reasons for not reviewing all such cases immediately ;

(e) whether these promotions/supersessions have since been reviewed and the affected senior U.D.C.s. given their due promotions with retrospective effect; if not the reasons therefor ; and

(f) whether immediate action would now be taken in this regard in the Central Excise M. P. and Vidarbha Collectorate, Nagpur?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) No particular percentage has been fixed for officials having 'Very Good' remarks in their Confidential Reports for promotion as Deputy Office Superintendents.

(b) Promotions from the grade of U.D.Cs. to the posts of Deputy Office Superintendent were made during Emergency. Only one D.P.C. was held on 17-7-1976 but there was no supersession on the basis of its findings. However, just before the promulgation of Emergency a D.P.C. was held on 12-6-1975 on the basis of which 10 Upper Division Clerks superseded 37 colleagues senior to them with in the consideration zone.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) Promotion from the grade of Upper Division Clerk to the grade of Deputy Office Superintendent Level -II , is in their normal line of promotion ; it is made by selection. Cases of officers, who are superseded on the basis of the findings of a D.P.C., are again reviewed by all subsequent D.P.C.s. and those found suitable are promoted. Such promotions are made with effect from the date of issue of the orders of promotions and not retrospectively .

(f) In view of (e) above, no further action is called for

Promotion of Junior U.D.Cs. in Central Excise M. P. and Vidarbha Collectorate, Nagpur

9355. DR. RAMJI SINGH :
SHRI RAM KRISHAN :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether junior UDCs were promoted to the grade of Deputy Office Superintendents Level II (Pay scale 425-700) in 1975 superseding many senior UDCs in then Central Excise M.P. and Vidarbha Collectorate, Nagpur during Emergency and if so, reasons therefor;

(b) whether names of UDCs were concidered on the basis of anticipated number of vacancies of Deputy Office Superintendents Level II or in view of actual number of vacancies of D.O.S.;

(c) if so, the reasons thereof and for not treating such promotions as illegal and not reviewing/revising the matter in terms of excesses during emergency;

(d) whether these supersessions are allowed only on the basis of one or two 'Very Good' and not five continuous remarks in the confidential reports during the Emergency ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) Yes Sir. A few Upper Division Clerks were promoted to the grade of D. O. S. (Level-II) superseding their seniors during the year 1975 on the basis of findings of the meeting of the Departmental Promotion Committee held on 12-6-1975. The cadre of Deputy Office Superintendents (Level-II) is filled by promotion of Upper Division Clerks and Stenographers (Ordinary) Grade) on the basis of selection on merit. Higher categorisation where warranted is given by the Departmental Promotion Committee taking into account the overall record of service of the individuals concerned. Officers with higher grading are included in the panel above those withlowergrading and are promoted against the vacancies as and when they occur. In a procedure of promotion involving selection on merits, supersessions are likely to occur.

(b) The number of U. D.Cs. considered for promotions as Deputy Office Superintendent (Level-II) was on the basis of both existing and anticipated vacancies in the cadre of D. O.S. (Level -II) in accordance with the general policy of Government.

(c) These promotions were made in accordance with the existing rules and procedures. They are not illegal, nor can they be treated as cases of excesses during Emergency.

(d) and (e), Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Price Support Operations to Growers of Lac

9356. SHRI RAM KISHAN :
SHRI RAM KANWAR BERWA:

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that growers are deeply disappointed due to steep fall in the price of lac; and

(d) what price support operations are proposed by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) The price of lac presently continue almost at par with prices prevailing during pervious year.

(b) Government has issued orders to the State Trading Corporation to procure, 5,500 tons of seedlac during 1978-79 at Rs. 2·25 per kg. of sticklac having 50% Yield of seedlac.

सोने के आभूषणों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

9357. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में भारत से आभूषणों के निर्यात के विदेशों से ऋयादेश प्राप्त हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कीमत के और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत से सोने के आभूषणों का निर्यात करने के लिए विदेशों से 1977 में प्राप्त आर्डरों का मूल्य 2,03,80,000 रुपये था। यह राशि निर्बाध विदेशी मुद्रा में पूर्णतः वसूल की जा चुकी है।

सरकारी कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

9358. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 तथा वर्ष 1977–78 के दौरान सरकारी कर्मचारियों को विभागवार कुल कितनी राशि समयोपरि भत्ते के रूप में अदा की गई;

(ख) क्या उक्त राशि इससे पूर्व के दो वर्षों के समयोपरि भत्ते की राशि से कम है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कम है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1976–77 तथा 1977–78 के पहले छः महीनों के दौरान विभागवार दी गई समयोपरि भत्ते की राशि के संबंध में एक विवरण-पत्र संलग्न है। 1977–78 की शेष अवधि के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). 1976–77 के दौरान समयोपरि भत्ते पर 49.15 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो 1975–76 के दौरान समयोपरि भत्ते पर हुए 61.75 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 12.6 करोड़ रुपये कम था और 1974–75 के दौरान समयोपरि भत्ते पर हुए 55 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 5.25 करोड़ रुपये कम था।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा समयोपरि भत्ते पर किया गया विभागवार व्यय

क्रम संख्या	विभाग	1976–77	1977–78 के पहले छः महीने
1	2	3	4
			हजार रुपये
1.	रक्षा लेखा विभाग	3102	1760
	रक्षा (जिन असैनिक कर्मचारियों को सुरक्षा सेवा अनुमानों में से वेतन दिया जाता है)	148634	71697
2.	रेलवे	103421	66759
3.	संचार मंत्रालय	117668	62078
4.	सूचना तथा प्रसार	5464	3180

1	2	3	4
5.	आर्थिक कार्य विभाग	65334	28231
6.	राजस्व तथा बीमा	15461	7558
7.	अन्तरिक्ष	2083	1192
8.	परमाणु ऊर्जा	5196	3265
9.	निर्माण तथा आवास	848	610
10.	नागर विमानन	10068	5613
11.	वाणिज्य	427	192
12.	विदेश कार्य	1049	441
13.	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग	980	452
14.	आपूर्ति	306	194
15.	गृह	1641	592
16.	कृषि	2874	1452
17.	औद्योगिक विकास	599	250
18.	खान	599	507
19.	सांस्कृतिक	384	259
20.	शिक्षा	291	179
21.	श्रम तथा रोजगार	425	241
22.	कार्मिक	634	278
23.	स्वास्थ्य	315	153
24.	सिंचाई	198	104
25.	खाद्य	90	76
26.	ग्राम विकास	49	26
27.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	—	—
28.	शक्ति	331	153
29.	नौवहन और परिवहन	673	345
30.	समाज कल्याण	32	9
31.	योजना	181	50
32.	संसदीय कार्य	52	18

1	2	3	4
33.	संघ लोक सेवा आयोग	124	81
34.	राष्ट्रपति सचिवालय	36	16
35.	पर्यटन	27	16
36.	भारी उद्योग	98	49
37.	व्यय	136	72
38.	परिवार कल्याण	55	60
39.	रक्षा	184	119
40.	इलैक्ट्रानिक्स	36	16
41.	उप-राष्ट्रपति सचिवालय	9	3
42.	सांख्यिकी	62	29
43.	कोयला	28	13
44.	इस्पात	122	65
45.	पुनर्वास	61	36
46	मंत्रीमंडल-कार्य	36	18
47.	पैट्रोलियम	73	38
48.	प्रधान मंत्री सचिवालय	131	63
49.	विधि तथा न्याय	325	166
50.	कम्पनी कार्य	117	44
51.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	354	209
52.	रसायन और उर्वरक	59	34
53.	सिविल आपूर्ति तथा सहकारिता	50	37
	जोड़	491532	259098
		(49.51 करोड़ रुपए)	(25.91 करोड़ रुपये)

असाम में रुग्ण चाय बागान

9359. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असाम में कुल कितने रुग्ण चाय बागान हैं ;

(ख) उनमें कुल कितने श्रमिक और अन्य कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें कहीं अन्यत्र काम पर लगाने का है और यदि हां, तो कहां और कैसे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) रुग्ण चाय बागानों की संख्या भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न रहती है । चाय (संशोधित) अधिनियम 1976 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने अब तक असम स्थित पांच रुग्ण बागानों के कार्यों की जांच की है ।

(ख) उपरोक्त पांच रुग्ण बागानों में कर्मचारियों की कुल संख्या 4470 है ।

(ग) ये चाय बागान अभी भी कार्य कर रहे हैं और इसलिए इस स्थिति में कर्मचारियों को अन्यत्र खपाने की प्रश्न नहीं उठता ।

Request from Kerala for withdrawal of Central Excise duty on Branded Biris

9360. SHRI SREEKANTAN NAIR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) has the Union Government received a request from the State Government of Kerala for the withdrawal of Central Excise duty on biris, or an alternate proposal to impose the duty on biri-tobacco instead of branded biris; and

(b) if so what is the reaction of the Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) The Minister of Industries, Government of Kerala has suggested that if it is not possible to withdraw the central excise duty on branded biris then in the place of duty on branded biris duty may be levied on biri tobacco.

(b) Central Excise duty on branded biris was imposed and the rate of duty on biri tabacco was reduced in pursuance of the recommendations of the Tobacco Excise Tariff Committee ; it had observed that in the long run from both fiscal and administrative angles the ideal would be to move away from a tax on unmanufactured tobacco to one on the finished manufactured products. Imposition of tax on biri tobacco instead of branded biris will thus be a retrograde step.

Amount Invested in Shares through Calcutta Share Market by Financial Institutions

9361. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the financial institutions have been aiding the institutional investors in buying shares of some private companies in Calcutta Share Market;

(b) if so, what is the total amount invested in shares by these institutional investors through Calcutta Share Market during the month of March 1978; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) No Sir. LIC, GIC and UTI do not make purchases in the shares of private companies.

(b) and (c). Question do not arise.

Tourist Centres in Kerala

9362. SHRI GEORGE MATHEW : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) how many tourist centres are in Kerala for which Central Government is giving help and has got development plans and what are the proposed development schemes;

(b) has the State Government submitted a plan to the Central Government for the development of Thekkady in Idukki District of Kerala or has the Central Government got any plans of its own; and

(c) how many more tourist centres will be developed in Kerala by the Centre in the coming years ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) With the abolition of centrally sponsored schemes from the commencement of the Fourth Plan no Central assistance has been given to the Kerala Government for any tourism schemes. However Kovalam is being developed as a beach resort with a view to attracting a larger number of international tourists.

(b) No detailed plans have been received from the State Government for the development of Thekkady. The Central Department of Tourism has however realeased a sum of Rs. 2·00 lakhs to the State Government for the purchase of one motor launch for operation on the lake to view wild life.

(c) The development of additional facilities at Kovalam will be continued with. As regards new centres in Kerala to be taken up for development no decision has been taken as these will be determined in consultation with the State Government when its perspective plan of tourism development is discussed at the time of finalising the State Five Year Plan 1978—83 so that an integrated approach to tourism development in the Central and State sectors is ensured. The nature and extent of this tourism development will however depend upon the funds made available for the purpose in the Five Year Plan 1978—83.

Proposal to Decanalise Export of Natural Rubber

9363. SHRI GEORGE MATHEW : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to decanalise the export of natural rubber ;

(b) what are the minimum formalities that have to be observed now for the export of natural rubber ; and

(c) whether private individuals can export natural rubber just like the S.T.C.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) There is no such proposal under Government's consideration.

(b) Government authorises S.T.C. to purchase and export surplus rubber in the country from time to time. No special formalities are needed for undertaking exports of rubber by S.T.C.

(c) Besides S.T.C. growers or consortium of growers are permitted to export rubber under the S.T.C. umbrella under specific authorisations.

Banning of Import of Natural and Synthetic Rubber into India

9364. SHRI GEORGE MATHEW : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to consider the banning of import of Natural and Synthetic rubber into India for a period of 10 years to promote the natural rubber industry in India; and

(b) whether by keeping the minimum price of natural rubber low - and unremunerative to the growers, the interests of the growers are hampered and also ruin the economy of a State like Kerala?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) Import of natural rubber has already been banned with effect from 1st April 1973. Only one type of synthetic rubber namely styrene butadiene rubber which is manufactured in the country is banned for import for the last 12 years. Manufacture of Nitrile another type of synthetic rubber has just commenced and its import is being permitted on restricted basis. The other types of synthetic rubber like butyl neoprene thikol etc. which are not manufactured in India are permitted for import on a restricted basis.

(b) Government had raised the minimum prices of RMA-I of Natural Rubber from Rs. 520/- to Rs. 655/- per quintal with differentials for other grades with effect from 6th August 1977. These prices are effective upto 31st May 1978. In the meantime the position is being reviewed.

Government while considering the question of refixing the prices will give due regard both for the need to give a fair return to the grower and for maintaining prices of essential commodities at reasonable levels.

Extension of Runway at Cochin Aerodrome

9365. SHRI GEORGE MATHEW : Will the minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the Central Government has taken note of the fact , that the funds provided for the extension of the ranway etc; at Cochin aerodrome for this year are inadequate to complete the work this year ; and

(b) if so, action proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). Adequate funds will be made available this year itself to complete the work.

Surplus Officers and Staff of STC

9366. SHRI R.L.P. VERMA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION, be pleased to state :

(a) whether STC has officers and Staff much in excess of their essential requirements ;

(b) whether the staff and officers have become surplus as the business handled by the Corporation has decreased ; and

(c) the number of officers and staff surplus at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) No, Sir.

(b) No., Sir. The business target for the current year has been planned at a level higher than that of the last year.

(c) Does not arise .

Iron ore exported by MMTC and Private Exporters in Goa

9367. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether exports of iron ore by MMTC have decreased during the last three years ;

(b) what was the quantity and value of iron ore exported by MMTC and private exporters in Goa separately; and

(c) what are the reasons for lower exports by MMTC ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) No, Sir.

(b) The statement below gives the quantity and value of iron ore exported by MMTC and Private exporters of Goa during the last three years :

(Qty. in million tonnes)
(Value : in Rs. crores)

Year	MMTC		Goan Shippers	
	Quantity	Value	Quantity	Value
1975-76	11·618	128·90	10·896	79·81
1976-77	11·738	148·85	11·360	90·19
1977-78	12·297	164·04	9·518	86·89

(c) Does not arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने पर प्रतिबन्ध

9368. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ने सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल : (क) यदयपि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों दवारा दिये जाने वाले ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई विशेष सुझाव नहीं दिया है, 2 मार्च, 1978 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महा प्रबंधकों को भेजे गये अपने पत्र में, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह संकेत दिया था कि वह सामान्य ढांचा जिसमें आर्थिक और ऋण नीतियों का परिचालन होगा समग्र रुप से नियंत्रक के भीतर ही कार्य करेगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Labour Cooperatives

9370. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government have formulated comprehensive plan for formulation and encouragement to labour cooperatives in the organised/unorganised sector; and

(b) if so, details of the plan formulated for 1978-79 alongwith the progress achieved in regard to the various schemes formation and encouragement of labour cooperative—State-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) State Governments have been requested to expand and strengthen labour cooperatives so that in construction activities particularly in the public and cooperative sectors increasing use is made of the services of labour cooperatives. The Plan for their development in the Medium -term plan 1978-79 is under formulation.

(b) State-wise tentative outlays for the development of labour cooperatives during 1978-79 is given at Statement I. Statement II shows the progress made by labour cooperatives in various States and Union Territories as on 30th June, 1977.

Statement I

State-wise Tentative Financial Outlays for the Development of Labour Cooperatives during 1978-79.

State/U.Ts.	(Rs. in lakhs)
Andhra Pradesh	8·40
Assam	
Bihar	5·80
Gujarat	1·90
Haryana	4·25

State/V.Ts.	(Rs. in lakhs)
Jammu & Kashmir	1·00
Himachal Pradesh	..
Karnataka	10·00
Kerala	0·20
Madhya Pradesh	..
Maharashtra	10·19
Manipur	..
Meghalaya	1·00
Nagaland	—
Orissa	5·00
Punjab	0·50
Rajsthan	0·02
Sikkim	..
Tamil Nadu	3·53
Tripura	1·80
Uttar Pradesh	0·80
West Bengal	19·43
Union Territories	
Andaman & Nicobar Islands	..
Arunachal Pradesh	
Chandigarh	..
D. & N. Haveli	0·10
Delhi	0·45
Goa, Diu & Daman	0·10
Lakshadweep	0·51
Mizoram	..
Pondicherryr	0·03
ALL—INDIA	75·01

Statement II

State-wise progress of labour cooperatives as on 30th June, 1977.

State/U.T.	No. of societies	Membership (Nos.)	Value of works executed (Rs. '000)
Andhra Pradesh	894	53,532	4385
Assam	37	1,056	4246
Bihar	718	24,535	2567
Gujarat	807	1,06,500	12650
Haryana	484	34,594	36637
Himachal Pradesh	20	1,333	141
Jammu and Kashmir	5	906	—
Karnataka	217	17,875	4689
Kerala	67	10,617	13290
Madhya Pradesh	245	24,280	13653
Maharashtra	2506	1,63,624	168147
Manipur	420	1,78,000	9947
Meghalaya	18	960	..
Nagaland	192	Nil	Nil
Orissa	198	22,578	3663
Punjab	814	60,964	37608
Rajasthan	1023	33,845	23590
Sikkim			
Tamil Nadu	116	23,917	11310
Tripura	10	522	79
Uttar Pradesh	363	17,663	4917
West Bengal	939	26,146	49660
Total/U.Ts.	102	8,952	6824
Total	10,093	6,52,189	521903

Remodelling and improvement of Airposts in Maharashtra for 1978-79

9371. SHRI VASTANT SATHE : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) details of proposals cleared for implementation by the Ministry for remodelling and improvement of Airports in Mahrarashtra State Airportwise for 1978-79.

(b) whether the Government have received representation from some organisations in Maharashtra regarding Air timings of the flights for Nagpur and related matters ; and

(c) if so, details thereof and action taken/proposed in the matter.

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) During 1978-79 no provision has been made in the budget for major expansion/modernisation of airports in Maharashtra. However, a provision of Rs. 495 lakhs has been made during 1978-79 for the continuing project of the new international passenger and cargo terminal complex (Phase I) at Bombay Airport.

(b) Yes, Sir.

(c) The representation calls for the timings of Delhi/Nagpur service to be advanced to morning departures. This proposition is not currently feasible because of constraints imposed by repair/development works at other aerodromes, Srinagar/Amritsar. However, it will be possible to revise timings of Delhi/Nagpur service when these civil works are completed and all the services to Amritsar add Srinagar have not got to be completed in the morning hours.

News Item Captioned 'Expansion of Marketing Cooperatives in Big Way'

9372. SHRI VASANT SATHE :
SHRI RAJ KESHAR SINGH :

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether attention of the Government has been drawn to the news report appearing in the *Times of India* dated 10th April, 1978 under the caption "Expansion of Marketing Cooperatives in Big Way" ;

(b) if so, what is the factual position in regard to the various observations made therein ; and

(c) details of Central Sector Centrally sponsored schemes formulated/proposed to strengthen cooperative marketing during 1978-79 with details of provisions made norms for assistance, the coverage proposed by type of societies and tentative allocations state-wise and in particular for Maharashtra State ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) Yes, Sir.

(b) The news report appeared as preview of the National Congress of Marketing Cooperatives convened by the National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) and held on 11th and 12th April, 1978, and of the 19th Annual General Meeting of the NAFED held on the 11th April, 1978, at New Delhi. It highlighted some of the major points included in the Background Papers circulated for discussion in the Congress. The proceedings of the congress are under finalisation by its Convener, the NAFED.

(c) The National Cooperative Development Corporation is charged with the responsiblity of promoting and financing programmes for the development of cooperative marketing, processing, supplies a and storage in the country and provides assistance to various States under the Central Sector/ Centrally sponsored schemes concerning these activities. The details of the Central Sector/ Centrally Sponsored Schemes proposed to be implemented during the year 1978-79 along with the financial provisions made are as below :

S. No.	Scheme	Outlay proposed for 1978-79
		(Rs. in lakhs)
1.	Development of Cooperative Marketing, processing and storage programmes in under-developed States/U.T.	650
2.	Assistance to the National Agricultural Cooperative Federation of India Ltd. (NAFED) . . .	20

The Scheme at Sl. No. 1 covers only the cooperatively under-developed States of Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jammc & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Orissa, Rajasthan, Tripura, West Bengal, Sikkim and Nagaland and the U.Ts. of Andaman & Nicbar Islands, Arunachal Pradesh,

Lakshadweep and Mizoram. The basic objective of this scheme is to correct the regional imbalances in cooperative development and to provide a momentum to the pace of various programmes of cooperative marketing, processing and storage of agrircultural produce in these areas. The assistance under this scheme is being provided for strengthening of share capital base of cooperative marketing societies at various levels to enable them to expand their business operation and for construction of godowns for storing of various commodities handled by them. The State of Maharashtra, however, is not covered under this scheme as it is a co-operatively developed State. The State-wise tentative allocations are still being workedout. The norms of assistance for the cooperative marketing societies are given in the statement enclosed.

The scheme at S. No. 2 above provides for assistance to the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd., which is the Federation of All Co-operative Marketing Societies at the All India level, to enable it to further develop the export and inter-state trade in agricultural produce and other commodities, agricultural processing and agricultlural services.

Statement

Norms of Assistance for Cooperative Marketing Sotieties

S. No.	Objectives of the Schemes for development of cooperative marketing r	From NCDC to State Government	From State Government to Cooperative marketing societies
1	2	3	4
1	*Marketing*		
	Strengthening the share capital base of Marketing Societies.	Quantum of assistance will depend on requirement of each case.	Same to be passed on as clean or refundable share capital.
2	Transport vehicles . . .	(a) Tribal & Difficult Areas: 50% loan 25% subsidy 75%	(i) 75% of which not less than 50% as loan; and (ii) 25% as subsidy.
		(d) Other Areas : 50% loan.	
3	*Processing*		
	Small and medium sized processing units (including fruit & vegetables, cold storages and dairy units).	(a) Tribal & Difficult Areas : 60% loan 20% subsidy 80%	55% loan 20% share capital 20% subsidy 95% (Members : 5%)
		(b) Other Areas : 80% loan	60% loan 32% share capital 92% (Members : 7%).
4	*Storage*		
	Construction of godowns .	(a) States : 50. loan 25% loan 75%	50% loan 50% subsidy 100%
		(b) Union Territories 50% loan 50% subsidy 100%	

Agreement with Malaysia import of Oil

9373. SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state :

(a) whether S.T.C. has entered into an agreement for importing 60,000 tonnes of oil from Malaysia; and

(b) if so, terms and conditions of the import ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) Yes, Sir.

(b) The main terms and conditions of the contract for import of crude Palm Oil are as follows :

(i) Contract period—Feb. '78 to Jan. '79.

(ii) Qty.—60,000 MT+/—2% at the rate of 15,000 MT per calendar quarter.

(iii) Payment by Letter of Credit.

(iv) Price to be based onthe Malaysian Government gazetted price according to a set formula.

Restructuring of State Bank of India and its subsiadiaries.

9374. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether All India Manufacturers Organisation has submitted a memorandum urging for restructuring State Bank of India and its subsidiaries; and

(b) if so, reasons advanced by them and Governmen's reaction thereon ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Neither Government nor the Reserve Bank received any such memorandum.

(b) Does not arise.

Creation of new post of a liaison Officer in Allahabad Bank.

9375. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) is it a fact that new post of a Liaison Officer has been created in Allahabad Bank;

(b) if so, why ;

(c) is it also a fact that a person of 61 years old has been appointed against that post;

(d) if so, why; and

(e) what will be his terms of service, including perquisites ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). Allahabad Bank has reported that a post of Special Officer has been created by the Bank at Delhi for performance of certain special assignments in the area of deposi mobilisation, liaison and public relation and for handling certain specialised tasks at the regional office and zonal level as may be assigned to him from time to time.

(c) Yes.

(d) The Bank has stated that because of lack of adequate number of senior executives in the Bank having commensurate experience in the relevant field and necessary specialisation and contacts required for this temporary position promotion was not feasible and hence, a retired officer of one of the nationalised banks was appointed to the post.

(e) The Bank has offered him- contrac tual appointment for one year on a consolidated salary of Rs. 2,500/- p.m. The perquisites will be made available to him only in accordance with the provisions of the Pillai Committee Report.

Building of Allahabad Bank in Lucknow.

9376. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) is Government aware of the fact that the building of Allahabad Bank in Lucknow has been lying vacant for some years;

(b) if so, the reasons therefor and what was the estimated loss on that score;

(c) is it a fact that Bank is taking a building at Calcutta on rent;

(d) if so, the details thereof;

(e) how much total rent is paid by the bank to the building owners in one year

(f) has Government received any complaint about taking the buildings on unreasonable higher rents and making advances to the owners; and

(g) if so, the details thereof and what action has been taken by Government over it ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The Lucknow building was handed over by the contractors to the Allahabad Bank in November, 1977. After completion of partitions and other necessary arrangements, the bank occupied in April 1978.

(b) Does not arise.

(c) and (d). For additional requirements of space for its Head Office, the bank is considering a proposal to hire a building having a floor area of about 10,400 sq.ft. in Calcutta.

(e) During the year 1977 the bank has paid a total sum of Rs. 79·55 lakhs as rent to the owners of buildings hired by it both for offices and residences for its employees all over the country.

(f) and (g). Yes Sir, In December, 1977 Government received a complaint in which allegations were made that the Allahabad Bank had hired premises at exhorbitant rents particularly for its Stephen House and Wellesly Street Branches in Calcutta. On enquiry the bank has intimated that the premises were hired with its Board's approval and the rents settled are at the rate of Rs. 3·37 per sq.ft. for ground and mezzanine floors of the Stephen House Branch and at the rate of Rs. 2·50 per sq.ft. for the ground floor of the Wellesly Street Branch. These rents do not appear to be excessive according to the prevailing rates at these locations.

Import of Palm Oil

9377. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) how much Palm oil was imported in the last one year;

(b) on which dates the imports were allowed and on which dates the imports were stopped in the last one year;

(c) the names of the countries from where this oil was imported;

(d) has Government received any complaint about the import of this oil;

(e) if so, the details thereof; and

(f) what action has been taken by the Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) Information is available of imports upto October 1977. During January 1977, to october 1977. the total quantity imported was 3,23,829 M.T.

(b) Palm oil was put on the free licensing scheme for imports on 17th January, 1977. On 20th September 1977, refined palm oil for direct human consumption was taken out of the said scheme. On 13th January 1978 palm oil of all types excluding palmoleine was taken out of the free licensing scheme.

(c) Indonesia, Malaysia, the U.K., the U.S.A., Canada & Singapore.

(d) to (f). Under the free licensing scheme, private parties imported large quantities of refined, bleached and deodorised palm oil and sold it as vanaspati. Hence this variety of palm oil was first removed from the free licensing scheme, Later, to eliminate the same possibility arising out of imported palm oil of other varieties, palm oil of all types, but excluding palmolein, was taken out of the scheme. In the import policy for 1978-79, this has been canalised through the State Trading Corporation of India.

Insecured loans of Allahabad Bank

9378. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) is government aware of a report appeared in "Blitz" dated 18th March, 1978 with the heading "Unsecured loans pile up huge loot" regarding Allahabad Bank;

(b) is it a fact that C.B.I. came across a tape record containing conversation between Sanjay and Kamal Nath which mentions senior officials of State Bank of India and Allahabad Banks; and

(c) if so, whether Government propose to make thorough probe over the working of this Bank by an independent authority.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Reserve Bank of India is looking into the allegations contained in the article which appeared in Blitz dated 18th March, 1978.

Purchase of sugar for export purposes

9379. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is true that the sugar meant for export by State Trading Corporation was kept at Kandla port;

(b) whether same sugar was not exported and it was sold out at low rate; and

(c) how much loss occurred due to demurrage ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir.

(b) During 1977-78, 12,116 metric tonnes of sugar had to be stocked in S.T.C.'s godowns at Kanadla port which could not be exported because of the Government decision not to export sugar at a loss. Subsequently sugar lying in stock at Kandla and other ports was released for sale in the domestic market by the Government at a price of Rs. 345/- quintal exgodown for C and D Grade and Rs. 335/- quintal for E Grade to private parties and Rs. 335/- and Rs. 325/- per quintal respectively to cooperatives. This price was much higher than the prevailing international prices.

(c) No loss has been reported due to demurrage on shipments from Kandla port during 1977-78.

Proposal to develop tea industry

9380. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRI G. M. BANATWALLA:

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to develop Tea Industry in the country;

(b) whether any plan has also been chalked out for cultivation an additional area for tea during the next three years;

(c) if so, the details thereof; and

(d) additional funds allocated for the purpose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) It is proposed to bring an additional area of approximately four thousand hectares under tea cultivation annually during the next five years.

(d) The Tea Board has been provided with a revolving fund amounting to Rs. 4·60 crores for financing loans for bringing additional areas under tea for re-plantation. The loans are sanctioned by the Tea Board under their Tea Plantation Finance Scheme. Loans are also available from institutional sources like Agricultural Refinance and Development Corporation, the quntum being dependent on the size of requirement and viability of the production programme.

Decline in export of Indian Tobacco

9382. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a decline in the export demand for Indian tobacco; and

(b) what steps Government propose to take to increase export of tobacco ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Against a quantity of 80·10 million kilograms valued at Rs. 96·62 crores exported during 1976-77, the exports of unmanufactured tobacco during April, 1977 to February, 1978 are estimated to have been 71·19 million kilomgrams valued at Rs. 105·37 crores. The export demand during 1978-79 appears at present to be somewhat less from our major buyers such as U.K., U.S.S.R. and Japan.

(b) The Tobacco Board is pressing the monopoly purchasers like U.S.S.R., Iraq, Bulgaria, Italy, G.D.R., Czechoslovakia, etc., to increase their imports from India. The Board is also participating in Trade Fairs abroad. It is also likely to sponsor a trade delegation to countries in the European Economic Community.

Malaysian firms declared insolvent with whom S.T.C. entered into contract for Palm oil purchases.

9383. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of COMMERCE,

CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation is likely to lose a substantial amount of money as a result of insolvency declared by a firm in Malaysia with whom it has struck a contract for the purchase of palm oil;

(b) what steps Government propose to take to retrieve the amount;

(c) the reasons why the S.T.C. entered into a big contract with a single firm for the supply of palm oil; and

(d) what other scurces it proposes to explore to purchase palm oil now and what would be likely difference of pric e on the total quantity of 30,000 tonnes of palm oil ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) to (d). The S.T.C. have not signed any deal with any foreign firm for supply of 30,000 tonnes of palm oil. However, 3 separate purchase transactions for crude palm oil were made by the S.T.C. from a Malaysian firm, M/s Palm & Vegetable Oil as follows:—

(*i*) 10,000 MT for December, 1977, shipment.

(*ii*) 5,000 MT for February, 1978, shipment

(*iii*) 5,000 MT for March, 1978, shipment.

Letter of Credit was opened only for 10,000 MT for December, 1977, shipment. In view of the default of the party, it was decided not to open Letters of Credit for the other two transactions. The firm was a registered supplier of the S.T.C. and had satisfactorily executed contracts entered into with them in the past. The above contracts were entered into with the firm on the basis of normal purchase procedure of S.T.C. of calling global offers. S.T.C. is taking the matter of arbitration as per provisions of International Regulations governing such transactions. There is no information available with S.T.C. that the firm has declared itself insolvent.

Subsequent to the contracting with this firm, S.T.C. has finalised purchase of 60,000 MT of crude palm oil from M/s FELDA, Malaysian Government company on a long term basis spread over a period of February, 1978 to January, 1979. A net advantage has accrued to the S.T.C. as compared to the prices at which purchases were made from the party which has defaulted. Further, no purchases were made at higher rates resulting in loss to S.T.C.

Trade delegations from Canada for talks to explore joint ventures

9384. SHRI JANARDHANA POOJARY:

SHRI YASHWANT BOROLEL.
SHRI MOHINDER SINGH SAYIANWALA:

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether a trade delegation from Canada visited our country during April, 1978, and held talks to explore joint ventures; and

(b) if so, the details thereof and conclusions drawn ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir.

(b) Canadian Delegation, which was essentially comprised of marketing officers of Canada's Trade Department, held discussions with various departments of the Govt. of India and public sector undertakings. As a result of these discussions, focal points to exchange information and to pursue possibilities to promote industrial cooperation and third country joint ventures have been identified. Through these focal points further action will be taken by the concerned parties in pursuance of these discussions.

Routes Operated by Air India all over World

9385. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleasdd to state:

(a) the number of routes operated by Air India all over the World;

(b) the number of routes which are uneconomic;

(c) the reasons for operating the uneconomic routes;

(d) whether recently any agreements have been arrived with British Airways to start some new flights; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) During 1977-78, Air-India operated 14 routes on its world-wide network including freighter operations on two routes.

(b) and (c). The only route, viz., India-Bangkok operated by Air-India from April 1977 to October 1977, proved uneconomical and was discontinued from November, 1977.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Amount of money allotted to State Government of Orissa

9386. SHRI PRADYUMNA BAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) in detail the amount of money allotted to the State Government of Orissa, department-wise during the last financial year (1977-78); and

(b) the amount of money released from the Centre and the amount spent by the Government of Orissa ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). The Central assistance for the State Plans is allocated in the form of block loans and grants for the State Plan as a whole and is not related to any particular sector of development, project or department. For 1977-78, the Annual Plan outlay for Orissa, including additional outlay for flood relief, amounted to Rs. 163·67 crores. For financing this outlay, Central assistance amounting to Rs. 83·52 crores was allocated. The State Government reported anticipated expenditure of Rs. 164·69 crores. Central assistance amounting to Rs. 82·25 crores was released to the State Government provisionally, subject to adjustment, on receipt of audited figures of expenditure.

Recovery of arrears of Income-tax of Dalmia Dairy Industries Limited

9387. SHRI K.LAKKAPPA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that on 25th January, 1978 the Income Tax authorities recovered by force from the Bank of India, New Delhi arrears of Income Tax outstanding against Dalmia Dairy Industries Limited ;

(b) whether under pressure from Income-tax authorities the Bank transferred money from Company's account in U. K. on their own, and made payment to the Income-tax authorities on the evening of 25th January, 1978 after close of banking hours ;

(c) whether this was done to aviod any adverse judgement by the Delhi High Court which had fixed 27th January, 1978 for disposing the appeal filed by the Company in the matter ;

(d) what steps have been taken by Government to investigate this matter and take suitable action against the concerned officers of Income-tax Department and Bank of India Limited; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE : (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) and (b). In respect of the outstanding tax demand for the assessment years 1964-65, 1965-66 and 1973-74 M/s. Dalmia Dairy Industries Ltd. had furnished a guarantee from the Bank of India, Janpath Branch, New Delhi for payment of a sum of Rs. 42·52 lakhs. This guarantee was given by the Bank at the specific request of the company for which the Bank had earmarked a lien on corresponding amount in Deposit Account of the Company with their London Branch. As the company did not pay the amount within the time allowed the Income-tax Officer asked the Bank on 25th January, 1978 to discharge its liability under the guarantee. The Bank credited the Government account with Rs. 42·52 lakhs on 25th January, 1978, in the ordinary course of business.

(c) No. Sir.

(d) and (e). In view of the replies to parts (a), (b) and (c) above, the question of taking action against the officers of Income-tax Department and Bank of India does not arise.

Financial position of States

9388. SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the financial position of the States of Bihar, Gujarat, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh was so bad during the year 1977-78 that they have asked the Centre for about Rs. 700 crores in loans and grants to make both ends meet; and

(b) if so, the full facts regarding the same State-wise ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATAL) : (a) After finalisation of the Annual Plan 1977-78, there was a serious erosion in the resources of these State due to various factors such

as grant of tax concessions and relief to employees, undertaking of additional non-Plan financial liabilities and shortfall in mobilization of additional resources. After discussions with the representatives of these State Governments it was assessed that the gap in their resources for financing the Plan outlay for 1977-78 was likely to be around Rs. 650 crores. These States approached the Central Government for additional assistance not only for covering the gaps in resources but also for various other purposes.

(b) The following amounts of advance Plan assistance were released to the above named States in 1977-78 for covering gap in resources :

State	Advance Plan assistance to cover gap in resources related in 1977-78
	(Rs. in crores)
1. Bihar . .	19·50
2. Gujarat .	9·50
3. Haryana	15·50
4. Rajasthan .	23·00
5. Madhya Pradesh	6·00
6. Orissa . .	29·50
7. Uttar Pradesh	102·50

These States were advised to effect economies and observe strict financial discipline and to cover the remaining gap by their own efforts.

पिल्लै समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

9389. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक अपने कर्मचारियों के स्टैंडर्ड वेतनमानों के बारे में पिल्लै समिति की सिफारिशों को क्रियान्विति करने में असफल रहे हैं ;

(ख) पिल्लै समिति की सिफारिशों को क्रियान्विति करने वाले बैंकों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार इन सिफारिशों में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) सब राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उन सिफारिशों की क्रियान्विति कब तक की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं । राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रिपोर्ट को लागू करने के कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र ।

(ग) बैंकरों के एक अध्ययन दल द्वारा फरवरी, 1977 में सुझाये गये कुछ संशोधन सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं । इस समय कोई अन्य संशोधन विचाराधीन नहीं हैं ।

(घ) इंडियन बैंक्स एसोसियेशन द्वारा शेष 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के परामर्श से ऐसे उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि ये बैंक इन सिफारिशों को यथाशीघ्र लागू कर सकें ।

Import of Raw Material for Colour Films

9390. SHRI GANANANTH PRADHAN : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state :

(a) the quantity of colour raw stock imported by film producers during the last three years for producing colour films in India;

(b) the number and names of coloured films exported from India during the last three years and the amount of foreign exchange earned therefrom; and

(c) Steps taken by Government to stop import of raw materials for colour films and making it available from indigenous sources ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERA-

TION (SHRI ARIF BEG) : (a) Import of colour film raw stock is canalised through Film Finance Corporation. The number of rolls (negative and positive) imported during 1975-76, 1976-77 and 1977-78 were 1,94,600, 2,12,400 and 2,13,300 respectively.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) A major part of the domestic requirements has been met by the production of Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd. from imported Jumbo rolls. This public sector company is also exploring the possibilities to manufacture such raw stock.

Exports and Imports

9391. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the last quarter every year is generally the peak activity period for exports and imports;

(b) the figures of exports outside and imports into the country made from 1st January, to 30th March, 1978 and the comparative figures in the previous two years ;

(c) the figures for each of the quarters ended 30th June, 30th September and 31st December, 1977 ; and

(d) the reason for a slackness in exports in the last quarter of 1977-78?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) Yes, Sir.

(b) Figures for the last quarter of 1977-78 (i. e. January-March, 1978) so far are not available. The comparative figures for the last quarter of the previous two years are as given below :

Quarter	Exports	Imports
	(Rs. crores)	(Rs. crores)
Jan.-March, 1976	1328	1354
Jan.-March, 1977	1510	1302

(c) Based on provisional data, the quarterly trend in foreign trade is indicated below :

Quarter	Exports	Imports
	(Rs. Crores)	(Rs. Crores)
April-June, 1977	1224	978
July- Sept., 1977	1361	1438
October- Dec., 1977	1367	1502

(d) The growth rate of exports during the year 1977-78 has been slower on account of various factors such as recession in world trade, protectionist policies adopted by developed countries, fall in dollar value and in the case of certain mass consumption items government's deliberate policy to regulate their exports in the interest of domestic market.

Agricultural Incomes under Direct Taxation

9392. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there is renewed thinking recently on the part of Government to bring agricultural incomes under direct taxation;

(b) if so, broad details thereof; and

(c) whether the State Governments have been consulted in the matter and their reaction thereon ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c). It is stated in the Draft Five Year Plan 1978-83 that, in view of the massive investments proposed to be made in agriculture and rural works of various kinds, earnest efforts must now be made to recover a part of the increased rural incomes for re-investment in the public sector. It is further stated that, in view of the evidence of unequal distribution of rural assets (especially land), the equitable way of doing this would be through appropriately structured taxes on agricultural income or progressive surcharges on land revenue. The draft Plan was circulated to the States and was discussed in the meeting of the National Development Council on the 18th and 19th March, 1978. It was agreed that the Planning Commission would hold discussions with the States in regard to the details of the draft Plan especially the State Plans and the related matters.

Payment of Income Tax by Shri Kamlapati Tripathi

9393. SHRI MANOHAR LAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether penal proceedings under Income Tax Act, Wealth Tax Act, and other provision of law, are not attracted in late filing of returns and payment of tax advance tax and C.D.S. in case of formerly Minister of Congress Government as no such proceedings were taken against Pt. Kamlapati Tripathi formerly Minister, who actually filed returns for 1974-75 to 1977-78 on 4th July, 1977; and

(b) what are the complete details of facts and reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : (a) and (b). Shri Kamlapati Tripathi has filed returns of income for the assessment year 1974-75 to 1977-78 in the Status of 'individual' on 4-7-77.

The assessment for the assessment year 1975-76 has been completed, resulting in refund. No penalty for late filing of return was, therefore, leviable. However, a show cause notice for non-payment of compulsory deposit has been issued.

As the return for the Assessment year 1974-75 was out of time, a notice under section 148 of the Income-tax Act, 1961 has been issued initiating the assessment proceedings. The assessments for the assessment years 1976-77 and 1977-78 are pending. Applicability of penal provisions, will be considered while completing the relevant assessments.

Memorandum from inspectors of Central Excise

9394. DR. VASANT KUMAR PANDIT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there is a great discontentment amongst the Inspectors of Central Excise who are stagnating in the inspectors Cadre for more than 25 years ;

(b) whether the Inspectors of Central Excise had observed "Demands Week" from 2nd January 1978 to 7th January 1978 by sporting Black Badges showing their demands on the same and have also submitted memorandum to the Government through their respective Collectors; and

(c) what effective steps have been taken to redress their grievances and what further steps are likely to be taken in near future for ameliorating their service conditions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) The time taken for an Inspector of Central Excise to be empanelled for promotion as a superintendent of Central Excise (Group-B) varies at present from about 19½ years to about 31 years in different Collectorates. There has been some discontent on this account amongst the Inspectors of Central Excise and more particularly in those Collectorates where promotion has been slower.

(b) Yes, Sir.

(c) One measure which has helped to relieve the stagnation amongst Inspectors to some extent is Government's decision to sanction a substantial number of posts of Superintendent of Central Excise (Group-B) for implementation of Governments' decisions on the recommendations of the S.R.P. (Review) Committee. 545 out of these posts have already been filled up by promotion of Inspectors of Central Excise and another 383 posts are proposed to be filled up. Another measure taken by Government on the basis of representations by the Inspectors and their Federation is to give up the proposal to fill 30% of the additional posts of Superintendents (Group-B) through a limited competitive examination. Yet another measure is the removal of discrimination between Customs and Central Excise officers in the matter of special pay on deputation to Directorates under the Central Board of Excise and Customs.

It will be seen from the above that Government have been considering the grievances of the Inspectors with due sympathy and taking remedial measures wherever possible.

सरदार बल्लभ भाई पटेल शुगर इंडस्ट्रीज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, धोराजी (गुजरात) की ओर से अभ्यावेदन

9395. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री 16 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4350 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरदार बल्लभ भाई पटेल शुगर इंडस्ट्रीज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, धोराजी, जिला राजकोट

(गुजरात) ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली को, चीनी मिल के विकास तथा कार्यकरण हेतु ब्याज-मुक्त अथवा कम ब्याज-दर पर 2 करोड़ रुपये का ऋण देने के बारे में 21 जनवरी, 1978 को, तर्को तथा तथ्यों सहित पुनः एक अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि चीनी मिल के बन्द हो जाने पर छः प्रकार से हानि होगी और यदि हां, तो ये छः प्रकार क्या है ; और

(घ) उपरोक्त (क) भाग में वर्णित मांगों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार हैं तथा यह कार्यवाही कब की जायेगी और क्या होगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) को भेजे अपने अभिवेदन में समिति ने इन बातों पर बल दिया है :—

(i) चूंकि पिछले दो वर्षों के दौरान अच्छी वर्षा हुई है, अतः कम से कम और दो वर्षों में सूखे की आशंका नहीं है और गन्ने की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा ;

(ii) इस समय कारखाने के इर्दगिर्द की खांडसारी यूनिटें प्रतियोगी के रूप में सामने नहीं आ सकती है, क्योंकि इनमें से 30% यूनिटें बीमार है और समिति गन्ने के लिए 141 रु० प्रति मीटरी टन दे रही है, जबकि खांडसारी यूनिटों द्वारा 110 रु० प्रति मीटरी टन दिए जा रहे है ; और

(iii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से मिली टिप्पणी के आधार पर चीनी मिल की अर्थ-व्यवस्था में संशोधन किए गए है ।

(ग) चीनी मिल के बन्द हो जाने पर जो परिणाम होंगें वे नीचे दिए गए है :—

(i) कम से कम 1000 मजदूर बेकार हो जायेंगे ;

(ii) भारत सरकार को लगभग 60 लाख रुपये वार्षिक हानि होगी, जो अन्यथा उत्पादन शुल्क के रूप में प्राप्त हो रहे है ;

(iii) गुजरात राज्य सरकार को गन्ने के क्रय कर के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख रुपये की हानि होगी ;

(iv) हजारों किसानों को खांडसारी यूनिटों को कम मूल्य पर गन्ना देने से धन की भारी हानि होगी ;

(v) गन्ने की बहुत बड़ी मात्रा गुड़ (जगरी) बनाने के उपयोग में लाई जायेगी । फलस्वरूप किसान केवल गन्ने की उत्पादन लागत भी वसूल नहीं कर पायेंगे और वे बिलकुल बरबाद हो जायेंगे ; और

(vi) राष्ट्र को लाखों क्विंटल चीनी के उत्पादन की हानि होगी ।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने यह मामला गुजरात सरकार को भेजा था । राज्य सरकार ने चीनी मिल के सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है और वह अपनी रिपोर्ट 6 महीनों के अन्दर प्रस्तुत करेगी । रिपोर्ट मिलने पर सरकार चीनी मिल के भविष्य के बारे में अंतिम निर्णय करेगी । राज्य सरकार के माध्यम से चीनी मिल को वित्तीय सहायता देने के अनुरोध पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा केवल उक्त रिपोर्ट के आधार पर राज्य

सरकार की सिफारिशें मिलने पर ही विचार किया जायेगा ।

Payment of Money by Government as Subsidy

9396. SHRI YASWANT BOROLE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount of money which the Government had to pay as subsidies on different counts in the last one year;

(b) what are the various areas where subsidies are given and the reasons for the same; and

(c) whether there are certain areas where subsidies have come to stay and rather have increasing trends and the action that is being considered to reduce the same ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b). Information about the subsidies given by Central Governments is available in the Annual Budget Documents of the Central Government and Railways.

(c) Not all subsidies have shown increasing trends. It is the Government's policy to review all subsidies and to reduce them progressively. In doing so the effects of such economies on commodity prices and the cost of living would be borne in mind.

Exporters included in the Directory of Exporters from India

9397. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) how many exporters are included in Directory of 'Exporters from India' published by Federation of Indian Export Organisations and what is the criteria for including name of exporters in this directory and how many of exporters included in it were merchants small industries and large industries;

(b) how many of exporters included in Directory of Exporters issued by Department of Commercial Intelligence and Statistics (as per reply to para (c) of Unstarred Question No. 3414 dated 17th March 1978) at end of I and III plans and on 1st January 1978 were (1) Indian firms (2) Foreign firms (3) Mercnants (4) small industries (5) large industries; and

(c) what are the details of information promised to be laid on the Table of the House in reply to part (e) of Unstarred Question No. 3414 dated 17th March, 1978 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) The total number of exporters included in the latest issue of the Directory of 'Exporters from India' of the Federation of Indian Export Organisations is 1189.

Names of exporting firms included in the Directory of FIEO are those of (i) Members of FIEO or Members of FIEO's constituents and (2) firms desirous of becoming members on payment of a nominal fee.

The names are not classified in the Directory on the basis of merchant small industries and large industries.

(b) This information is not maintained by Department of Commercial Intelligence and Statistics Calcutta.

(c) The information regarding number of merchant exporters, manufacturer exporters and SSI Units among the recognised Export Houses as on 1-1-1978 is being collected and will be laid on the Table of the House.

Allegations against Chairman of United Commercial Bank

9398. DR. BIJOY MONDAL :
SHRI MADHAV PRASAD TRIPATHI :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government's attention has been drawn towards the allegations against the Chairman of United Commercial Bank published in Panchajanya Hindi weekly dated 23rd March, 1975;

(b) whether it is a fact that during the same period a number of Members of Parliament had submitted allegations against the Chairman, United Commercial Bank to the then Prime Minister and Finance Minister;

(c) if so, has any enquiry been made in those allegations;

(d) if so, with what results;

(e) if not, the reasons therefor and whether the Government now propose to institute any enquiry;

(f) if it is a fact, that inspite of all the allegations the Chairman, United Commercial Bank was granted three years' extension from 1st April, 1975;

(g) was this extension granted on the recommendation by one Ex-Chief Minister and some political leaders; and

(h) if so, how the Government now propose to rectify the irregularity?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H.M. PATEL) : (a) to (e). Government have seen the news item referred to by the Hon'ble Members. During the material time certain allegations against the Chairman of the United Commercial Bank were also brought to the notice of Government. These allegations were looked into and found to be without any basis.

(f) to (h) . Shri V. R. Desai was reappointed as Chairman and Managing Director of the United Commercial Bank with effect from April 1, 1975 by the Central Government after consultation with the Reserve Bank according to the legal provisions.

Foreign orders on projects Equipments Corporation

9399. SHRI SUKHENDRA SINGH: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) the names of the countries which had placed orders during the years 1976-77 and 1977-78 with the Indian Projects and Equipments Corporation for the supply of diesel engines manufactured in the Railway Diesel Engine Workshops; and

(b) the number of engines supplied to each of those countries during that period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) and (b) . During 1976-77 and 1977-78, no order was placed by any country with the Projects and Equipment Corporation of India for supply of diesel engines manufactured by the Indian Railways. A contract for supply of 15 Diesel Electric Locomotives manufactured by Indian Railways was entered into with Tanzania in September, 1975. The deliveries made to Tanzania against this contract are as follows:—

1975-76 . Two Nos.

1976-77 . Four numbers

1977-78 . Nine numbers

Terms of office of Chairman of non-Nationalised Banks

9400. SHRI DHIRENDRANATH BASU:
SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the terms of office of a number of Chairman of non-nationalised banks are going to expire soon or have already expired, against whom cases of corruption. favouritism, nepotism and mal-administration are lying pending:

(b) if so, the names of such Chairmen and the banks concerned; and

(c) the policy of Government with regard to giving extentions time and again to the Chairman of non-nationalised banks?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H.M. PATEL) : (a) and (b). During the period January 1, 1978 to June 30, 1978 the term of office of the under noted Chairman of non-nationalised banks expired or is due to expire:

1. Shri M.L.Inasu	Purbanchal Bank Ltd.
2. Shri K.S.N. Adiga .	Karnataka Bank Ltd.
3. Shri K.C. Jain .	Naini Tal Bank Ltd.
4. Shri D.A. Dewan	Miraj State Bank Ltd.
5. Shri B.R. Shah .	Bareilly Corporation Bank Ltd.
6. Shri P.V. Seshagiri	Bharat Overseas Bank Ltd.
7. Shri M.N. Mehrotra	Kashi Nath Seth Bank Ltd.
8. Shri M. Sunder Ram Shetty	Vijaya Bank Ltd.
9. Shri Inderjit Singh	Punjab & Sind Bank Ltd.
10. Shri D. Varthamanan	Lakshmi Vilas Bank Ltd.

Reserve Bank of India have reported that complaints of corruption, favouritism, nepotism, maladministration etc. are received by them from time to time against almost all private sector banks and are looked into by them.

(c) Appointments/reappointments of the Chairmen of non-nationalised banks are made by the respective Boards of Directors. Under the statute, each such appointment, however, has to be approved by the Reserve Bank. Before according this approval the Reserve Bank takes into consideration all relevant facts.

12.23 hrs.

MR. SPEAKER : Papers to be laid on the Table— Shri H.M. Patel.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani) : I am on a point of order.

MR. SPEAKER : No, no. I got it at 10·35 A.M. I am considering it. You cannot raise it until I permit you.

SHRI G. M. BANATWALLA : I am merely raising a point of order quoting your rule 222 and not discussing the merits of the notice of the breach of privilege that I have given. I request you to please check it up.

MR. SPEAKER : I am checking it up. I got it at 10·35 A.M.

SHRI G. M. BANATWALLA : This is a particular point of order. I am quoting rules 222 and 223 and making a submission for your consideration. I am not here discussing the merits of the breach of privilege notice given by me against the Education Minister. Sir, if you look to rule 222 about the notices with respect to breach of privilege, you will find that the spirit of this rule 222 is to see that the questions involving breach of privilege by any Minister are raised in the House as promptly as possible and in order to see that they may not, because of the lapse of time, become redundant. Now this is a particular point. The Education Minister made a statement with respect to Aligarh Muslim University yesterday. He had misled the House about the persistent demand....

MR. SPEAKER : No, no, you are going into the facts of the case.

SHRI G.M. BANATWALLA : You listen to me. You give your ruling and I shall abide by that.

MR. SPEAKER : I am listening to you. I cannot give the ruling because it is under examination. It came to me at 10·35 A.M.

SHRI G.M. BANATWALLA : I am raising this point of order under rule 222. You just consider the implication of it and give the ruling whatever you like and I shall abide by your ruling, no doubt as a disciplined Member over here. I say yesterday Dr. Pratap Chandra Chunder, the hon. Education Minister, misled this House saying that the demand had been for the restoration of the historic character....

MR. SPEAKER : Again you are going into the facts of the case. Your attempt is to go into the facts of the case and mention them.

SHRI G.M. BANATWALLA : I am not going into it.

MR. SPEAKER : This matter has been considered.

SHRI G.M. BANATWALLA : You listen to me.

MR. SPEAKER: I am not allowing that. Now you cannot go into the facts of the case. I have not gone into it and therefore you cannot go into them.

SHRI G.M. BANATWALLA : I am not stating the facts.

MR. SPEAKER : Now you are again and again going into the facts of the case. There is nothing like that. Rule 222 has been interpreted a number of times here.

SHRI G. M. BANATWALLA : Under rule 222, I am entitled to raise this question.

MR. SPEAKER : No; not until I permit you.

SHRI G.M. BANATWALLA : Because his statement was that....

MR. SPEAKER : Rule 222 does not permit you until my consent is obtained. No please. You are trying to disobey my orders. I am giving the ruling that you are not allowed. I have over-ruled your point of order. Don't record.

*(Interruptions)***

**Not recorded.

MR. SPEAKER : Now, papers to be laid on the Table....

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Sir, I want to make a submission. I have given notice under rule 377. News has appeared today that yesterday near the Tughlaqabad Railway Station there was a clash between railway employees and members of a marriage party....

MR. SPEAKER : It is being considered.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Sir, I have given notice under rule 377 about the decision of the American Government to send peace corps to India....

MR. SPEAKER : It is being considered.

Papers to be laid on the Table.

12.26 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 66 DATED 24-2-78

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : on behalf of Shri H. M. Patel, I beg to lay on the Table a statement (i) correcting the reply given on the 24th February, 1978 to supplementary question by Shri Arjun Singh Bhadoria on Starred Question No. 66 regarding steps to realise arrears of taxes and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply. [*Placed in Library. See* No. LT-2232/78].

TEA (REGISTRATION OF DEALERS AND DECLARATION OF STOCKS) ORDER, 1978 & ANNUAL REPORT OF I.S.I. FOR 1976-77

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Tea (Registration of Dealers and Declaration of Stocks) Order, 1978 (Hindi and English versions), published in Notification No. S.O. 271(E) in Gazette of India dated the 15th April, 1978 under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See* No. LT-2233/78].

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Standards Institution, New Delhi for the year 1976-77. [*Placed in Library. See* No. LT-2234/78].

12.27 hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

FOURTH REPORT

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Sir, I beg to present the Fourth Report of the Committee on Papers Laid on the Table.

12.27½ hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) CENTRALLY SPONSORED RURAL LINK ROADS SCHEME

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं । केन्द्र प्रवर्तित रूरल लिंक रोड्स योजना 1977–78 के लिए प्रारम्भ की है किन्तु दुःख की बात है कि इस योजना को जिस प्रकार से चालू रखना चाहिए था, केन्द्र सरकार ने चालू नहीं रखा है और इस कारण अनेक राज्यों को काफी कठिनाई भी अनुभव करनी पड़ेगी ।

भारत सरकार, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने वर्ष 1977–78 में ग्रामीण पहुंच मार्गों की एक केन्द्रीय योजना का शुभारम्भ किया है । इसके अनुसार तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स देते हुये उन्होंने कहा कि लगभग 1500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ा जाये । ऐसे किसी एक पहुंच मार्ग की लम्बाई पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये । इन सड़कों के माध्यम से ग्रामीणों की कृषि उपज सुगमता से बाजार में पहुंचेगी और कृषक समृद्ध होंगे । सभी राज्यों को वर्ष 1977–78 में आवंटन दिया गया । मध्य प्रदेश को कुछ आवंटन 1.80 करोड़ रुपए मिला । भारत सरकार ने यह संकेत किया था कि योजना वर्ष 1978–79 में भी चालू रहेगी

[श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय]

और प्रथम वर्ष की प्रगति देख कर अगले वर्ष राज्य को अधिक अनुदान दिया जा सकेगा।

तदनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर लम्बाई की और 6 करोड़ रुपए लागत की सड़कों की स्वीकृति दी गई जिनका निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से आदेशित किया गया। यह इस उद्देश्य से किया गया कि जब वर्ष 1978–79 में बढ़ा हुआ अनुदान प्राप्त हो तो उसका पूर्ण उपयोग हो सके।

परन्तु मार्च, 1978 में भारत सरकार ने सूचित किया कि 1 अप्रैल, 1978 के बाद इस योजना के अधीन कृषि-मंत्रालय से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होगा। यह कहा गया कि प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की बढ़ी हुई वार्षिक योजना-सीमा में यह कार्यक्रम संचालित होना चाहिये। इस निर्देश से प्रदेश सरकार के सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई है। लोक निर्माण विभाग के अपने कार्यक्रम हैं और उनकी वार्षिक योजना-सीमा उनके बढ़े हुये कार्यों के लिए ही पर्याप्त है। ग्रामीण लिंक रोडस को केन्द्रीय योजना के इस बढ़े हुये उत्तरदायित्व को अनपेक्षित रूप से लोक निर्माण विभाग की योजना में शामिल किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। यह समीचीन होता कि भारत सरकार पूर्व नोटिस देकर सूचित करती कि उनके संकेतों के अनुसार वर्ष 1978–79 में अनुदान मिलेगा परन्तु भविष्य में नहीं। ऐसा होने पर प्रदेश शासन कार्यक्रम को योग्य रूप से समायोजित करने की स्थिति में रहता। भारत सरकार ने यह छूट दी है कि वर्ष 1977–78 के आवंटन का उपयोग जून, 1978 तक किया जा सकता है। परन्तु इससे समस्या का हल नहीं होगा।

प्रदेश शासन इस अनपेक्षित केन्द्रीय निर्णय से संकट की स्थिति में पहुंच गया है। उसने जो निर्माण कार्य हाथ में लिए हैं उनके अपूर्ण रहने की सम्भावना बन गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि केन्द्र इस पर पुनर्विचार करे।

अतः सार्वजनिक महत्व के इस विषय पर कृषि मंत्री स्थिति स्पष्ट करते हुये तथा आश्वस्त करते हुये कि प्रदेश को समुचित सहायता दी जाएगी वक्तव्य देने का कष्ट करेंगे और घोषणा करेंगे कि ग्रामीण लिंक रोडस योजना ठीक कार्यान्वित होगी।

(ii) REPORTED SHARP FALL IN PRICE OF SHORT STAPLE COTTON IN GUJARAT

श्री मोती भाई आर० चौधरी: (बनासकांठा) : मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के बारे में पन्द्रह दिन पहले 377 के अधीन मामले को उठाया था लेकिन मुझे समय पर इस के बारे में कहने का मौका नहीं मिला। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे समय पर लोक हित के विषय को उठाने का मौका दिया जाना चाहिये था। ये जो अविलम्बनीय महत्व के विषय उठाये जाते हैं उनके बारे में तुरन्त कुछ न कुछ कार्यवाही करनी होती है।

मैं आपकी अनुमति से निम्न विषय जो अविलम्बनीय लोक महत्व का है, उठाना चाहता हूं :

MR. SPEAKER: Just to correct you, I allowed it last week but you were absent: and now you are blaming us for not giving you an opportunity earlier. You were absent on 2nd May and now you are turning the table on us.

श्री मोती भाई आर० चौधरी: यह सिमेंट के बारे में था। मैंने पहले से लिख कर दिया था।

MR. SPEAKER: On this very matter we allowed you.

श्री मोती भाई आर० चौधरी : वह रुई के बारे में नहीं था । सिमेंट के बारे में था । मैंने लिखकर दिया था । मैंने लिख कर दिया था कि दो तारीख को मैं नहीं रहूंगा इसलिए मुझे तीन तारीख को मौका दिया जाये । मैंने जो आप के पास सबमिट किया था उसमें लिखा था कि तीन तरीख को मुझे मौका दिया जाये । ऐसे मैं नहीं करता हूं ।

अब मैं इस मामले पर जो रुई के बारे में हैं कुछ कहना चाहता हूं । गुजरात में शार्ट स्टेपल रुई का भाव एक दम घट जाने के कारण किसान का तैयार किया हुआ माल नहीं बिक रहा है जिसका रेट 1977 जून में 4000 रुपए से ज्यादा था अब इसका भाव 2500 रुपए से कम हो गया है । फिर भी इनका माल लेने वाला कोई नहीं है । मेरे विचार में जिस समय देश में शार्ट स्टेपल रुई की कमी थी उसी समय बाहर से विस्कोस फाइबर—आयात करने की छूट दी गई थी । वह छूट अब भी जारी है । ऐसी स्थिति में भी यह छूट जारी है । इतना ही नहीं उस पर जो एक्साइज डयूटी थी वह दूर कर दी गई हैं, इसलिए किसान को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है ।

इसलिए सरकार को चाहिये कि वह विस्कोस फाइबर का आयात तुरन्त बन्द कर दे नहीं तो काटन कारपोरेशन की ओर से किसानों का माल उचित कीमत पर यानि उत्पादन खर्च जितना आता है उस कीमत पर खरीदें जाने की व्यवस्था करे और यह शार्ट स्टेपल रुई जिसका भाव बहुत घट गया है उसके निकास की छूट दे ताकि किसान का उत्पादन किया हुआ माल बिक सके और उसको ठीक मूल्य मिल सके ।

काटन कारपोरेशन की ओर से कई केन्द्रों पर खरीद का काम शुरू हुआ है लेकिन बहुत सी जगहें बाकी बच गई हैं जहां शुरू नहीं हुआ है । गुजरात में कई जिलों में माल तैयार होता है । मैं चाहता हूं कि हर जगह पर खरीद की व्यवस्था की जाय ।

अन्त में मैं चाहता हूं कि विस्कोस फाइबर का आयात तुरन्त बन्द कर दिया जाना चाहिये क्योंकि देश में शार्ट स्टेपल रुई काफी मात्रा में उपलब्ध है ।

(iii) REPORTED STRIKE BY EMPLOYEES OF INSTRUMENTATION LTD.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : I would like to draw the attention of Government to the following matter of public importance.

The 46 skilled workers and technicians of the Instrumentation Limited, a Government of India enterprise with the collaboration of USSR, under the Ministry of Industry, are on strike and hunger-strike since 10-4-78 at Patratu Thermal Power Station, Bihar, Protesting against the retrenchment of 30 workers working there continuously for more than three years. This retrenchment of technicians and skilled workers is completely uncalled for as there is work in the Instrumentation Ltd. all over India and in Patratu in particular as this particular establishment is expanding all over the country, and the workmen are ready to go anywhere for jobs. I may also point out the fact that by retrenchment the Government is losing skilled hands trained for the purpose of instrumentation for years.

It may be noted that the same type of workers under BHEL under the same Ministry of Industry were made regular as per the agreement dated 8th April, 1978 in Delhi and there is no reason why different standards should be pursued in the case of workers of Instrumentation Ltd., and if this is allowed, the agitation is bound to spread to all other sites of work of Thermal Plants where the Instrumentation Ltd., is working. So, the Government should at once intervene in the matter, withdraw the retrenchment order and solve the crisis arising out of the strike and hunger strike for the just cause.

(iv) GANGES PRINTING INK FACTORY LTD., HOWARAH (WEST BENGAL).

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Mr Speaker, Sir, with your permission, under Rule 377 I rise to plead with the Government of India to take over the Ganges Printing Ink Factory Ltd. This factory has been closed for the last seven months and the payment of salaries to the workers has not been made since October, 1977. The Government of West Bengal has already forwarded to the Government of India a proposal for taking over the concern. It is urgently necessary that the Ministry of Industry, Government of India, do take into consideration the situation prevaling in the Ganges Printing Ink Factory, Howrah, West Bengal and do take expeditious steps for opening the same.

(v) REPORTED DETERIORATION IN LAW AND ORDER SITUATION IN DELHI

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सदन और सरकार का ध्यान दिल्ली की बिगड़ती हुई शान्ति और व्यवस्था की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । अकेले 2-5-78 के दिन छः ऐसे केस पुलिस को रिपोर्ट किये गये, जिनमें रावरी हुई । ऐसे भी बहत से केस हो सकते हैं, जिन में ये घटनायें रिपोर्ट न की गई हों । ये डकैतियां मोहन गार्डन और राउज ऐवेन्यू जैसे महत्वपूर्ण स्थानों और घनी बस्तियों में हुई हैं ।

MR SPEAKER : For your information, a direction has been issued after consulting leaders of the various parties that Members who want to make statements under Rule 377 would only read out the written statement....

श्री निर्मल चन्द्र जैन :

I am merely translating it into Hindi; If you want, I will read out the statement in English.

ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं हैं कि सड़क पर कोई छीना-झपटी हो गई हो, बल्कि घरों में घुस कर डकैतियां की गई हैं । इस प्रकार की घटना एक बहुत गम्भीर समस्या बन गई हैं । इसमें या तो पुलिस ठीक तरह से तफतीश नहीं करती है, या ठीक तरह से विजिलेंस नहीं रखती है । मैं चाहता हुं कि इस बारे में उचित कार्यवाही की जाये ।

12.37 hrs.

MOTION *RE.* DRAFT FIVE YEAR PLAN 1978—83—*contd.*

MR SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Morarji Desai on the 3rd May, namely :—

> "That this House do consider the 'Draft Five Year Plan 1978—83' laid on the Table of the House on the 26th April, 1978".

Shri Govindan Nair.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandram): Mr Speaker, Sir, it had been the normal practice in the past that before the draft of the Five Year Plan is finalised, preliminary discussions with the State Governments were conducted. This time the Planning Commission in their hurry did not care to have that kind of preliminary discussions with the State Governments. They have also come out with this Plan by cutting short the Fifth Plan by one year. From all this hurry. I was feeling very optimistic that the planning Commission is going to present a Plan that will find solution to the various problems facing our country. Going through the Plan document, I was happy to understand that the Planning Commission has identified the problems and they have also identified the possibilities. But when I went through the rest of the document, I felt very much disappointed.

The Planning Commission admits that during the past 27 years from a stagnant economy we have reached the stage of a growing economy. We have modernised our activities so that today we can feel proud that we are almost self-reliant. We have diversified our activities. In every field of industry we have certain developments. In the field of producing capital goods we are very much in advance. And also in the matter of foreign exchange and food we are in a very advantageous position. With all these possibilities we would have expected a Plan which would have really meant a solution to most of our problems. It has also been noted that during the past, in spite of all these developments, people were getting impoverished. If it was 40 percent during the Fifth Plan period, now they admit that

the number of people below the poverty line has gone up to 47 per cent. So also they will agree that in spite of the growth in the agricultural sector, the agriculturists were getting pauperised. The per capita income to-day is Rupee 1 less than what it was in 1951. Not only that, the agriculturists, the cultivators, the working force....

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : Is your calcutlation all right ?

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR : It is not my calculation. It is the Government of India calculation.

So also the percentage of cultivators....

MR SPEAKER : You have only 11 minutes for you. Please do not allow yourself to be interrupted.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR : Then I can even stop now. The point is.....

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): He has no backing in the opposition.

MR. SPEAKER : That is not my concern.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): The minister is making a running commentlary and is just walking out.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR : He is a Minister without Portfolio commenting on everything.

SHRI BIJU PATNAIK : I must back you.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: You come and sit here.

Now in one way you can consider that this reduction in the percentage of agricultirists to the working force may be due to industrial development. But, unfortunately, the fact remains that while the peasants are getting pauperised, the percentage of landless labour has increased from 19 to 26 per cent. That shows that in spite of doubling of production, the agricultural sector—the agricultural worker and the peasant are getting pauperised.

In the industrial sector also the percentage of added wealth that formerly went to the workers by way of wages has gone down and the profits and the salaries have increased.

So unless this process is reversed whatever be your impressive investment in the agriculture sector you are not going to remove poverty. Rather a few people one of such persons was discussed here are getting richer. During the last 27 or 20 years 20 Houses which owned Rs. 511 crores have today Rs. 5,111 crores. On the one side the mass of the people are getting pauperised but on the other side a few houses are getting rich. Unless this process is reversed whatever be the investment—whether it is in the agriculture sector or in the industrial sector it is not going to help remove either poverty or unemployment.

Then again when you look into the financial resources on which the Planning Commission is depending the situation in the countryside is going to aggravate rather than improve. Here it was mentioned—about tax evasion—that nearly over Rs. 1,000 crores as income tax arrears have to be realised from the richer section. You are not depending on that. But you are depending on taxation. For 24,000 crores of additional resources, you are depending on indirect tax of Rs. 13,000 crores. This is going to further do away with the purchasing capacity of the people. For every industrial goods which he needs, by the enhancement of the excise duty he has to pay more.

Another process by which the Government wants to make resources for the plan is by taking away all the subsidies that already exist. Take for example sugar. You want to almost double the production of sugar during the coming years. But the increased production this year itself is caught in a serious crisis. For this sugar industry Government today is giving nearly Rs. 13 crores by way of export subsidy. If that subsidy is to be taken away it will further aggravate the situation, if the production is to go high.

Now you are increasing the cost of electricity. Is this the way to deal with the problem ?

For wheat you are giving Rs. 23 by way of subsidy and we are all happy about the food situation in our country. Supposing this subsidy is taken away and you want to enhance production, it will have its effect. Unless the peasants are helped you will not be able to reach the production level which you want to reach. My point is in order to find resources for the plan the methods adopted by the Government have to be liberalised and new methods have to be found. Here I would say even if some of the leading members are allergic to socialism the only way to raise the necessary resource

[Shri M. N. Govindan Nair]

is by tapping the rich. In certain spheres if our economy has to advance, if the purchasing power of the people is to be enhanced, then nationalisation of the monopoly concerns is a 'must.' I want them to consider whether in order to save over hundred million families to deal with 20 monopoly houses is a problem for the Government. Our Prime Minister is well-known for his courage. I hope he will have the courage to take the necessary step in this regard. I hope he will take this step without prejudicing the larger interests of the nation.

In spite of the limited public distribution system that we have, the benefits do not go to the people. This is a limited way of public distribution system now which is also subsidised. Take the case of the Delhi Milk Scheme. There is consumer resistance. On the question whether price is to be raised or not my point is this. As far as the essential commodities are concerned you should have a proper public distribution system which should help the poor people in this country. For that you will have to nationalise the foreign trade as well as the internal trade and you may have to utilise the cooperatives for that purpose. Then again the present credit structure must change. So my point is that the Government has to intervene in a big way in the field of trade as also in regard to the system of credit facilities now existing.

Sir, the hon. Finance Minister has said that he is not going ahead with further Nationalisation of Banks. Nationalisation of Banks is one way of raising resources for your Plan.

Then with regard to the policy to be followed about prices and wages unless you have a proper machinery by which the real wages of the workers are increased in proportion to the production they make, there will always be this problem. Therefore with regard to prices and wages also you should have a proper approach.

I have only one point to make. We have reached a stage of development in this country where we are not dependent upon other nations. We are self-reliant. The capitalist class in the past has to some extent contributed in our development. I do admit that.

But now today if you want to take the country forward there is only one way and that is the socialist way ; and there is only one path and that is the non-capitalist path. Thank you.

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीस वर्षों में जिस संस्था के पास, जिस पार्टी के पास, शासन का भार रहा है और जिन्होंने हमारे देश की तरक्की करने के लिए बड़े-बड़े वायदे किये, बड़े-बड़े विचार व्यक्त किये, प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया और उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किये, वे उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सके । आज यह सौभाग्य की बात है कि देश ने करवट ली और ऐसे लोगों के हाथ में शासन का भार सौंपा है, जिनसे जनता को बड़ी-बड़ी आशाएं हैं । हमारी इस जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसे सुयोग्य और गांधी वादी विचार रखने वाले नेता के हाथों में है, जिससे जनता को बड़ी आशाएं हैं । हम सभी जानते हैं और यह बात सबको मालूम है कि हमारे देश में बहुत बड़ी गरीबी है और कोई भी योजना हमारे देश में, बनाई जाएगी या कोई भी लक्ष्य हम निर्धारित करना चाहेंगे तो वह लक्ष्य एक ही हो सकता है कि यहां से गरीबी का उन्मूलन हो जाए, गरीबी दूर हो जाए और देश में कोई भी बेरोजगार न रहे, बिना काम के न रहे और सबको काम मिले । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है । दूसरा यह भी एक लक्ष्य हमारे सामने हैं कि धन का वितरण भी ऐसे हो कि आम जनता का स्टैण्डर्ड आफ लिविंग करीब करीब एक सा हो । ये तीन लक्ष्य सामने आते हैं और इन तीनों लक्ष्यों को सामने रख कर सारी योजना का निर्माण हो । जब मैं इस ड्राफ्ट प्लान की आउटलाइन्स को देख रहा था तो मैंने देखा कि बड़ी अच्छी तरह से उसको लिखा गया है । इसमें कुछ आंकड़े दिये गये हैं जिनको आप देखेंगे तो यह पायेंगे कि हमारे रूरल एरियाज में, देहाती क्षेत्रों में 20 परसेन्ट गरीब लोग ऐसे हैं, जो सारा कन्जम्पशन होता है, जो भी उपभोक्ता

वस्तुओं का इस्तेमाल होता है उसका 9.5 परसेन्ट ही इस्तेमाल कर पाते हैं। कितनी दुर्दशा है उनकी। आप अगर आंकड़ों पर न जायें, हम जो देहाती क्षेत्रों में जाते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो यह देखते हैं कि उनकी कितनी दुर्दशा है। हमारे देश में 25, 30 परसेन्ट लोग निश्चित ही ऐसे मिल जायेंगे जिनको सन्तुलित आहार की बात तो क्या, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। उनके पास कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है जो कि प्राथमिक आवश्यकतायें हैं वे भी उनके पास नहीं हैं। इस तरह की हालत हमारे देश के उन लोगों की है।

यही हालत हमारे शहरी क्षेत्रों में स्लम एरियाज का है, जिनमें शहर का बड़ा भारी हिस्सा रहता है। हम वहां देख सकते हैं कि हमारे देश की क्या दुर्दशा है और यह बात निर्विवाद है और इस बारे में नेशनल कनसेंसस है और कोई दो राय इसमें नहीं हो सकती हैं। चाहे व्यक्ति का लक्ष्य हो, चाहे राष्ट्र का लक्ष्य हो, यह बहुत महत्व की बात है कि देश की जनता को भोजन चाहिये, कपड़ा चाहिये और मकान चाहिये। आखिर हम कोई भी योजना बनायें। चाहे हम एक घर की योजना बनायें या पूरे राष्ट्र की योजना बनयें, उसके बनाने में तीन बातें बहुत ही प्रमुख हैं। एक तो यह है कि हमें उसकी जानकारी होनी चाहिये। जानकारी अगर हमें नहीं होगी, तो हम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानकरी होनी चाहिये, ज्ञान होना चाहिये।

दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लगन। अगर काम को करने की लगन नहीं है, तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है चाहे जितनी भी जानकारी हम रखें। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगन का होना बहुत ही आवश्यक है।

तीसरा महत्वपूर्ण अंग है क्रिया-शक्ति का, हमने जो योजना बनाई है उसके लिए क्रिया-शक्ति चाहिये। उसे करने के लिए हम कोई कदम उठाते हैं या नहीं, जिसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इसका होना बहुत आवश्यक है। इस तरह तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं।

MR. SPEAKER : The hon. Member will continue after lunch. We now adjourn to re-assemble at 2 p.m.

13 00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Nine Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*].

MOTION RE. DRAFT FIVE-YEAR PLAN 1978-83—*contd.*

श्री तेज प्रताप सिंह : मैं यह बता रहा था कि हमारे जो भी लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं। एक यह है कि हमें पूरी जानकारी होनी चाहिये। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, किन किन बातों की जानकारी लेना आवश्यक है यह हमें पता होना चाहिये और वह जानकारी हमारे पास होनी चाहिये। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान लगन को मिलता है। सारी जानकारी हो, अगर लगन नहीं है तो सफलता हमें नहीं मिल सकेगी। तीसरी बात है क्रियाशक्ति की। अगर हम क्रियाशील नहीं हैं तो उन लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप देखें कि पहले वाले प्लान में छः हजार करोड़ रुपये बंधे बनाने के लिए डैम बनाने के लिए रखे गए थे लेकिन दो हजार करोड़ के ही हम पांच साल में बना सके हैं। चार हजार का शार्टफाल हुआ। पूरा उपयोग नहीं कर सके। अब इनको या तो जानकारी नहीं थी और जानकारी थी

[श्री तेज प्रताप सिंह]

तो लगन नहीं थी । आज इस दशा में हम पहुंचे हैं कि बहुत ही गरीबी हमारे देश में छायी हुई है । 50 से 60 प्रतिशत लोग बेहद गरीब हैं । तो इसके जो लक्ष्य रखे गए हैं वह उत्तम हैं परन्तु उनको हम प्राप्त कैसे करें यह देखने की आवश्यकता होती है ।

मैंने ड्राफ्ट फाइव ईयर प्लान को देखा । उसमें जो हमारे प्लानर्स हैं वह एक जगह क्या कहते हैं, यह आप देखें । क्योंकि हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारी आमदनी भी सही रूप में वितरित होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं हो हमारे देश में और कोई गरीब नहीं हो, दोनों की बीच की खाई को पाटना चाहिए, जब इस बात को देखते हैं हमारे प्लानर्स तो वे क्या कहते हैं, यह पेज 7 पर दिया हुआ है :

"The trends in the distribution of income and wealth are difficult to discern."

यह प्लानर्स को पता नहीं है कि हमारे देश में क्या ट्रेन्ड्स हैं । अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इसका इन को पता नहीं है । इन को ट्रेन्ड्स का ही पता नहीं है । समझ में नहीं आता है, जब इनको इस बात का पता नहीं है तो ये प्लान किस प्रकार से कर सकेंगे । ज्यादातर लोग शहर से आते हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको देहातों का पता नहीं है । तो यह सारी घिसी पिटी वस्तु हम बनाते रहेंगे कि पिछले प्लान में सिंचाई के लिए इतना था तो चलो उसको कुछ बढ़ा दिया जाय, कुछ उद्योग के लिए बढ़ा दिया जाय, इस प्रकार से हमारे प्लान बनेंगे तो कभी भी हम सफलता तक पहुंचेंगे नहीं और जो हमारी परेशानियां हैं उनको हम हल नहीं कर पायेंगे ।

आंकड़ों में यह दिया हुआ है कि हमारे देहातों में 20 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 परसेंट एसेंट है । यानी सारे धन का 1 ही परसेंट उन 20 परसेंट आदमियों के पास है । इस कदर गरीबी है और चार परसेंट के पास करीब करीब 30 परसेंट एसेंट्स है । यह इतना बड़ा गैप है और इस के बाद भी वह कहते हैं कि हमें ट्रेन्ड का ही पता नहीं है, तो वे किस प्रकार यह काम कर पाएंगे । हमारी ग्रोथ रेट कुछ भी हो जाय, दस परसेंट भी हम उसको कर दें बढ़ा कर लेकिन उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जनता में तो हमारी योजना रद्दी की टोकरी में डालने लायक रहेगी । आज क्या हो रहा है ? दस दस हजार करोड़ रुपये के हमारे विग विजनेस हाउसेज हैं, वह बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं कर पा रहा है किस तरह से गरीबी हटा पाएंगे और किस तरह से विलेज ओरियेन्टिड कर सकेंगे जैसा कि हमारे मित्र कह रहे हैं ।

हमारी जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि हम देहातों की तरफ देखें, शहरों में ही सारा धन इकट्ठा न होता जाय, इस ओर कोशिश की जाय । मैं देहातों में घूमता हूं । मैं यह कहूंगा कि हमारी योजना में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए । यदि वे दो बातें सफल हो जाती हैं तो हमारे यहां से गरीबी दूर हो जायगी, ऐसा मैं समझता हूं । देहातों में 60–70 प्रतिशत किसान हैं, सब से पहला प्रश्न किसान पूछता है पानी के बारे में । वह कहता है कि हमें पानी दे दीजिए, चाहे ट्यूबवेल से दे दीजिए चाहे नहर का साधन दे दीजिए .....

एक माननीय सदस्य : किसान तो 80 परसेंट हैं ।

श्री तेज प्रताप सिंह : 60–70 परसेंट ही मान लें ।

तो यह सब से बड़ी बात है, सिंचाई की सब से ज्यादा आवश्यकता है । सिंचाई पर हमारा बजट बढ़ाया गया है, यह ठीक है लेकिन उसमें ज्यादा इजाफा होना चाहिए । आप देखें 50–51 में 23 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई होती थी । 76 तक उस को 45 मिलियन हेक्टेयर तक ले गए । लेकिन

हजारों मिलियन हेक्टेयर अभी भी पड़े हुए हैं । हमारी इस योजना में दिया हुआ है कि 17 मिलियन हेक्टेयर तक हम अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता 1983 तक पैदा कर देंगे । यह वंदनीय है, अच्छी बात है । लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर हम इस देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो दस साल में हमें हर खेत पर पानी पहुंचा देना चाहिए और इतना पानी पहुंचा देना चाहिए कि जब भी वह पानी चाहे उसको पानी मिले । हमारा बुन्देलखंड है । वहां वह कहते हैं कि They are mere apologies नहर एक पानी देती है । गेहूं अच्छा उगता है, अच्छी पैदावार के लायक होता है, लेकिन सूख जाता है । उसमें दाना ठीक से नहीं पड़ पाता है । तो मियर एपालजी से क्या फायदा ? इतना पानी हो कि कम से कम पांच पांच, छः छः पानी तो मिल सके । हमारी क्षमता, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए । उस लक्ष्य को आप देखें । उस साधन की जानकारी आपको करनी पड़ेगी । मेरे पास वह मशीनरी नहीं है । प्लानिंग कमीशन है, उस को आप देखें । लेकिन लक्ष्य यह रखें कि दस साल में आप हर खेत को बराबर पानी पहुंचा सकें । तभी इस देश की सब से बड़ी समस्या हल हो सकती है । बाकी 30 प्रतिशत जनता देहातों में ऐसी है जिसके पास कोई काम नहीं है । उनकी ओर सरकार का और प्लानिंग कमीशन का ध्यान गया है कि उनके लिए गृह उद्योग-धंधों का प्रबन्ध होना चाहिए । पिछली हर एक सरकार कहती रही कि उद्योग-धंधे बढ़ाये जायें लेकिन आज तक नहीं बढ़ाये जा सके । आई टी आई में हमारे यहां के लोहार और बढ़ई जाते हैं लेकिन वे मेज कुर्सी तक बनाना नहीं जानते हैं । खुर्पा और लोहे के अन्य संयंत्र बाहर से आते हैं । जो छोटी-छोटी काटेज इण्डस्ट्रीज हैं वह समाप्त होती जा रही हैं । इसकी तरफ भी हमरा ध्यान जाना चाहिए ।

कृषि के बारे में एक और भी बात ध्यान में रखने की है । हमारे यहां केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है । मुझे बचपन का खयाल आता है तो मैं महसूस करता हूं कि आज न तो दाल में वह स्वाद है और न गेहूं में वह स्वाद है । कहीं ऐसा न हो जाये कि केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हमारे खेत ही ऊसर बंजर हो जायें । इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा । जैसी कि हमारी नीति है, हम ऐसी लकड़ी ज्यादा पैदा करें जोकि जलाने के काम में आ सके । इसके अलावा हमारे देश में सूरज बहुत चमकता है; हम सूरज की रोशनी से एनर्जी क्रिएट करें । अमरीका में जहां पर 8 महीने बरफ घिरी रहती है उनके मुकाबले हमारे देश में जहां इतनी अधिक सूरज की रोशनी रहती है, हमें इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । गोबर गैस प्लान्ट का भी हम प्रचार करें लेकिन अभी उसकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं, वह हर एक को मोहैया नहीं किया जा सकता है । गोबर की खाद पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए । आज अधिकतर गोबर इसलिए नष्ट हो जाता है कि जलाने के लिए फूयल नहीं है । उसके लिए हमें प्रबन्ध करना चाहिए ।

इस प्रकार से अगर हम सभी खेतों को सिंचाई देते हैं, अच्छे सीड्स, पेस्टीसाइड्स की व्यवस्था करते हैं और किसानों की अच्छी पैदावार होती है उसके बाद भी अगर मार्केटिंग की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, बिचौलिए बने रहते हैं तब भी गरीब किसानों तक पैसा नहीं पहुंच पायेगा, वह पैसा अमीरों के पास ही रह जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । हमारे बुंदेलखण्ड में मसूर की दाल पैदा होती है जोकि डेढ़ सौ रुपए क्वींटल में बिक जाती है लेकिन वही दाल यहां पर आ करके साढ़े चार सौ रुपये क्वींटल बेची जाती है । यह बिचौलिए न कुछ करते हैं न धरते हैं सिर्फ पूंजी के बल पर उससे दुगुना तिगुना मुनाफा कमाते हैं । इसलिए इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए

[श्री तेज प्रताप सिंह]

कि अगर किसान की पैदावार बढ़ती है तो उसका फायदा भी किसानों को मिलना चाहिए। कनाडा में सारे किसानों की कोआपरेटिव यूनियन्स बनी हुई हैं जोकि प्रति क्वींटल प्राइस फिक्स कर देती हैं और उसके हिसाब से किसानों को पैसा दे देती हैं। वह माल जब बाहर बिकता है और उसमें जो फायदा होता है वह किसानों में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाता है। वह पैसा बीच के व्यापारी के पास नहीं जाता है। इसलिए मेरी राय है कि इस देश में कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज को सफल बनाना चाहिए। इस योजना में कोआपरेटिव्ज के लिए जो कहा गया है उसको अगर मैं लिप सिम्पैथी कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी 376 करोड़ के बजाये 500 करोड़ कोआपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने के लिए रखा है लेकिन उससे बढ़ोत्तरी नहीं होगी। हम चाहते हैं कि किसान के गल्ले की मार्केटिंग की व्यवस्था कोआपरेटिव के हाथ में आनी चाहिए ताकि बीच में इंटरमीडियरीज फायदा न ले जायें।

इस तरह से धन के वितरण करने का एक दूसरा साधन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है। 5 हजार करोड़ के एक्सपोर्ट में पिछले वर्ष कोआपरेटिव सेक्टर के जरिए से केवल 72 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया गया और बाकी सारा का सारा बिजनेस हाउसेज के जरिये से एक्सपोर्ट किया गया। इस तरह से सारा मुनाफा चन्द आदमियों के हाथों में ही रहता है। पिछले तीस सालों से यही होता आ रहा है। इस सरकार को कोई क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए जिससे कि आमदनी जनता तक पहुंचे। कोआपरेटिव सेक्टर के जरिए से ही ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। गल्ले की मार्केटिंग जिसका सम्बन्ध इस देश के 60-70 फीसदी लोगों से है जोकि किसान हैं, उसकी व्यवस्था कोआपरेटिव सेक्टर में ही होनी चाहिए वरना न तो किसानों को आर्थिक लाभ ही पहुचेगा और न उनकी पर्चेजिंग पावर ही बढ़ेगी।

कृषि के सम्बन्ध में एक बात में यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां करोड़ों एकड़ जमीन ऊबर-खाबड़ पड़ी हुई है। मुझे एक सज्जन मिले थे, जो जर्मनी से आये थे। उन्होंने बतलाया कि हमारे यहां बड़े पतले-पतले फारेस्ट्स हैं, जंगलों में बहुत सारी जमीन ऊबड़-खाबड़ पड़ी हुई है, जो न कृषि के काम आती है और न फारेस्ट्री के काम आती है। उन्होंने बतलाया--जर्मनी में उन्होंने डायनामाइट लगा कर जहां फारेस्ट लैंड थी, उसको उड़ा दिया और वहां पर चिकने मोटे तने के पेड़ होते हैं, लाखों रुपया खर्च करके उन पेड़ों को लगा दिया। इससे क्या हुआ कि उनकी पैदावार बढ़ गई, हमारा इस तरह का दृष्टिकोण नहीं है। आप देखें--हमारे यहां जो वन-सम्पदा है करोड़ों एकड़ जमीन उसमें पड़ी है, लेकिन उनमें अच्छे वन नहीं होते हैं। यदि हम इनको अच्छा वन नहीं बना सकते, तो समतलीकरण कर दें। पिछले दिनों हमें चित्रकूट में देखने को मिला, प्रधान मंत्री जी ने भी देखा--वहां पर ऊबर-खाबड़ जमीन का समतलीकरण करके कृषि के योग्य बना दिया, जिससे पैदावार हो रही है। हमारा ध्यान इस तरफ़ क्यों नहीं जाता है? हम जमीनों का समतलीकरण करके उनमें सिंचाई के साधन पैदा करें और उन जमीनों को भूमिहीनों को दे दें तो इससे हमारी पैदावार भी बढ़ेगी और भूमिहीनों को काम भी मिलेगा।

उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में आप ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनेंगी--लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप कहते हैं छोटे-छोटे उद्योग धन्धे पनपने चाहियें, हैण्डलूम इण्डस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिये, उनको संरक्षण मिलना चाहिये--यह सब तो ठीक है, लेकिन उसके लिये सभी प्रकार की सुविधायें चाहियें। इम्प्लीमेन्टेशन अगर ठीक नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा।

आप यह भी कहते हैं--अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो हमारा इम्प्लीमेन्टेशन कभी भी सफल नहीं होगा, जनता उसके साथ नहीं होगी तो हम को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी—लेकिन उसी के पहले आप यह भी कह रहे हैं कि जो पंचायती राज है उसमें—

"Will be reviewed after the Asoka Mehta Committee's report on Panchayati Raj Bodies has been examined by the government".

मेरा यह कहना है कि जो ब्लाक कमेटीज़ हैं, विलेज-पंचायत हैं, इनको प्लानिंग में शामिल कीजिये। उनको पावर दीजिये, बिना पावर दिये आपका प्लान सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। आपकी ब्यूरोक्रेसी कभी सफलता नहीं ला सकती। पिछले तीस वर्षों से हम यही देखते आ रहे हैं। हम को इस तरह का स्टेप लेना चाहिये कि जो हमारी कमेटीज़ हैं, उनको डीसेन्ट्रलाइज़ करके पावर दें और वे भी अपना योगदान प्लान को दें। आप देखिये--मेरे क्षेत्र बुन्देलखण्ड में ऊन बहुत होता है, लेकिन सारा ऊन सस्ते दामों में लोग ले जाते हैं और उससे कालीन बनाते हैं। हम इस तरह की व्यवस्था उसी स्थान पर क्यों नहीं करते जिससे वहीं पर कालीन बनने लगें। जब रा-मैटीरियल वहां पर उपलब्ध है तो उसके कारखाने भी वहीं पर स्थापित किये जांय। मेरा निवेदन है कि इम्प्लीमेन्टेशन की जो मशीनरी है उसमें पीपल्ज पार्टिसिपेशन होना चाहिये, लेकिन यहां घर में बैठ कर वह नहीं हो सकता है। हमें बाहर जा कर जनता का सहयोग लेकर इसे करना चाहिये।

मैं तो ऐसा महसूस करता हूं--

पोथी पढ़-पढ़ जा मुआ, पण्डित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पण्डित होय।

इसके लिये हमें लगन और निष्ठा से जनता को जगाना होगा, उसके पास जाकर, उसको इस प्रेम के पाठ को पढ़ाना होगा, तब हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे।

इस समय जो ड्राफ्ट प्लान बनाया गया है, उसमें हमारी दृष्टि देहाती क्षेत्रों की ओर गई है और हमें विश्वास है कि हम इसमें फेल नहीं होंगे, इसको ऐसे चार चान्द लगायेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, जनता पार्टी को याद करेंगे।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से इस ड्राफ्ट प्लान पर चर्चा चल रही है। कतिपय माननीय सदस्यों ने कहा कि इस प्रारूप को जल्द-बाज़ी में लाया गया है, इसे गांव स्तर, पंचायत स्तर पर भेजना चाहिये था। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। पिछले तीन दिनों से मैं देख रहा हूं—इस पर जो चर्चा चल रही है, उसमें माननीय सदस्यों की कितनी कम दिलचस्पी है, कोरम तक सदन में पूरा नहीं होता है, सदस्य यहां मौजूद नहीं रहते हैं। होना तो यह चाहिये था कि प्लानिंग कमीशन के सदस्य भी यहां मौजूद होते, उनको भी माननीय सदस्यों की राय को सुनना चाहिये था, लेकिन वे भी यहां मौजूद नहीं हैं। फिर भी मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं--उन्होंने इसे यहां पर सदस्यों की राय जानने के लिये रखा और यह भी कहा है कि सबकी राय जानने के बाद नवम्बर तक वे इसको फाइनल करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, मैं विपक्षी दल के नेता माननीय स्टीफन साहब का भाषण सुन रहा था। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि जो योजना आपने आज बनाई है, उसकी जो इमारत खड़ी हुई है--पिछले अनेक वर्षों के मज़बूत आर्थिक आधार का परिणाम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं, इसलिये बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मोटी-मोटी दो-तीन बातों की तरफ़ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। 31 दिसम्बर, 1976 तक हम ने विदेशों से जो कर्ज़ा लिया, वह 10,41,600 करोड़ था। इतने रुपये

[श्री राम जीवन सिंह]

आपने विदेशों से कर्ज लिये, दुनिया के 27 देशों से कर्ज लिये। इतना ही नहीं 1951 में जब प्रथम योजना लागू हुई थी, तो सेन्ट्रल टैक्स लगे थे करीब 120 करोड़ रुपये और जो बढ़कर 1971–72 में 614 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में लगे। आज स्थिति क्या है? भले ही आप कहते हों कि हम ने बहुत प्रगति की है लेकिन इस्पात में हमारा उत्पादन मात्र 77.3 लाख टन है। 1951 में जिस समय योजना शुरू हुई थी तो दुनिया में इस्पात के उत्पादन में भारत का आठवां स्थान था और अब घट कर उसका स्थान 13वां हो गया है। इसी तरह से जहां 1946–47 में कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा था वहां आज वह चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ल्ड ट्रेड में हमारा क्या स्थान रहा है? 1951 में वर्ल्ड ट्रेड का औसत 78,000 करोड़ रुपये के करीब था और हिन्दुस्तान का ट्रेड था 1611 करोड़ रुपये यानी सम्पूर्ण वर्ल्ड ट्रेड का वह 2.1 परसेन्ट था। अब हमारी इतनी सारी योजनाओं के बाद वह घट कर कहां चला गया? 1973 में जहां वर्ल्ड ट्रेड था 5,10,000 करोड़ रुपये, हिन्दुस्तान का हुआ 2942 करोड़ रुपये यानी 2.1 परसेन्ट से घट कर 0.6 परसेन्ट यह हो गया। यही आप ने इतनी प्लानों के बाद प्रगति की है और इसी आधार पर आप अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं। इतना ही नहीं, 1961 में 26 परसेन्ट भूमिहीन थे तो 1971 में 39 परसेन्ट हो गये। अगर आप यह कहते हैं कि हम ने मुद्रा कोष को बढ़ाने का काम किया है, अन्न का उत्पादन बढ़ाने का काम किया है, तो जिस समय अंग्रेज यहां से जा रहा था, आपको उससे करीब 35 अरब रुपये प्राप्त हुए थे। उतनी बड़ी राशि आपको प्राप्त हुई थी। थोड़ी देर के लिए, हम यह मान भी लें कि आप ने अर्थ भरने का काम किया है, तो क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि ईमान का खजाना जो इस देश के अन्दर था, उसको आप ने खाली कर दिया, एफिशियेन्सी के खजाने को आप ने खाली कर दिया है और अब जो भी सरकार बनती है, उसके सामने ईमान और ऐफिशियेन्सी की समस्या खड़ी हो जाती है। प्रधान मंत्री जी लाख अच्छे हों, लाख उनकी योजनाएं अच्छी हों लेकिन देश के अन्दर जो ईमान का खजाना खाली कर दिया गया है, उससे सारी चीजें यहां पर बेकार हो जाती हैं, कुछ हो ही नहीं पाता है। इसलिए जितनी भी योजनाएं चलती हैं और उन योजनाओं में चाहे जितना भी खर्च बढ़ता चला जाए, कुछ प्रगति सामने नहीं आती है। मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा होती गई। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी योजना बनती है, उस योजना को बनाने से पहले एक बात को जरूर देखना चाहिए कि ये जो हमारी पांच योजनाएं रही हैं, विफल क्यों रहीं? क्या कारण हैं कि इन योजनाओं में जो लक्ष्य रखे गये थे, उनकी पूर्ति नहीं हो सकी।

आप यह देखें प्रथम योजना में बिजली के ऊपर कुल मिलाकर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए, द्वितीय योजना में 235 करोड़, तृतीय में 1152.3 करोड़ और जो तीन वार्षिक योजनाएं बनी थीं उन में हम ने करीब 1225 करोड़ रुपये खर्च किये, चौथी योजना में 2448 करोड़ और पांचवीं योजना में 7293 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और इतना खर्च करने पर भी अब तक 32.3 परसेन्ट गांवों को ही इलेक्ट्रिफाई कर सके हैं। यही हालत सिंचाई की है। पिछले वर्षों में 84 अरब रुपया हम ने इस पर खर्च किया है। जब अंग्रेज जा रहे थे उस वक्त सिंचाई होती थी 17.6 परसेन्ट एरिया में और इतने अरब रुपये खर्च करने के बाद अब हम ज्यादा से ज्यादा 26 परसेंट पर आए हैं यानी मात्र 10 परसेंट की हमने बढ़ोतरी की है इन पिछले 30 वर्षों में। हमारे यहां यही स्थिति है फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग पर प्रथम योजना में 18 लाख 50 हजार रुपये खर्च हुए थे,

द्वितीय में 3 करोड़ रुपये, ततीय में 24.86 करोड़ रुपये, चौथी फाइव इयर प्लान में 315 करोड़ रुपये और पांचवीं फाइव ईयर प्लान में 430.62 रुपये खर्च हुए और इसके बाद नतीजा क्या निकलता है? हर वष हिन्दुस्तान में एक आस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या बढ़ जाती है। करीब 1 करोड़ 20 लाख आदमी हर वर्ष हिन्दुस्तान में पदा हो जाते हैं और उन आदमियों को खिलाने के लिए प्रति वर्ष चाहिए 1 करोड़ 20 लाख क्विंटल अनाज, 25 लाख मकान चाहिए, 1 लाख 26 हज़ार स्कूल चाहिए, करीब 3.72 लाख शिक्षक चाहिए और 47 लाख लोगों को हर वर्ष रोजगार चाहिए। पहले से ही कितने लोग बेरोजगार है, यह सब जानते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो योजना आप बनाएं, निश्चित तौर पर यह देखे कि पिछली योजनाओं की विफलता के क्या कारण थे और उनको कैसे दूर कर सकते हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना बनाने पर यह अवश्य ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमारी समस्यायें क्या हैं, हमारे साधन क्या हैं और हमारा सिस्टम क्या हैं? हमारे यहां बेकारी की और भुखमरी की समस्या है। हिन्दुस्तान एक बहुत गरीब देश है। अमेरिका में एक व्यक्ति को रोजगार देने के पीछे 20-25 हजार रुपया खर्च किया जाता है। इसी काम के लिए रूस 15 हजार रुपया खर्च करता है लेकिन हिन्दुस्तान मात्र पांच-सात सौ रुपया खर्च कर सकता है। जो आज अमेरिका में चलता हैं, उसकी हम नकल तो कर सकते हैं लेकिन नकल करने के लिए अकल चाहिए अन्यथा शकल बिगड़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। और पिछले तीस वर्षों में यही हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो साधन है, हमारी जो समस्याएं हैं, उन्हीं के अनुरूप हमें करना है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें आगे चलना है। हमारे यहां प्रजातांत्रिक पद्धति है। प्रजातांत्रिक परिस्थितियों में जो कुछ हो सकता है, वही हमें करना है। इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रख कर ही हम योजना बनावें। जब हम देश के सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनावें तो यह सोचें कि क्या इससे देश का सर्वांगीण विकास हो सकेगा, कहीं सर्वांगीण विकास के नाम पर एकांगी विकास भी नहीं हो पाए। पिछले तीस वर्षों में यही होता रहा है। जब हम यह सोच कर चलते हैं कि यह भी हो, वह भी हो तो कुछ भी नहीं हो पाता है। पिछले तीस वर्षों में न तो हम इर्रीगेशन के मामले को सोल्व कर सके हैं, न इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले को सोल्व कर सके हैं, न कम्युनिकेशन के मामले को सोल्व कर सके है। इस तरह हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम तो आप से यह चाहेंगे कि आप जो योजना बनावें उसमें कम से कम एक-दो समस्याओं का तो समाधान अवश्य कर दें। आप प्रत्येक योजना का नामकरण कर दें। अमुक योजना कृषि, विद्युत और उद्योग योजना है। आप उसमें यह रख दें कि पांच वर्ष के अन्दर कृषि उद्योग, उद्योग और विद्युत की समस्या का समाधान कर देंगे। यह भी निश्चित कर दें कि सिंचाई की समस्या का समाधान इस योजना में कर देंगे। आप फिर सातवीं योजना जब बनावें तो उसमें कोई दूसरे-दूसरे मद, कम्युनिकेशन आदि रख सकते हैं कि अगले पांच वर्ष में हम इसकी समस्या का समाधान करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि पांच वर्ष तक या दस वर्ष तक हम कच्ची सड़क पर न चल सकें, पक्की सड़क पर ही चलें। आप गांवों में पानी का प्रबन्ध कर दीजिए और यह निर्धारित कर दीजिये कि इतनी अवधि में हम इस समस्या का समाधान करेंगे।

पिछले तीस वर्षों में आप शहरों की तरफ गये हैं, शहर का विकास किया हैं।

[श्री रामजीवन सिंह]

किया हैं। परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य समाज कल्याण आदि बहुत सारी मदों पर भी आपकी यह योजनाएं बनी हैं। मैं तो कहूंगा कि आप बहुत सारी मदों को समाप्त कर दें। कोई जरूरत नहीं है, इतनी सारी मदें रखने की। जब देश पर चीन का आक्रमण हुआ था तो उस समय हिन्दुस्तान में 262 करोड़ रुपया डिफेंस पर खर्च होता था। लेकिन जब विशेष परिस्थिति देश में उत्पन्न हुई तो बहुत सी मदों पर से खर्चा समाप्त कर के आपने 662 करोड़ रुपया डिफेंस पर खर्च करना शुरू कर दिया। उसी तरह आज भी हमारे देश में एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई है। अपने देश में एक शान्तिपूर्ण क्रांति हुई है। अगर इस विशेष परिस्थिति का हमने लाभ नहीं उठाया और यह परिस्थिति विफल हो गयी तो अच्छा नहीं होगा। 1967 में क्या हुआ था? संविदवाद देश में शुरू हुआ था। कतिपय राज्यों में संविद की सरकारें बनी थीं। उस संविदवाद की जितनी सरकारें थीं वे दो महीने, चार महीने, 6 महीने -में ही गिरती गयीं और संविदवाद विफल हो गया। उस संविदवाद की विफलता से इस देश में नक्सलवाद पैदा हुआ। उसका अंजाम भुगत रहे हैं। एक बार फिर से जनता ने डेमोक्रेसी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। आज सवाल इस पक्ष का या उस पक्ष का नहीं है। सवाल जनतंत्र का है। आज सवाल है कि हम अपनी योजना के माध्यम से जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करें। नहीं तो जनता में जब क्रोध आयेगा तो स्थिति कहां तक पहुंच सकती है, कह नहीं सकता? आदमी डेस्प्रेट हो जाता है, कहीं उसे आशा की किरण दिखायी नहीं देती है तो वह अपनी जिन्दगी को जो कि दुनिया की सब से बहुमूल्य चीज होती है, उसको भी खत्म कर देता है। भूख से तड़पने वाला आदमी और क्या कर सकता है? बर्टेण्ड रसेल ने कहा था कि भूखे आदमी से कोई अगर पूछने जाये कि रोटी और जनतन्त्र में तुम किस को पसन्द करोगे तो इन्सान पहले रोटी को पसन्द करेगा बाद में जनतन्त्र को पसन्द करेगा। इसी दृष्टि से हमें सभी चीजों को देखना होगा। अगर हमने आज दीवार पर लिखी रेखाओं को नहीं पढ़ा तो फिर काम नहीं चलेगा। हमको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा अगर हम उसको भूलेंगे। इसलिये में कहना चाहता हूं कि हम इस दृष्टि से सोचें।

आज यह कहा जाता है कि हमने इतनी बड़ी योजना बनायी है जितनी कि पहले कभी नहीं बनी थी। हमने इसमें इतनी राशि रखी है, हम इस मद में इतना रुपया खर्च करेंगे। मैं तो कहूंगा कि बड़ी राशि रखने से ही योजना बड़ी नहीं हो जाती है। हमने प्रथम योजना में 1960 करोड़ रुपया खर्च किया था, द्वितीय योजना में 7000 करोड़ पया तृतीय में 12767 करोड़ रुपया चतुर्थ योजना में 24882 करोड़ रुपया और पांचवी योजना में 53,350 करोड़ रुपया खर्च किया था। प्रथम योजना से द्वितीय योजना साढ़े तीन गुनी बड़ी थी, द्वितीय योजना से तृतीय योजना एक गुने से कुछ कम बड़ी थी, तृतीय योजना से चतुर्थ योजना दुगने से कुछ बड़ी थी और चतुर्थ योजना से पांचवी योजना भी दुगने से कुछ बड़ी थी। अब छठी योजना 1 लाख 16 हजार, 240 करोड़ रुपये की है। इसमें भी हम पांचवी योजना से दुगना ही खर्च कर रहे हैं। अगर योजना की राशि पर ही चला जाए तो में द्वितीय योजना को क्रांतिकारी योजना कहूंगा क्योंकि उसमें पहली योजना से करीब 350 प्रतिशत राशि अधिक खर्च की गयी थी। लेकिन क्या स्थिति हुई? इस लिये में कहूंगा कि योजना की राशि से योजना का बड़ा होना न माना जाए।

हमारे प्रधान मंत्री जी बड़े अच्छे सर्जन हैं। आपने मर्ज को पकड़ा है और आप उसका आप्रेशन करके इलाज करना चाहते हैं।

किन्तु जिस इन्स्ट्रूमेंट के द्वारा आप आप्रेट करेंगे वह स्टेरेलाइज्ड होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मरीज भी मर जाएगा और आप्रेशन भी फेल हो जाएगा। इस वास्ते जिस यंत्र के द्वारा आप योजना को लागू करना चाहते हैं अगर उस यंत्र को आपने ठीक नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि आप रिसपांसिविलटी फिक्स करें। संतानम कमेटी ने भी कुछ सुझाव दिये थे। ए आर सी जिस के चेयरमैन हनुमन्तैया साहब थे उन्होंने भी कहा था कि प्रोमोशन का तरीका ठीक होना चाहिए, प्रोमोशन सिर्फ इस आधार पर नहीं दी जानी चाहिए कि उसकी लैंथ आफ सर्विस देखी जाय बल्कि उसका आधार होना चाहिए एफिशेंसी। जो राशि और जो समय तय किया जाय उसे उस राशि और उतने समय के अन्दर ही जो कार्य पूरा करता है उसी चीज को सब से बड़ी एफिशेंसी माना जाए। जो कम राशि और कम समय में पूरा करेगा तो उसको उससे अधिक एफिशेंट माना जाये। इस तरह की कोई चीज नहीं होगी तो फिर आपकी योजना सफल नहीं हो सकेगी।

आज स्थिति क्या है? हम पिछली योजनाओं को देखें। नागार्जुन सागर बांध योजना का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। 1955 में यह योजना चालू की गई थी। योजना के अनुसार 8 लाख तीस हजार हैक्टर जमीन में सिचाई होगी यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एस्टीमेट के मुताबिक 122 करोड़ रुपए इस पर खर्च होना चाहिए था। 1976 तक उस पर कुल दो सौ करोड़ व्यय हो चुका है और कम से कम 120 करोड़ रुपया और व्यय करने की आवश्यकता होगी, तब जा कर यह योजना पूरी होगी। इस तरह से काम चलेगा तो हमें सफलता नहीं मिल सकेगी।

नैशनलाइजेशन की मांग भी यहां की जाती है। हमने अपने देश के लिये मिश्रित अर्थ व्यवस्था को अपनाया है, मिक्स्ड इकोनोमी को अपनाया है। इसका प्रादुर्भाव-पश्चिम यूरोप में हुआ था। यूरोप में आउट-गोइंग कपिटलिज्म और इमर्जिंग सोशलिज्म दोनों ने अपना अस्तित्व कायम रखा है। मैं मानता हूं कि हमने अपनी पिछली चार योजनाओं में पब्लिक सैक्टर पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। उस पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया है। निजी क्षेत्र की तुलना में उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा निरन्तर बढ़ता गया है और निजी क्षेत्र का शनैः शनैः कम किया जाता रहा है। पांचवीं योजना के अन्तिम रूप में अचानक निजी क्षेत्र में दस प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई। पहली योजनाओं में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन नहीं मिला फिर भी उसका वर्चस्व कायम रहा। पांचवीं योजना ने उसको और भी प्रोत्साहित किया। इसके बाद क्या स्थिति बनी इसको आप देखें। आज निजी क्षेत्र का वर्चस्व कितना अधिक हो गया है इसको आप देखें। आज देश में एक करोड़ से अधिक पूंजी वाली कम्पनियों की संख्या करीब 370 है जो कुल कम्पनियों की संख्या का मात्र करीब 22.3 प्रतिशत है किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल प्रदत्त पूंजी का 74.8 प्रतिशत, कुल परिसम्पत्ति का 70 प्रतिशत, कुल उत्पादित मूल्य का 65.3 प्रतिशत और कुल बिक्री का 65.6 प्रतिशत और कुल परिचालन मुनाफा अर्थात् अप्रेटिंग प्राफिट का 74 प्रतिशत निजी क्षेत्र में है। उसका वर्चस्व यहां तक है। भारी उद्योगों के क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर में मजबूत नीव डाली है। पब्लिक सेक्टर के प्रादुर्भाव के बावजूद भी आन्तरिक बाजारों पर निजी क्षेत्र का आधिमूल्य है। वही सामान तैयार करता है और वहां बाजार में बेचता है। बहुत सामान सरकार द्वारा निजी क्षेत्र से खरीदा जाता है। इस सब का परिणाम यह हो रहा है कि निजी क्षेत्र पब्लिक सैक्टर को निगलता चला जा रहा है।

[श्री रामजीवन सिंह]

मैं अन्त में कुछ सुझाव दे कर खत्म करता हूं। पहला सुझाव मेरा यह है कि आप रिसपांसिबिलिटी को फिक्स कर दें। आप पब्लिक इनिशिएटिव और इनसैंटिव को जगाने का काम करें। योजना को आप पापुलराइज़ करें। जिस के लिए योजना बनी है उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसको जानकारी नहीं होगी तो कुछ विशेष हमारे हाथ नहीं लगेगा। खर्च की सीमा आप बांधें। इसको बांधे बगैर कुछ नहीं होगा। विलासित सामान, लग्जुरियस गुड्ज का उत्पादन कुछ वर्षों तक पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए। बेकारी को खत्म करने के लिए वन मैन वन जाब आप नहीं करेंगे तो बेरोजगारी को खत्म करने में मदद नहीं मिलेगी।

अब मैं बिहार की स्थिति थोड़े शब्दों में बता कर खत्म करता हूं। आज बिहार प्रदेश देश का वह प्रान्त है जो देश को 41 परसेंट मिनरल्ज़ देता है, 25 परसेंट आयरन और देता है, 84 परसेंट कोकिंग कोल देता है। लेकिन उसकी स्थिपि यह है कि सम्पूर्ण भारत में जहां 110 किलोवाट औसत प्रति व्यक्ति बिजली की कंजम्पशन है वहां बिहार में केवल 84 किलोवाट ही है। देश के सम्पूर्ण इनरजाइज्ड पम्पों का मात्र 3.3 प्रतिशत बिहार में है। अस्पतालों में सारे देश में प्रति लाख 51 बड़े हैं, बिहार में मात्र 27 सारे देश में 32.33 प्रतिशत गांव इलैक्ट्रिफ़ाइड हैं, जब कि बिहार में केवल 24.52 प्रतिशत गांव इलेक्ट्रिफ़ाइड हैं। सारे देश में प्रति-लाख आबादी पर पक्की सड़कों की लम्बाई का औसत 98 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में वह केवल 38 किलोमीटर है। सम्पूर्ण देश में 32 प्रतिशत लोग साक्षर हैं, जबकि बिहार में केवल 22 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। सम्पूर्ण देश में औसतन 44 प्रतिशत गरीबी रेखा क नीचे हैं, बिहार में 66 प्रतिशत।

उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति का कारण क्या है, मैं यह बता कर समाप्त करता हूं। प्रथम योजना में दूसरे राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत खर्च 39 रुपये था, जब कि बिहार में वह केवल 19 रुपये था। इसी प्रकार दूसरी योजना में दूसरे राज्यों में प्रति-व्यक्ति औसत खर्च 51 रुपये और बिहार में 42 रुपये, तीसरी योजना में दूसरे राज्यों में 97 रुपये और बिहार में 71 रुपये, चौथी योजना में दूसरे राज्यों में 128 रुपये और बिहार में 97 रुपये और पांचवीं योजना में दूसरे राज्यों में 337 रुपये और बिहार में 230 रुपये प्रति-व्यक्ति औसत खर्च किया गया। इस कारण यह क्षेत्र नेगलेक्टेड रहा है। उपाध्यक्ष जी, मैं अब समाप्त कर रहा हूं.....

MR. DEPUTY SPEAKER : You can never finish. You have a lot of material. I know that.

श्री रामजीवन सिंह : ऋण वितरण में भी यही हुआ। 1969 से 1974 तक तामिलनाडू, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन पांच राज्यों में नेशनलाइज्ड बैंकों के द्वारा 62 प्रतिशत लोन दिये गये, केन्द्र-शासित क्षेत्रों में 13.7 प्रतिशत, यू० पी० में 4.8 प्रतिशत और बिहार में केवल 1.5 प्रतिशत ऋण दिये गये। इस स्थिति को देखते हुए सरकार बिहार को ज्यादा से ज्यादा रुपया विकास करने हेतु दे जिससे बिहार का पिछड़ापन दूर हो सके।

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri D. N. Bosu. You have only ten minutes. Please see that you make your points within that time. At the end of ten minutes please do not ask for more time.

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa) : I thank you for giving me an opportuity to speak on this important document. This draft plan is a very

important document placed by our esteemed Prime Minister on the Table of the House on the 26th April.

In the draft Plan at pages 26-27 it will be seen that for the developmet of shipping and ports a sum of Rs. 625 crores has been provided for five years but the details or port-wise allocations have not been shown in the Plan nor have the infra-structures been shown. What about the development of the Calcutta port and its subsidiary the Haldia port ? As a matter of fact the Calcutta port and the Haldia port are on the verge of ruin for want of flow of Ganga water. As you know development of commerce and industry in the eastern region mainly depends on the Calcutta port but for want of regular flow of water steamers and ships cannot go to Calcutta port. This is due to the fact that the Farakka Agreement has been reached with Bangladesh on the understanding that India shall get 20,000 cusecs of Ganga water and the rest will go to Bangladesh as a result of which we cannot get sufficient water in the Hooghly river. I do not know whether the Government has a right to negotiate for increase in the supply of the Ganga water to Farakka from 20,000 to 40,000 cusecs for which we have already submitted our memorandum to our esteemed Prime Minister.

For energy, only a small amount has been provided, sufficient amount has not been provided in the draft Plan. If the Energy Minister does not get more funds, how can there be more generation of electricity ? Electricity generation has to be given the topmost priority. As a matter of fact, due to shortage of power, most of the industries are now in difficulties, and only 50 to 60 per cent of the capacity is being utilised. Our Prime Minister will also agree that even the capacity of Government undertakings is not being utilised properly. There have been answers by the Industry Minister and Energy Minister, to various questions that due to shortage of power, about 50 per cent capacity of Heavy Engineering Corporation cannot be utilised. As a matter of fact, some of the sections of the Steel Plants are still closed. 30 to 40 per cent of the capacity is being utilised there. It is mainly due to shortage of power. So, sufficient funds should have been provided in the Plan for electricity generation. I would like to given an example of Farakka Thermal Power Station. It has been hanging fire since long. But there is no mention of that in the Draft Plan. No money has been provided for it. How will the industries survive ? If the industries cannot survive, if even 60 per cent of the capacity of the industries cannot be utilised for want of power, then there will be more unemployment. Lakhs and lakhs of people have been laid off in various industries for want of power as a result of which it has become almost impossible to cope with the unemployment problem. So, I would urge to our Prime Minister to provide more funds for electricity generation so that industries could be run upto their full capacity and the employees are not made to suffer. Even two years back, the Heavy Engineering Corporation was running at a profit. How is it that this Government-run Corporation is now running at a loss ? It is due to mismanagement. It is due to shortage of power and this has to be solved.

Coming to adult education, many of our esteemed colleagues have been speaking time and again on this subject and the Education Minister the other day, practically expressed his helplessness in this matter because of want of funds. For removing illiteracy, only Rs. 200 crores have been provided for five years. That comes to Rs. 40 crores per year. There are 65 per cent people who still do not have literacy. So, this adult education programme should be given top priority. We should have at least provided Rs. 1000 crores for removing adult illiteracy. Centres should be opened in all schools and colleges. Television and radio should be provided in all villages so that people there may get some educaion, may be some what educated. Unless the people get proper education, unless illiteracy is removed, how can the Nation progress ? The nation cannot progress.

If you see page twenty four of this Draft Plan, you will find mention of petro-chemicals. Some amount has been provided for that. But there is no mention of a petro-chemical complex at Haldia. I want to know through you from our esteemed Prime Minister as to what is the fate of the petro-chemical complex at Haldia. The other day, the Minister incharge of Chemicals has assured that a petro-chemical complex at Haldia is almost a certainty. There is no mention of any fund in this Plan Document. This is surpirising; this is really disappointing to us.

The Prime Minister has agreed that basic programmes will be prepared for removing illiteracy and well thought out plans must be prepared for the implementation of projects. But the point is where is the infrastructure for implementing those projects; there is no infrastructure for implementing those projects. Then how will those projects be implemented. Then theres is no mention of any amount being provided for it in the Plan Document. That is also surprising.

[Shri Dhirendra Nath Basu]

As far as agricultural sector is concerned, I am glad to find that too much stress has been laid on this sector and about 40 per cent of the amount has been provided for improving the rural sector. But there is no policy laid down and no positive programme has been drawn up for this. Then how will they be able to implement it ? The other day, I saw so many manufactured equipments were lying unsold in the Agricultural Research Institute ; they are rotting in the godowns. There is no sales promotion organisation for selling these equipments. Something has to be done in this respect. I appeal to the Government through you Mr. Deputy Speaker that necessary infrastructure must be prepared along with this Plan Document. I do not want to tire your patience as you have allowed only 10 minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER : You have 12 minutes.

SHRI DHIRENDRANATH BASU : In conclusion, I appeal to the Prime Minister to look after the demands of West Bengal, because West Bengal is part of India. If West Bengal goes, then the eastern region will also go.

श्रीमती कमला बहुगुणा (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप हमारे सामने प्रस्तुत है उसको देखने से ऐसा लगता है कि यह योजना बहुत जल्दी में बनाई गई है । ऐसा भी लगता है कि यह अमीर को और अमीर बनाने की योजना है और इस योजना में कई सीरियस लैकुने हैं । मुझे कहने में हिचकचाहट नहीं है कि यह वेग है, इसमें न पाजिटिव गाइडलाइन्स हैं और न पाजिटिव प्रोग्राम हैं । इसमें सब से अधिक अखरने वाली बात यह है कि इसमें लेबर के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है । जिन मजदूरों के पसीने से सारा उत्पादन होता है, इस देश की सारी नेशनल एकोनामी जिन मजदूरों के बल पर खड़ी हुई है उसके सम्बन्ध में इसमें कोई चैप्टर नहीं है। कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की क्या स्थिति होगी, मैनेजमेंट में उनका क्या इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, गेन में उनकी क्या हिस्सेदारी होगी—इन बातों का इसमें कोई जिक्र नहीं है । उनके अलावा इस देश में जो करोड़ों खेतिहर मजदूर हैं उनकी मिनिमम वेज का किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा—इसका भी कोई जिक्र नहीं है । खाली कानून बना देने से कि मिनिमम वेज हो जानी चाहिए वह नहीं हो सकती है । उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जायेगा, यह बात प्लान में आनी चाहिए थी । आज गांवों में जिनको हम खेतिहर मजदूर बोलते हैं उनकी हालत में तीस सालों में कोई फर्क नहीं आया है । इन सब बातों को देखते हुए मैं समझती हूं इसमें एक लेबर का चैप्टर इनक्लूड होना चाहिए और गहराई से लेबर प्राब्लम को साल्व करना चाहिए अगर हम वास्तव में इस देश में प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं ।

दूसरी चीज यह है कि इसमें जिस चीज को कैसलनेस से डील किया गया है वह है औरतों की प्राब्लम । इस देश में 50 फीसदी औरतें हैं । यह नारा भी है कि सोशियो एकोनामिक डेवलपमेंट में औरतों को हिस्सा लेना चाहिए । ऐसा भी नहीं कि वे हिस्सा नहीं ले रही हैं । आज इस देश की वर्किंग फोर्स में—कारखानों, खेतों, खदानों, टी-गार्डन्स में—तीन करोड़ औरतें काम कर रही हैं । सर्विसेज में भी काम कर रही हैं । आगे वे कैसे हिस्सा लेंगी, इसका कोई प्रोग्राम इसमें नहीं दिया गया है । ..... (**व्यवधान**) ..... मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज कुटीर उद्योगों की बहुत बात हो रही है, अगर इस शक्ति को कुटीर उद्योगों में लगा दिया जाये तो इससे देश में बहुत लाभ होगा ।

मेरा यह फर्म-कन्विक्शन है—यदि गांव-गांव में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना है तो पंचायतें ही ऐसी संस्थायें हैं, जिनसे गांव-गांव में पहुंच सकते हैं । अन्यथा न कोई लोन लेने आयेगा न कोई बैंकों के पास जायगा और न ही कोई सोशल आर्गेनिजेशन्ज हैं जो उनके बीच में काम करेंगी—इसलिये हम किस तरह से ग्रामीण अंचलों में गहराई से घुस सकेंगे—मैं समझ

नहीं पा रही हूं । फिर भी मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देती हूं, उनकी नजर ग्रामीण अंचलों की तरफ जा रही है ।

बड़ी मुश्किल यह है कि प्लान से अभी भी ऐसा लगता है कि जिन्होंने पिछले 30 सालों से फायदा उठाया है, वही आज भी उठाते चले जा रहे हैं और आगे भी उठाते जायेंगे । आज भी 30 प्रतिशत लोगों के हाथों में देश की 82 प्रतिशत दौलत है और शेष 18 प्रतिशत दौलत बाकी 70 प्रतिशत लोगों के पास है, जिनमें 30 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 प्रतिशत भी नहीं है। इसलिये प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या इस प्लान के द्वारा हम अपने देश के छोटे काश्तकारों, गरीब काश्तकारों, मार्जिनल फार्मर्स तक पहुंच पायेंगे ? आज जितनी रिसर्चेज हुई, जितनी टेक्नालाजी बनी, एग्रीकल्चर में जितनी भी नो-हाऊ बनी, सब का लाभ इन 30 प्रतिशत बड़े फार्मर्स ने उठाया, हमारा अब यह प्रयास होना चाहिए कि हमारे पास जितनी टेकनालाजी है--एग्रीकल्चर सैक्टर में--वह देश के 70 प्रतिशत छोटे काश्तकारों तक पहुंचे-- इस बात को आप प्लान में जरूर देखें । "ग्रैटेस्ट-गुड-आफ दी ग्रैटेस्ट-नम्बर" होना चाहिये । यदि सचमुच में हम गरीबी मिटाने की तरफ जा रहे हैं तो हमें कृषि के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये ।

पशुधन की तरफ भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूं—पशुधन के लिये हमने कुछ आगे कदम बढ़ाया है, उसका प्राफिट केवल 20 परसेंट हो गया है। जैसे महाराष्ट्र में "एग्रो फाउण्डेशन" है, "मुरली-कांचन" में एक प्रोग्राम बनाया गया है, उसको व्यापक तौर से सारे देश में चलाया जाय, तो मुझे यकीन है कि 70 फीसदी छोटे काश्तकारों में पशुधन के विकास की सम्भानायें बढ़ सकेंगी ।

अब मैं हरिजनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । यहां पर बार-बार यह सवाल आता है । पिछले तीस सालों में अगर हम ईमानादारी से देखें तो मन में एक चुभन-सी होती है । क्या हमने वास्तव में इनके लिए उतना किया है, जितना करना चाहिये था ? थोड़ी सी नौकरियां दे देने से या थोड़ी सी जमीन दे देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता । ज़मीन भी कहां बांटी गई है—ऊसर, बंजर, नालों के पास दी गई है, उन में बहुतों को कब्जा नहीं दिलवा सके हैं इस तरह से हम लैण्ड रिफार्म्ज को कैसे इम्पलीमेंट कर सकेंगे । इस पंच-वर्षीय योजना में गहराई से इन बातों पर विचार नहीं किया गया है । मेरा निवेदन है कि केवल आउट-ले रख देने से इस देश की समस्याओं का हल नहीं निकल सकता है, प्रोडक्शन बढ़ने से भी नहीं निकलेगा । प्रोडक्शन का सही मायनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक हिसाब से लोगों को उसका लाभ मिले—तब इसका फायदा हो सकता है, तभी हमारी आउट-ले भी सही साबित होगी और प्रोडक्शन भी सही साबित होगी । वरना जैसी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है--रिज़र्व बैंक ने साफ लिखा है कि इस समय केवल 30 परसेंट लोग ही फायदा ले रहे हैं। यदि हमें 30 परसेंट के लिये ही सब कुछ करना है, तो यह प्लान उसकी एक कड़ी हो जाती है, जो आज तक होता रहा है । इसलिये मैं आशा करती हूं कि इस प्लान में एक रेडिकल-चेन्ज लाया जायगा, इसकी वेगनेस को खत्म किया जायगा और सही मायनों में यदि हरिजनों के लिए कुछ करना है तो केवल यही नहीं कि हम उनकी कुछ मदद करें, यह भी करना होगा कि साथ-साथ उनको शिक्षित करें और उनकी मदद करने के लिए ज़रिये निकालें ।

आज कोआपरेटिव बैंकों और कामर्शियल बैंकों से किसको फायदा होता है । इन बैंकों से आज 70 फीसदी फायदा अमीरों को जा रहा है, छोटे किसानों और मार्जिनल किसानों को केवल 30 परसेंट फायदा हो रहा

[श्रीमति कमला बहुगुणा]

है । अमीर लोग तो स्टेट बैंक और दूसरे बड़े बकों से फायदा उठा सकते हैं । इसलिये यदि सही मायलों में हमें उनकी मदद करनी है तो कोआपरेटिव बैंकों और कामर्शियल बैंकों का ज्यादातर लाभ हरिजनों को मिलना चाहिये, छोटे कारीगरों को मिलना चाहिये, माइनारिटीज़ को मिलना चाहिये ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं—यदि हमें हरिजनों को वाकई उठाना है तो हर स्टेट में फाइनेन्स कारपोरेशन खुलवाने की व्यवस्था करनी चाहिये, जिसके ज़रिये हरिजनों को पैसा मिले और वे आगे बढ़ने की चेष्टा क सकें । इन को कोआर्डिनेट करने के लिये यदि आल इंडिया पैटर्न पर आप कोई फेड्रेशन बना दें, तो तमाम स्टेट्स में खोली गई फाइनेन्स कार्पोरेशन्ज़ की फैड्रेशन हो, तो इससे काफी मदद मिल सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हू । केपिटल-इम्पोर्ट इस कन्ट्री में इतना होना चाहिए जिससे कि अपनी इण्डस्ट्रीज़ को धक्का न लगे । हमारे पास फारेन रिजर्व्ज फैवरएबिल हैं लेकिन उसके बावजूद फारेन एड में दूसरे मुल्कों में कमी नहीं की गई है । मेरा कहना यह है कि इसमें कमी करनी चाहिए अगर हम अपनी इण्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ।

मैं आशा करती हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी इन सब बातों को देख कर इस प्लान को फिरसे गहराई से दिखलवायेंगा और फिरसे यह तैयार की जाएगी । इसमें कोई जल्दी नहीं है और हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए । हमारा मकसद, हमारी गाइडलाइन्स साफ होनी चाहिए और हमारे प्रोग्राम्स सही होने चाहिएं जिससे इम्प्ली मेंटेशन करने वाली मशीनरी उनको सही माइनों में इम्प्लीमेंट कर सके । अगर ऐसा होगा तब तो यह प्लान सही मायने में हिन्दुस्तान को आगे इन पांच सालों में ले जा सकती है अन्यथा यह प्लान एक स्वप्न बन कर रह जाएगी ।

इन शब्दों के साथ मैं खत्म करती हूं ।

SHRI VASANT SATHE (Akola) : First, let me express my gratitude and congratulations to the Prime Minister for setting an example of staying on throughout the debate to listen to practically every speaker who has spoken....

SHRI K. GOPAL (Karur) : But it is a great torture to him.

SHRI VASANT SATHE : Whenever he found that the speech was not interesting, he switched himself off.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : As he is doing now.

SHRI VASANT SATHE : I hope not.

Now, let us consider the whole question of planning from its basic objective and see whether we have really achieved the aims and objectives. Planning, essentially, is a process of mobilising the resources of a nation, both human as well as material for the good of the people. If this was the basic concept of planning, let us see, when we launched on this whole programme, what was our objective and to what extent we have achieved the objective and where we have gone wrong.

I would like to recall, without going into any doctrinaire considerations, the speech of Pt. Jawaharlal Nehru when he was replying to the debate on planning in 1963. He remarked :

" We are not tied upto any doctrinaire view of socialism. But these are fundamental to socialism, and which are accepted now in the greater part of the world, even in the capitalist world. There is no developing country that I know of, which does not accept them. A socialist approach is inevitable. There is no other way. I submit to this House with great confidence that if we adopted the capitalist approach, it would lead us nowhere.

Therefore, we have adopted a mixed economy. We have a private sector and a public sector being the more important, dominated the economic policy. Otherwise, there is no point in having a public sector to help the private sector. We want all kinds of things to be produced ; we want the private sector to be helped."

As a matter of fact, what is the private sector in our economy? The whole of our land is in the private sector. Our small industries are very largely in the private sector. Tfe whole conflict comes—not conflict exactly but a certain pull—for two reasons. Certain basic indusetries are in the private sector; some of the great ndustrialiists want more of them because not only they might prove to be very profitable but becasue it gives them economic power. I think, it is highly objectionable that economic power should be in the hands of the small group of persons, however able or good they might be. Such a thing must be prevented. That is our broad approach."

Now , these were the hopes. Have we been able to achieve this objective? The result of the mixed economy concept has been that the rich have grown richer and the poor have not only remained poor,but have grown poorer. The number of people below poverty line has gone up. Why ? This is because the very basic concept of capitalist formation in our country is distorted. Ultimately, whatever investible surplus is created in this country, it is the result of labour on land. The surplus generated by the produciion of goods is concentrated in the hands of the few. That Capital formation will be in-built in the system, called the capitalist system. That capitalist system essentially remains in the hands of the few for the benefit of the few. This has been the tragedy and the travesty and the distortion of our whole planning. All our efforts, all our investment that we have made, have gone so help a few Houses. It has been stated in this House and in this Plan also that the assets of the twenty large Houses were Rs. 650 crores in 1958 and their assets now in 1978 are Rs. 4,500 crores.

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी): यह सब किस ने किया ?

SHRI VASANT SATHE : It is not the question of who did it. The hon. Prime Minister was a part of the whole process for a long time. I am saying , look at this question ; this is a distortion. As long as this distortion remains, whatever investments that we may make, or you may increase the plan allocations, we will not be able to achieve the objectives.

It was stated that we are changing our whole direction to agricultural economy, and going to invest more in agricultural sector giving an impression thereby that the standard of life of the agricultural poor people will improve. How will that happen for the simple reason that whatever you may invest, or whatever has been invested before, gets mopped up by the magnet of the in-built mechanism of the few, who have the business and the trade and the capital in their hands. This is inherent in the system, this is not the fault of the individual, this is the fault of the system. My submission is that unless we pay attention to the change of this system, the capitalist system—you may not like any other system or if you do not like the word socialism, do not use that—the fact remains, we will not be able to achieve the objective. Now it has been stated—it is also not correct, I would like to point out—that we are really investing more in agriculture. Kindly see the amount spent on agriculture in all the five year Plans. In the first Five Year Plan it was Rs. 290 crores and 14·8— of the total outlay. In the Second Five Year Plan it was Rs. 549 crores and 11·7—. In the Third Five Year Plan we spent Rs. 1088 crores and it was 12·7%. In the Fourth Plan we spent Rs. 2320 crores which was 14.7% In the Fifth Plan we spent Rs. 4643 crores which was 11·8%. Now, we are going to spend Rs. 8,600 crores which is 12·4%. So it is not true that in terms of percentage of the total plan allocation we are doing something extraordinary by investing more in the agricultural sector. So, let us not unnecessarily praise our selves by saying that we are doing something extraordinary for the agriculturists.

The question is this. All this investment we may do. But where will this money go ? Because of the inherent weakness of the capitalist structure, whatever surplus that may be generated will again go in the hands of the few. Then you will set up Commissions to inquire where has this money gone as the Mahalanobis Commission was set up.

What did it find out ? They found that the black money, unaccounted money and undisclosed income had risen in this country to the projections of the Wanchoo Committee. That was in 1975. The magnitude of the undisclosed income in this country was Rs. 20,000 crores. To-day it may be even more. The Select Committee on Taxation Laws Amendment Bill of which I had the privilege of being a member went into this question. But nobooy is able to find a way out because taxation is a system of mopping up the surplus by telling the thief, 'You commit theft, you give me my share.' This is essentially a part of the capitalist structure. This wil never help in mopping up the rea surplus that may be created in the country. I therefore beg to submit one thing. Last time I had tried to find out certain figures and distortions that have taken place in the economy,from the Planning Commission and I was really surprised. I find that those whose incomes are between Rs. 200 per month and Rs. 1000

[Shri Vasant Sathe]

per month are hardly 1·71% of the population in the country. Let the Planning Commission find out whether this is true or not. Those whose incomes are above Rs. 100 per month are 0·4%. You know a person getting less than Rs. 200 per month cannot have fully even the necessities of life or a modicum of comfort. Therefore, you see the magnitude of distortion that has taken place in the country. You always think in terms to a capitalist system and demand and supply. All your productive activity in the country is restricted to what is known as the economic demand, the effective demand and that effective demand is of this 2·1% of the population, hardly a couple of crores of people . That is the market. All your productive activity takes place for that market, for those people. So, the country has an economy for mini India consisting of two to three crores and there is another India of 60 crores of people—our population being 63 crores. Therefore, for that India you have no Plan. You cannot have any planning. You have no control either on the resources or on productive activity or distribution activity. What is Planning if you do not control or are not able to regulate the two basic economic activities, viz., production and distribution? Therefore, my submission is that you will have to seriously think about it. I have absolutely no doubt about the sincerity of the Planning Commission or the Prime Minister. If they really want to take up this issue,—you will have to go to this whole question of basic structure, mixed economy. Let us be honest to ourselves. Unfortunately, it led us to the creation of an unmitigated, unmixed evil— master of black wealth and black money and a parallel economy in this country.

According to income-tax statistics of 1971-72, the total assessments during, 1971-72 were of 38,44,000 assessees, out of which 17,40, 719 are not reflected in the data as they did not result either in demand of refund.

Out of the total assessments of 21,09,108 assessees; those whose annual income was below Rs. 20,000 were approximately 17,45,078 and those whose income was between Rs. 20, 000 and Rs. 1,00,000 were about 3,35,988 and those whose income was above Rs. 1,00 000 were only 27, 442. It is also interesting to note that out of the total tax paid these assessees, those income was above 1,00,000 paid approximated 70 per cent of the total tax.

MR. DEPUTY SPEAKER : You have already taken 17 minutes.

SHRI VASANT SATHE : Our party has got more time.

MR. DEPUTY SPEAKER : The other members of your party have also to speak.

SHRI VASANT SATHE : My colleagues will allow me to have more time. I have taken permission from my colleagues.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : (Jadavpur) : What is that book from which you had been quoting ?

SHRI VASANT SATHE : On 1st June, 1975 I had submitted a paper and on that previous Planning Commission had said that there should be a national debate. That national debate never took place. I hope I will lay it on the table of the House. I will give it to the Prime Minister provided the Planning Commission organises a national debate on it.

MR. DEPUTY SPEAKER : Even so you have eight minutes more. There will be no laying here. You continue your speech.

SHRI VASANT SATHE : My submission is if you realy want to set these distortions right, the entire concept of planning must be to regulate both production and distribution activities. This can be done within the framework of democratic system. It is not necessary to adopt a totalitarian system. That can be done provided all productive sectors are brought under one discipline—call it 'social structure'. Once the Prime Minister had used this word 'social structure' as against nationalised structure because nationalisation, unfortunately has come to mean bureaucratisation, which leads to State capitalism which is of no use. You bring in social structure, I do not mind.

Similarly distribution—all your marketing activities of the wholesale and retail traders should be brought under one national marketing organisation as a part of national discipline. You can easily regulate both productive and distributive activities. In every productive activity—whether it is public sector or private sector or whatever field it is—the workers have their role to play. These are the three main factors—workers financing institutions and entrepreneurs. Well why should these three factors not have equal control in the management ?

If workers and entrepreneurs have equal proportion by law in the Board of Management from Management right up to the floor level then workers cannot be cheated by the management of the real surplus. Similarly you have the financing institutions which give more than eighty per

cent of the finances of all private industries where the consumers goods production takes place where the real profits take place.

If they can have the controlling power, if they can have one-third representatives on the Board of Management then you can have one-third of labour representation. one third representation of the financing institutions. They will be the Government representatives. If you have this system you will be able to regulate their working and determine the surplus how this is to be used. Sir all surpluses of productive activities in the country must belong to the State so that the State can determine how it can be ploughed back for what benefit in which areas etc.

Now, Sir, regarding the production activity in the rural areas the basic constraint is this : In respect of whatever they produce where can they market it, because as I said the market is restricted to the urban areas consisting hardly of three crores of effective demand ?

So, if you have one national marketing organisation, then you can regulate the marketing.

There cannot be any competition from a monopoly house or a big house to push out an ordinary soap manufacturer a young man manufacturing soap or buckets or shovels or small boxes or anything like that in a rural area. He cannot be pushed out by the monopoly houses. So, you will be able to regulate all these things. That is the only way to ensure the creation of effective demand in the rural areas and supply all commensurate consumer wage goods to the people. That is the only way in which you can rise the standard of life of the people.

Otherwise, all your hopes will remain mere hopes. In your planning process you will again be faced with this very same problem. As long as you are at the mercy of 'Demand and supply' which is a capitalist concept, as long as all your planning is at the mercy of that, do what you may you will never be able to plan for the welfare of the millions of people of this country.

All your surpluses will again be mopped up by a few vested interests who control so much of black money in this country. They and the bureaucracy are the permanent factors. Actually you don't run the Government; you are wrong if you think so. The bureaucracy which is the permanent factor, thinks it is they who are running the Government. They a re hand-in-glove with the capitalist syste m as a whole the capitalist vested-interest class. They together today, with the tremendous parallel economy and money power they have control this Government. You and I, on different sides go at each other's neck at each other's throaht quarrel with each other. But they are enjoying laughing sitting there knowing fully well let these people quarrel and fight among themselves, we ultimately control the administration we are the permanent factor. This is what they think.

Now the question is : Can you change this basic structure? Can you take away their real capacity to mop up the resources of this country? By Taxation you can never do it. You can even break your head against a rock but it is impossible. You tried it in this country. What happened ? Much money went under- ground. That is how black-money has grown in this country.

And now take the question of undisclosed income. The hon. Finance Minister was today replying to a question. He said that enquiries are going on, investigations are going on., etc. They will go on endlessly. The hon. Finance Minister will never be able to touch them. Because, your machinery is not capable of it.

Therefore, Sir, I would submit that in respect of all this planning , you will have to re-think in terms of the system that you have. The fault really is not of the individuals at all.

There is a very good couplet in Sanskrit which says :—

अमंत्रम् अक्षरं नास्ति ।
नास्ति मूलम् अनौषधम् ।
अयोग्यः पुरुषो नास्ति ।
योजकः स्तत्र दुर्लभः ॥

It means : What is 'durlab' is 'yozak'. Be that 'yozak'. That is the real planner who can think in terms of total mobilisation of resources of the country.

Sir, we are sixty crores of people. Japan has only four crores of people. What do they do ? They do not have resources . They bring all the raw material from out-side and produce goods and sell them to the world. They are producing 110 million tonnes of steel. Here we with a population of 60 crores when think of producing 7 million tonnes of steel we start perspiring . We get worried for the market of our iron-ore. We have

[Shri Vasant Sathe]

huge resources of coal but we do not know what to do with that coal. It is only when you think in terms of sixty crores that you can produce and give them productive activity. With so much of labour force you can flood the world market with goods. That means you will have to determine and regulate. Within the democratic frame-work have such systems so that you can regulate all productive activity, marketing and distributing activity without being unfair to anybody. Then you will know where is the surplus and how that surplus is to be used. That is the basic approach to which I wanted to invite the attention of the Prime Minister. If routine thinking is to be done, if just multiplication of planning is to be done, namely, this time you have doubled and next time you will treble or this time you have allocated so much for this sector and next time you will allocate more for that sector, by this type of thinking we will only go on breaking our heads and there will be total waste of energy not only of yours but also of the whole country. Kindly give thought to this. Then you will find that there will be a feeling of belonging and energising the whole nation.

Today, Sir, so much of our energy and time in this country is being wasted unfortunately in non-issues. That is the real fear. Our anger is wasting our energy on non-issues and the latest example of non-issue—I cannot help but express it—is that this Government, this mighty Government, with whole power at its command, Sir, could plead with the court to put in jail a young boy who has no backing of this kind. This is what has pained me. I want to say so. I am sorry this has been done.

MR. DEPUTY SPEAKER : Dr. Baldev Prakash. Since you want to go and you won't be coming tomorrow you please try to complete your speech in four minutes.

DR. BALDEV PRAKASH (Amritsar): It is not possible to finish in four minutes. Let me start and I will continue tomorrow.

MR. DEPUTY SPEAKER : No. No. Shri Chandra Pal Singh.

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर इस सदन में विचार-विमर्श चल रहा है उसके बारे में यह जरूर देखना पड़ेगा कि अब तक की जो योजनाएं रही हैं—पांच योजनाएं बीत गईं—उन योजनाओं का जो लाभ देश को मिलना चाहिए था वह मिला या नहीं । जैसा कि और विद्वानों ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो सुविधायें अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए थीं वह कुछ ही लोगों तक पहुंच पाई हैं । आज जो योजना का प्रारूप हमारे सामने है उसमें इस बात पर ोर दिया गया है कि 80 फीसदी जनता जो कि देहातों में रहती है उसके ऊपर विशेष बल दिया जाये । इस तरह की जो सुविधायें उनको अभी तक नहीं मिली हैं, वे उन को मिलनी चाहिए । चारों तरफ सिंचाई हो, बिजली हो, वे तमाम सुविधायें जो देश को उठाने के लिये आवश्यक हैं—जैसा योजनाओं में प्रायः हुआ करता है, उसी तरह का जोर इसमें भी दिया गया है ।

इस अवसर पर मैं दो-तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज तक जो योजनायें बनी, उनकी असफलता के कारण जनता योजनाओं के प्रति उदासीन हो गई है । रोज़ योजनाओं की बातें चलती हैं, गांव से लेकर दिल्ली तक योजनायें-ही-योजनायें, लेकिन उनका फल आज तक देश को नहीं मिल पाया, जहां तक मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल पाया है । सब से पहली बात तो यह है कि देश में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त है । सारे देश में जहां तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिये, वहां तक नहीं पहुंच पाता है । भ्रष्टाचार की एक ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा ।

MR. DEPUTY SPEAKER : You can continue tomorrow.

Now, let us go to the Private Members' Legislative Business—Introduction of Bills.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Sir, I want to make a

submission before you take up the Private Members' Business.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY SPEAKER : You should have made your submission then and there. It is very unfair. After we have started the Private Members' Business, you should not discuss the previous subject. Now, nothing except the matter concerning the Private Members' Business will go on record. Anything else will go off the record.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, Item No. 1—Shri Ugrasen— Not here. Item No. 2—Shri Manohar Lal—Not here. Then again Item No. 3—Shri Ugrasen—Not here. Item No. 4—Shri R. D. Gattani.

15·31 hrs.

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL†.

(Amendment of Section 95).

SHRI R. D. GATTANI (Jodhpur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939".

The Motion was adopted.

SHRI R. D. GATTANI : Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : Next item—Shri Raj Krishna Dawn— Not here. Next item No. 6. —Shri Tej Pratap Singh.

15·31 ½hrs.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL †

(insertion of new section 404).

श्री तेज प्रताप सिंह (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973."

The motion was adopted.

श्री तेज प्रताप सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

15·32 hrs.

TRADE AND MERCHANDISE MARKS (AMENDMENT) BILL†

(Amendment of sections 78, 79, etc.)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : (Delhi Sadar) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Trade and Merchandiese Marks Act, 1958.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Trade and Merchandise Marks Act, 1958."

The motion was adopted.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Item No.8—Shri P. Rajagopal Naidu—Not here. Next item—Shri Raj Krishna Dawn—He is also not here. Then Shri G. M. Banatwalla.

15·32½hrs.

CONSTITUTION AMENDMENT) BILL†

(Amendment of article 30)

SHRI G. M. BANATWALLA : (Ponnani) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

**Not recorded.

†Published in Gazette of India Extra- ordinary, Part II, Section 2 dated 5-5-78.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. "

The motion was adopted.

SHRI G. M. BANATWALLA : Sir, I introduce the Bill.

15·33 hrs.

MINIMUM WAGES (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 2 and 3)

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mimimum Wages Act, 1948.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Minimum Wages Act, 1948 ".

The motion was adopted.

SHRIMATI PRAVATHI KRISHNAN: Sir, I introduce the Bill.

15·33½ hrs.

BEEDI AND CIGAR WORKERS (CONDITIONS OF EMPLOYMENT) AMENDMENT BILL*

(Amendment of sections 2, 17, etc.)

SHRIMATI PARVATHI KRISHANAN (Coimbatore) : I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to amendment the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966. "

The motion was adopted.

SHRIMATI PRAVATHI KRISHNAN: Sir, I introduce the Bill.

15·34 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of article 48 and Seventh Schedule)

SHRI R. D. GATTANI (Jodhpur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. "

The motion was adopted.

SHRI R. D. GATTANI : Sir, I introduce the Bill.

15·34½ hrs.

INDIAN TRUSTEESHIP BILL*

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे ट्रस्ट निगमों की स्थापना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of Trust Corporations and for matters connected therewith . "

The motion was adopted.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित† करता हूं ।

MR. DEPUTY -SPEAKER : Now, let us take up Mr. Kamath's Bill which was under discussion last time.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary , Part II, Section 2, dated 5-5-1978.

†Introduced with the recommendation of the President.

15·35 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL— *contd.*

(Amendment of Article 51).

by Shri Hari Vishnu Kamath

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) I beg to move:

"That this House do suspend rule 75(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires the moving of amendment that the Constitution (Amendment) Bill, 1977 (*Amendment of article* 51) by Shri Hari Vishnu Kamath be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon at an early stage. "

I also move :

"That the Constitution (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of article 51) by Shri Hari Vishnu Kamath ....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Deo, please listen. You cannot go on reading what you want, disregarding the chair. You have to move first for the suspension of the rule and then only you can read the other motion.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I do not want to oppose the suspension on condition that there will not be any discussion and only voting will take place. We have been discussing this for the last three weeks. Otherwise I will be losing the opportunity of moving my Bill. And Shri Shastri will also be losing his opportunity.

SHRI P. K. DEO: I should like to make a few subsmissions in this regard. It is the compulsion of my conscience which has forced me to move this motion. India with her ancient cultural and spiritual heritage has in all ages shown light in darkness, whether it was Lord Buddha or Gandhi or Vivekananda. Today in the seventies of the 20th century, how can we allow such a laudable Bill to lapse ?

I very carefully went through the speech of the learned Law Minister Shri Shanti Bhushan. The hon. Law Minister in his speech in one breath " apprehends surrender of sovereignty, the concept that India is a sovereign , socialist, secular democratic republic, to uphold which we are pledged. " According to him the acceptance of this Bill will amount to surrender of national sovereignty. What is national sovereignty ?

आसेतु हिमाचलम उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रि च्चैव दक्षिणम वर्षं भारतम् नाम भारतीय यत्रे सन्तति ।

What was the concept of national sovereignty when in the lust for power this motherland was vivisected and we got a truncated India. I being one of those who placed what I had at the feet of mother India to build a united India, reconcile myself to this truncated India. The less we talk of sovereignty the better it is not that after the lapse of paramountcy the so called sovereignty of the erstwhile Indian States returned to uphold which the Government of India was a party in the instrument of accession. But did that work? Things and events move so fast that preservation of sovereignty become just an academic exercise.

In the other breath the Law Minister Spoke very highly about Shri Kamath and he euologised him as an acknowledged artist trying to paint a bright future and said : "World government has to be established . It is essential. In fact it is inevitable and that is the only solution for preventing the catastrophe facing the entire humanity." These are the two contradictions. How can we compromise ? The only compromise between these two statements of the hon. Law Minister is Mr. Kamath's Bill which provides an answer which provides the substitution in the Directive Principle. It is just a pious hope and to achieve that end we may educate our people. We cannot afford to scotch this Bill or throttle this Bill. Let it not die: let us circulate it for eliciting public opinion and educate the people inside and outside the country. It can go to a Select Committee. I consider that the Prime Nubuster Minister is a world citizen. All along he has said : Vasudeva Kudumbakam. I hope that the hon. Law Minister will accept my amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You must first move the motion for suspension of rule.

SHRI P. K. DEO : I have already moved it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House do suspend rule 75(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires the moving of amendment that the Constitution (Amendment) Bill, 1977 (*Amendment of article* 51) by Shri Hari Vishnu Kamath be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon at an early stage. "

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Shankar Dev.

SHRI P. K. DEO : Mine is item No. 4. How can he precede me ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I thought you have already moved it. He is only speaking on it.

SHRI P. K. DEO: I beg to move:

"That the Constitution (Amendment) Bill, 1977 (*Amendment of Article* 51) by Shri Hari Vishnu Kamath be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 10th August, 1978."

SHRI KANWAR LAL GUPTA: We supported the motion for suspension of rule—I think Mr. Kamath also agreed to it—on the condition that there will be no further discussion. After they move the motions, you kindly take the vote.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Shankar Dev.

SHRI SHANKAR DEV (Bidar): I beg to move:

"That the Constitution (Amendment) Bill, 1977 (Amendment of article 51) by Shri Hari Vishnu Kamath be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 14th August, 1978."

श्रीमन्, पिछली बार जब यह बिल सेशन में आया था तो उस वक्त हमारे विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री ने यह कहा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में सोचने के लिए यह वक्त नहीं है, यह मौका नहीं है । किन्तु थोड़े दिन पहले ही जब डिसआर्मामेंट के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा चल रही थी तो स्वयं विदेश मंत्री श्री वाजपेयी जी और उसके बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह बात दोहरायी थी कि विश्व के अन्दर विश्व शक्तियों द्वारा इतना बारूद इकट्ठा किया जा चुका है कि वह तमाम विश्व को 15 बार भस्म कर सकता है । आज जब कि समस्त विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, उस समय हम यह कहें कि अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में सोचने का समय नहीं है यह बड़े अफसोस की बात है । क्या जब आधी दुनिया समाप्त हो जाएगी, जब एटम बम तमाम चीजों को खत्म कर देंगे, उस वक्त हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट बना कर इसका इलाज सोचना होगा ?

बाद में हमारे ला मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी कन्ट्री सोवर्न डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक है । उन्होंने अपनी सोवर्निटी के बारे में बहुत जोर दिया । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया था और वह हमारी धरती पर घुसता चला आ रहा था तो क्या हम युनाइटेड नेशंस में उसकी सहायता लेने नहीं गये थे ? इसी तरह से हमारी हजारों एकड़ जमीन चीन ने हमला कर के हथिया ली है । हम इन दोनों वक्तों में देखते रहे । क्या उस समय हमारी स्टेट सोवर्न नहीं थी ?

इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रस्ताव हिन्दुस्तान जैसा देश ही कर सकता है। हमारे यहां मनु ने एक हजार साल पहले कहा था —

एतद्देश प्रसूतस्य
एकाशादग्र जन्मनः
स्वं स्वंन चरित्रं शिक्षेवंश
पृथिव्यां सर्वे मानवाः

हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के सब लोगों को अपने यहां आचार और सदाचार का अध्ययन करने की सुविधा देता रहा है और यहां से आचार और सदाचार सिखा कर लोगों को भेजता रहा है । हिन्दुस्तान एक शान्तिप्रिय देश है । इसलिए हिन्दुस्तान को ही सब से पहले वर्ल्ड गवर्नमेंन्ट के बारे में पहल करनी पड़ेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Mr. Deputy Speaker, Sir, I have no difficulty in accepting the proposal which has been made. As I had said on the last occasion, there was no quarrel whatsoever with the objectives of the Bill which had been brought. I had only pointed out as to what were the difficulties in the way of the Government accepting the Bill. But so far as the question of the Bill being circulated for eliciting public opinion is concerned, I donot object to that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Constitution (Amendment) Bill, 1977 (*Amendment of Article* 51) by Shri Hari Vishnu Kamath be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 10th August, 1978."

The motion was adopted

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Mr. Deputy Speaker, Sir, in all humility I would like to say that it is a day for rejoicing. India is the first country in the world whose Parliament has taken a step towards World-Government, and I thank the Government as also the Members of Parliament for having taken this very wise decision today on this historic occasion. The 5th of May, 1978 will be remembered in the annals of our country.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Let us congratulate Mr. Kamath.

MR. DEPUTY SPEAKER The other motions are all barred. Now we take up Shri Kanwarlal Gupta's Bill.

15.46 hrs.

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of Section* 10)

श्री कंवर लाल गुप्ते (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 को और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेरा जो विधेवक है मैं समझता हूं कि इस में बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी और सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करेंगे। इस में यह मांग की गई है कि जितने राजनीतिक दल हैं उनको जो इनकम होती है वह आयकर से मुक्त होनी चाहिए, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस वक्त मूवेबल और इन्मूवेबल प्रापर्टी से उनको जो आय होती है उस पर इनकम टैक्स और वैल्थ टैक्स भी लगता है। सैक्शन 10 जिस के तहत इनकम टैक्स एक्ट में एक्जैम्पशंज दी गई हैं उस में राजनीतिक दलों को नहीं दी गई हैं। मेरी मांग है कि उनको भी दी जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि पोलिटिकल एजुकेशन जो है वह भी हमारे देश की शिक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हमारे लोग राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित होंगे, उनको पता होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए तो यह देश आगे प्रगति करेगा और अगर नहीं होंगे तो नहीं करेगा। किस तरह का ढांचा देश में होना चाहिए, सैक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक्क होना चाहिए, मार्किस्ट होना चाहिए, तानाशाही होना चाहिए, यह सब जब तक लोगों के सामने ठीक तरह से नहीं रखा जाएगा और उनको एजूकेट नहीं किया जाएगा तब तक मुझे दुख है कि हमारे लोग ठीक निर्णय नहीं ले सकेंगे और उसका परिणाम हमारे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत घातक हो सकता है। देश के विकास के लिए भी जरूरी है कि सब राजनीतिक दलों के पास इतने रिर्सोसस हो कि वे अपनी विचारधाराओं का ठीक प्रकार से प्रचार कर सकें और आयकर उन से लेना मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा और ऐसा करना उनके रास्ते में बाधा डालना होगा। अगर लोग ठीक तरह से पोलिटिकली एजुकेट नहीं हुए तो देश का डिवेलेपमेंट भी रुक जाएगा, हमारा प्रजातंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा और तब क्या होगा यह कहना मुश्किल है।

15.47 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR *In the Chair*]

मार्च, 1977 में हमारे देश में क्रान्ति आई उसका एक ही कारण था कि राजनैतिक दृष्टि से देश में एक कांशैंसनैंस थी और उसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग देश में तानाशाही लाना चाहते थे उनको लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। इस लिए मेरी मांग है कि कोई भी राजनीतिक दल हो अगर वह इलैक्शन कमीशन से रिकगनाइज्ड है तो उस पर आयकर नहीं लगना चाहिए।

एक दूसरी शर्त भी है। हर राजनीतक दल अपने एकाउन्ट्स को ठीक तरह से मेंटेन करे। साल के बाद उनका उसको आडिट करवाना चाहिए और आडिट करवाने के

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

बाद एकाउंट्स को जनता के सामने रखना चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि उसकी कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडीचर है और लोगों को पता लग जाना चाहिए कि उसके पास कहां से पैसा आया और कहां खर्च हुआ और इस में कोई गड़बड़ तो नहीं हैं। लोगों की पोलीटिकल एजूकेशन के लिए यह बहुत जरूरी है। अब मूवेबल और इम्मूवेबल प्रापर्टी में जो इनवेस्टमेंट होता है, उस पर वैल्थ टैक्स आदि टैक्स लगते हैं। मैं चाहता हूं कि सब पोलीटिकल पार्टियों के एकाउंट्स आडिट होने के बाद पब्लिक किये जाने चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि जो लोग पैसा देने वाले हैं और जिन के जरिये से कोई पैसा आता है, उनके नाम भी पब्लिक के सामने आने चाहिएं। मैं मानता हूं कि यह बिल कोई काम्प्रिमा हेसिव बिल नहीं है--इस बारे में सरकार को कोई काम्प्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए--, बल्कि मैं ने केवल सिद्धांत रूप में बता दिया है कि सरकार को राजनैतिक दलों पर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहिए।

इमर्जेन्सी के दौरान और उससे पहले हम ने देखा कि पिछले तीस सालों में राजनीतिक पर धन का प्रभाव लगातार बढ़ता गया, और इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े सरमायादार राजनीति पर छा गये। वह नहीं होना चाहिए और इस की रोक-थाम के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

आपको मालूम होगा कि यूथ कांग्रेस के 22 लाख रुपये किसी एक व्यक्ति के नाम से हरियाणा में जमा थे। हमारी सरकार बनने के बाद वह व्यक्ति पकड़ा गया। सी० बी० आई इस बारे में भी एनक्वायरी कर रही है कि कांग्रेस का फंड कैसे आया, किस तरह उस का दुरूपयोग और एमबैजलमेंट हुआ। जब हम यह मांग करते हैं कि पोलीटिकल पार्टियां इनकम टैक्स से फ्री हों, तो इन बातों को रोकने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए।

हम यह भी चाहते हैं कि पोलीटिकल पार्टियों का पैसा एक सेक्रिड और पाक चीज होनी चाहिए, ताकि कोई आदमी उस का एमबैजलमेंट या दुरूपयोग न कर सके। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति पर पैसे का इतना अधिक प्रभाव न हो। यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हर एक पोलीटिकल पार्टी जब आडिटिड एकांउट्स दे, तो उस में यह भी दर्ज हो कि पैसा कहां से आया, किस ने दिया और किस ने कलेक्ट किया--उन सब के नाम आने चाहिएं, ताकि उस पैसे में एमबजलमेंट न हो सके।

संजय गांधी ने क्या किया? इन्दिराजी ने क्या किया? मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं ने एक सवाल पूछा था, जिस का फिनांस मिनिस्टर ने तीन दिन पहले जवाब दिया है। एक मि० भाटियां हैं। कांग्रेस--जो अब **कांगी** हो गई है--कि तरफ उन का सिर्फ टेंट का बिल करीब डेढ़ करोड़ रुपये का है, जो उन्होंने लिया। उन्होंने उस को एकाउंट्स में जमा भी नहीं किया। वह अपना बिल बढ़ा-चढ़ा कर देते थे और उस का कुछ पैसा अपने पास रखते थे और कुछ पैसा नेताओं को देते थे। सी० बी० आई० इस मामले की भी एनक्वायरी कर रही है। इन बातों की भी रोक-थाम होनी चाहिए। इस के लिए जरूरी है कि पैसा कहां से आया और कौन लाया, यह सब पब्लिक होना चाहिए, और ये एकाउंट्स आडिटिड हो कर लोगों के सामने आने चाहिएं।

सब मंत्रियों पर, चाहे वे राज्यों के मंत्री हों या केन्द्र के मंत्री, **बाई ला** यह पाबन्दी लगानी चाहिए कि वे पोलीटिकल पार्टियों के लिए फंड इकट्ठा न कर सकें। अगर हम ने अपने सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लानी है, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करनी है, देश में ऐसा आदर्श रखना है कि राजनीति पर पैसे का प्रभाव न हो, तो यह जरूरी है कि जो लोग सत्ता में सीधे हैं चे डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली किसी

तरह से भी पैसा इकठ्ठा न करें । तब तो मैं समझता हू कि जनता पार्टी तीस साल की जो गन्दगी है उस गन्दगी को दूर करने में कुछ हद तक कामयाब होगी ।

(i) एक इस में यह भी लाना चाहिए कि अगर कहीं पार्टी फंड का मिसयूज हो, एम्बैजलमेंट हो तो उस में भी कानून के अनुसार उस को सजा मिलेगी । चाहे वह किसी पार्टी का हो । यह भी उस में होना चाहिए । अभी साठे जी ने कहा कि संजय गांधी की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कैंसिल कर दी । लेकिन अभी तक उन को गिरफ्तार नहीं किया गया । पुलिस वालों ने कहा कि आज हम किसी वक्त गिरफ्तार करेंगे यह कानून के खिलाफ हैं । जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उन की जमानत कैंसिल की थी उसी समय गिरफ्तार करना चाहिए था, कानून यह कहता है । कानून हर एक के लिए बराबर होना चाहिए । वह पुराना इतिहास नहीं दोहराया जाना चाहिए कि जब इन्दिरा गांधी को पकड़ने के लिए गए तो इन्दिरा गांधी ने क्या नाटक किया । पुलिस को उसी समय गिरफ्तार करना चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि कानून के खिलाफ काम किया जाए । हम रूल आफ ला में विश्वास करते हैं । रूल आफ ला को हम मानेंगे । लेकिन उनको एकदम तिहाड़ जेल में ले जा कर रखना चाहिए था । हम भी वहां रहे हैं । एक ही महीना तो उन्हें वहां रहना है । सेशन फोर्ट में जैसे हमें लाया जाता था मैं चाहता हूं कि उसी तरह उनको भी लाया जाये । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह गृह मंत्री से कहें, सदन की भावनाएं, उन के पास कन्वे की जानी चाहिए कि उन के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव हो लेकिन कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए । जो उन्होंने जुर्म किया है उस जुर्म के हिसाब से भी क्लास तो शायद उन्हें मिलेगी नहीं क्योंकि ग्रेज्युएट तो वह हैं नहीं । उस हिसाब से तो बी क्लास नहीं मिल सकती । लेकिन शायद वह इन्कमटैक्स देते हों तो भी बी क्लास मिल सकती है । खैर, वह तो मजिस्ट्रेट तय करेगा । लेकिन कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए और अननेसेसरी हरेसमेंट भी नहीं होना चाहिए ।

(ii) मेरा कहना यह है कि यह जो पोलिटिकल पार्टी के पैसे का एम्बैजलमेंट और मिसयूज है, उस पर जनता पार्टी अब रोक लगा दे और मंत्रियों पर भी यह रोक लगनी चाहिए कि वह पैसा इकट्ठा न करें । एक चीज की मैं इस में अपवाद भी करना चाहता हूं । अगर आज जनता पार्टी इन्वेस्टमेंट कर के इन्कम करती है मूवेबल प्रापर्टी या इम्मूवेबल प्रापर्टी से तो उस पर तो एग्जम्पशन होना चाहिए लेकिन अगर कोई पोलिटिकल पार्टी बिजनेस करने लगे, मान लीजिए कि जनता पार्टी हुकूमत में है, हमें अपनी पालिसी मालूम है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करने लगे प्राफिट मोटिव से तो उस में एग्जम्पशन नहीं होना चाहिए । किसी ट्रेड का काम कोई भी पोलिटिकल पार्टी करे तो वह एग्जम्पशन में नहीं आना चाहिए । हां, जो डोनेशन से पैसा आए चाहे मेम्बर से हो या नान-मैम्बर से हो, या इन्वेस्टमेंट से हो मूवेबल या इम्मूवेबल प्रापर्टी के, वह एग्जम्पट होना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : पोलोटिकल पार्टी बिजनेस भी करती है ?

श्री कंवर लाल गुप्त: करती है । आप की पार्टी ने किया । अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं बता सकता हूं ।

16.00 hrs.

एक चीज की मांग मैं और माननीय मंत्री जी से करूंगा कि काम्प्रीहेंसिव बिल लाने से पहले एक सिस्टेमेटिक स्टडी करें।

I want to suggest to the Minister that he should make a scientific study of the whole problem, how to utilize the funds of a political party properly, how should they collect it, how should them to utilize

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

it and see to it that there is no embezzlement or misuse of money by any person, whomsoever it may be, highest or lowest. so, a proper study should be made, keeping in view the experience of the last 18 months in particular.

और उसको दृष्टि में रखते हुए मंत्री महोदय बिल लायें। किस तरीके से मंत्रियों ने और प्रधान मंत्रियों ने पार्टी के नाम से पैसा लिया है वह तो आपको मालूम ही है। मंत्री लोग जब पैसा लेते हैं तब यही कहते हैं कि पार्टी के लिए जरूरत है। पार्टी के नाम से ही सारी खुराफात होती है। वे यह कभी नहीं कहते कि मुझे पैसे की जरूरत है, अपनी जेब के लिए पैसे की जरूरत है बल्कि वे कहते हैं पार्टी के लिए चाहिए, एलेक्शन के लिए चाहिए, पार्टी के रोज़ रोज के खर्चे के लिए चाहिए। पार्टी के नाम से ही वे सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पोलिटिकल लाइफ पर पैसे का प्रभाव न हो, इसके लिए हमें पाबंदी लगानी चाहिए कि किसी भी सर्कम्सटांस पर मंत्री लोग पैसा इकट्ठा न करें।

ट्रेड यूनियन की इनकम पर टैक्स एग्ज़म्शन है इसलिए अगर पोलिटिकल पार्टी को भी एग्ज़ेम्ट कर देंगे तो दोनों [illegible] जायेंगे। जब ट्रेड यूनियन की इनकम पर टैक्स नहीं लगता तो मैं समझता हूं पोलिटिकल पार्टी की इनकम पर भी नहीं लगना चाहिए। मैंने सुना है--पता नहीं कहां तक सही है--कि सरकार ने इस बारे में कुछ विचार किया है और शायद सरकार इससे सहमत भी है, मंत्री महोदय इसको बतायेंगे लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।

एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव के दिनों में अगर पैसे के प्रभाव को कम रखना है तो जो कम्पनीज़ के ऊपर डोनेशंस और एडवर्टीज़मेन्ट पर पाबन्दी है वह रहनी चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कंपनीज़ पर पाबंदी नहीं रही तो शेयर-होल्डर्स का करोड़ों रुपया इस तरीके से पोलिटिकल पार्टीज़ में जायेगा और उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए यह जो व्यवस्था है वह बनी रहनी चाहिये।

इससे ज्यादा कुछ और न कहते हुए, मेरे जो दो तीन सुझाव हैं, मैं चाहूंगा उन पर मंत्री जी अपने विचार रखें। एक बात तो मैंने कही है कि स्टडी करके एक कांप्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए, दूसरे मंत्री लोग किसी भी हालत में पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा न करें--इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और जो लोग पोलिटिकल फंड्स का मिसयूज़ करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यह भी प्रावधान हो कि पोलिटिकल पार्टी की इनकम पर टैक्स एग्ज़ेम्शन होगा। इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक पेश करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, be taken into consideration."

श्री युवराज का मोशन है, वे मूव करना चाहते हैं? वे उपस्थित नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र झा सुमन का भी मोशन है--वे भी नहीं हैं।

डा० रामजी सिंह: आपके अमेन्डमेन्ट क्लाजेज़ पर हैं । आप बोल लीजिए ।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र कंवरलाल गुप्त जी ने इनकम टैक्स के संशोधन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है और उसके बाद जो उन्होंने कुछ भावनायें व्यक्त की हैं उसके तो मैं साथ हूं लेकिन जैसा वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह बिल अत्यन्त अपर्याप्त है और इस बिल को प्रस्तुत करने में उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि सरकार एक कांप्रिहेंसिव बिल लाये जिसमें और बातों की भी चर्चा हो । जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, उससे राजनीतिक दलों को मुक्ति देने की बात करते हैं तो हमारे सामने एक संशय भी उपस्थित हो जाता है । एक तो देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि भ्रष्टाचार ही देश में शिष्टाचार बन गया है और यह भी सत्य है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री राजनीति है । जब तक राजनीति में भ्रष्टाचार का निराकरण नहीं होगा, तब तक प्रशासनिक भ्रष्टाचार या व्यावसायिक भ्रष्टाचार का भी निराकरण नहीं हो सकता है ।

आज प्रातः काल ही हम लोगों ने देखा—बिरला घराने पर जो आय-कर बाकी है, आज वर्षों से उस के ऊपर अनुसन्धान चल रहे हैं, लेकिन पिछले 30 वर्षों की राजनीति में संरक्षण देने के कारण आज बिड़ला के यहां जनता का जो करोड़ों रुपया बाकी है, वह वसूल नहीं हो पाया है । इसलिये यह आवश्यक है—यदि हम भ्रष्टाचार का निर्मूलन करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें राजनीतिक जीवन से करनी होगी । इस के लिये जैसा हमारे माननीय मित्र श्री कंवर लाल गुप्त ने कहा है—मेरा संशोधन भी इसी प्रकार का है—राजनीतिक दलों को भी अपना हिसाब किताब रखना चाहिये—यह उचित ही है । आज अन्य सब के ऊपर नियन्त्रण है, व्यावसायिक संस्थाओं को न केवल हिसाब-किताब रखना पड़ता है, बल्कि आडिट भी कराना पडता है, लेकिन राजनीतिज्ञों पर कोई नियन्त्रण नहीं है । यही कारण है कि राजनीतिक में हिसाब-किताब के सम्बन्ध में जो स्वेच्छाचारिता है, उसके कारण ही राजनीति में इतना भ्रष्टाचार होता है और इसी राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण व्यापारियों से करोड़ों रुपया वसूल किया जाता है ।

मैं किसी विशेष दल के सम्बन्ध में यह बात नहीं कह रहा हूं लेकिन इन भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए, जैसा मुझे मालूम है, किसी सम्मानित सदस्य ने एक बिल भी यहां पर उपस्थित किया है, जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक दलों के हिसाब-किताब को भी दूसरी संस्थाओं के हिसाब किताब की तरह पाक साफ रहना चाहिये और लोगों के सामने सार्वजनिक अवलोकन के लिये पेश किया जाना चाहिए । जहां तक इस इन्कमटैक्स बिल का सवाल है, सभापति महोदय, आप को मालूम है—27 अप्रैल, 1961 को ही यह इन्कमटैक्स बिल हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी यहां लाये थे, उसके बाद 10-8-1961 को इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया, 18-8-1961 को फिर इसे सदन में प्रस्तुत किया गया, उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी कि क्या स्वयंसेवी संस्थाओं को जो पैसा दिया जाता है, उसमें छूट दी जानी चाहिये या नहीं । सिलेक्ट कमेटी में हमारे मसानी साहब ने एक नोट आफ डिसेंट दिया था । जैसा हमारे कंवरलाल गुप्ता जी ने भी कहा है— राजनीतिक दलों का काम लोगों को लोक शिक्षा देना है, इसलिये उन पर कोई कर नहीं लगना चाहिये । इसी प्रकार से जब इन्कम टैक्स में छूट देने की बात हुई थी तो हमारे मसानी साहब ने यह कहा था

[डा० रामजी सिंह]

कि यह छूट दी जानी चाहिये, उन पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये : "We cannot legistlate people into goodness. We cannot take them into rationalisation."

मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि हम राजनीतिक दलों को छोड़ देते हैं, उन्मुक्त कर देते हैं तो उस से सब प्रकार के भ्रष्टाचार पैदा होंगे। इसलिये मैं तो यह समझता हूं—पहले इस बात पर विचार कीजिये कि राजनीतिक दलों की किस इन्कम को, कौन सी आय को छूट मिलनी चाहिये। अपने देश में तो ऐसे ऐसे राजनीतिक दल हुए हैं जो एक एक चुनाव में 27–28 करोड़ रुपया ऐठतें हैं—क्या ऐसे राजनीतिक दलों को छूट देंगे ? अगर कोई दल पूंजी इकट्ठी करके कोई आलीशान इमारत बना ले, तो इससे जो निहित स्वार्थ निकलता है, उस पर नियन्त्रण नहीं रह जायगा ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल भी जमीदारों की तरह से, धन्ना सेठ हो जायेंगे और उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे सम्मानित सदस्य—माननीय कंवर लाल जी अपने इस बिल के सम्बन्ध में मेरा जो संशोधन है, उस को स्वीकार कर लें तो शायद उन की भावना का और ज्यादा आदर होगा।

मैंने कहा है :

"Provided that this Bill not to be applicable...."

MR. CHAIRMAN: That will come at the stage of clauses.

डा० रामजी सिंह : इसलिए मैंने यह चीज उनके सामने रखी है। यह जो इन्कम टैक्स (एमेंडमेंट) बिल गुप्ता साहब का है, वह स्वयं अनुभव करते हैं कि यह अत्यन्त अपर्याप्त है और खास कर राजनीतिक दलों के संदर्भ में जब एक बिल लाना ही है तो एक अच्छा बिल लावें। यह बात ठीक है कि उन्होंने कहा है कि ट्रेड यूनियन संस्थाओं को आयकर नहीं लगता है, तो जब ट्रेड यूनियन संस्थाओं को नहीं लगता है तो क्या राजनीतिक दल कोई अछूत हैं उन को लगना चाहिए। उन को यह तर्क ठीक है। (व्यवधान) .... मैंने दूसरे भाव में यह कहा है, घृणा के भाव से नहीं कहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन की जो बात उन्होंने कही वह ठीक है लेकिन हम लोगों ने भी देखा है और सार्वजनिक जीवन का जो हमारा छोटा सा अनुभव है, उस के आधार पर मैं कह सकता कि चाहे ट्रेड यूनियन संस्था हो चाहे राजनीतिक दल हो, अगर इन की आमदनी और खर्चे पर और इन के हिसाब-किताब पर कोई नियंत्रण न हो, तो भारत वर्ष को भ्रष्टाचार से कोई बचा नहीं सकता हम तो देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो मुख्य मंत्री जो होते हैं वे लोगों से कहते हैं कि तुम 10,000 रुपये ले लो और तुम 10,000 रुपये ले लो और यह काम करो। इस प्रकार के वातावरण में, राजनीतिक भ्रष्ट वातावरण में हम अगर सदाचरण की कल्पना करें तो यह बिल्कुल बेकार है। इसलिये यह परम आवश्यक है कि हमें राजनीतिक दलों पर नियत्रण रखना चाहिए। सदाचार और भ्रष्टाचार नियंत्रण की शिक्षा दूसकों के लिये हो और मेरे लिए न हो, यह चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सदाचरण का पालन करें, आयकर की चोरी न करें और अपना हिसाब-किताब दुरुस्त रखें तो राजनैतिक दलों को आगे बढ़ कर अपनी आचार सहिता को न केवल प्रस्तुत ही करना होगा बल्कि उन को अपने आप को बने हुए नियमों और कानून में भी आबद्ध रखने के लिए तत्पर रहना होगा। इसलिए इन्कम टैक्स बिल के सम्बन्ध में उस समय जो बहस हुई थी, उस में सारी बातों पर विचार विमर्श किया गया था। इसीलिए क्लाज, 11, 13, और 215 में यह कहा गया है :

"The group of clauses relating to the income of charitable institutions, that is, clauses 11 to 13 of the Bill and

clause 215 defining charitable purpose received considerable thought. These clauses give effect to the recommendations of the Tyagi Committee that if any trsut accumulated its funds in excess of 25 per cent of its income in any year, the excess should be brought to tax.

तो जब हम स्वयंसेवी संस्थाओं की आमदनी पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो राजनीतिक दल करोड़ों करोड़ रुपया ले कर अगर कोई पूंजी का निर्माण करें और उस से देश में निहित स्वार्थों की स्थापना करें, तो उस पर कोई अंकुश न रखना यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे और इस सम्बन्ध में आप के माध्यम से गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि वे इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजें और उस के बाद वहां पर जैसा उन का सुझाव है सरकार एक काम्प्रीहैंसिव बिल लावे जिस में राजनीतिक दलों की भी बात हो। मैं यह नहीं चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का जो कार्य है राजनीतिक शिक्षण देना, जनता को शिक्षित करना जनतंत्र में और नागरिकता में, उसमें वे चूकें। लेकिन उस के बहाने आया राम, गया राम के व्यापार में राजनीतिक दल अपने को लिप्त नहीं करेंगे। इस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अगर सरकार भ्रष्टाचार निवारण के लिए सचमुच में कटिबद्ध है और जल्दी से जल्दी इसे करना चाहती है तो वह इसी सत्र में दल बदल पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लाये। वह केवल यही विधेयक न लाये बल्कि राजनीतिक दलों को अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखने पर भी बाध्य करे। उनको बाध्य करने वाला कानून भी यहां लाये। इतना ही नहीं राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य हो, कोई भी नेता हो, उसकी क्या आमदनी है, उसके क्या असेसट् हैं, उनको प्रकट करने का भी कोई कानून होना चाहिए। हम देखते हैं कि राजनीति में जो लोग प्रवेश करते हैं, या राजनीति में आते हैं तो उन से लोग पूछते हैं कि आपके पास गाड़ी है कि नहीं? वे ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई एम० पी० हो जाता है तो उस के पास सब कुछ हो जाता है। यह क्यों होता है? लोगों की जो राजनीति में प्रवेश करते हैं, उनकी सचमुच में यह आकांक्षा होती है कि राजनीति में प्रवेश करते ही उन्हें कुबेर का खजाना मिल जाए। वे समझते हैं कि उन्हें सारे लोगों की शक्ति मिल गयी है। हमें इन चीजों पर भी चोट करनी होगी तभी हम भ्रष्टाचार का निवारण कर सकेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आमदनी और लाएब्लिटी एवं असेट्स की घोषणा करे और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वह उसकी इन बातों को देख सकें। जब तक हम राजनीतिक दलों के प्रत्येक व्यक्ति को सचमुच में कानून के कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, जब तक राजनीतिक दलों के आय और व्यय को सार्वजनिक दर्पण में नहीं रखेंगे तब तक राजनीति में भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहेगी और जब तक राजनीतिक में भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहेगी तब तक व्यापारियों का भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने सम्मानित मित्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बिल के विषय में पुनः विचार करें और एक कम्प्रीहेंसिव बिल लावें जिससे कि राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त हो सके और राजनीतिक दलों को अवैध धन न प्राप्त हो सके।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति जी, यह जो विधेयक आया है, उस पर बोलते हुए मैं यह कहूंगा कि राजनीतिक पार्टी एक निर्गुण चीज है। असल में सगुण क्या चीज है? सगुण चीज उस पार्टी में काम करने वाले, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता हैं जिनके जरिए से पार्टी की सारी नीति का निर्धारण होता है, पार्टी का संचालन होता है। राजनीतिक पार्टी में जो पैसा आये, उस पर कर लगे या न लगे, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने वाले लोगों का

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

आचरण , व्यवहार, कारोबार महत्वपूर्ण है। यह चीज इसके दायरे में आनी चाहिए। डा० राम मनोहर लोहिया जैसे विद्वान ने एक जगह पर लिखा है कि मंच पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बातें क्रांतिकारी हुआ करती हैं। मंच पर कही गयी उनकी बातों से उनको न परखा जाए, बल्कि मंच से उतर कर उनका जो आचरण है, उसको परखा जाए। यह देखा जाए कि वह कहां रहता है, कहां सोता है, क्या खाता है, किससे दोस्ती करता है, उनके अनुसार यही चीजें किसी नेता के आचरण को परखने का आधार होनी चाहिए। यह एक बुनियादी सवाल है । पहले राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा है, उन पर कर नहीं लगा है । फिर जनता पार्टी यह काम करने को कैसे तैयार हो जाएगी कि राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा आवे और वह करमुक्त न हो जावे । अब तक कानून के रहते हुए भी किस राजनीतिक दल ने टैक्स नहीं दिया है ? ऐसा कानून है लेकिन किसी ने टैक्स नहीं दिया है । ये दोनों बातें देश में चल रही हैं। दूसरी तरफ सरकार के जरिए यह भी किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान में एक स्मारिका कांड में एक पार्टी ने तीन करोड़ रुपया जमा कर लिया, इस कांड में तीन करोड़ रुपया राजनीति की सत्ता के सर्व प्रमुख स्थान पर बैठी हुई ने हिन्दुस्तान के व्यापार का संचालन करने वाले एक नम्बर के आदमी बिड़ला से तीन करोड़ रुपया ले लिया। राजनीति की एक नम्बर की कुर्सी, प्रधान मंत्री, व्यापार की एक नम्बर की कुर्सी श्रीमान बिड़ला ये दोनों एक ही स्मारिका केस में मुजरिम होते हैं। मैं छोटे मोटे लोग छोटे मोटे भुगते जो होते हैं उनके साथ उनकी बात नहीं करता हूं। इस तीन करोड़ पर कितना आयकर सरकार को दिया गया, कुछ नहीं । राजनीतिक दल जो पैसा एकत्र करते हैं उसका संचालन कैसे होता है अगर यही देखें और इसको ठीक आप कर दें तो भारत की राजनीति परिमार्जित हो सकती है । जब तक वह परिमार्जित नहीं होगी देश से भ्रष्टाचार का अन्त नहीं होगा । तब तक भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करना निरी मूर्खता होगी। सब से बड़ी भ्रष्टाचार की जननी राजनीति है । इसी के गन्दे कूड़े पर भ्रष्टाचार के कीड़े जन्मते और पनपते हैं और विकसित होते हैं । अगर राजनीति शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए तो फिर हिन्दुस्तान में से भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो जाए ।

घूस लेने के कितने नाम हैं इसको आप देखें । दारोगा जी के पास जाए तो हमारे यहां बिहार में घूस नहीं मागेंगा, कहेगा सलामी लाए हो । कोर्ट में पेशकार घूस नहीं कहेगा, कहेगा पेशी दीजिएगा । किसी बड़े हाकिम के पास जाएं तो घूस नहीं मांगी जाएगी, कहा जाएगा कि कुछ डाली ला हो यानी कुछ नजराना उनको पहुंचाया जाए। राजनीतिक दल घूस नहीं मागते । उनकी घूस होती है चन्दा। घूस के अनेक नाम हैं। कहीं चन्दा घूस का नाम है, कहीं नजराना कहीं पेशी, कहीं सलामी। इस तरह से उसके अनेकों नाम हैं ।

जो राजनीति चलाने वाले होते हैं और जो सत्ताधारी दल होता है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। पैसा बटोरने के उसके पास अनेक यंत्र और अनेक साधन होते हैं। मेरे जैसा साधारण आदमी, गांव का गरीब आदमी अगर बेईमानी करना चाहे तो एक दो रुपए की बेईमानी कर सकता है लेकिन अगर कोई मंत्री बेईमानी करना चाहे तो बिना किसी को पता लगे, बिना ज्यादा मेहनत किए, केवल कलम की नोक से एक शून्य घटा बढ़ा देने से हजारों लाखो का मामला निपटा सकता है। जहां एक बिन्दु, एक शून्य, एक डैसीमल से इतनी बड़ी रकम की बात उठती है वहीं राजनीति को पवित्र करना भी हमारा सब से बड़ा कर्तव्य हो जाता है ।

डा० रामजी सिंह ने प्रश्न उठाया है कि केवल पार्लियामेंट के सदस्य ही नहीं, विधान सभाओं के सदस्य ही नहीं बल्कि आपको सोचना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल के पद पर आसीन व्यक्ति, अध्यक्ष हो, सचिव हो या उसकी कार्य समिति का सदस्य है, सब की सम्पत्ति के बारे में, सब के पास धन के बारे में जानकारी लेने का अधिकार आपके पास होना चाहिए। सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, सचिव बनता है, कार्य समिति का सदस्य बनता है तो क्या उसका प्रभाव अपनी सरकार पर कम रहता है। हम लोग राजनीति के अन्दर बचपन से ही रहे हैं, उसी में हम पले हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया से ले कर विधान सभा के सदस्य और अब यहां लोक सभा के सदस्य हैं। गांवों में साधारण पद से यहां तक आ कर हमने देखा है और जब मैं विधान सभा का सदस्य था उस समय भी मैंने कहा था—मैंने, माननीय श्री राम जीवन सिंह ने तथा औरों ने भी श्री जय प्रकाश नारायण के आह्वान पर विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था—कि हम लोग फटे हाल हैं, खाया पीया बराबर है, कुछ भी पास में बचा नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने लाखों की सम्पत्ति पाटना से बना ली है, जिन की लाखों की जायदाद आज भी पटना के शहर में विराजमान है। उन के बड़े बड़े मकान हैं। वे कहां से आये? मैं लोक सभा का एक सदस्य हूं और दूसरे भी लोक सभा के सदस्य हैं। लेकिन अगर वे बड़े होटलों में ठहरते हैं, बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, बड़ी अच्छी सवारी करते हैं, उन के बड़े ठाट-बाट हैं, तो क्या दुनिया इस को देखती है या नहीं? भले ही हम दुनिया को मूर्ख बनाना चाहें, मगर हम भूल जाते हैं कि हम दुनिया को दो आंखों से देखती हैं। जबकि दनिया हमें करोड़ों आंखों से देखते हैं, दो आंखो से देखने में कभी गलती हो सकती है; लेकिन करोड़ों आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई किसी दल का नेता या पदाधिकारी हो।

हमारे देश में राजनेता, नौकरशाह और व्यापार, इन तीनों के भ्रष्टाचार का संयोग रहा है—इन तीनों ने मिल कर देश में भ्रष्टाचार का अड्डा जमाया है। राजनेता से संरक्षण मिलता है व्यापार और नौकरशाह को, और व्यापारी तथा नौकरशाह अपने को संरक्षण देने वाले के प्रति उसी तरह से स्वामीभक्त होते हैं, जैसे कोई ऐलसेशन कुत्ता अपने स्वामी का भक्त होता है—इतनी बड़ी उन की स्वामीभक्ति होती है, यह सिद्ध हो चुका है।

राजनैतिक दलों के चंदे संग्रह किए जाते हैं, वे कहां से लिये जाते हैं? चुनावों में जो खर्च किए जाते हैं, वे कहा से खर्चे किये जाते हैं? चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पीपल्ज रिप्रेजेन्टेशन एक्ट के मुताबिक चुनाव में 33,000 या 35,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है। सभी लोग जब चुनाव-खर्च की रिटर्न दाखिल करते हैं, तो वे खर्च को 33,000 रुपए से कम दिखाते हैं, क्योंकि कानून की पाबन्दी है। अगर वे ज्यादा दिखायें, तो उन का चुनाव अवैध ठहराया जा सकता है। लेकिन क्या यह ईमानदारी की बात है कि सब लोग 33,000 रुपये सब 35,000 रुपए के अन्दर ही चुनाव जीत कर आते हैं? सच्चाई कुछ और है, ईमान की बात कुछ और है, कानून अपनी जगह कुछ और है।

अगर हम बिड़ला, टाटा या डालमिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो उन्हें कहां से नियंत्रित किया जायेगा। कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि बिड़ला के विरुद्ध बरसों से एनक्वायरी बैठी हुई है, लेकिन उस का कोई नतीजा नहीं निकला है। मुर्गी को फांसा गया है, लेकिन वह कोई अंडा नहीं दे रही है। बिड़ला जी के बारे में जांच करने के लिए आयोग बैठा हुआ

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

है, लेकिन अभी तक उस जांच का कोई नतीजा नहीं निकला है, बल्कि उस आयोग पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है।

जब से देश आजाद हुआ है—1947 से लेकर अब तक के बिड़ला जी के खाते को अगर देखा जाये, तो उसमें देश के बड़े से बड़े राजनेताओं के नाम दर्ज होंगे--उस में लिखा होगा कि किन को उन्होंने कितना पैसा दिया, किस पोलीटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। जब हिन्दुस्तान का पूंजीपति हिन्दुस्तान की राजनीति को बंधक रखता है, जब हिन्दूस्तान की राजनीति हिन्दुस्तान के पंजीपति के यहां कैद हो, तब अगर पोलीटिकल पार्टियों पर नियंत्रण नहीं रखा जायगा, तो वह राक्षस या अजगर को अनियंत्रित छोड़ देने के समान होगा।

इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ श्री कंवर लाल गुप्त से निवेदन करूंगा कि अगर जनता सरकार उनके इस विधेयक को स्वीकार करना चाहे भी, तो हम लोग कहेंगे कि यह जनता सरकार के नाम पर कलंक होगा। जिस सरकार को हम भ्रष्ट, दिशाहीन, दृष्टिहीन और पूंजीपतियों की संरक्षक संरकार कहते थे, जिस सरकार को हम सम्पूर्ण भ्रष्टाचार जननी कहते थे, उस सरकार ने कम से कम दिखावे के लिए पोलीटिकल पार्टियों पर नियंत्रण लगाया था। लेकिन अगर आज हम जनता पार्टी वाले, जो भ्रष्टाचार का समूल नाश चाहते हैं, भ्रष्टाचार का अन्त करना चाहते हैं, यह कहते हैं कि राजनैतिक दलों को जो चंदा मिलता है, उसको कर मुक्त टैक्स फ्री, कर दिया जाये, तो यह उचित नहीं है। बल्कि, यह साफ जाहिर होना चाहिए कि कोई राजनैतिक दल जो पैसा इकट्ठा करे, वह उसे बैंक में जमा करे, उस के थ्रू ही निकले और खर्च करे। राजनैतिक दलों पर यह नियंत्रण लगाने से उन्हें यह हिसाब देना पड़ेगा कि उन के पास कितना पैसा आया कहां से आया, कहां कहां खर्च किया और कितना खर्च किया। जब हिन्दुस्तान के समाज सेवी संगठनों और अन्य संगठनों पर टैक्स लगता है, तो राजनैतिक दलों को क्यों बरी किया जाये? राजनैतिक दल को छोड़ दिया जाय इसलिए कि आज जनता पार्टी पावर में आई है, जनता पार्टी की सरकार बनी है? राजनैतिक दल को जो चन्दा मिलता है उस पर से टैक्स का अन्त कर दिया जाय इसलिए कि जनता, यह समझे कि जनता पार्टी की सरकार बनी है, यह पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं यह पार्टी चाहती है कि करोड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा करे जिस का कोई हिसाब न देना पड़े इसीलिए इसको कर मुक्त कर दिया जाय? यह जनता पार्टी के ऊपर सब से बड़ा इल्जाम होगा। जनता इसी दृष्टि से देखेगी इस बिल को, हम और आप चाहे कोई दृष्टि दे लें वह उस से चलने वाली नहीं है। इन शब्दों के साथ जो कंवर लाल जी का विधेयक है मैं उस का विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस विधेयक को सरकार स्वीकार न करे। राजनैतिक दल के ऊपर, राजनैतिक दल के संचालक जितने लोग हैं, राजनैतिक नेता जितने लोग है, चाहे वह विधान मंडल या संसद के सदस्य हों या न हों, राजनैतिक दल के अन्दर गांव से लेकर दिल्ली तक किसी भी पद पर पदाधिकारी हों उन की भी सम्पत्ति की जांच होनी चाहिए, ऐसा विधेयक बने तब कहीं काम चल सकता है और देश से भ्रष्टाचार को मिटाने का जो काम है वह मजबूती से किया जा सकता है। वरना भ्रष्टाचार हम लाख कहेंगे मिटाने के लिए वह नहीं मिट सकता है। हम दुनिया से भ्रष्टाचार को मिटाने चलें लेकिन जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले हैं वे

स्वयं अपने ऊपर अंकुश न लगाएं तो कैसे काम चल सकता है ? हम तो चाहते हैं कि दुनिया पवित्र हो जाय लेकिन मुझ पर कोई उंगली न उठाए, हम तो सब की बात कहें, मेरी बात कोई न कहे, हम सब की आलोचना करें, मेरी आलोचना कोई न करे, हम सब को भ्रष्टाचारी कहें लकिन कोई मुझे भ्रष्टाचारी कहे तो संसद् के विशेषाधिकार की गिरफ्त में आ जाय, यह इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा जहां रहेगी वहां देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा । इसलिए भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिए इस विधेयक का विरोध होना चाहिए और राजनैतिक दल, राजनैतिक दल के लोग इन तमाम लोगों को नियंत्रित करने के लिए कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए जिस से वे भ्रष्टाचार को संरक्षण न दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): In this country where the sapling of democracy has not yet taken firm roots, it becomes imperative on the part of political parties to educate the masses and to carry on their legitimate duties. For that they definitely require some money for their expenses and this money could easily come by way of membrship fee and also in the shape of donations from party members. But the way money flows during elections brings a genuine doubt in the mind of the electorate from where this money comes. Most of the returns that we Members of Parliament submit as election expenses, are not true as they have exceeded the limit prescribed by the Election Commission for such elections. Each one of us has contested the election and we know very well that we have spent much more than Rs. 35,000 which have been prescribed by the Election Commission as the limit for election expenses.

Further in this House many a time there have been discussions regarding the corrupting influence of CIA, KGB and other similar organisations of foreign countries. It is a matter of serius concern as it jeopardises the security of the country. Inside the country also, financial support to political parties comes in various ways, in a clandestine manner; it is so siphoned through various channels to the efforts of political parties; it comes from big business houses in the shape of advertisements in souvenirs donations, lending jeeps etc. etc.

When big business houses or monopoly houses invest in any political party, they expect some return, and the political parties are eager to oblige if at all they came to power. The entire election becomes a mockery. They pay donations to parties from the black money which is an undeclared wealth. That is how there will be a parallel economy in operation in this country. The entire election becomes a mockery. Voters are exploited of their poverty and ignorance .

It is high time that the people of this country should get a clear picture regarding the sources of income and the manner of expenditure of the political parties. If we take a substantive step and pass proper legislation in this House, it will check unjustified flow of money to party coffers. Then only the election will be inexpensive. Candidates should be compelled to restrict the election expenses to prescribed limit and it is the patriotic duty of every citizen to watch the activities of the political parties and to see that even a poor man can afford to contest the election. But as it stands now, unless you get a political patronage or get a political backing of a very rich party, it is not possible for a poor individual to contest the election, however popular he may be. In this regard, I would like to make certain concrete suggestions.

My suggestions are that all the political parites should be registered under the Societies Registration Act, 1860. All political parties shall maintain accounts of all their receipts and expenditure. All receipts shall be accompanied by a list of sources from which they have come. All expenditure shall be supported by stamped vouchers. An annual statement of accounts of all receipts and expenditure shall be prepared by all political parties from the Ist day of April upto the 31st day of March every year. All political parties shall submit an annual statement of their receipts and expenditure, duly audited and certified by a chartered accountant, to the Election Commission. The annual statement of receipts and expenditure of the political parties shall be published in the Official Gazettee, by the Election Commission within one month of the receipt of such annual statements. Failure to comply with these provisions will make the political party de-recognised by the Election Commissin and the Election Cimmission shall take away the symbol which has been allotted to the particular party.

Unless these safeguards are there, I have my own genuine fear that if Shri Kanwar Lal Gupta's Bill is passed in this

[Shri P. K. Deo]

House and comes on the Statute Book, there will be complete misuse of it and it will open the flood-gates of corruption. I, therefore, strongly oppose the Bill of my learned friend, Shri Kanwar Lal Gupta.

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, मुझे श्री कंवरलाल गुप्त, श्री हुकमदेव नारायण यादव और डा० रामजी सिंह का भाषण सुनने का मौका मिला और अभी-अभी श्री पी० के० देव ने जो भाषण दिया है उसको भी सुनने का मौका मिला। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि यादव साहब इतने इमोशन के साथ क्यों बोल रहे थे क्योंकि कंवरलाल गुप्त जी ने जो बिल इस सदन में रखा है उसमें उनका कहना है कि जो भी डोनेशन पोलिटिकल पार्टीज को मिलते हैं उनके लिए तो आज के दिन भी इनकम टैक्स की पावन्दी नहीं है लेकिन अगर कोई प्रापर्टी पोलिटिकल पार्टीज के पास है, जिस प्रापर्टी से रेंट मिलता है जिससे वे अपना दफ्तर चलाते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास डोनेशन की आमदनी नहीं है, उनको बिग बिजनेस हाउसेज भी पैसा नहीं देते हैं तो जो ऐसी पोलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने साधन से कुछ न कुछ प्रापर्टी बनाकर उसकी आमदनी से पार्टी को चलाना चाहती हैं, डे टुडे पार्टी एक्टविटीज को चलाना चाहती हैं उन के ऊपर जो पावन्दी इन्कम टैक्स की रखी गई है, उस को हटाना चाहिये। यह बात सच है और सब जानते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दे के नाम पर क्या-क्या होता है, रुपये के खेल कैसे होते हैं, किस तरह से पावर में आया जा सकता है। जब हम अपनी रिटन दाखिल करते हैं तो वह कितनी साफ और सही तरीके से दाखिल करते हैं—देश को यह सब मालूम है। असल बात यह है कि सरकार की तरफ से इस की अच्छी तरह से जांच करने की जरूरत है कि हम किस तरह से पोलिटीकल पार्टीज में व्याप्त करप्शन को हटा सकते हैं और किस तरीके से विधि के द्वारा इन पर अच्छी तरह से कन्ट्रोल कर सकते हैं।

इन्कम टैक्स को हटाने की जब बात आती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस को ऐसे ही हटा दिया जाय, उस तरह से तो फिर कोई नियम ही नहीं रहेगा। इस समय में उसमें यह नियम है कि उस का प्रापर एकाउन्ट मैन्टेन होना चाहिये, उस के बाद आडिट होना चाहिये, तमाम एमाउन्ट सही तरीके से जमा होना चाहिये। मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि जितने डोनर्स हैं, उन सब के नाम उस में दिये जायें, उन में 1 रुपया देने वाला डोनर भी हो सकता है—ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस में ऐसा दिया जा सकता है कि हजार रुपये से ऊपर देने वाले डोनर का नाम जरूर दिया जाना चाहिए, उसका एड्रेस भी देना चाहिये। लेकिन जो 1 रुपया या डेढ़ रुपया देने वाला डोनर है, उस का नाम देने से तो क्लेरिकल एक्सपेण्डिचर बहुत बढ़ जायेगा। इसलिये मैं ऐसा चाहता हूं—पोलिटिकल करप्शन को हटाने के लिये अगर कोई कदम उठाना है तो सरकार उस पर विचार करे और कोई इस तरह का विधेयक लाये जिस में पोलिटिकल पार्टीज का सारा एकाउन्ट सही तरीके से रखा जाये, उन के एकाउन्ट का आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट करे और उसके बाद वह एकाउन्ट पब्लिक के लिये खोला जाय, लोगों की जनरल इन्फर्मेशन के लिये, जानकारी के लिये ओपन किया जाये। यदि हम ऐसा करेंगे तो काले धन के बारे में काफी चैक हो सकेगा। जैसा यादव जी ने कई प्रकार के घूस की बात कही है—उस की रोक थाम के लिये यह जरूरी है कि इस तरह का बिल लाया जाए। हमारे देव साहब और यादव जी ने तो इस को टोटली अपोज किया है, मेरा यह कहना है कि इस को इस एंगिल से नहीं देखना चाहिये।

इस पर विचार होना चाहिये और विचार कर के--मेरा यह कहना नहीं है कि आप इसी बिल को स्वीकार कीजिये--सरकार की तरफ से कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल लाया जाना चाहिये । डाक्टर साहब ने कहा है कि इस को सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाये--मैं यह समझता हूं कि यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है, यह बड़ा गम्भीर और महत्व-पूर्ण मामला है--इस पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिये । इस सदन में हम लोग जो आते हैं, हर प्रान्त से आते हैं, सारे देश का भाग्य उन के हाथ में है, उन लोगों की पोलि-टिकल पार्टीज हैं जो इस से प्रभावित होंगे --इसलिये सब के लिये ऐसा नियम बने, जिस में करप्शन से मुक्ति मिल सके, तब ही देश की राजनीति स्वच्छ हो सकेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आया है, इस को आउट-राइट रिजेक्ट न कर के इस पर विचार होना चाहिये, इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिये और कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल कैसे आ सकता है, उस पर सोचना चाहिये ।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) : I think I must support this Bill. We are all aware of the fact that the political parties function in this country with the will and support of the people and the day the people reject the party and withdraw their support, that party will perish. In every democracy we can see... This power failure is an indication how Delhi is in the grip of a power crisis and Mr. Kanwar Lal Gupta has to explain it.

Even in Britain we know some of the Parties which ruled that country have become a big cipher because the people did not support those parties. Today the functioning of the political parties is very expensive. Day-to-day functioning and fighting elections are very difficult for a small party and more so for a regional party. It is very difficult for a political party to complete with a party which is in power. I am not denying the fact that this kind of expensive political activity has come into the political life only after 1969. The entire morals and ethics of Indian politics have been torn into pieces since the great split in the Indian National Congress party.

Later on, I could say that the functioning of the political parties in this country became very expensive and every political party has been spending money like water. During the last Parliamentary election there has been a big change in the political scene. A new political party came into power. People expected that political parties will have to keep away from such immoral acts of collecting huge amounts for spending on elections. But even people like Santhanam had to complain. He made a public complaint and criticism that Janata Party used the same method as was done by the Indian National Congress Party once upon a time to extract money from people in Madras city. I am only showing that no political party can escape from this criticism—that they are using coercive methods to collect money.

Many suggestions have come to help the political parties to free themselves from corrupt practices. Everybody is paying money to the ruling party with an objective to get favour.

It is very difficult to collect money. When a telephone from an Opposition Party goes, the person at the receiving end says—he is not available. He, it is said, is not at home. They say, he is out of station. When they were in power, they were anxious to meet them. This order has to change day by day.

The hon. Minister while replying to the question regarding the arrears of Birlas said that Birlas could escape all the time. I do not blame you Mr. Patel because you came last year. Arrears of tax accumulated over the last 30 years and Birlas were capable enough to use their influence to that extent. It was notoriusly known how Shri K. K. Birla was influencing the previous regime. So, he could easily accumulate the arrears of tax and he could evade punishment. That is why this much of accumulation has come.

There was a CBI enquiry against him. He could come to courts and fight every day. Even in High Court and Supreme Court cases were pending for many years. I only take this opportunity to warn Shri H. M. Patel and the friends sitting in Janata Party, do not think that Birla is innocent and he will not influence your party also. I have my own suspicion. I have my own doubts—that Birlas will allow you to escape from the cluches of their influence. Please see that action is taken with all vigour.

How to make the political parties function is a question ? The only solution is that the Government should finance the political parties on the basis of the voting strength. You can evolve any formula,

[Shri Vayalar Ravi]

otherwise all these corrupt practices of big and small business Houses will influence the political parties through payment of money. The political party has to function. It is impossible for any political party to function to day within this present set up. The only way to keep these people out is that the Government should fix a kind of percentage of any other method. At least the source of finance should come from the Government as is in Germany.

As far as taxation is concerned, every political party has to keep books of Accounts. The political parties make bogus accounts. They make black money and they place a baseless report before the Government. Even the political party which rules the country, which is expected to be honest, the political party expected to be of integrity and which has to lead the people, the first thing that they do is to submit false accounts before the Income Tax authorities. Here you are asking the political parties to submit their accounts, and here are accounts which are always bogus and wrong. They are playing with black-money which we have to avoid. The only solution for this is this: The Government shold come forward to the help of these political parties; they should give them whatever support they could. They have got to be exempt from income-tax. There is no justification to impose income-tax on a political party.

Sir a political party is not an Association. It is not a profit-making institution or organisation. It is not a profit-earning society. It is not a commercial society. It is not a trading society. It is just simply a political party, living and functioning out of the contributions of the people. It is not right and proper for the Government to continue with this law which the Government is unable to enforce for the last thirty years.

It is better to open up a free atmosphere a better atmosphere. Let the people and let the political parties be more, honest.

Lastly, Madam Chairman, I would like to tell the Government about this point. This is regarding the functioning of the Income-tax Department, how the powers are being exercised in the Income Tax Department.

Who is powerful today ? Mr. H. M. Patel may think that he is very powerful. No. It is not so. He is wrong. The Income-tax Officer is the most powerful person in the country today.

During emergency he used this power to a great extent. These income tax Officers raided every house, they haunted, harassed and humiliated every family, in every big city and every small city. And then what happened - Accounts Books have been seized and kept in lorries and taken to these income-tax offices. These lorry-loads of account books have not yet been returned.

I appeal to the hon. Finance Minister to please see how many raids have been conducted since 1975 and how many records books have been seized and how many were returned so far. To my knowledge, in many cases, the books of accounts have not been returned so far because your people cannot look into them.

Unnecessarily, because of some small prejudice on the part of the Income-tax Officer, a raid was conducted, the innocent persons were put to harassmant and bumiliation. That was the order of the day during emergency. In those unfortunate days all these things happened.

Therefore, I appeal to you: Kindly have this checked up.. Such things happened in cities like Madras, Cochin, Bombay, Delhi and Calcutta. In other big cities also this happened. Please go into it. Please see how many account-books have been seized. Please see how many they are still keeping with them still, and have not returned back so far. If they are not returned so far, I request you to please see that they are returned and the cases are settled. Please see that the whole thing is settled. Please do something in the matter and see that this kind of harassment is not repeated in future.

Also, I would like to know whether you could take any action against those Income-tax officers who did the wrong things. So far as the Income-tax Department is concerned, I know, no action was taken those Income-tax Officers. Even the cases were proved by the Appellate Tribunal that the Income-tax Officer acted in a harsh manner. Even then he could escape. In every way, legally and otherwise, in every manner, he is fully protected. The poor people, the innocent people have been harassed and humiliated.

I don't know whether there is any provision in the law, but I feel, even if it is there, it is not evoked or enforced. No Income-tax Officer has been punished for his harsh action, where he ruined many poor families. This I know personally...

My only appeal to the hon. Finance Minister is this : Please look into this.

I give my support to the Bill.

I can only appeal to the hon. Finance Minister to look into the spirit of the Bill. The spirit of the Bill is that the political parties must function freely, function above the influence of the big business houses, function without corruption.

If you ask them to pay Income-tax, they will all indulge in transactions of black-money.

Allow the political parties to function in a proper manner. The only solution is this :

Allow the political parties not to pay any income-tax. Exempt them from income-tax altogether. Give financial aid to them from the Government.

I hope the hon. Finance Minister will consider all these points.

With these words I support the Bill.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : I wish to make a submission, Madam Chairman.

Two hours have been allotted for this discussion. After this Bill, we have another Bill in the name of Shri Yamuna Prasad Shastri. That Bill has also come in the ballot. He is a blind man and he is waiting and I request that at least five minutes may be granted to him so that he may move his Bill. This is my submission.

MR. CHAIRMAN : But discussion and voting on this Bill has to conclude before we come to Mr. Shastri's Bill.

SHRI P. K. DEO : That is right. That is why I say, if we stick to the time-schedule we can easily finish this business in time and we can also allow Mr. Shastri to move his Bill.

MR. CHAIRMAN : The House will go on till 6 O'clock. That will give time for Mr. Shastri also to move his Bill.

Now, Shri Ram Naresh Kushwaha.

श्री राम नरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : मैं इस बिल का विरोध करता हूं। जहां राजा बैठता है उस स्थान का नाम गद्दी है, जहां सेठ बैठता है उस स्थान का नाम गद्दी है, जहां महंतजी बैठते हैं उस स्थान का नाम भी गद्दी है। यह सारा गद्दियों का झगड़ा है। ग्रादमी के पास धन होता है, तन होता है ग्रौर मन होता है। सारे संसार में तन का मालिक राजा होता है। जब चाहे जल में डाल दे जैसे ग्राज संजय गांधी को डाल दिया है ग्रौर जब चाहे छोड़ दे। तन का मालिक राजा। फांसी भी दे दे ग्रौर चाहे तो छोड़ भी दे। मन का राजा है महन्त, धर्म गुरु, जो कह दे सब सही, मान लिया जाएगा। धन का मालिक सेठ है जो महंगी ला दे ग्रौर जब चाहे सस्ती ला दे, जब चाहे भूखों मारने लग जाए ग्रौर जब चाहे मंडी को सामान से पाट दे ग्रौर सस्ती ला दे। हर एक संकट का कारण है। जब इन तीन में से दो भी इकट्ठे हो जायें तब तो कहना ही क्या। यह गठबंधन इन तीनों का ग्राज से नहीं सृष्टि के ग्रादिकाल से चला ग्रा रहा है।

कानून बना हुग्रा है ग्रस्पृश्यता निवारण का। हरिजन मन्दिर में जाता है। उसको पुजारी रोकता है। छुग्राछूत कौन मानता है? पुजारी मानता है। लेकिन गिरफ्तार हरिजन होता है। इसलिये यह होता है कि महंत की सांठगांठ गद्दी से होती है। बजाय पुजारी के गिरफ्तार होने के वह होता है। इसी तरह से सेठ की सांठगांठ भी सरकार से होती है। मजदूर हड़ताल करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर लाठी गोली चलती है। यह सब चीज होती है ग्रौर उनको बन्द कर दिया जाता है धारा 107, 116, 147, 148 में जोकि बल्वे की तमाम धारायें हैं। मजदूर किस से शांति भंग करता है, लोहे से, कारखाने की दीवारों से? वह लड़ता है मैनेजर से या मिल मालिक से। लेकिन कहीं मैनेजर या मिल मालिक की गिरफ्तारी नहीं होती है। शांति भंग का ग्रंदेशा होता है तो गिरफ्तार होता है मजदूर। इतना ही नहीं, इन दोनों से राज सत्ता की सांठगांठ होती है। ग्रगर ऐसा न होता तो हरिजन को गिरफ्तार न किया जाता, मजदूर को ही न किया जाता मिल के मैनेजर को भी उस के

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

सांठ गांठ किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह सांठगांठ सेठ की भी और मठ की भी, महन्त की भी। अब सत्ता पर संकट कब आता है ? तब आता है जब धर्म खतरे में पड़ जाता है, जब चुनाव आते हैं। पांच बरस तक धर्म पर कोई खतरा नहीं। जब चुनाव आते हैं तो धर्म पर खतरा आ जाता है। यह आज की बात नहीं है। आज की ही यह बात नहीं है। पहले भी यही हालत थी। प्राचीनकाल में भी यही हालत थी। सब ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। धर्म ने हम को पढ़ाया : "मुट्ठी बांधे आये हो और हाथ पसारे जाओगे"। यह "हाथ पसारे जाओगे" वाली बात किस के लिये है?—हम रे लिये। यह उन के लिये नहीं है, जो महन्त हैं। उनके लिये यह संसार अपना और हमारे लिये यह संसार सपना है। चूंकि हमारे लिये यह संसार सपना है, इसलिये हम सब कुछ उनको दान-दक्षिणा दे दें। और हम वहां जाकर लेंगे, जहां से आज तक किसी ने चिट्ठी नहीं भेजी है। जिनको वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, उनको हम सब कुछ दे दें, ताकि वे मौज-मस्ती मारें।

17.00 hrs.

राज्य सत्ता के लिये उन्होंने क्या व्यवस्था की है ? वह राजा, नरेश है—नर के रूप में ईश्वर है। ईश्वर से कौन लड़ेगा ? अपने लिये उन्होंने यह व्यवस्था दे दी कि "गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पांय। बलिहारी गुरु आप की जिन हरि दियो दिखाए।" अर्थात गुरु भगवान से भी बड़ा है।

और सेठ के लिये क्या व्यवस्था हुई ? हमारे यहां जब किसी का जवान बेटा या बैल मर जाता है, तो लोग उसे सांत्वना देने के लिये कहते हैं : "बबुआ काहे रोवताड़। ई तू कर्जा खइले रहलह ऊ कर्जा भरवा के चलि गइल। अब मति रोअ।" यानी, तुम ने पिछले जन्म में इस बैल या लड़के का कर्जा खाया; इस जन्म में वह कर्जा भरवाने के लिये आया था; तुम ने उसको खिलाया पिलाया, पालापोसा; कर्जा चुक गया और वह मर गया; क्यों रोते हो ?

किसी सेठ की इकन्नी मत लूटो, नहीं तो तुम्हारा जवान बेटा मर जाएगा, यह उसका भावार्थ है।

पांच रुपये के बदले में अगर सेठ जी ने पांच हजार ले लिये, और फिर भी उन के पांच रुपये बकाया रह जाते हैं। क्या किसी धर्म-ग्रन्थ में यह व्यवस्था है—सिवाये कुरान के, जिसमें इसको अपराध माना गया है—कि वह किस नरक में जाएगा ?—किसी धर्म-ग्रन्थ में यह व्यवस्था नहीं है। बाकी सब धर्म ग्रन्थों में यही व्यवस्था है कि भले ही सेठ जी ने किसी से पांच रुपये के बदले में पांच हजार ले लिये, मगर वे पांच रुपये बकाया रहेंगे और वह व्यक्ति नरक में जाएगा।

इन तीनों में सांठ गांठ रही है। कम्पनियों द्वारा चन्दा देने पर जो रोक लगाई गई है, उसके पीछे यही भावना है। पुरानी सरकार को हम चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन अगर उसने भूले भटके एक आध सही काम कर दिया—जिस तरह लेबपाल या पुलिस वाले भूले भटके एक आध सही काम कर देते हैं—कि कम्पनियां चन्दा न दे सकें, तो मैं समझता हूं कि उसे समाप्त नहीं करना चाहिए। इन तीनों में से एक एक ही लोगों को बर्बाद करने के लिये काफी है, चाहे राजा की गद्दी हो, चाहे सेठ की गद्दी हो और चाहे महन्त की गद्दी हो। तो फिर अगर सेठ की और राजा की दो गद्दियां मिल जायेंगी, तो क्या हश्र होगा ?

पिछले शासन में तीन गद्दियां इकट्ठी हो गई थीं। भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने दक्षिण भारत के दौरे में कहा था कि मैं भी हिन्दू हूं—अर्थात् हे हिन्दुओ, मैं जवाहरलाल की बेटी हूं, ब्राह्मण हूं। इस तरह वह पंडित बन गईं, और जब पंडित बन गईं, तो धर्मगुरू और

महन्त बन गई। और राज्य-सत्ता पर तो वह थीं ही। वह मारुति कारखाना खोल कर सेठ भी बन गई थीं। इस प्रकार सेठ, मठ और राजा का एक ही व्यक्ति में गठबन्धन हो गया--उसके पास वे तीनों ताकतें आ गईं। इन तीनों के गठबन्धन का जो नतीजा निकला, वह सारे देश ने बीस महीने तक भोगा। भविष्य में इन तीनों में से किसी का एक दूसरे के साथ गठबन्धन नहीं होना चाहिये, वर्ना यह देश तबाह हो जाएगा। बिलकुल यह देश तबाह हो जाएगा। और ईमानदारी की बात मैं आप से कहना चाहता हूं कि राजनीति में हम लोगों ने लोकतन्त्र कबूल किया है, लोकतन्त्र में पैसे का प्रभाव रहता है। तो एक तो करेला, दूजे, वह नीम चढ़ा। एक तो वैसे ही लोकतन्त्र में बिना चन्दा किये काम नहीं चलने वाला है और इन सेठों का जब चन्दा चलने लगेगा तो फिर होगा क्या ? हम ने देखा है अपनी आखों से, कांग्रेस में भी हम लोग रहे हैं, बहुत पहले अलग हो गए थे सन 48 में लेकिन इधर जो कांग्रेस का रवैया चल रहा है, चन्द्रभानु गुप्त और किसकी किसकी लड़ाई चलती रही है, उसमें मैंने देखा है कि जाली मैम्बर बनाये जाते थे कार्यकर्त्ता बनाये जाते थे और क्या क्या होता रहा है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री के जमाने में भी और अभी भी क्या होता है पैसे के बल पर, मैं आप से कहना चाहता हूं कि राजनीति में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये यह जरूरी है कि इस प्रकार के चन्दे बन्द किये जायें। अगर इस प्रकार का चन्दा बन्द नहीं किया जायगा तो इन्सान कब बदल जाय कोई ठीक नहीं और ईमान कब लुढ़क जाए कोई ठीक नहीं। लालच का समुद्र जब सामने लहराता रहेगा तो वह आदमी ईमानदार नहीं रहेगा। आदमी में अगर कोई कमजोरी न हो तो वह देवता बन जाएगा। इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि आदमी को आदमी रहने देने के लिये हमें आदमी को आदमी मान कर के चलना चाहिए और जानकर के ऐसा कोई उपाय नहीं करना चाहिए जिस से कि आदमी की खरीद और बिक्री शुरू हो जाय, किसी दल को खरीदने का काम शुरू हो जाय। मुझे याद है, एक बार बिरला साहब के किसी आदमी ने बयान दिया था कि मेरे 45 संसद सदस्य हैं--तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि फिर किसी पूंजीपति की यह हिम्मत न हो, फिर किसी संसद सदस्य पर इस प्रकार की उंगली न उठायी जाय कि वह हमारा है या पूंजीपति का क्रीत दास है, इसलिये जरूरी है कि पूंजीपतियों का चन्दा, कम्पनियों का चन्दा बन्द किया जाय। मैं आप के माध्यम से माननीय मित्र कंवर लाल जी गुप्त को हमारे सम्माननीय नेता भी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कम्पनियों के चन्दे के लिये यह सारी बात है तो इसको वह वापस ले लें।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : I should like to say that the principle of the Bill is clearly acceptable. In fact the government had taken a decision in February and an announcement had been made that this question had been considered in the Cabinet and that the government would be bringing forward a Bill, I hope, during this session. It was consider certain aspects which, understandably, have not been considered in Mr. Kanwar Lal Gupta's Bill. It says that income derived by political parties should be exempt from income-tax. What income ? Income derived from what source ? There will have to be certain types of income which may have to be excluded and so on. Those have to be clearly specified. Similarly, the point to consider is whether wealth tax exemption is desirable or not. Wealth tax was brought in for the purpose of reducing disparities. But there is no question of disparties of wealth in regard to political parties. All those matters have been considered and we propose to bring in a Bill which will take care of all those aspects and I hope, if possible, to introduce it during this session. Various other suggestions really do not belong to the Income-tax Act. The suggestions as to whether funds may be collected by the Ministers or not are separate issues which can be dealt with appropriately through other methods and not at all through the Income Tax Bill. I hope ....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Do you agree with it or not ?

SHRI H. M. PATEL : Of course. I have no quarrel with it whatsoever. But as I said certain suggestions are counsels of perfection. I entirely agree with what you said. However, the method of doing it may be difficult to find out and that is why I said that it is not something which can take care of through the Income-tax Bill. It is to be looked into further. The main point is, as I had already said, that the Government has already considered tha matter and taken the view that this is something which should be done in order that the political parties may function satisfactorily and may have no difficulty in having their funds from recognised and approved sources. This is all I want to say and there is no reason why I should take more time of the House. I am very glad that all those who spoke on this Bill consider that a move in this direction is desirable and should be considered by the Government. It so happened that Government was also thinking on these lines. I must congratulate Mr. Kanwar Lal Gupta for thinking on these lines simultaneously. Great minds think alike and evidently, Government collectively is great and so also is Mr. Kanwar Lal Gupta.

Mr. CHAIRMAN : But you are not asking him to withdraw the Bill ?

SHRI H. M. PATEL : I am asking him to withdraw the Bill now.

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने मेरे विधेयक के सिद्धान्त को मान लिया है और इस बात की भी घोषणा की है कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

मेरे मित्र श्री हुकमदेव नारायण यादव जी ने और दूसरे साथी ने कुछ आपत्ति उठाई। या तो शायद मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाया या उन्होंने इस विधेयक को ठीक तरह से पढ़ा नहीं इसी कारण उनकी आपत्ति है। उन्होंने जो बातें कहीं उन बातों से किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता है। उनकी सभी बातें ठीक हैं। मैंने तो स्वयं कहा कि आज क्या स्थिति है – आज की स्थिति यह है कि आप किसी से भी पैसा ले जाइये, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है लेकिन लेने के बाद अगर बैंक में पैसा जमा करके ब्याज लेंगे या प्रापर्टी पर रेंट से या किसी दूसरे तरीके से इनकम होगी उस पर है। लेकिन गड़बड़ कहां होती है ? आपने ठीक कहा कि चन्दे के नाम से, सलामी के नाम से, नजराने के नाम से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वह जेबों में जाता है जोकि जेबों में नहीं जाना चाहिए। पैसे का प्रभाव राजनीति पर नहीं होना चाहिए इसमें मैं आपसे बिलकुल सहमत हूं और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। जैसा कि मैं ने खुद कहा मैं मंत्री जी से इस बारे में सहमत हूं कि यह कांप्रिहेंसिव बिल नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि इस पर दोबारा और ज्यादा थिंकिंग की जरूरत सरकार को पड़ेगी। यह बिल तो मैं ने सिद्धान्त रूप में पेश किया है।

SHRI H. M. PATEL : If I may interrupt, I should also say that the Bill, which Mr. Kanwar Lal Gupta has presented, for instance does not point out that proper accounts should be maintained and those accounts should be audited carefully. Unless this is done, to give exemption otherwise would not be proper. Therefore, all these things are necessary to be incorporated.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I totally agree with the Minister that proper accounts should be maintained and should be audited. I go a step further and say that it should be open to the public, so that the public may know who has contributed what. Of course, I agree with the suggestions made by my friend, Mr. Baktha that it is not possible to give the name of each and every donor. But if somebody contributes more than a thousand, two thousand or ten thousand rupees, their names should be known to everybody. After the accounts are duly audited and approved, they should be open to public like Companies' Accounts. What is the position with regard to Companies' Accounts ? You go to the Registrar of Companies, you pay Rs. 2/-, you can see the accounts of the company. Suppose I had taken one lakh for my party and I have given only Rs. 50,000, to Janata Party, and put Rs. 50,000 in my pocket.

इस तरह से 50 हजार रुपया खा गये। अगर एकाउन्ट्स ठीक तरह से रखे जायेंगे, उस का आडिट ठीक होगा, तो पब्लिक को भी देखने का अवसर मिलेगा। आप यह मालूम

कर सकते हैं कि किसी से एक लाख रुपया लिया है या 50 हजार रुपया लिया—जो बात आप कह रहे हैं, वह इस चीज से पूरी होगी।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पोलिटीकल एजुकेशन का होना भी बहुत जरूरी है। आप इस तरह से देखिए—इन्दिरा जी ने नारा लगाया कि हम गरीबी हटा रहे हैं, आप जानते हैं हम ने अपनी कांस्टीचूएन्सी में कितना काम किया था, लेकिन हम और आप कहां चले गये। किसी ने आंख से आंख नहीं मिलाई, सब यह सोचते रहे कि अब तो गरीबी मिट जायगी। इस लिये मेरा कहना है कि जब तक पोलिटीकल कांशनेस नहीं होगी, पोलिटीकल एजूकेशन नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलेगा।

मैं इस बात स सहमत नहीं हूं—जैसा श्री वयालार रवि जी ने कहा कि सरकार को पोलिटीकल पार्टीज को पैसा देना चाहिये। जिस पोलिटीकल पार्टी के पीछे जनता नहीं है, सरकार उस को पैसा दे कर जिन्दा करे – मैं इस सिद्धान्त को ठीक नहीं मानता। ये लोग तो एक ही साल में तंग आ गये हैं, कोई कहता है कि हमारा टेलीफोन कट रहा है, कोई कुछ कहता है, हम भी 30 साल विरोध पक्ष में रहे हैं, जो पार्टी सक्रिय रहेगी, जिसे जनता का समर्थन प्राप्त होगा, उसे पैसे की कमी नहीं रहेगी। जिसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है वे ही सरकार से अपेक्षा करेंगे कि सरकार उन को अपनी पोलिटीकल पार्टी जो चलाने के लिये पैसा दें। इस तरह की परम्परा डालना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। इलैक्शन के लिये तो मैं मान सकता हूं और इस बात से सहमत हूं कि इलैक्शन के दिनों में सरकार को मदद करनी चाहिये – हर एक कैण्डीडेट की। लेकिन पोलिटीकल पार्टीज को सरकार चलाये, इस से क्या होगा कि बहुत ज्यादा पार्टीज बन जायेंगी, क्योंकि पार्टी को चलाने के लिये सरकार से पैसा मिलेगा यह चीज ठीक नहीं है।

यह समझना भी ठीक नहीं होगा कि पोलिटीकल पार्टीज पैसे से ही जीतती या हारती है। हम ने अभी देखा — जिस समय हम लोग चुने गये, यदि पैसे से और सरकार के दबाव से सब कुछ होता तो हम यहां पर नजर नहीं आते, दरवाजे के बाहर ही नजर आते। लेकिन भारत की जनता में पोलिटीकल–मैच्योरिटी है, उस ने इस बात को साबित कर दिया कि पैसा सब कुछ नहीं है, सत्ता ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जिस सिद्धान्त और जिस उद्देश्य को लेकर कोई राजनीतिक दल चलता है, वे सिद्धान्त कैसे है, जनता को पसन्द हैं या नहीं हैं, उस के हित में है या नहीं है– यह महत्व रखता है। हम लोग 17 महीने जेल में रह, वहां रह कर भी हम ने जनता को एजुकेट किया कि किस तरह से उस सत्ता ने जिस का उस समय राज था, लोगों को दबाया, लोगों की आजादी को समाप्त किया, समाचार पत्रों को दबाया, उस को यदि ठीक करना है तो आप के सामने जनता पार्टी को वोट देने के अलावा और कोई साधन नहीं है। आप यदि यह चाहेंगे कि बिरला से पैसा मत लो, बड़े बड़े सरमायेदारों से पैसा मत लो, छोटे छोटे लोगों से पैसा लो, उस पर भी सरकार को टैक्स दो,—तो ये दोनों काम नहीं चल सकते। इसी लिये मैं समझता हुं कि हमारे श्री हुकुम देव नारायण यादव जी ने गलतफहमी में इस का विरोध किया है। यह वास्तव में ऐसा बिल है, जो पहले ही आना चाहिये था। मान लीजिये यदि मन्दिर की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता, मस्जिद की आमदनी पर नही लगता, गुरुद्वारे पर नहीं लगता, एजुकेशनल इंटीट्यूशन्ज पर नहीं लगता, तो फिर पोलिटीकल पार्टीज पर भी नहीं लगना चाहिये, क्योंकि हम भी एजुकेशन देते हैं।

मैं अब इस के ऊपर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उन्होंने इस बात को माना और मैं भी यही मानता हूं कि यह कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार जल्दी ही एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लायेगी, यदि सम्भव हो तो इसी सशन में लाया

[श्री कंवर लाल गुप्ता

जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

Mr. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961."

The motion was adopted.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, I withdraw the Bill.

17.21 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new Articles 23A, 23B and 23C)]

SHRI Y. P. SHASTRI (Rewa) : Sir, I beg to move* :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । श्रीमन्, अपने जीवन का सब से समहत्वपूर्ण और सुखद दिन मैं आज मानता हूं जबकि भारत की सर्वोच्च पंचायत के सामने मैं यह महत्वपूर्ण विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि संविधान का यह संशोधन विधेयक न केवल आज की पीढ़ी बल्कि अनन्तकाल तक भारत की भूमि पर पैदा होने वाली संतानों से सम्बन्ध रखता है । हमारे संविधान में आज से 28 वर्ष पूर्व निर्देशक सिद्धान्तों में अनच्छेद 41 में इस बात का समावेश किया गया था कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के स्तर को देखते हुए इस देश के निवासियों को काम का अधिकार प्रदान करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा और जो लोग बेकार होंगे, अपंग होंगे, वृद्ध होंगे उन को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी । यह अनुच्छेद निर्देशक सिद्धान्तों में आज से 28 वर्ष पूर्व लिखा गया था । उस समय जिन लोगों ने संविधान बनाया था, उन्होंने सोचा होगा कि यह कार्य बहुत जल्द हो जाएगा और समूचे भारत में जो बेरोजगार लोग हैं, उन को काम का अधिकार मिलेगा और जब तक काम उन्हें नहीं मिलेगा, तो सरकार उन्हें सहायता देगी बेकारी के भत्ते के रूप में, अनएम्पलायमेंट बनिफिट के रूप में या अनएम्प्लायमेंट एलाऊन्स के रूप में, जो कुछ भी उसे कहा जाए, उनको सहायता प्रदान की जाएगी । यह उनका सपना था लेकिन संविधान बनने के पश्चात् इस देश में चुनाव हुए, सरकारें बनीं और उन्होंने बड़े-बड़े वायदे भी किये और देश की जनता को आंखों में धूल भी झोंकी लेकिन इस निर्देशक सिद्धान्त का पालन कहीं भी नहीं किया गया, एक अक्षर भी पालन नहीं किया गया और यह संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में लिखा ही रह गया और हमारा संविधान निष्प्राण रह गया ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : बेलाडीला में क्या हुआ ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : बेलाडीला में क्या हुआ है, उस को छोड़िये । हमने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है । बेलाडीला की तरह के हज़ारों कांड कांग्रेस वालों ने किये हैं । मैं समझता हूं कि कांग्रेस वाले ने यह प्रश्न किया है। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि संविधान निष्प्राण बना रह गया, संविधान का जो अनुच्छेद 41 था, उसको कार्यान्वित करने के लिए कुछ नहीं हुआ । मैं ऐसा मानता हूं कि यह अनुच्छेद संविधान का प्रण है । अगर किसी देश में लोकतंत्र रहना है, लोकतांत्रिक संविधान को अगर कार्यान्वियन करना है तो उस देश के लोगों को, देश के नौजवानों को, देश की संतान को काम का अधिकार मिलना चाहिए, जीविका का अधिकार मिलना चाहिए । अगर हम जीविका के अवसर नहीं प्रदान कर सके

*Moved with the recommendation of the President.

तो लोकतंत्र कभी भी जीवित नहीं रह सकता, यह एक अकाट्य सत्य है। इतिहास हमें यह बताता है और इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा यदि हम इस सबक को भूल जाएंगे। हमारे पास-पड़ोस के देशों में जो कुछ हुआ है, उससे अगर हम शिक्षा नहीं लेंगे तो इतिहास हमें क्षमा करने वाला नहीं है। हमारा जो घोषणा पत्र है, उसमें हमने पृष्ठ 11 में लिखा है। ग्यारहवें पृष्ठ पर लिखा है लेकिन उसे पढ़ने की मेरे साथ नेताओं की मजबूरी है। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अपने देश की जनता को वचन दिया है कि हम संविधान के अनुच्छेद 41 को कार्यान्वित करेंगे, इसको मूर्त रूप प्रदान करेंगे और इस देश के सभी नागरिकों को रोजगार की पूर्ण सुविधा प्रदान करेंगे, राइट टू वर्क, अर्थात् काम करने का अधिकार हम इस देश के नागरिकों को प्रदान करेंगे। दूसरा वचन हमने यह दिया है कि देश के नागरिकों को पूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रदान करेंगे। तीसरा वचन हमने यह दिया है कि जो लोग बेकार हैं, निराश्रित और वृद्ध हैं, उन लोगों को जीविका कमाने लायक बनाने के लिए सरकार सहायता प्रदान करेगी। ये वचन हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिये हैं।

हमको यह कहने में गर्व का अनुभव होता है कि जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, बहुत हद तक उसने अपने वचनों को निभाया है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में हमने वचन दिया था कि हम देश में लोकतंत्र पुनः बहाल करेंगे, हम देश के नागरिकों की भाषण की, संगठन बनाने की आजादी बहाल करेंगे। जनता पार्टी की सरकार ने उस वचन को पूरा किया है। आज देश की जनता इस बात को स्वीकार करती है कि जनता पार्टी ने जो कहा था, उसका उसी तरह से पालन किया जिस तरह से भी हमारे यहां के महर्षियों ने कहा था—

"रघुकुल रीति सदा चली आयी
प्राण जाए पर वचन न जाई।"

चाहे प्राण चले जाए, पर वचन नहीं जाएगा। उसी तरह से हमने अपने वचन का पालन किया है। हमने उन सभी आजादियों को बहाल कर दिया है जिनका अपहरण श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कर लिया गया था और लोगों को तानाशाही के शिकंजे में डाल दिया गया था। जनता पार्टी ने कानूनी असमानताओं को दूर करने का भी वचन दिया था जो कि इस देश में पैदा कर दी गयी थीं। जैसे कि प्रधान मंत्री के चुनाव को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस तरह के गन्दे और कुत्सित कानून बनाये गये थे। हमने उन कानूनों को भी निरस्त किया। यह भी कानून बनाया गया था कि संसद् में जो कुछ कहा जाएगा वह छप नहीं सकेगा। इस कानून को भी समाप्त किया गया। जितने भी इस तरह के अलोकतांत्रिक कदम उठाये गये थे, उन सभी को जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया है। यह खुशी और गर्व की बात है।

लेकिन श्रीमन्, यह सब जो जनता पार्टी ने किया, यह सब अभी निष्प्राण है, इसमें प्राण फूंकने की आवश्यकता है। जब तक लोगों को रोटी नहीं मिलेगी तब तक लोकतंत्र निर्जीव रहेगा। इस दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सब को जीविका के अवसर प्राप्त हैं लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं है। रूस और चीन में बेकारी नहीं है। यह बात सभी जानते हैं कि वहां सभी को काम मिला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से वहां लोगों को अपने विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की आजादी नहीं है। हमारे देश में इस बात की जरूरत है कि देश के किसी व्यक्ति को यह नहीं लगे कि राजनैतिक आजादी अथवा लोकतंत्र के रहते हुए जीविका का अवसर अथवा काम करने का अधिकार नागरिकों को मिल ही नहीं सकता। वे लोग यह न सोचने लगे कि चाहे लोकतंत्र समाप्त हो जाए लेकिन उन्हें जीविका का अवसर तो मिल जाय, काम का अधिकार प्राप्त करना है। ऐसी भावना

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

लोगों में नहीं आनी चाहिए । यह काम दुनिया के अन्दर सब से पहले अगर कोई देश कर सकता है तो वह हिन्दुस्तान कर सकता है क्योंकि हिन्दुस्तान दुनिया का विशालतम लोकतंत्र है । उसको यह प्रमाणित करना है कि लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा ही देश के लोगों को जीविका के अवसर दिये जा सकते हैं, लोगों को काम का मौलिक अधिकार दिया जा सकता है । हमारे लोकतंत्र में कोई भूख से नहीं मरेगा, लोगों में यह भावना नहीं आने दी जाएगी कि लोकतंत्र निरर्थक है । यहां पर हर बच्चे को इस बात की गारन्टी होगी कि वह कभी भी इस देश में अपनी जीविका के अवसर से वंचित नहीं रहेगा । यह बात लोकतंत्रीय पद्धति में संभव हैं, ऐसा विश्वास जब तक हम देश की जनता को नहीं देंगे तब तक लोकतंत्र में उतना विश्वास लोगों में नहीं जमेगा जितना कि जमना चाहिए । यह इस देश का महानतम उत्तरदायित्व है जिसको हमें निभाना चाहिये । आज दुनिया के जिन छोटे-छोटे देशों में लोकतंत्र है उन्होंने भी कामकाज का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान कर रखा है । आप जापान को लें । उसके संविधान में जो कि 1946 में बना था आर्टिकल्ज़ 26 और 27 में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है । कोई भी व्यक्ति विना काम के नहीं रहेगा यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है । यह जिम्मेदारी देश की, समाज की है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बिना भेदभाव के काम पाने का अधिकारी होगा ।

जर्मनी के वेमर कंस्टीट्यूशन को आप देखें उसमें भी काम का अधिकार लोगों को दिया गया है । आयरलैंड के कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल्ज 42 से 45 तक में काम का अधिकार वहां के लोगों को देने का प्रावधान है । आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम से भारत ने प्रेरणा ग्रहण की थी । स्वयं महात्मा गांधी ने डी वलेरा से मुलाकात की थी और उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी । जिन देशों से हमने अपनी आजादी की लड़ाई में सहयोग लिया, प्रेरणा ग्रहण की या जिन को हमने प्रेरणा प्रदान की, आजाद होने के बाद उन देशों ने काम के अधिकार को मौलिक अधिकार माना । उन्होंने जो कुछ किया उससे हमें भी कुछ सीखना चाहिए । आयरलैंड के संविधान में 42 से 45 तक के अनुच्छेदों में काम का अधिकार वहां के लोगों को दिया गया है । सोवियत रूस में तो है ही । वहां के कांस्टीट्यूशन में 118 से 121 आर्टिकल्ज काम के अधिकार के बारे में हैं । अपना संविधान संशोधन प्रस्तुत करते हुए मैंने भी इन्हीं तीन अनुच्छेदों को प्रस्थापित करने का प्रयास किया है ताकि जो वचन हमने देश की जनता को दिया है उसका हम निर्वाह कर सकें । लोग आशा भरी नजरों से हमारी ओर देख रहे हैं । अगर यह संविधान संशोधन पास हो जाए तो न केवल यह जो जन क्रान्ति हुई है यह भारत के बल्कि दुनिया के इतिहास में अमर हो जाएगी । जनता पार्टी तो छोटी चीज़ है । दुनिया के इतिहास में हमारा यह जो महान् लोकतंत्र है यह अमर हो जाएगा क्योंकि यह विशालतम लोकतंत्र है । छोटे छोटे देशों के लोकतंत्र से दुनिया के लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती । वहां कुछ प्रयोग हुए हैं लोकतांत्रिक तरीकों से लेकिन उससे समूची दुनिया को प्रेरणा नहीं मिलती । रूस और चीन बड़े देश हैं लेकिन वहां लोकतांत्रिक आजादी का हनन करके यह अधिकार लोगों को प्रदान किया गया है । दुनिया के लोगों को यह पता लगना चाहिये कि लोकतंत्र के रहते हुए भी काम पाने का अधिकार लोगों को प्राप्त हो सकता है । बिना लोकतंत्र का हनन किए भी यह अधिकार प्रदान किया जा सकता है । रूस और चीन की बात तो आप जाने दें । पश्चिमी जर्मनी है, आयरलैंड है । वहां पर लोकतंत्र है । लेकिन वे हमारे मुकाबले में छोटे देश हैं ।

हिन्दुस्तान रूस से जनसंख्या में बड़ा है, चीन से आबादी में थोड़ा कम है । इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक ढंग से अगर इस चीज को हम कर दें तो दुनिया के सभी लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी । इजराइल, जर्मनी या आयरलैंड से समूची दुनिया के लोगों को प्रेरणा नहीं मिल सकती है । हमारे महान जनतंत्र से उन्हें प्रेरणा मिलेगी । इतने बड़े मुल्क में लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा लोगों को काम का अधिकार दिया जा सकता है, जीविका का अधिकार दिया जा सकता है, उसकी गारंटी दी जा सकती है, तो वे कहेंगे कि क्यों न हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना कर, बिना अपनी आजादी को समाप्त किए जीविका का अधिकार प्राप्त करें । जीविका का अधिकार रहते हुए लोकतंत्र भी रह सकता है तो यह तो सोने में सुहागे वाली बात है । इससे बढ़ कर और कोई आदर्श हो नहीं सकता है कि रोजी का अधिकार भी रहे और लोकतंत्र भी रहे ।

देश की आज की स्थिति को आप देखें । यहां बैलाडीला की बात कही गई है । आंध्र में भी कुछ हुआ, कर्नाटक, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में भी हुआ है । सब जगह रक्तपात हो रहा है । छात्रों में गम्भीर असन्तोष है । उसकी प्रतिक्रिया अनेक रूपों में देखने को मिलती है । इस असन्तोष के कारण उनमें अनुशासनहीनता की भावना है । कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं बम फेंके जा रहे हैं, पटरियों की फिश प्लेट्स उखाड़ी जारही हैं । भोपाल में मौलाना आजाद कालेज में आग लगा दी गई । कहीं यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर का घेराव होता है, उसे मारा-पीटा जाता है, छुरे चलते हैं । यह सब क्यों होता है ? लोग आसानी से कह देते हैं कि छात्रों में अनुशासनहीनता है, उदंडता है । कोई कहता है कि सिनेमा देखने के कारण इन में इस प्रकार की प्रवृत्ति जाग्रत हो गई है । लेकिन इन बातों में कोई तथ्य नहीं है । हमें इस की गहराई में जाना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है, हमारे देश की यह स्थिति क्यों है । मैं समझता हूं कि यह स्थिति केवल इसलिए है कि छात्रों और नौजवानों में अपने भविष्य के प्रति आशंका और अनिश्चितता की भावना है । आज हमारे देश में काश्मीर से ले कर कन्या कुमारी तक नौजवानों के सामने क्या भविष्य है ? आज उन्हें लगता है कि हम कितना ही पढ़-लिख जायें, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा, क्या हम एक पैसे की भी कमाई कर सकेंगे ।

पिछले दो दिनों से छठी योजना पर बहस चल रही है, जिसके बारे में हम ने कहा है कि हम इस योजना को एक रोजगार-अभिमुखी रूप प्रदान कर रहे हैं, रोजगार देना उसका पहला लक्ष्य है । लेकिन वह कैसे सम्भव होगा ? इस पर कौन विश्वास करेगा ? रोजगार-अभिमुखी होने की बात तो पहली योजनाओं में भी कही गई थी । इसलिए लोग कैसे इस पर विश्वास करें ।

अगर हम इस विधेयक को पारित करते हैं, तो फिर इस देश के नवयुवकों के हृदय में एक नई आशा का संचार हो जायेगा । वे कहेंगे कि जिस दिन हमारी उम्र 18 बरस से अधिक हो जायेगी, उस दिन हमें काम देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, और जब तक वह काम नहीं देगी, तब तक उसे हमें बेकारी का भत्ता देना पड़ेगा । किसी भी व्यक्ति के दिमाग़ में अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता नहीं रहेगी । आज जो असन्तोष व्याप्त है, जो उपद्रव और उत्पाद हो रहे हैं, उन सब को इस विधेयक को पारित करके, कलम की नोक से एक साथ समाप्त किया जा सकता है । यह पैनेशिया है । इस रोग की जड़ का पता लगा कर उसका निदान करना चाहिए । केवल गोली-लाठी चला कर और यूनिवर्सिटियों को बन्द करके हम छात्रों और युवकों के असन्तोष को समाप्त नहीं कर सकेंगे, चाहे कितनी गोलियां चलाई जायें, चाहे कितने लोगों को भून दिया जाये ।

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

आखिर बैलाडिला में यह काण्ड क्यों हुआ ? उन मजदूरों को लगा कि अगर हमारी छटनी हो जायेगी, तो कल से हमारा क्या होगा । हमारे बाल बच्चों को रोटी कहां से मिलेगी । अभी तो उनको काम देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । अगर मेरा यह संविधान संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो गया होता, अगर मौलिक अधिकारों में काम और आजीविका प्राप्त करने का अधिकार भी जोड़ दिया गया होता, जिसको मैंने अनुच्छेद 23ए के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, तो सरकार इस बात के लिए बाध्य होती कि यदि जापान द्वारा आयरन और न खरीदो आने के कारण बैलाडिला में खदाने बन्द हो जाती हैं, तो भी उसे वहां के कर्मचारियों को दूसरा काम देना पड़ेगा और जब तक वह काम नहीं देगी, तब तक उन्हें बेकारी भभा देना पड़ेगा । यदि यह स्थिति होती तो बैलाडिला का हृदय विदारक काण्ड नहीं होता ।

यदि संविधान में इस आशय का संशोधन पहले से हो गया होता, तो पन्तनगर में जो कुछ हुआ है, वह क्यों होता ? वहां फार्म-लेबर के साथ जो व्यवहार हुआ, वह सर्वविदित है । सैकड़ों लोगों को भून दिया गया । अगर यह संशोधन पहले ही हो गया होता, तो पन्तनगर और बैलाडिला के जैसे कांड न होते, बच्चों को आग में डाल देने जैसे अनर्थ न होते । मैं तो समझता हूं कि यदि इस देश की धरती पर इस प्रकार की घटनायें होती हैं, तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। यह धरती फट जाये और हम रसातल में चले जायें ।

हम जनता के प्रतिनिधि हैं । जनता ने बड़ी आशा के साथ हमें चुन कर यहां भेजा है । आज इस देश में जो कुछ हो रहा है, उस का एकमात्र कारण यह है कि लोग अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं हैं । हमने जनता को भी वचन दिया है, अभी तक हम ने उसे पूरा नहीं किया है । जब इतने दिनों तक उसे पूरा नहीं किया है, तो जनता में निराशा और प्रतिकूल प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक है । इसलिए हमने जनता को जो वचन दिया है, हमें उसे निभाना ही होगा जिससे समूचे देश में फैले हुए असन्तोष और अशान्ति का निवारण किया जा सके ।

हमारे कुछ राज्यों ने इस दिशा में कुछ कदम उठाये हैं । वह प्रशंसा के पात्र हैं । जैसे बंगाल है । बंगाल की सरकार ने अभी हाल ही में एक कानून बनाया है । उन्होंने कहा है कि पांच साल से जिन लोगों के नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज के रजिस्टर में लिखे हुए हैं और अगर उन को काम नहीं मिल सका है तो उनको वहां की सरकार बेकारी का भत्ता देगी । यह एक शुभारंभ है । इसी तरह पंजाब की सरकार ने भी एक निर्णय किया है कि वह भी उन लोगों को बेकारी का भत्ता देंगी जो लोग पांच वर्षों से एम्लायमेंन्ट एक्सचेंज के रिजस्टर में दर्ज हैं और उन्हें काम नहीं मिला है । महाराष्ट्र में भी यह किया गया है । मैं इस को पार्टी ईश्यू नहीं बनाना चाहता, आप इस को गलत न समझें । महाराष्ट्र की सरकार ने भी जो एम्प्लायमेंन्ट गारंटी स्कीम लागू की है उसके हम हृदय से प्रशंसक हैं । उन्होंने भी यह किया है कि तीन वर्षों से जो लोग काम चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिल सका है तो उन्हें शायद वह एक रुपया रोज, तीस रुपया महीना ऐसा कुछ देंगे, लेकिन भूखों नहीं मरने देंगे । यह जिम्मेदारी कम से कम उन्होंने कबूल की है कि समाज की, राष्ट्र की, राज्य की यह जिम्मेदारी है कि इस देश में जो पैदा हुआ है उस को भूखों नहीं मरने देंगे, उस को जीविका का अधिकार हम प्रदान करेंगे, यह समाज की जिम्मेदारी है । काम पाना जन्मसिद्ध अधिकार उस दिन से हो जाता है जिस दिन से हम इस भूमि पर पैदा होते हैं । जिस दिन से कोई इस वसुन्धरा पर आता है उस दिन से उसके प्रति समाज की यह जिम्मेदारी है कि वह उसे जीविका का अवसर प्रदान अवश्य

करे। उस का यह अधिकार हो जाता है कि वह अपना पूर्ण जीवन जिये और उसको वह सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। यह बात अगर कहीं भी स्वीकार की गई तो हम उसकी भूरिभूरि प्रशंसा करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने एम्पलायमेंट गारंटी की स्कीम लागू की है और केन्द्रीय सरकार के सामने वह स्वीकृति के लिए है। अभी उस को स्वीकृति नहीं मिली है। मैं मानता हूं कि न केवल उस को ही केन्द्रीय सरकार स्वीकृति देगी बल्कि समूचे देश के लिए इसे स्वीकार किया जाएगा और लागू किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री सही माने में इस देश के महान गांधीवादी नेता हैं। सत्य पर उन की अटूट निष्ठा है। यह जो घोषणापत्र तैयार किया गया था इस में उन की भी सहमति है। यह वचन उन्होंने दिया है कि देश की जनता को इसलिए उनसे हमारी यह अपेक्षा है कि वह यह अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिससे आगे आने वाली मानव जाति उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए याद रखे कि उन्होंने अपने देश के नागरिकों को काम करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया, हिन्दुस्तान को उन्होंने यह अमिट वरदान दिया और आगे आने वाली संतति के लिए भी सदा सदा के लिए यह वरदान दिया। कभी कभी वह यहां कह दिया करते हैं कि यह अनएम्प्लायमेंट एलावेंस नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह डोल है, यह भिक्षा है, दान है। किन्तु यह भिक्षा नहीं है। यह अधिकार है। काम प्राप्त करने का हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। वे भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इस देश में हम पैदा हुए और आप से चाहते हैं कि आप इस अधिकार को स्वीकार करें और मान्यता प्रदान करें क्योंकि आप ने वचन दिया है और आपके वचन पर अगर हिन्दुस्तान का नागरिक विश्वास नहीं करेगा तो फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति इस देश के अन्दर है जिस के वचन पर विश्वास किया जायगा? इसलिए इस बात को नहीं कहना चाहिए कि यह डोल है, यह दान है, यह भिक्षा है। यह भिक्षा नहीं है। यह हमारा अधिकार है और हमें प्राप्त होना चाहिये। यहां के हर नागरिक को हर नवयुवक को यह मिलना चाहिए। इस से उस को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप वंचित रखना चाहेंगे तो इस देश की जनता अब यह जान गई है कि वह अपना अधिकार कैसे ले सकती है। अगर उसने अपनी लोकतांत्रिक आजादी का अधिकार ले लिया है तो वह काम और जीविका का अधिकार भी ले लेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कहा करती थीं कि 26 जून 1975 के पूर्व की स्थिति अब इस देश में कभी नहीं आएगी, वह समझती थी कि इस देश की नियति का निर्णय करने का अधिकार के वल उन को है, लेकिन देश की जनता ने बता दिया कि 26 जून, 1975 के पूर्व की स्थिति आएगी तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारी कुछ भी स्थिति नहीं है। देश की जनता ने यह बता दिया. कि 26 जून 1975 के पहले की स्थिति हम लौटा कर ही रहेंगे और वह कर के दिखा दिया। अगर हम यह कहेंगे कि यह अधिकार हम तुम्हें नहीं प्रदान करेंगे तो जिस तरह से उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से वह अधिकार ले लिया और उन को इतिहास के गर्त में ढकेल दिया, उसी तरह इतिहास के गर्त में हमारा भी कहीं पता नहीं रहेगा अगर हम ने अपने वचनों को पूरा नहीं किया।

आज देश के नवयुवकों को बहुत बड़ा आघात लगा है। उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा है भविष्य की अनिश्चितता की। उनकी इस भविष्य की अनिश्चितता को मिटाना, उनके भविष्य में प्रकाश लाना-यह हमारी सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य का यह दायित्व आज से ही नहीं है, प्राचीन काल में भी माना गया था कि राज्य का दायित्व है कि जो लोग उस राज्य में बसते हैं, उनको आघात से बचाये,

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

उनके ऊपर जो मुसीबत आयें उससे उनकी रक्षा करें। आज देश के नागरिकों के सामने, देश के नवयुवकों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी आशंका है भविष्य की अनिश्चितता और इस अनिश्चितता को मिटाना राज्य का कर्त्तव्य है। महाराज दलीप ने एक बार कहा था :

छतात् किल त्रायत् इत्युदग्रह :
क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़: ।
राज्येन् किमतद् विपरीत वृत्ते:
प्राण रूत्कोषमली मसैर्वा ।

छत्र का अर्थ हैं शासन । शासन शब्द दुनिया में प्रसिद्ध है । उसका अर्थ है कि शासन छत से, आघात से, मुसीबत से, संकट से लोगों को बचावे ; वही शासन होता है। जो शासन उसके विपरीत आचरण करता है उस हमको क्या लेना देना ? अगर राज्य हमको मुसीबत से नहीं बचा सकता, संकट से हमारी रक्षा नहीं कर सकता, आज देश मे व्याप्त भयावह बेकारी के संकट मे नहीं बचा सकता तो उस राज्य से हमे क्या लेना देना ? उसका अर्थ है कि उस प्राण से भी क्या प्रयोजन है जिसको ताडना सहनी पड़े, जिसको निंदा सहनी पड़े। यदि इस देश की जनता के सामने हमको यह सुनना पड़े कि तुमने जो वचन जनता को दिया था क्या वह पूरा किया तो इसको सुनने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। इस तरह के प्राण रखकर हम क्या करेंगे ? जो संभावित है, लोक मे प्रतिष्ठित है, जिसकी लोक मे इज्जत है उसकी अपकीर्ति हो जाये, उसके वचन पर विश्वास न रह जाये तो उसके लिए वह मृत्यु से भी दु:खद है।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप 25-30 मिनट बोल चुके है, अब दूसरों को भी मौका दीजिए।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं दो बातें कह कर समाप्त करूंगा।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप काम का अधिकार प्रदान कर दें यहां की जनता को तो एक बहुत बड़ा काम आपका और होगा, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इसका एक बहुत बड़ा परिणाम यह होगा कि आज जो सम्पत्ति का मोह है वह समाप्त हो जायेगा। अभी आज लोग सम्पत्ति क्यों इकट्ठी करते है ? लोग रिश्वत लेकर, काला धंधा करके और टैक्स की चोरी करके सम्पत्ति क्यों जोड़ते हैं ? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बाल बच्चों के लिए क्या होगा, उनके लिए तो हमे कुछ बचाकर रखना ही चाहिए। अगर उनको एक बार इस बात का विश्वास हो जाये कि देश के संविधान में लिखा हुआ है कि उनको जीविका का अधिकार मिलेगा तो उन्हें अपने बाल बच्चों के लिए सम्पत्ति छोड कर जाने की आवश्यकता नही रह जायेगी। एक बार उनको विश्वास हो जाये कि उनके बाल बच्चे भूखे नही मरेंगे तो उनके मन से सम्पत्ति का मोह समाप्त हो जायेगा। हम सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालने की बात करते हैं लेकिन उसके बाद भी लोगों का सम्पत्ति के प्रति मोह बना रहेगा और लोग गलत तरीके से सम्पत्ति एकत्र करते रहेंगे, धन का संचय करते रहेंगे क्योंकि अपने बाल बच्चों के लिए कुछ बचाकर जायें—यह भावना उनके मन मे बनी रहेगी। इस सम्पत्ति के मोह को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि हम काम का अधिकार दे। अगर यह कहा जाये कि इस काम के लिए शासन के पास धन नही है तो यह बात भी स्वीकार नही की जा सकती। इसी साल सरकार ने 1075 करोड़ के घाटे का बजट पास कराया है। अगर उस घाटे को हम पूरा कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने फाइनेंशियल मेमोरैंडम में दिया है, अगर आप रोजगार का अधिकार देते हैं तो दस अरब रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस देश में नशाबंदी के लिए 4-6 अरब रुपए का घाटा हम बरदाश्त करते जा रहे हैं तब इस देश के नागरिकों को, इस देश के नवयुवकों

को काम का अधिकार देने के लिए क्या आ 4-6 अरब रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हैं ? यह काम केवल आज के लिए ही नहीं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है । क्या इसके लिए आप इतना रुपया भी खर्च नहीं कर सकते हैं ? लोग बड़ी खुशी से टैक्स देंगे । मैं इंग्लैंड में गया था, वहां लिखित कांस्टीटयूशन नहीं है लेकिन काम का अधिकार लोगों को है । वहां हमने देखा कि अगर किसी को एक हफ्ते में 21 पौंड मजदूरी मिलती है तो उसे 6 या साढ़े 6 पौंड टैक्स देना पड़ता है । और बड़ी खुशी से दे देता है, कोई टैक्स इवेजन नहीं होता है। क्यों दे देता है ? इसलिये कि वह जानता है कि बचा कर क्या करना है मेरे लड़के को अन-एम्पलायमेन्ट बेनिफिट मिलेगा या काम मिलेगा । हिन्दुस्तान से जो लोग इंग्लैंड जाते हैं, वे वहां घर खरीदते हैं, अपना घर बनाते हैं, लेकिन इंग्लैंड के लोग किराये के मकान में रहते हैं और हिन्दुस्तान के लोगों पर हंसते हैं । वे जानते हैं कि हमारे लडके को तो घर मिलेगा ही, इसलिये खरीद कर क्या करना है । जहां-कहीं भी इस तरह की व्यवस्था है, वहां टैक्स इवेजन नही होता है, काला-धन इकट्ठा नहीं होता है, वहां सम्पत्ति का मोह भी नहीं होता है।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, बहुत अधिक विस्तृत ढंग से कहने की जरूरत नहीं है । प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी किया जाना चाहिये । हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के अन्दर इस काम को किया जायेगा, 1960 तक यूनीवर्सलाइज करना था, लेकिन 1978 आ गया, आज तक प्राइमरी एजूकेशन कम्पलसरी नहीं हुआ । इसलिये इस को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

जहां तक तीसरी बात का सम्बन्ध है— मैंने इस में यह अनुच्छेद जोड़ा है कि वृद्धावस्था में पेन्शन की व्यवस्था होनी चाहिये । यह पेन्शन उन वृद्धों को मिलनी चाहिये—जिन के पास कोई साधन नहीं है । आप ने पार्लियामेन्ट के मेम्बरों को पेन्शन देने की व्यवस्था की है वे राजे-महाराजे जिन के पास अरबों की सम्पत्ति है, यदि वे 5 वर्ष पार्लियामेन्ट के मेम्बर रह चुके हैं तो उन को भी पेन्शन मिल रही है और देश का गरीब, हरिजन, आदिवासी जो 60 वर्ष काम करने के बाद काम के लायक नहीं रह जाता है, वह पेन्शन पाने का अधिकारी नहीं है। आई०ए० एस० और आई० सी एस० अफसरों को पेन्शन मिलती है चाहे वे रिटायर होने के बाद भी किसी भी ओहदे पर काम करते हों, अगर वे मिनिस्टर बन जायें तो भी उन्हें पेन्शन मिलती है, लेकिन इस देश के साधारण से साधारण नागरिक को, गरीब-से-गरीब नागरिक को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, 60 वर्ष के बाद जब वह काम करने के लायक नहीं रहता, तो भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं हैं । इसलिये मैं यह संशोधन चाहता हूं कि उस को भी पेन्शन पाने का अधिकार मिलना चाहिये ।

मुझे विश्वास है कि सारा सदन मेरे इस संविधान संशोधन विधेयक का एक स्वर से समर्थन करेगा । यह किसी विशेष दल का प्रश्न नहीं है, किसी विशेष पक्ष का प्रश्न नहीं है, समूची मानवता को प्रेरणा देने का प्रश्न है देश की जनता को जो आपने वचन दिया है उसे पूरा करना है । इसलिये मुझे विश्वास है कि मेरा यह विधेयक एक स्वर से पारित होगा ।

Mr. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, आदरणीय शास्त्री जी ने जिस साधु-विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है, उस के सम्बन्ध में कोई विचार-वैभिन्य

[डा० रामजी सिंह]

नहीं हो सकता है । वस्तुत : जीवन में अजीविका का अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है । जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था—स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह से जीविका का भी अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । हमारे संविधान के निदेशक-सिद्धान्तों में अनुच्छेद 39 में इस का विधान-निर्माताओं ने पहले ही उल्लेख किया था, लेकिन आज 30 वर्ष के बाद भी यह एक दिवास्वप्न ही रहा है और अभी जनता पार्टी ने भी जो छठी पंच वर्षीय योजना प्रस्तुत की है उस में भी यह पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं होने की ही बात है । इसलिये यह आवश्यक है कि केवल शासकों पर, चाहे वे जिस दल के हों, यह नतिक ही नहीं बल्कि वैधानिक दायित्व भी हो इस दृष्टि से काम का अधिकार संविधान में अंकित कर लिया जाय । जब तक यह हमारे मौलिक अधिकार में नहीं रहेगा, शासक और प्रशासक इसको किसी न किसी बहाने टालते ही रहेंगे ।

यह कहा जाता है कि यह बात तो अच्छी है, लेकिन यह व्यवहार्य नहीं है । सभापति महोदय, दुनिया के अनेक देशों में जब यह व्यवहार्य हो सकती है, तो भारत में व्यवहार्य क्यों नहीं हो सकती । रूस के संविधान की धारा 118 में दिया गया है—

"The citizens of the U.S.S.R. shall have the right to work, that is the right to guaranteed employment and payment for their work in accordance with its quantity and quality."

रूस का तो बहुत पहले से था लेकिन युगोस्लाविया के संविधान की धारा 159 में यह लिखा हुआ है :

"The right to work shall be guaranteed.

"Rights acquired on account of labour shall be inalienable."

मैं विस्तार से तो इस में नहीं जाऊंगा लेकिन बहुत सारे देशों के संविधानों में यह बात है । जापान एशिया का देश है और जापान के संविधान की धारा 27 में यह लिखा हुआ है :

"All people shall have the right and obligation to work. Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law. Children shall not be exploited."

उसी तरह से फिर अगर हम एशिया से योरप की तरफ जाएं, तो छोटे से देश रोमानिया की तरफ अगर ध्यान देते हैं, तो उन के संविधान में भी धारा 18 में यह लिखा हुआ है :

"In the Socialist Republic of Rumania, the citizens have the right to work. Each citizen is given the possibility to carry on, according to his training an activity in the economic, administrative, social or cultural field and is remunerated according to its quantity and quality. For equal work there is equal pay."

इस प्रकार से दुनिया के अनेक देशों में जैसे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के संविधान की धारा 24 में यह है :

"Every citizen of the German Democratic Republic has the right to work. He has the right to employment and its free selection in accordance with social requirements and personal qualifications. He has the right to pay according to the quality and quantity of the work. Men and women, adults and young people have the right to equal pay for equal work/output."

इसी तरह से दुनिया के अन्य देशों के संविधानों में ऐसा दिया हुआ है । चीन के संविधान की धारा 27 में, जो संविधान 1975 में लागू हुआ था, लिखा हुआ है :

"Acticle 27 of 1975 Constitution *inter alia* provides 'citizens 'have the right to work and the right to education'. Working people have the right to rest and the right to matierial assistance in old age and in case of illness or disability."

मैंने इन देशों के संविधानों का इसलिए जिक्र किया है कि अगर हमारे यहां कहा जाता है कि यह व्यवहारिक नहीं है तो यह केवल एक प्रकार का लोगों के सामने एक जाल खड़ा करना है । यह व्यवहारिक

हो सकता है अगर इस के लिए राजनीतिक संकल्प हो । अगर इस के लिए पालिटीकल बिल हो, तो यह लागू हो सकता है । हमारे हृदय मे राजनीतिक सकल्प नही होगा, तो जिस तरह से 30 वर्षों मे यह लागू नहीं हुआ तो अगले 100 वर्ष मे भी लागू नही हो सकता है । इसलिए यह हमारे ध्यान मे रखने की बात है और हमारी जनता पार्टी की सरकार का तो यह नैतिक अनुबध है । अगर वह वायदा-खिलाफी इस सम्बन्ध मे करती है, तो जनता पार्टी की सरकार मे रहने के हम हकदार नही हैं । जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस की जो आर्थिक रूप रेखा है, उस पर जब हम विचार करते हैं तो उस मे पहली चीज यह दी गई है, 'सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को रद्द करना ।' यह बहुत खुशी की बात है कि जनता पार्टी इस दिशा मे आगे बढ़ रही है और सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को निरस्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं । यह तो प्रथम हुआ ...

MR CHAIRMAN : Dr. Ramji Singh, you will continue on the next occasion. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, May 6 1978/Vaisakha 16, 1900 (Saka).

MGIPND—JOB III—1014 LS—8-7-78—